राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 143

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 1 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

टीम इंडिया में दखल पर अनुष्का ने तोड़ी चुप्पी

>> 14

सरोकार

युवाओं को रोजगार दे रही मुरादाबादी बिरयानी

रामपुर : बिरयानी का नाम सुनते ही नॉनवेज के शौकीनों के मुंह में पानी आ जाता है।

मुरादाबादी बिरयानी की अपनी पहचान है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत अनेक शहरों में मुरादाबादी बिरयानी खूब बिक रही है। युवाओं ने इसे रोजगार का साधन बना लिया है। (पेज-10)

जागरण विशेष

फूलों के खेतों में लिविंग कॉटेज से लेकर स्वीमिंग पूल तक

मेरठ : 'पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ गन्ना की खेती' के मिथक को प्रगतिशील किसान ने तोड़ दिया।

फल-फूल और सब्जियों की खेती के अलावा खेतों में ही सुंदर नेचर पार्क भी बनाया, जिसमें पर्यटकों की भीड़ जुटती है। (पेज-10)

भारतीय पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की हुई जासूसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टैंट मैसेजिंग कंपनी वाट्सएप ने गुरुवार को कहा कि इजरायली स्पाइवेयर 'पेगासस' के जरिए अनाम इकाइयों ने भारतीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की। कंपनी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर करीब 1,400 वाट्सएप उपयोगकर्ताओं की जासूसी की गई है। केंद्र सरकार ने इस मामले में वाट्सएप से जवाब मांगा है।

वाट्सएप ने यह नहीं बताया है कि किसके कहने पर पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए। कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि भारत में इस स्पाइवेयर हमले से कितने पत्रकार और कार्यकर्ता प्रभावित हुए। लेकिन उसके प्रवक्ता ने कहा कि इस सप्ताह हमने जिन लोगों से संपर्क किया है उनमें भारतीय उपयोगकर्ता भी शामिल हैं।

वाट्सएप ने कहा है कि मई में उसे ऐसे अत्याधुनिक साइबर हमले का पता चला जिसमें उसकी वीडियो कालिंग प्रणाली को हैक कर उसके उपयोगकर्ताओं को मालवेयर भेजा गया।

- वाट्सएप ने राज खोला, इजरायली स्पाइवेयर 'पेगासस' ने की जासूसी
- वाट्सएप ने कहा, कंपनी को मई में इसके बारे में चला था पता
- सरकार ने मैसेजिंग एप कंपनी से चार नवंबर तक मांगा जवाब

यूजरों को दी थी जानकारी

कंपनी ने कहा है कि उसने लगभग 1,400 उपयोगकर्ता को विशेष संदेश भेजकर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि दुनियाभर में वाट्सएप के लगभग 1.5 अरब यूजर हैं। इनमें भारत के करीब 40 करोड़ लोग शामिल हैं।

इजरायली कंपनी पर ठोका मुकदमा

वाट्सएप ने कहा है कि इस साइबर हमले के लिए उसने इजरायली निगरानी फर्म एनएसओ ग्रुप पर मंगलवार को कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में केस दर्ज कराया है। कहा जा रहा है कि इसी कंपनी की तकनीक की मदद से अज्ञात इकाइयों ने जासूसी के लिए दुनिया के 1400 वाट्सएप यूजरों के फोन हैक किए। इनमें राजनयिक, पत्रकार और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

इजरायली कंपनी ने आरोप नकारे : इजरायल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने अज्ञात इकाइयों को तकनीकी मुहैया कराने के आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि वह आतंकवाद और गंभीर अपराध से निपटने के लिए सिर्फ लाइसेंस वाली सरकारी खुफिया एजेंसियों को ही अपनी तकनीक उपलब्ध कराती है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार निजता की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध

इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार अपने नागरिकों की निजता की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, सरकार

भारतीय नागरिकों की निजता के हनन को लेकर चिंतित है और वाट्सएप से पूछा गया है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ और वह भारतीय नागरिकों की निजता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। प्रसाद ने कहा, किसी भी तरह की निगरानी के लिए सुरक्षा एजेंसियां एक निश्चित प्रोटोकॉल का पालन करती हैं। यह कदम केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में ही उठाया जाता है। मंत्रालय ने इस मामले में वाट्सएप से चार नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है। वहीं, गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने जासूसी संबंधी खबरों को सरकार की छवि खराब करने की कोशिश बताते हुए कहा, अगर कोई लोगों की निजता के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरकार शुरू से ही सोशल मीडिया कंपनियों खासतौर पर वाट्सएप पर इस बात का दबाव बना रही है कि वह मैसेज डिक्रिप्ट करने के बजाए उसके स्रोत का पता लगाने में मदद करे। लेकिन वाट्सएप निजता में हनन का हवाला देकर ऐसा करने से बचती रही है।

सरकार का स्पाइवेयर पेगासस खरीदने से इन्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने इजरायली स्पाइवेयर पेगासस खरीदा है। सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई सूचना उसके पास नहीं है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 23 अक्टूबर 2019 को ही सौरव दास नाम के एक व्यक्ति ने आरटीआइ के जरिए केंद्र सरकार से पेगासस स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने संबंधी जानकारी मांगी थी। यह सॉफ्टवेयर फोन पर मैसेज पढ़ने, पासवर्ड एकत्र करने और फोन की लोकशन जानने में माहिर माना जाता है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को भेजे अपने जवाब में ऐसी कोई भी सूचना उपलब्ध होने से इन्कार किया है। मंत्रालय के सीपीआइओ के हस्ताक्षर से भेजे गए अपने जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रार्थी संतुष्ट न होने की स्थिति में एक महीने के भीतर एपीलैट अथॉरिटी में अपील दाखिल कर सकता है।

न्यूज गैलरी

सिटी न्यूज ▸ पृष्ठ 2

फांसी के तख्ते के और करीब पहुंचे निर्भया के गुनहगार

नई दिल्ली : देश को झकझोर देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड के गुनहगार फांसी के तख्ते के और करीब पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही दोषियों की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा माफ किए जाने पर ही वे फांसी के फंदे से बच सकते हैं, अन्यथा मौत की सजा तय है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 5

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बने केंद्रशासित प्रदेश

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर व लद्दाख गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश बन गए। श्रीनगर के राजभवन में जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू और लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर राधाकृष्ण माथुर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही विकास का नया दौर शुरू होगा।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

आरसेप पर अंतिम फैसले से पहले भारत कशमकश में

नई दिल्ली : सोमवार को आसियान के 10 देशों समेत 16 देशों के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते यानी आरसेप पर अंतिम फैसला होना है, लेकिन भारत इसे लेकर कशमकश में है। सभी देशों के अधिकारी बैंकॉक में मंत्रणा कर रहे हैं। भारत चाहता है कि कृषि उत्पादों व सेवा उद्योग पर उसकी चिंताएं अंतिम मसौदे में शामिल की जाएं।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

जाधव मामले में पाकिस्तान ने किया वियना संधि का उल्लंघन

संयुक्त राष्ट्र : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के अध्यक्ष जज अब्दुलकावी यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में वियना संधि का उल्लंघन किया। यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जाधव को वियना संधि के तहत सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

चीन ने बढ़ाया तनाव, भारत ने याद दिलाया कश्मीर पर अवैध कब्जा

रिश्तों में तल्खी ▸ पहले बीजिंग फिर पाक ने अनुच्छेद 370 हटाने को बताया गैरकानूनी

भारत ने कहा, आंतरिक मामलों में किसी भी देश को बोलने का हक नहीं

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

ठीक 20 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच मामल्लपुरम में द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने के लिए जो सहमति (चेन्नई कनेक्ट) बनी थी वह हवा होती दिख रही है। इसके पीछे कश्मीर सबसे बड़ी वजह के तौर पर सामने आया है। गुरुवार को जब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नया सवेरा हो रहा था तो चीन और पाकिस्तान ने एक सुर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को गैरकानूनी करार दिया। भारत ने पाक के बयान पर तो प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन चीन के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए चीन को याद दिलाया कि उसने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर

रवीश कुमार — फाइल फोटो

कब्जा कर रखा है और पाक के साथ मिलकर कश्मीर के एक हिस्से पर सड़क बना रहा है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और उसके हिस्से को केंद्र सरकार के अधीन लेने का फैसला पूरी तरह से गैरकानूनी है। भारत ने इस फैसले से चीन के एक हिस्से को अपने में मिलाने का काम किया है और इससे चीन की संप्रभुता को चुनौती दी गई है। चीन इसकी भर्त्सना करता है। भारत ने जिस तरह यह कदम उठाया है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। भारत का यह कदम इस सच्चाई को नहीं बदल सकता कि वह हिस्सा चीन के नियंत्रण वाला है। चीन भारत से आग्रह करता है कि वह फैसले को तुरंत बदले और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए पूर्व में की गई संधियों का पालन करे ताकि सीमा विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हल हो सके।' वहीं, पाक का कहना था कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का मकसद जनसांख्यिकी ढांचे को बदलना है। पाक विदेश मंत्रालय के अनुसार, 'कश्मीर की स्थिति में बदलाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और भारत-पाक के बीच समझौतों खासकर शिमला समझौते का उल्लंघन है। कश्मीर अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य विवादित क्षेत्र है और भारत से इसे बदल नहीं सकता।'

चीन के बयान के कुछ ही घंटे बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'चीन इस बारे में भारत की स्थायी नीति से भली भांति परिचित है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के इलाके को लेकर भारत का फैसला पूरी तरह से आंतरिक है। इन मुद्दों पर हम चीन या किसी भी दूसरे देश की तरफ से टिप्पणी की उम्मीद नहीं करते। वैसे चीन भी जम्मू-कश्मीर के बड़े इलाके पर कब्जा किए हुए है। साथ ही 1963 में किए गए चीन-पाक सीमा समझौते के तहत चीन ने भारत के एक हिस्से को भी गैरकानूनी तरीके से कब्जे में ले रखा है। इस हिस्से को पाक ने चीन को सौंपा है।' भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की याद भी दिलाई जो जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर बनाया जा रहा है। कहा, चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हिस्सा भी पाकिस्तान के पास 1947 से गैरकानूनी तरीके से है। जहां तक सीमा विवाद सुलझाने का मामला है तो भारत हमेशा से इसे शांतिपूर्ण तरीके और बातचीत से सुलझाने का समर्थक रहा है। इसको लेकर 2005 में दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी और हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में भी ऐसी समझ बनी थी। दोनों देश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भी तैयार हुए हैं।

अमेरिका से जुड़ा है तनाव का सिरा पेज>>3

राष्ट्रगान के दौरान बैठी रह सकेंगी जर्मन चांसलर एंजिला मर्केल

नई दिल्ली : जर्मनी की चांसलर एंजिला मर्केल शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक कार्यक्रम में दोनों देशों के राष्ट्रगान के दौरान बैठी रह सकेंगी। मर्केल की बीमारी को देखते हुए जर्मनी ने इसके लिए विशेष अनुरोध किया था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मर्केल को अनुमति देने के लिए राष्ट्र गान से जुड़े आदेश के कुछ खास प्रावधानों को लागू किया जाएगा। (पेज-3)

राम मंदिर पर फैसले के लिए खुद को तैयार कर रहा संघ

नई दिल्ली : अयोध्या में राम मंदिर पर किसी भी फैसले के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को तैयार कर रहा है। संघ का मानना है कि नवंबर मध्य तक आने वाला कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में होगा। हालांकि, विपरीत फैसला आने की स्थिति के लिए भी वह रणनीति पुख्ता कर लेना चाहता है। छतरपुर में चल रही संघ परिवार की तीन दिनी बैठक में गुरुवार को दूसरे दिन भी मंदिर का मुद्दा छाया रहा। (पेज-7)

'जानबूझकर नहीं लंबित रहा अयोध्या मामला'

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि के मुकदमे को सुनने वाले न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे अयोध्या विवाद आठ वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के सवाल पर कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा जानबूझकर हुआ। इसके पीछे और कई कारण हो सकते हैं। जैसे मुकदमे से जुड़े रिकार्ड के अनुवाद में बहुत वक्त लगना, सुनवाई करने वाली पीठ का गठन न हो सकना आदि। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में जस्टिस बोबडे से पूछा गया कि क्या फैसला लिखने में न्यायाधीशों की अपनी आस्था और विश्वास का प्रभाव होता है तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। न्यायाधीश इस सबसे ऊपर उठ कर मुकदमे के तथ्यों और कानून को देखकर फैसला देते हैं। ये चीजें उनके आड़े नहीं आतीं।

जस्टिस एसए बोबडे इतना जरूर मानते हैं कि अयोध्या के मुकदमे की व्यापकता उसका असर और अवधि आदि सब मिला कर देखा जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है।

- भावी सीजेआइ बोले-नहीं लगता किसी कोर्ट ने ऐसा मामला सुना होगा
- कहा-लोग देश की न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखें

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। — जागरण

मुकदमे का महत्व बताते हुए वह कहते हैं कि उनकी जानकारी में नहीं है कि दुनिया की किसी अदालत ने इस तरह का मुकदमा सुना होगा। हालांकि मामले में फैसला लंबित होने के कारण मुकदमे की मेरिट पर बोलने से परहेज कर गए।

भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए जस्टिस एसए बोबडे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के सेवानिवृत होने के बाद 18 नवंबर को 47वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। जस्टिस बोबडे अयोध्या राम जन्मभूमि का मुकदमा सुनने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा हैं। इस मामले में 17 नवंबर से पहले फैसला आना है क्योंकि उसी दिन जस्टिस गोगोई सेवानिवृत हो रहे हैं।

सुनवाई के सीधे प्रसारण पर होगा विचार : सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के सीधे प्रसारण के मुद्दे पर उनका कहना है कि यह महत्वपूर्ण मामला है और अभी तक उन्होंने इस मामले को जांचा परखा नहीं है। अब वे इसे देखेंगे। अयोध्या मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसके सजीव प्रसारण की मांग उठी थी लेकिन बात बनी नहीं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इसे शुरू करने की व्यवस्था पर रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी थी।

संतुलन कायम रखने की जरूरत पेज>>7

जम्मू-कश्मीर में दीवार की तरह काम कर रहा था अनुच्छेद 370 : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के केवडिया में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। — एएनआइ

केवडिया (गुजरात), प्रेट्र : राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 एक दीवार की तरह काम कर रहा था और उसने राज्य में सिर्फ आतंकवाद को ही पोषित किया। साथ ही उन्होंने भारत की विविधता में एकता को देश के दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार दिया।

सरदार पटेल की 144वीं जयंती पर यहां 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नई व्यवस्था का मकसद जमीन पर लकीर खींचना नहीं बल्कि विश्वास की मजबूत कड़ी का निर्माण करना है।' मोदी ने कहा कि अनुच्छेद-370 हटाने के केंद्र के फैसले को वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के चरणों में समर्पित करते हैं। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर में एक दीवार की तरह था जो अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी। मोदी ने कहा, 'मैं सरदार पटेल को बेहद विनम्रता से यह बताने आया हूं कि दीवार गिरा दी गई है।' उन्होंने बताया कि राज्य में आतंकवाद के तीन दशक के दौर में 40 हजार से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल से प्रभावित उनकी सरकार देश के भावनात्मक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण के लिए काम कर रही है। इसके बगैर 21वीं सदी में शक्तिशाली भारत की कल्पना मुश्किल है। पूर्वोत्तर भी अब अलगाववाद से जुड़ाव की ओर बढ़ रहा है क्योंकि दशकों पुरानी समस्याएं अब समाधान के करीब हैं।

पाक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जो भारत के खिलाफ लड़ाइयां नहीं जीत सके वे अलगाववाद और आतंकवाद फैलाकर भारत की एकता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सदियों तक कोशिश करने के बावजूद कोई भी हमें मिटा नहीं सका या हरा नहीं सका। विविधता में एकता हमारा गौरव है और हमारी पहचान है। इतनी विविधता के बावजूद हमारी एकता से दुनिया आश्चर्यचकित है। भारत दुनिया के अन्य देशों से अलग है। हम अपनी विविधता से खुश हैं। हम विविधता में विरोधाभास नहीं बल्कि एकता देखते हैं। जब हम विभिन्न समुदायों और धर्मों की आस्था और परंपराओं का सम्मान करते हैं तो प्रेम और लगाव बढ़ता है। जब सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने का मिशन शुरू किया था तो एकता की भावना ने कई शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। सदियों पहले भारत को चाणक्य ने एकजुट किया था और उसके बाद पटेल ने यह काम किया। इस मौके पर पुलवामा हमले में शहीद जवान नसीर अहमद की पत्नी ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की प्रतिकृति भेंट की।

शाह बोले, पटेल के प्रयास से बना देश का वर्तमान मानचित्र पेज>>6

हाल बेहाल

1998 से 2016 के बीच सात राज्यों में सात साल कम हुई भारतीयों की आयु, उत्तर भारत में प्रदूषण बाकी देश के मुकाबले तीन गुना अधिक जानलेवा, सर्वाधिक प्रभावित हरियाणा, उप्र, दिल्ली, पंजाब समेत सात राज्यों में रहती है देश की 40 फीसद आबादी

जहरीली हवा का असर, घटी गंगा किनारे रहने वालों की उम्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

वायु प्रदूषण यानी जहरीली हवा अब लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। एक अध्ययन ने बताया है कि उत्तर भारत में जहरीली हवा के कारण गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले भारतीयों की आयु सात साल तक कम हो गई है। 1998-2016 के बीच हुए शोध में कहा गया है कि उत्तर भारत में प्रदूषण बाकी भारत के मुकाबले तीन गुना अधिक जानलेवा है। इस अध्ययन में सबसे अधिक प्रदूषित दिल्ली को बताया गया है। यहां 2016 के दौरान पीएम 2.5 का स्तर 114 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर रहा।

उत्तर भारत में 48 करोड़ से अधिक आबादी या कहें कि देश की 40 फीसद जनसंख्या गंगा नदी के किनारे रहती है। अत्यधिक दूषित हवा वाले यह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हैं। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट के अनुसार, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक 2016 आते-आते क्षेत्र में वायु प्रदूषण 72 फीसद तक बढ़ गया। इसके चलते उत्तर भारत में रहने वालों का जीवन 3.4 साल था, जो अब 7.1 साल तक कम होने लगा है।

शोध में कहा गया है कि गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वालों की आयु भारत के अन्य इलाकों में रहने वालों की आयु की अपेक्षा तीन गुना कम हो रही है। एक्यूएलआइ के अनुसार, भारत अगर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लक्ष्यों को हासिल कर लेता है और मौजूदा प्रदूषण में 25 फीसद की कटौती कर लेता है तो वायु गुणवत्ता में इस कदर सुधार होगा कि भारतीयों का औसत जीवन 1.3 साल बढ़ जाएगा। मैदानी इलाकों के लोगों की आयु दो साल बढ़ जाएगी। हिंदी बेल्ट के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के एक कार्यक्रम में असम के सांसद गौरव गोगोई ने कहा, वह इस विषय में एक प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश करेंगे। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उनका नया स्वच्छ वायु (संशोधन) अधिनियम उनकी सर्वोच्च वरीयता होगा। इसी कार्यक्रम में दिल्ली के अस्पताल गंगाराम के लंग्स स्पेशलिस्ट डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि दिल्ली में जनस्वास्थ्य की आपात स्थिति है। अब समय आ गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए।

नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मास्क पहनकर अभ्यास करते लिटन दास। — एएनआइ

मास्क पहनकर अभ्यास

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को टी-20 सीरीज खेलने के लिए आई बांग्लादेश टीम के बल्लेबाज लिटन दास ने अरुण जेटली स्टेडियम में मास्क पहनकर अभ्यास किया। ध्यान रहे 2017 में टेस्ट मैच के दौरान भी कुछ ऐसे ही हालत थे उस समय श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने मास्क पहनकर मैच खेला था। वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंचने की वजह से 20 मिनट तक खेल रोकना पड़ा था। (पेज-14)

शरद पवार से मिले संजय राउत और कांग्रेस नेता

मुंबई, एजेंसियां : महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना के बीच सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध के बीच अन्य विकल्पों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गईं हैं। इस क्रम में गुरुवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने राकांपा सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थरोट, वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण ने भी शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की।

पवार से राउत की मुलाकात ने सूबे में गैरभाजपा सरकार की अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि राउत ने चुनाव परिणाम की घोषणा वाले दिन (24 अक्टूबर) भी पवार से भेंट की थी। वहीं, कांग्रेस नेताओं की पवार से मुलाकात के बारे में सूत्रों ने बताया कि उन्होंने वर्तमान राजनीति हालात के मद्देनजर अपने गठबंधन की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। इसके बाद तीनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। बताते हैं कि पवार ने ही उनसे इस बारे में सोनिया से बात करने को कहा है। कांग्रेस ने गुरुवार को अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ भी बैठक की। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे।

- मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली रवाना
- कांग्रेस-राकांपा के समर्थन से शिवसेना सरकार गठन की अटकलें

एकनाथ शिंदे बने शिवसेना विधायक दल के नेता

मुंबई : महाराष्ट्र में विस चुनाव नतीजों की घोषणा के एक हफ्ते बाद भी सरकार गठन पर गतिरोध जारी है। इस बीच चौथी बार विस सदस्य बने एकनाथ शिंदे को गुरुवार को शिवसेना विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फड़नवीस के दिए बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा, हम मित्रपक्ष को मित्रपक्ष मानते हैं शत्रुपक्ष नहीं। (पेज-4)

इससे पहले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चह्वाण ने एक बार फिर शिवसेना को उकसाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। इसके बावजूद यदि वह सरकार बनाने में अक्षम रहती है तो दूसरे बड़े दल के रूप में शिवसेना को मौका मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि शिवसेना सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगती है तो हम कांग्रेस आलाकमान से इस पर विचार करने को कहेंगे। पृथ्वीराज चह्वाण चुनाव ने परिणाम आने के दिन भी कहा था कि शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा की संयुक्त सरकार बन सकती है।

हालांकि राकांपा के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल एक दिन पहले ही कह चुके हैं कि सरकार बनाने का जनादेश भाजपा-शिवसेना गठबंधन को मिला है। यदि उनमें कोई मतभेद है तो उन्हें आपस में सुलझाकर राज्य को स्थिर सरकार देने का प्रयास करना चाहिए। पटेल का साफ कहना था कि राकांपा किसी को समर्थन देने के बजाय विपक्ष में बैठेगी। बता दें कि 2014 के चुनाव के बाद 288 सदस्यीय विधानसभा में जब 122 विधायकों वाली फड़नवीस की अल्पमत सरकार ने शपथ ली थी तो राकांपा ने उसे बाहर से समर्थन दिया था। जबकि इस बार भाजपा ने 105, शिवसेना ने 56, राकांपा ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल की है। (पेज-4 भी देखें)

15 से 20 फीसद यात्री महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है मुफ्त सफर की सुविधा दिए जाने के बाद। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को इस योजना की शुरुआत की थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 1 नवंबर 2019

राहत के आसार ▶ चौथे दिन बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया एयर इंडेक्स, हालांकि मामूली सुधार हुआ दर्ज

दिल्ली में आज से छंटेगा स्मॉग, सुधरेगी हवा

प्रदूषण में पराली जलाने की घटनाओं का योगदान 27 फीसद रहा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर के आसमान पर गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी स्मॉग की परत छाई रही। लेकिन शुक्रवार से स्मॉग छंटना शुरू हो जाएगा। हवा की गति बढ़ने से दिल्ली-एनसीआर का आसमान कुछ साफ होगा, जबकि शनिवार को यह पूरी तरह साफ हो जाने की संभावना है। हालांकि यह जानलेवा स्मॉग छह नवंबर को दोबारा वापस आ जाएगा।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है जिसका असर शनिवार से दिल्ली-एनसीआर पर दिखाई देगा। इससे यह स्मॉग छंट जाएगा, हवाएं तेज होंगी। चार और पांच नवंबर को हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। हवा की रफ्तार सुस्त पड़ते ही छह से यह जानलेवा स्मॉग एक बार फिर जोरदार वापसी करेगा।

गुरुवार को एयर इंडेक्स भी गंभीर श्रेणी में ही रिकार्ड किया गया। हालांकि इसमें नौ अंकों का सुधार हुआ और यह 410 पर पहुंच गया। शाम के छह बजे हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 की मात्रा 468 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 2.5 की मात्रा 281 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। मालूम हो कि हवा में पीएम 10 कणों की मात्रा 100 और पीएम 2.5 की मात्रा 60 रहने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है।

सफर द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं पिछले तीन दिनों में बढ़ी हैं। दोनों राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में 27 अक्टूबर को पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 7842 से बढ़कर 12027 हो गईं, जबकि 30 अक्टूबर को यह आंकड़ा 19869 पर पहुंच गया। वहीं हरियाणा में इन घटनाओं की संख्या 27 अक्टूबर को 476 से बढ़कर 3735 हो गई और राज्य में 30 अक्टूबर को पराली जलाने की 4221 घटनाएं दर्ज की गईं।

दिल्ली के वायुमंडल में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पार्टिकुलेट तत्वों की उपस्थिति काफी ज्यादा है। पीएम 2.5 के स्तर को बढ़ाने में पराली जलाने की घटनाओं का गुरुवार को योगदान 27 फीसद रहा, जबकि शुक्रवार को यह स्तर 25 फीसद रहने की संभावना है। इससे पहले दिल्ली में इसका स्तर अब तक के अपने उच्चतम स्तर 35 फीसद पर पहुंच चुका है।

तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक : मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह भी सामान्य से एक डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 40 से 92 फीसद तक रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान में भी दो दिनों के लिए इजाफा होगा और यह 18 डिग्री तक पहुंच जाएगा।

यह दृश्य यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के सामने मुख्य मार्ग का है। दोपहर 1.48 बजे धुंध छाई रही। इससे दृश्यता भी कामी कम हो गई है। संजय

एनसीआर के शहरों का एयर इंडेक्स

शहर	एयर इंडेक्स
फरीदाबाद	402
गाजियाबाद	482
नोएडा	452
ग्रेटर नोएडा	473
गुरुग्राम	341

सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में चलेगा सघन अभियान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिवाली के बाद दिल्ली में लगातार बिगड़ रही हवा के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान सभी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। पहले चरण में दिल्ली के पांच सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों वजीरपुर, आनंद विहार, अशोक विहार, विवेक विहार और बवाना का चयन किया गया है। यहां पर प्रदूषण का स्तर अमूमन 450 से 500 के बीच पाया गया है। इन क्षेत्रों की पहचान पिछले तीन दिनों के दौरान पीएम 10 और पीएम 2.5 के स्तर को देखते हुए की गई है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव विजय कुमार देव की अध्यक्षता में प्रदूषण नियंत्रण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पानी के छिड़काव, मशीनों से सड़क की सफाई सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से धूल प्रदूषण नियंत्रण, अवैध डंपिंग व मलबे को रोकने, कचरे के जलने के उल्लंघन मामले में सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया। डीपीसीसी के निर्देश देने के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने आनंद विहार और विवेक विहार में 10 रोड स्वीपिंग मशीनें की सफाई के लिए लगाई हैं और 40 जगह पानी के छिड़काव की व्यवस्था की है। उत्तरी दिल्ली निगम ने वजीरपुर, अशोक विहार और बवाना में सात रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं और 46 जगह पानी के छिड़काव की व्यवस्था की है। अधिकारियों ने बताया कि उक्त पांच जगहों पर तो हर छह घंटे में पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

प्रदूषण पर तेज हुई सियासत, उपवास पर बैठेंगे गोयल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण से लोग परेशान हैं। वहीं, इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा इस स्थिति के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बनाने का भी एलान कर चुकी है। भाजपा नेता इसे लेकर दिल्ली सरकार को लगातार कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल शुक्रवार को दिल्ली सरकार के खिलाफ उपवास करेंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया जिस वजह से आज दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लोग बीमार हो रहे हैं और दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सफर मुख्यमंत्री की बात से सहमत नहीं हैं, इनके अनुसार पराली जलने से चार से दस फीसद ही प्रदूषण होता है।

एनसीआर में जनरेटर चलेंगे या नहीं, आज हो सकता है फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

एनसीआर के शहरों में बंद पड़े डीजल जनरेटर इस बार सर्दी में चलेंगे या नहीं, यह शुक्रवार को तय हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने अपराह्न तीन बजे समीक्षा बैठक बुलाई है। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान सरकार से उनका एक्शन प्लान और शपथ पत्र भी लिया जाएगा। इनसे मिले प्लान एवं शपथ पत्र को जांचकर ही ईपीसीए कोई निर्णय लेगा।

गौरतलब है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू हो गया है। इसके साथ ही सभी जगह डीजल जनरेटरों पर भी रोक लग गई है। हालांकि पिछले दो साल से एनसीआर के शहरों को छूट दी जा रही थी, लेकिन इस साल उन्हें भी शामिल कर लिया गया। अब समस्या यह है कि एनसीआर के शहरों में कहीं ग्रिड से बिजली का नेटवर्क नहीं होने तो कहीं अघोषित कटौती होने से परेशानी उत्पन्न हो रही है। इसीलिए हरियाणा सरकार और नोएडा प्रशासन की ओर से ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल को पत्र लिखकर जेनरेटर पर प्रतिबंध से छूट देने की मांग की गई थी।

हरियाणा सरकार ने खासतौर पर इस प्रतिबंध को लागू करने में असमर्थता जताई थी। तर्क यह दिया था कि गुरुग्राम में तो एक से 57 सेक्टर तक बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। इसी तरह नोएडा की ओर से भी कटौती की समस्या का रोना रोया गया था। इसके बावजूद ईपीसीए ने सीधे तौर पर किसी को भी छूट देने से इन्कार कर दिया। ईपीसीए का कहना है कि गत दो सालों तक एनसीआर को छूट दी जाती रही है। अब तीसरे साल भी यह छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन इन राज्यों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए इनसे 22 अक्टूबर तक पूरा एक्शन प्लान मांगा और हलफनामा देने को भी कहा था, जिसमें बताया जाए कि उन्हें तब तक छूट चाहिए और कब तक वह ग्रिड से कनेक्शन ले लेंगे। लेकिन अब तक किसी भी राज्य ने न तो ईपीसीए के पास प्लान भेजा और न ही शपथ पत्र। बाद में दिवाली के कारण मामला लटक गया। अब ईपीसीए ने ही इसी मसले पर शुक्रवार को बैठक रखी है।

आज ही मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे ईपीसीए अध्यक्ष : शुक्रवार दोपहर 12 बजे ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का एजेंडा भी वायु प्रदूषण ही है। इस दौरान दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति, हालात पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की जाएगी।

> ईपीसीए की बैठक के दौरान सभी का शपथ पत्र देखा जाएगा कि कौन कितने समय के लिए मोहलत मांग रहा है और उसका एक्शन प्लान कितना कारगर तथा व्यावहारिक है। इसी आधार पर कोई निर्णय लिया जाएगा। साथ ही बैठक में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पालन पर भी बात की जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।
> –भूरेलाल, अध्यक्ष, ईपीसीए

फांसी के तख्ते के और करीब पहुंचे निर्भया के गुनहगार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : देश को झकझोर देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड के गुनहगार फांसी के तख्ते के और करीब पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही दोषियों की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा माफ किए जाने पर ही वे फांसी के फंदे से बच सकते हैं, अन्यथा मौत की सजा तय है।

तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोषियों को 29 अक्टूबर को नोटिस देकर बता दिया कि उनके पास राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करने के लिए 5 नवंबर तक का समय है। उनको हिंदी व अंग्रेजी में नोटिस पढ़कर सुनाया गया और इसका वीडियो भी बनाया था। जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि यदि दोषी दया याचिका दायर नहीं करते हैं तो जेल प्रशासन पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर डेथ वारंट जारी करने की मांग करेगा। इनमें तीन कैदी तिहाड़ जेल परिसर में तो एक मंडोली जेल परिसर में बंद है। संबंधित जेल अधीक्षकों को जारी नोटिस में कहा गया है कि आठवें दिन मुख्यालय को अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाए ताकि आगे की कार्रवाई शुरू हो। अभी तक किसी दोषी की ओर से जेल प्रशासन को दया याचिका दायर किए जाने की सूचना नहीं दी गई है।

किसी एक की याचिका पर टल जाएगी सभी की फांसी : जेल प्रशासन के अनुसार यदि किसी भी एक कैदी ने दया याचिका दायर कर दी तो अंतिम फैसला होने तक सभी कैदियों की फांसी टाली जा सकती है। हालांकि दया याचिका का लाभ केवल उसी कैदी को मिलेगा जो याचिका दायर करेगा।

घटनाक्रम

16 दिसंबर 2012 वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की कोशिश को अंजाम दिया गया
29 दिसंबर, 2012 को इलाज के दौरान सिंगापुर के अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई
मार्च 2013 में मुख्य आरोपित बस चालक राम सिंह ने तिहाड़ में खुदकशी कर ली
सितंबर 2013 में निचली अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई
मार्च 2014 में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी
मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी

दिनभर हंगामे के बाद रात को बनाया गया छठ घाट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कालकाजी के डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क में छठ घाट बनाने को लेकर गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर देर शाम तक हंगामा हुआ। सुबह से ही ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज व चितरंजन पार्क से भाजपा के निगम पार्षद सुभाष भड़ाना के समर्थकों सहित आरडब्ल्यूए के लोग यहां जुटे थे। दोनों पक्षों में जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि देर शाम विवाद का पटाक्षेप हो गया और पार्क में जेसीबी से खोदाई करके छठ घाट तैयार कर दिया गया।

दरअसल, सौरभ भारद्वाज इस पार्क में छठ घाट बनवाना चाह रहे थे। स्थानीय निगम पार्षद के साथ ही यहां के लोग इसका विरोध कर रह थे। उनका कहना था कि बगल में ही एक बड़े पार्क में छठ पूजा होती है इसलिए इस पार्क को न उजाड़ा जाए। इसमें हरी घास लगी है और बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। बुधवार की शाम से ही दोनों पक्षों में इसे लेकर टकराव की स्थिति बन गई थी। गुरुवार की सुबह ही स्थानीय निगम पार्षद सुभाष भड़ाना और विधायक सौरभ भारद्वाज आमने-सामने आ गए थे। कुछ ही देर में दोनों पक्षों से लोग यहां जुटने लगे। सौरभ भारद्वाज के समर्थन में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, विधायक प्रकाश जारवाल, अजय दत्त, अवतार सिंह कालका, एनडी शर्मा, नरेश यादव, संजीव झा, सोमनाथ भारती, सहीराम पहलवान, आप नेता दिलीप पांडेय समेत कई नेता समर्थकों के साथ पहुंच गए और पार्क के सामने धरने पर बैठ गए। उधर, सुभाष भड़ाना के समर्थन में भाजपा की दिल्ली प्रदेश मंत्री सुमित्रा दहिया, ग्रेटर कैलाश विधानसभा प्रभारी संदीप सैनी, भाजपा किसान मोर्चा से सूरज चौहान आदि के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। दोनों ओर से जमकर नारेबाजी होने लगी।

इस मौके पर तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पार्षद सुभाष भड़ाना ने कहा कि इस पार्क के बगल वाले पार्क में पहले से ही छठ पूजा की जाती है। उन्होंने छठ घाट बनाने का विरोध नहीं किया, बल्कि पार्क की हरियाली बचाने व स्थानीय आरडब्ल्यूए की मांग का समर्थन किया था। वहीं, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस पार्क में छठ घाट बनाने की अनुमति दिल्ली सरकार ने दी है।

नहाय खाय के साथ शुरू हुआ छठ का महापर्व

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नहाय खाय के साथ गुरुवार को छठ के पावन पर्व का आगाज हो गया है। व्रतियों ने नहाने के बाद नए वस्त्र धारण कर चावल के साथ घीया व चने की दाल बनाकर खाई। इसके बाद से अगले तीन दिन तक व्रत रखा जाएगा। इसमें शुक्रवार को व्रती खरना की विधि करेंगे। पूरा दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को व्रती गुड़ की खीर व रोटी का शाम को प्रसाद के रूप में सेवन करेंगे। इसके बाद शनिवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। रविवार को पारन की विधि की जाएगी।

पूजन को लेकर लोगों ने गुरुवार को भी बाजारों में परिवार समेत पहुंच कर खरीदारी की। इसमें दउरा, सूप व डगरा समेत अन्य चीजों की खरीदारी की गई। नहाय खाय से ही व्रतियों को पूरी पवित्रता का पालन करना होता है। ऐसे में व्रती इस दिन आम की लकड़ियों की आंच पर नए चूल्हे पर खाना पकाती हैं, वहीं पूरे घर में पवित्रता का माहौल रहता है। करोलबाग निवासी मंजू झा ने बताया कि छठ के पावन पर्व पर पवित्रता का ध्यान रखना होता है। इस पर्व के दौरान व्रती जमीन पर ही सोते हैं। विशेषतौर पर पूजा वाले स्थान के पास ही सोया जाता है। घर में किसी भी प्रकार का बाहरी भोजन नहीं खाया जाता है। पर्व में सिर्फ घर का ही शुद्ध शाकाहारी भोजन ही प्रसाद के रूप में लिया जाता है।

घाटों पर भी पूरी हुई तैयारियां : नहाय खाय के बाद छठ घाटों पर भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कश्मीरी गेट स्थित कुदेसिया घाट व आइटीओ घाट पर भी गुरुवार को तैयारी देखने को मिली। कश्मीरी गेट स्थित घाट पर भी बल्लियों को गाड़ दिया गया है। इस पर आगे जाने पर गहरे पानी की भी चेतावनी लिखी गई है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच तैयार करने के साथ लोगों के रुकने के लिए टेंट की भी व्यवस्था की गई है। घाट किनारे की मिट्टी को काटकर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। पूजन के लिए वेदियां भी तैयार की जा रही हैं। दूसरी ओर आइटीओ घाट पर भी तैयारियां जोरों पर है। यहां पर व्रतियों के रुकने के लिए भी टेंट की व्यवस्था की गई है। पूजा समिति के उपाध्यक्ष आशीष पांडे ने बताया कि इस बार 70 वेदियों को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ के कलाकारों की ओर से भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पहाड़गंज में पूजा सामाग्री की खरीदारी करती व्रती। जागरण

दिल्ली सरकार से की मुफ्त बिजली की मांग

आइटीओ घाट स्थित पूजा समिति ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्य को लेकर रोष जताया है। पूजा समिति का कहना है कि पीडब्ल्यूडी का इस बार छठ घाट पर तैयारियों को लेकर ढुलमुल रवैया रहा है। यही कारण है कि इस बार छठ घाट पर व्यवस्था को सुधारा नहीं गया है। दूसरी ओर समिति ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार सरकार ने दिल्लीवासियों के लिए मुफ्त बिजली की है, इसका लाभ पूजन समितियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में पूजन समितियां इसके लिए अलग से बिल का भुगतान करती हैं।

गृहमंत्री ने कहा, पुलिस की भूमिका को सकारात्मक नजरिए से देखने की जरूरत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लुटियंस दिल्ली में संसद भवन के पास जय सिंह रोड पर नव निर्मित दिल्ली पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर शाह ने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश के लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर दिल्ली पुलिस के नए मुख्यालय का उद्घाटन का अवसर हमें मिला। उन्होंने दिल्ली पुलिस के आयुक्त अमूल्य पटनायक समेत पूरे महकमे को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को 70 साल बाद अपना घर मिला है।

शाह ने कहा कि लोग पुलिस को सकारात्मक नजरिये से नहीं देखते हैं। आए दिन सुनने को मिलता है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने रिश्वत ली, मुकदमा दर्ज नहीं किया। लोग पुलिस की कमियां पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें गलत नजरों से देखते हैं। लेकिन लोगों को यह दिखाई नहीं देता कि जब सब लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे होते हैं या जब लोग सड़कों पर निकलते हैं तब पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए काम कर रहे होते हैं और तमाम विषम परिस्थितयों मुस्तैद रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस को सकारात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है। हालांकि इस मौके पर गृहमंत्री ने नसीहत भी दी कि भवन से ज्यादा अहम होती है भावनाएं। हमें अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर संसद हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों और बाटला हाउस में शहीद हुए मोहन चंद्र शर्मा को भी याद किया।

पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही पुलिस जनता के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित करने की दिशा में काम करते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए 50 मोबाइल एप व वेबसाइट शुरू की हैं जिनकी मदद से अब नागरिक संकट के समय में सीधा पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन समेत दिल्ली पुलिस के समस्त अधिकारी मौजूद थे।

जय सिंह रोड स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय की नई बिल्डिंग के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिह्न भेंट करते पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक। साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और उपराज्यपाल अनिल बैजल। जागरण

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिला स्पेशल ऑपरेशन अवार्ड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाह, एसीपी अतर सिंह, इंस्पेक्टर शिव कुमार, एएसआइ राजेश शर्मा और हेड कांस्टेबल आदेश कुमार को वर्ष 2019 का स्पेशल ऑपरेशन अवार्ड दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से हर राज्य की पुलिस को किसी विशेष ऑपरेशन के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड इस बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 20 जनवरी 2019 को जैश-ए-मुहम्मद के एक आतंकी को दिल्ली में एक स्वचालित पिस्टल, 26 कारतूस और जैश-ए-मुहम्मद के कमांडर के नाम के तीन स्टांप के साथ पकड़ा था। उसके दूसरे साथी और जैश के दूसरे आतंकी को जम्मू-कश्मीर से हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा अपनी टीम के साथ लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद सहित हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकियों पर कड़ी नजर रखे हुए थे। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भी पुलिस चौकस थी। इसी बीच सैन्य खूफिया तंत्र से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लक्ष्मी नगर स्थित एक घर में लगातार आवाजाही कर रहे हैं। जांच में पता लगा कि आतंकी संदिग्ध जैश-ए-मुहम्मद से जुड़े हुए हैं। यह भी पता चला कि इनमें से कुछ श्रीनगर में ग्रेनेड हमला कर चुके हैं। उनका अगला निशाना दिल्ली है। इसका पता चलते ही एसीपी अतर सिंह और इंस्पेक्टर शिव कुमार, एसआइ हरद्वारी लाल, पवन, हवलदार आदेश और एएसआइ राजेश शर्मा की टीम ने 20 जनवरी की देर रात राजघाट के समीप से अब्दुल लतीफ को गिरफ्तार कर लिया। छानबीन में पता चला कि आतंकी जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस की एक टीम को जम्मू-कश्मीर रवाना किया गया। वहां से अब्दुल लतीफ का एक अन्य साथी हिलाल अहमद भट दबोचा गया। लतीफ के घर से दो ग्रेनेड बरामद हुए। अब्दुल लतीफ जैश-ए-मुहम्मद का गांदरबाल का जिला कमांडर था। लतीफ ने बताया कि वे पाकिस्तानी आका अबुल मौज के इशारे पर काम कर रहे थे। मौज ने उसे नवंबर 2018 में सात ग्रेनेड दिए थे। अन्य आतंकी आकिब से उसे 12 ग्रेनेड एक पिस्टल और 30 कारतूस मिले थे। ये ग्रेनेड जम्मू-कश्मीर के सैन्य ठिकाने और दिल्ली में प्रयोग किए जाने थे। आतंकियों ने बताया कि नवंबर 2018 में दोनों हवाई जहाज से दिल्ली आए थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के पांच वीवीआइपी इलाके, धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाली जगह की रेकी की थी।

गाजियाबाद के हिंडन से शिमला के लिए दिसंबर से शुरू होगी फ्लाइट

सौरभ पांडेय, गाजियाबाद : पिथौरागढ़ के लिए उड़ान शुरू होने के बाद जल्द ही हिंडन से यात्रियों को शिमला जाने की भी सुविधा मिलने वाली है। अमेरिका से आया 20 सीटर विमान दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में शिमला के लिए उड़ान भरेगा। पिथौरागढ़ के लिए उड़ान सेवा दे रही कंपनी हेरिटेज एविएशन ही शिमला के लिए भी उड़ान शुरू करेगी।

बता दें कि छह नवंबर से कर्नाटक के हुबली के लिए भी यहां से लोगों को विमान सेवा मिल सकेगी। इसके लिए भी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। हुबली के लिए विमान संचालक कंपनी स्टार एयर ने यहां अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी है। कंपनी के एयरपोर्ट मैनेजर किरण ने बताया कि यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी पूरी तरह तैयार है। कुल मिलाकर, पिथौरागढ़ और हुबली के बाद अब शिमला भी हिंडन से जुड़ जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के अनुसार, शिमला-हिंडन के लिए हेरिटेज एविएशन ने अमेरिकी कंपनी का 20 सीटर विमान लीज पर लिया है। शुरुआत में दिन में एक ही फ्लाइट होगी, लेकिन माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए इसी विमान को अन्य रूटों पर भी उड़ाया जा सकता है।

सख्ती

काम के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए डीडीए उपाध्यक्ष ने इंजीनियरिंग विभाग का किया पुनर्गठन

डीडीए इंजीनियर अब नहीं खेल पाएंगे 'फुटबॉल'

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के इंजीनियर काम को किसी और के सिर मढ़कर लटका नहीं पाएंगे। उन्हें जो क्षेत्र दिया जाएगा, वहां डीडीए के क्षेत्राधिकार में आने वाला हर काम निपटाना होगा। केवल उद्यान विभाग की जिम्मेदारी इसमें शामिल नहीं होगी। काम के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए ही डीडीए उपाध्यक्ष ने इंजीनियरिंग विभाग का पुनर्गठन किया है।

डीडीए में छोटे-बड़े मिलाकर करीब एक हजार इंजीनियर हैं। सभी दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात हैं और सभी को अलग-अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन समस्या यह है कि यह अपने काम को फुटबॉल की तरह एक-दूसरे की तरफ डालते रहते हैं। कोई भी मामला आता है तो उसे दूसरे इंजीनियर के कार्यक्षेत्र का हिस्सा बताकर खुद बच निकलते हैं। नतीजतन शिकायतें अनसुलझी रह जाती हैं और प्रोजेक्ट लटक जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। इन्हीं मामलों का निदान करने के लिए डीडीए उपाध्यक्ष ने इंजीनियरिंग विभाग का पुनर्गठन किया है।

आइएनए स्थित मुख्यालय से इतर डीडीए को अब पांच क्षेत्रीय कार्यालयों में बांट दिया गया ह - दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी, द्वारका और रोहिणी। क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी मुख्य अभियंता होंगे। इनके अधीन 65 डिविजन रखे गए हैं। प्रत्येक डिविजन का प्रभारी कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) को बनाया गया है। यह एक्सईन अब किसी जिला उपायुक्त की तरह काम करेंगे। मतलब यह कि वे अपने डिविजन में डीडीए से संबद्ध हर मामले को देखेंगे। चाहे वह बिल्डिंग का हो, सिविल का हो, पर्यावरण का हो, भूमि प्रबंधन का हो अथवा 50 करोड़ से कम का कोई भी प्रोजेक्ट हो। केवल एक उद्यान विभाग ही अलग रहेगा।

इसके अलावा 50 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट देखने के लिए दो मुख्य अभियंताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे प्रोजेक्टों से जुड़ी तमाम समस्याओं को सुलझाने का दायित्व इन्हीं का होगा। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इस नई व्यवस्था का विरोध हो रहा है, लेकिन तब भी इसे लागू किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे इंजीनियरों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और विभिन्न प्रोजेक्ट समय से पूरे हो सकेंगे। विभिन्न मसलों से जुड़ी शिकायतों की अनदेखी भी नहीं ही हो पाएगी।

> इंजीनियरिंग विभाग का पुनर्गठन कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। जवाबदेही बहुत जरूरी है। इसीलिए इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इस नई व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगेंगे।
> –तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

बैंकॉक से आया सोना तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी में एक भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह बैंकॉक से दिल्ली आया था। उसके पास से 255 ग्राम का सोना बरामद किया गया है। इसकी कीमत करीब नौ लाख रुपये है। पूछताछ में पता चला कि तस्कर इससे पहले भी विदेश से सोने की तस्करी कर चुका है। कस्टम अधिकारी तस्कर से पूछताछ कर रहे हैं। कस्टम के एडिशनल कमिश्नर डॉ. अमनदीप सिंह ने बताया कि घटना 28 अक्टूबर की है। बैंकॉक से आई विस्तारा एयरलाइंस से उतरा एक संदिग्ध शख्स एयरपोर्ट से बाहर निकलने के प्रयास में लगा हुआ था।

शक होने पर कस्टम अधिकारियों ने उसकी तलाशी ली। इसमें उसके पास से सोने का सिलेंडरनुमा एक टुकड़ा बरामद हुआ। यह सोना उसने अपने संवेदनशील अंग में छुपा रखा था। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि इससे पहले भी वह दो बार 14 लाख मूल्य के सोने की तस्करी कर चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

प्रति यात्री अधिकतम राजस्व देने वाली कंपनी को मिलेगा जेवर एयरपोर्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कंपनी चयन का आधार प्रति यात्री मिलने वाला राजस्व है। जो कंपनी प्रति यात्री अधिकतम राजस्व की बोली लगाएगी, जेवर एयरपोर्ट उसी कंपनी को मिलेगा। फाइनेंशियल बिड की मुख्य शर्त यही है। देश में बन रहे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट में इस शर्त पर कंपनी चयन होने वाला जेवर एयरपोर्ट पहला होगा।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकनीकी बिड ख

255 करोड़ का योगदान दिया है आइआइटी दिल्ली के पूर्व छात्रों ने। छात्रों ने ग्लोबल एल्युमिनी एंडोमेंट फंड (अक्षय निधि) तैयार किया है। गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस फंड को लांच किया।

जासूसी पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

बड़ा मुद्दा ▸ सुप्रीम कोर्ट से सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की

अपने ही नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही यह सरकार : सुरजेवाला

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह इस मामले पर तत्काल स्वतः संज्ञान ले एवं सरकार की जवाबदेही तय करे।

इस मामले में सरकार द्वारा वाट्सएप से जवाब मांगने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल ने ट्वीट किया, 'सरकार ने वाट्सएप से पूछा है कि भारतीय नागरिकों की जासूसी के लिए पेगासस को किसने खरीदा है, यह वैसे ही है जैसे मोदी दासौ से पूछें कि राफेल जेट्स की भारत को बिक्री से किसने पैसे बनाए!'

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि 'अपने ही नागरिकों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करने वाली यह सरकार' इस देश का नेतृत्व करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर आरोप लगाया, 'मोदी सरकार जासूसी करते पकड़ी गई है। यह चिंताजनक है, लेकिन हैरान करने वाली बात नहीं है। आखिरकार भाजपा सरकार ने ही हमारे निजता के अधिकार का हनन किया, करोड़ों रुपये का निगरानी ढांचा बनाया।'

रणदीप सुरजेवाला फाइल फोटो

सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी को संदेह है कि जासूसी के शिकार भारतीयों में विरोधी दल के कई नेता और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कई जज भी शामि हैं। सुरजेवाला ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और भाजपा सरकार से यह भी पूछा कि किस सरकारी एजेंसी ने स्पाइवेयर पेगासस को खरीदा और लगाया है। उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि क्या प्रधानमंत्री या एनएसए ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए मंजूरी दी है?

कैंब्रिज एनालिटिका और फेसबुक से मिली जानकारियों का विश्लेषण कर रही सीबीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय मतदाताओं की निजी जानकारियों को हासिल करने की जांच से जुड़े मामले में सीबीआइ द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारियों को फेसबुक और कैंब्रिज एनालिटिका ने उपलब्ध करा दिया है। जांच एजेंसी अब इन जानकारियों का विश्लेषण कर रही है।

केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने के बाद सीबीआइ ने पिछले साल कैंब्रिज एनालिटिका और ग्लोबल साइंस रिसर्च के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी। इसके बाद सीबीआइ ने अमेरिका स्थित फेसबुक और ब्रिटेन स्थित कैंब्रिज एनालिटिका से आंकड़ें इकट्ठे करने के तरीकों की जानकारी मांगी थी। इन जानकारियों को मिलने के बाद सीबीआइ ने इस साल की शुरुआत में कुछ और सवाल पूछे थे जिनके जवाब अब उपलब्ध कराए गए हैं।

▸ इस साल की शुरुआत में मांगे थे अपने सवालों के जवाब

▸ भारत में फेसबुक के 20 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं

आरोप है कि कैंब्रिज एनालिटिका ने ग्लोबल साइंस रिसर्च से आंकड़े हासिल किए थे जिसने गैरकानूनी तरीकों से फेसबुक इस्तेमाल करने वाले भारतीय मतदाताओं के आंकड़े जुटाए थे। मालूम हो कि भारत में फेसबुक के 20 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच शुरू करने के एक साल बाद भी सीबीआइ को अभी यह तय करना है कि इस मामले में वह पूर्ण आपराधिक जांच शुरू कर सकती है अथवा नहीं। बता दें कि प्रारंभिक जांच यह तय करने का पहला चरण होती है कि आरोप एफआइआर के जरिये पूर्ण जांच के लायक हैं अथवा नहीं।

एससीओ की बैठक आज से, राजनाथ करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताशकंद में शुक्रवार से शुरू होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासनाध्यक्षों (सीएचजी) की परिषद की दो दिवसीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बता दें कि वर्ष 2017 में एससीओ में भारत के सदस्य बनने के बाद सीएचजी की यह तीसरी बैठक होगी। पिछले वर्ष एससीओ की बैठक ताजिकिस्तान के दुशान्बे में हुई थी, जबकि वर्ष 2017 में रूस के सोची में यह बैठक हुई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत क्षेत्र में विभिन्न एससीओ सहयोग गतिविधियों/संवाद तंत्र में शामिल है। हम बहुपक्षीय सहयोग को और विकसित करने के लिए भी प्रयासरत हैं।' मंत्रालय ने कहा कि ताशकंद में होने वाली बैठक में भाग लेने वाले नेताओं के एससीओ क्षेत्र में बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग और विकास को लेकर होने वाली चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। सिंह एससीओ बैठक के इतर द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। एससीओ का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना है।

पल्स पोलियो की तर्ज पर चलेगा टीकाकरण अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर देश के सभी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान की रजत जयंती के अवसर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि अगले महीने दो दिसंबर से देश के 271 जिलों में 'सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0' शुरू किया जाएगा जहां टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों की संख्या ज्यादा है। इनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के 652 ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हर्षवर्धन ने कहा कि देश के सभी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने में पल्स पोलियो अभियान के अनुभवों से सहायता मिलेगी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल दो करोड़ 60 लाख बच्चे पैदा होते हैं। इनमें से 87 फीसद बच्चों को ही टीके की पूरी खुराक मिल पाती है। 31 लाख बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें किसी न किसी कारण टीके की पूरी खुराक नहीं मिल पाती है। जाहिर है ऐसे बच्चों के विभिन्न बीमारियों की गिरफ्त में आने की आशंका बनी रहती है। हर्षवर्धन ने कहा कि नए अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दो साल की आयु तक का एक भी बच्चा टीके से वंचित ना रहे। इसके लिए ऐसे जिलों और ब्लॉकों की पहचान की गई है, जहां बच्चे और गर्भवती महिलाएं टीके से वंचित रह जाती हैं। 'सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0' के तहत पल्स पोलियो की तर्ज पर टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। हर्षवर्धन ने कहा कि दो दिसंबर के बाद हर महीने सात दिनों तक टीकाकरण का अभियान चलेगा।

टीकाकरण में पीछे छूट गए बिहार और उत्तर प्रदेश के 652 ब्लॉक : हर्षवर्धन

1994 में शुरू किए गए पल्स पोलियो अभियान को याद करते हुए हर्षवर्धन ने बताया कि इसमें किस तरह आरएसएस और सेवा भारती ने अहम भूमिका निभाई। इनमें आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से लेकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्वयंसेवक शामिल थे, लेकिन कभी भी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। हर्षवर्धन के अनुसार खुद उन्होंने अहमदाबाद के कर्णावती में आरएसएस पदाधिकारियों और प्रचारकों के सामने पल्स पोलियो अभियान पर 45 मिनट का प्रजेंटेशन दिया था। आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक केसी सुदर्शन ने सभी राज्यों का दौरा कर स्वयंसेवकों को पल्स पोलियो अभियान में सहयोग देने का निर्देश दिया था।

अमेरिका से जुड़ा है इस तनातनी का सिरा

प्रथम पृष्ठ से आगे

भारत और चीन के बीच इस गरमा-गरम बहस का एक सिरा अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। दो दिन पूर्व अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र की यात्रा की है। इस क्षेत्र पर चीन हमेशा दावा करता है कि यह उसका हिस्सा है। लेकिन अमेरिकी राजदूत की यात्रा के एक दिन बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि वह भारत की संप्रभुता का पूरी तरह से आदर करता है। जानकार कश्मीर पर चीन की कड़ी प्रतिक्रिया को अमेरिका के उस बयान से जोड़कर देख रहे हैं। चीन की इस बयानबाजी का मकसद बहुत हद तक कूटनीतिक पैंतरेबाजी भी हो सकता है क्योंकि वह लद्दाख के एक हिस्से पर अपना दावा जताता रहा है। अब अगर वह चुप रहेगा तो यह संदेश जाएगा कि उसने भारत के फैसले को स्वीकार कर लिया है। बहरहाल, 11 अक्टूबर, 2019 को चेन्नई के पास मोदी और चिनफिंग के बीच हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात को चेन्नई कनेक्ट का नाम दिया गया था, लेकिन अब यह कनेक्शन टूटता दिख रहा है।

राष्ट्रगान के दौरान बैठी रह सकेंगी जर्मनी की चांसलर एंजिला मर्केल

नई दिल्ली, प्रेट्र : जर्मनी की चांसलर एंजिला मर्केल शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक कार्यक्रम में दोनों देशों के राष्ट्रगान के दौरान बैठी रह सकेंगी। मर्केल की बीमारी को देखते हुए जर्मनी ने इसके लिए विशेष अनुरोध किया था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया है।

मर्केल को अनुमति देने के लिए राष्ट्र गान से जुड़े आदेश के कुछ खास प्रावधानों को लागू किया जाएगा। मर्केल दो दिन की भारत यात्रा पर गुरुवार की रात को नई दिल्ली पहुंच गई हैं। आधिकारिक तौर पर उनकी यात्रा शुक्रवार को शुरू होगी। यात्रा के दौरान उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। दरअसल, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान व्यक्त करना हर भारतीय का कर्तव्य है। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान को चलाए जाने से रोकने या राष्ट्रगान के दौरान जानबूझ कर व्यवधान पैदा करने पर तीन साल कैद या जुर्माने की सजा का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 51-ए(ए) में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 'संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों व संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।' लेकिन इन किसी भी प्रावधानों में सम्मान व्यक्त करने के उचित तरीके को वर्णित नहीं किया गया है। साथ ही राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहने या खड़ा होने के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।

दो दिवसीय भारत यात्रा पर आईं जर्मन चांसलर एंजिला मर्केल का गुरुवार को नई दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वागत किया। एएनआइ

मप्र लोक सेवा आयोग ने परीक्षा केंद्र पर लगवाया जैमर, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट

लोकेश सोलंकी, इंदौर

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा और चयन प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग ने बीते वर्ष सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अनधिकृत रूप से कई परीक्षा कक्षों में 'जैमर' का उपयोग किया था। मामले पर केंद्रीय रक्षा सचिव कार्यालय ने भी आपत्ति ली है। अवर सचिव (सुरक्षा) ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले पर रिपोर्ट मांगी गई। एडीजी इंदौर कार्यालय से जांच रिपोर्ट एडीजी इंटेलीजेंस को भेजी भी गई है। इसमें साफ हुआ है कि आयोग ने संदिग्ध तरीके से कुछ खास परीक्षा कक्षों में अनधिकृत 'जैमर' का उपयोग किया। साथ ही जांच के दौरान पुलिस को भी आयोग के अधिकारियों ने गलत जानकारी देकर मामले को दबाने की पूरी कोशिश की।

गौरतलब है कि आयोग द्वारा बीते साल जून माह में आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा पहले से ही विवादों में है। इस परीक्षा के विज्ञापन से लेकर परीक्षा आयोजित करवाने के बीच करीब 20 बार संशोधन किए गए। आयु सीमा, अनुभव के अंकों से लेकर चयन प्रक्रिया तक में बदलाव किया गया। बीते साल चुनाव के ठीक पहले जल्दबाजी में चयन सूची जारी कर दी गई। बाद में परीक्षा परिणाम में भी संशोधन हुए। अब इस चयन प्रक्रिया में नियम विरुद्ध 'जैमर' के उपयोग का नया विवाद जुड़ गया है। आयोग अब तक इस बात से इन्कार कर रहा था कि उसने परीक्षा में 'जैमर' लगाए थे, लेकिन 30 अक्टूबर को सूचना के अधिकार में मिली जानकारी में साफ हो गया कि जैमर के मामले में आयोग की भूमिका संदिग्ध है। आयोग पुलिस और सरकार की जांच एजेंसियों से भी जानकारी छिपा रहा है।

▸ सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका

▸ जांच एजेंसियों से जानकारी छिपाने का भी आयोग पर आरोप

केंद्र सरकार की आपत्ति से पर्दाफाश

चयन प्रक्रिया में 'जैमर' के मनमाने उपयोग और नियम तोड़ने पर केंद्र सरकार के अवर सचिव (सुरक्षा) ने न केवल आपत्ति ली है बल्कि कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। परीक्षा के बाद दिल्ली से अवर सचिव (सुरक्षा) अंतर कुमार ने प्रदेश के मुख्य सचिव को बीते साल अगस्त में पत्र लिखकर पूरी जानकारी मांगी थी। पत्र में साफ लिखा था कि आयोग ने इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट के साथ केंद्र के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। जैमर सिर्फ सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों से ही किराए पर लिए जा सकते हैं। एक्ट के उल्लंघन पर तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

भाजपा सरकार ने संशोधित कानून से सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता की बलि चढ़ाई : सोनिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सूचना का अधिकार कानून में संशोधनों को लेकर गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने अपने एजेंडे के तहत संशोधित कानून के माध्यम से सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता की बलि चढ़ा दी। मोदी सरकार अब अपनी चापलूसी करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी।

सोनिया ने कहा, 'हमने संसद में इन संशोधनों का विरोध किया है और आगे भी इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम अपने लोकतांत्रिक संस्थानों पर इस षडयंत्रकारी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भाजपा सरकार के निर्णयों तथा निरंकुश एवं तानाशाही गतिविधियों का निरंतर विरोध करते रहेंगे।' सोनिया ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'यह बात किसी से छिपी नहीं है कि मोदी सरकार आरटीआइ की संस्था को अपने निरंकुश एजेंडे को लागू करने में एक बड़ी अड़चन के तौर पर देखती आई है। यह कानून जवाबदेही मांगता है और भाजपा सरकार जवाब देने से साफ-साफ गुरेज करती आई है।'

सोनिया ने आरोप लगाया, 'भाजपा सरकार ने आरटीआइ कानून पर अपना निर्णायक प्रहार कर दिया है। इस कानून को कमजोर करने के लिए मोदी सरकार ने ऐसे संशोधन किए, जो सूचना आयुक्तों की शक्तियों को कमजोर करके उन्हें सरकार की अनुकंपा के अधीन कर देंगे।' उन्होंने कहा, 'सूचना आयुक्तों के पद का कार्यकाल सरकार के निर्णय के अधीन करते हुए पांच से घटाकर तीन साल कर दिया गया है। 2005 के कानून के तहत उनका कार्यकाल पांच साल के लिए निर्धारित था, ताकि वह सरकार और प्रशासन के हस्तक्षेप एवं दबाव से पूरी तरह मुक्त रहें, लेकिन संशोधित कानून में उनकी स्वायत्तता की पूरी तरह बलि दे दी गई है।'

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पर गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एएनआइ

सोनिया ने दावा किया कि सरकार के खिलाफ सूचना जारी करने वाले किसी भी सूचना अधिकारी को अब तत्काल हटाया जा सकता है या फिर पद से बर्खास्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'दूसरे संशोधन के तहत सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और शर्तों के नियम केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से तय किए जाएंगे।' उन्होंने कहा कि इन संशोधनों के बाद कोई भी सूचना आयुक्त मोदी सरकार के हस्तक्षेप और निर्देशों से बचा नहीं रह सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया, 'इसके द्वारा मोदी सरकार अपने इशारों पर काम करने वाले अधिकारियों को जब तक चाहे, जैसे चाहे, नियुक्त कर सकेगी। वे मजबूरी में सरकार की चापलूसी के लिए काम करेंगे और जिन प्रश्नों के उत्तर सरकार नहीं देना चाहेगी, उन पर मौन साध लेंगे।'

भाजपा ने राहुल के विदेश दौरों पर उठाया सवाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि उनके विदेशी दौरों का राज क्या है और वह किस गोपनीय मिशन पर विदेशों का बारबार दौरा करते हैं। क्या वह किसी गुप्त मिशन में लगे हैं।

भाजपा प्रवक्ता जीवी एल नरसिंह राव ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी के लगातार विदेश दौरे जनहित के विषय हैं, क्योंकि वह जनप्रतिनिधि हैं। राव ने दावा किया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पिछले पांच साल में 16 बार विदेश यात्राएं की हैं जो उनके संसदीय क्षेत्र रहे उत्तर प्रदेश के अमेठी के उनके दौरों से अधिक है। भाजपा प्रवक्ता ने यहां पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, 'यह भी एक वजह है कि अमेठी ने उन्हें नकार दिया। उनकी 16 विदेश यात्राओं में से नौ का गंतव्य स्थान ही नहीं पता।'

संसद में एक मंत्री के बयान का उल्लेख करते हुए राव ने कहा कि संसद सदस्यों को अपने विदेश दौरों के बारे में संसद को अग्रिम सूचना देनी चाहिए, भले ही यात्राएं विशुद्ध रूप से निजी हों। राव ने दावा किया कि लोकसभा सचिवालय को राहुल की तरफ से उनकी विदेश यात्राओं के बारे में कोई भी सूचना नहीं मिली।

भाजपा नेता ने विदेश यात्राओं पर होने वाले अत्यधिक खर्च की ओर इशारा करते हुए सवाल किया कि गांधी की विदेश यात्राओं में हवाई टिकट, पांच सितारा होटलों में उनके ठहरने से लेकर अन्य खर्च कौन उठाता है। बता दें कि राहुल गांधी इस साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। वह केरल के वायनाड से लोकसभा पहुंचे हैं।

सीजीएल परीक्षा-2017 के सफल प्रत्याशियों की नियुक्ति पर रोक की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की विवादों में रही 2017 की संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) परीक्षा में चयनित हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। याचिका में शीर्ष न्यायालय द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति के अपनी रिपोर्ट सौंपने तक सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

शांतनु कुमार की तरफ से अधिवक्ता गौरव गुप्ता के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि एसएससी द्वारा ली गई सीजीएल-2017 परीक्षा में भ्रष्टाचार के कई उदाहरण प्रकाश में आए थे। 21 फरवरी 2018 को ली गई परीक्षा से पहले ही उत्तर कुंजी सोशल मीडिया पर साझा किए जाने से जुड़ी अनियमितताएं भी दर्ज की गई। प्राथमिक जांच के आधार पर सीबीआई ने 22 मई 2018 को कई लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति से एसएससी पर्चा लीक मामले में सीबीआई द्वारा सौंपी गई 'केस डायरी', आरोप पत्रों और एक निचली अदालत के जमानत आदेशों पर गौर करने का अनुरोध किया है। याचिका के जरिए एसएससी को रिपोर्ट सौंपे जाने तक और समिति द्वारा कोई रिपोर्ट सौंपे जाने की स्थिति में उसे लागू किए जाने तक सीजीएल की कोई और परीक्षा लेने से रोकने का भी अनुरोध किया गया है।

▸ नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

▸ पेपर लीक होने को लेकर विवादों में रही थी परीक्षा

सरकारी नौकरी पाने के लिए हर साल एसएससी की परीक्षाओं में लाखों छात्र शामिल होते हैं। यह आयोग केंद्र सरकार के नियंत्रण क्षेत्र में आता है और विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों में 'समूह ग' और 'समूह घ' श्रेणी में भर्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। हाल के दिनों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल उठते रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के शामिल होने की कोई बात ही नहीं : नीतीश कुमार

राज्य ब्यूरो, पटना : जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह दो टूक कहा कि जदयू के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोई बात नहीं है। दिल्ली में बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने यह कहा था कि सांसदों की संख्या के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण आता है तो जदयू उस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। पार्टी के एक अन्य नेता पवन वर्मा ने त्यागी से सहमति जताई थी। गुरुवार को पत्रकारों ने जब इस संबंध में मुख्यमंत्री से पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह सब फालतू बात है। ऐसी कोई बात नहीं है।

मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य के बाद साफ हो गया है कि जदयू अपने उस स्टैंड से हटा नहीं है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा था कि भविष्य में भी उनका दल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल गठन के क्रम में जदयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल एक सांसद को शामिल किए जाने का ऑफर मिला था। इसके पीछे यह तर्क दिया गया था कि भाजपा अपने गठबंधन दलों को मंत्रिमंडल में केवल एक स्थान दे रही। जबकि जदयू का यह तर्क था कि सांसदों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए।

कोर्ट का निर्देश

आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व वित्त मंत्री तिहाड़ जेल में हैं बंद, तबीयत बिगड़ने के कारण चिदंबरम को हाल के दिनों में दो बार अस्पताल ले जाना पड़ा है

चिदंबरम की सेहत पर मेडिकल बोर्ड बनाए एम्स

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की स्थिति पर राय देने के लिए हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को गुरुवार शाम तक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया। मेडिकल रिपोर्ट पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने कहा कि इस बोर्ड में चिदंबरम का उपचार करने वाले हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट गैस्ट्रोथेरोलॉजी (एआइजी) के नागेश्वर रेड्डी को भी शामिल किया जाए, ताकि वह अपनी राय दे सकें। पीठ ने स्पष्ट किया कि गुरुवार शाम सात बजे तक मेडिकल बोर्ड बैठक कर ले। यदि डॉक्टर रेड्डी तब तक हैदराबाद से दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं, तो बैठक शुक्रवार सुबह दस बजे होगी।

इससे पहले चिदंबरम की तरफ से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस नेता को उपचार के लिए उनके खर्च पर हैदराबाद ले जाना चाहिए क्योंकि उन्हें जीवाणु रहित वातावरण की जरूरत है। बाद में उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि चिदंबरम को अपोलो अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है या फिर डॉक्टर रेड्डी को बुलाया जा सकता है। अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिरासत में चिदंबरम की सेहत में लगातार गिरावट हो रही है। उनका वजन 73 किग्रा से कम होकर 63 किग्रा रह गया है। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि चिदंबरम को एम्स के निजी वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि वहां पर सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। एम्स के सबसे अच्छे डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है।

▸ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर आज होगी आगे की सुनवाई

पी चिदंबरम फाइल फोटो

कपिल सिब्बल की बात पर अदालत ने जताई नाराजगी

सिब्बल ने अदालत में नाराजगी जताते हुए कहा कि जब सरकार एक व्यक्ति को जीवाणु रहित वातावरण नहीं देना चाहती तो वह अपनी याचिका वापस ले रहे हैं और वह कुछ नहीं चाहते। इससे खफा पीठ ने कहा कि ठीक है आपकी याचिका खारिज की जाती है। इस कद का अधिवक्ता ऐसा व्यवहार कर रहा है, जो ठीक नहीं है। हालांकि, बाद में दूसरे अधिवक्ता ने माहौल को ठीक करने की कोशिश की।

चिदंबरम ने मांगी छह दिन की अंतरिम जमानत

स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चिदंबरम ने छह दिन की अंतरिम जमानत देने की मांग नियमित जमानत याचिका के आवेदन पर की है। नियमित जमानत याचिका 4 नवंबर के लिए सूचीबद्ध है। उन्होंने दावा किया है कि 5 अक्टूबर से उन्हें पेट में दर्द है और उन्हें तत्काल उपचार की जरूरत है। एम्स की दवाइयां उन पर असर नहीं कर रहीं और उनका वजन गिर रहा है। ऐसे में उन्हें एआइजी स्थित उनके नियमित डॉक्टर को दिखाने का सुझाव दिया गया है।

भाजपा के प्रभात झा बने राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष

नई दिल्ली, प्रेट्र : सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की आठ समितियों का पुनर्गठन किया है। इसके तहत भाजपा के प्रभात झा को आचार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। वह पार्टी के सहयोगी नारायण लाल पंचारिया की जगह लेंगे। झा अभी तक याचिका समिति के अध्यक्ष थे। उनका स्थान बीजद के प्रसन्न आचार्य लेंगे। नायडू ने कांग्रेस के टी. सुब्बीरामी रेड्डी को पुनः अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है। अन्नाद्रमुक के ए. नवनीत कृष्णन को आश्वासन समिति, भाजपा के ओम प्रकाश माथुर को आवास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नवगठित कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य के रूप में कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद, भाजपा के नारायण लाल पंचारिया व विनय पी. सहस्त्रबुद्धे को शामिल किया गया है। टीआरएस के के. केशव राव एवं नेता प्रतिपक्ष को इस समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। नियम संबंधी समिति में भाजपा के सत्यनारायण जटिया, स्वप्नदास गुप्ता और वाईएस चौधरी, कांग्रेस के पीएल पूनिया, अकाली दल के नरेश गुजराल है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

31 में 24 कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से हैं हरियाणा में। ऐसे में हुड्डा का विपक्ष का नेता बनना तय है। पिछली बार कांग्रेस के पास कुल 15 विधायक थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 1 नवंबर 2019

एकनाथ शिंदे बने शिवसेना विधायक दल के नेता

नरम रुख ▸ उद्धव बोले, हम मित्रपक्ष को मित्रपक्ष मानते हैं शत्रुपक्ष नहीं, हम चाहते हैं स्थिर सरकार

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के एक हफ्ते बाद भी सरकार गठन को लेकर गतिरोध नहीं टूटा है। इस बीच चौथी बार विधानसभा सदस्य बने एकनाथ शिंदे को गुरुवार को शिवसेना विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के दो दिन पहले दिए बयान पर नाराजगी तो जताई, लेकिन यह भी कहा कि हम मित्रपक्ष को मित्रपक्ष मानते हैं, शत्रुपक्ष नहीं। हमें स्थिर सरकार देने का प्रयास करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद शिवसेना के नियंत्रण वाले बृहनमुंबई नगर निगम ने ठाकरे परिवार के निवास 'मातोश्री' के बाहर लगे उस होर्डिंग को हटा लिया जिस पर सिर्फ आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात लिखी थी।

शिवसेना विधायक दल का नेता चुनने के लिए गुरुवार दोपहर दादर स्थित शिवसेना भवन में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें शिवसेना को समर्थन की घोषणा कर चुके निर्दलीय विधायकों ने भी हिस्सा लिया।

बैठक में ठाणे की पांचपाखड़ी सीट से चौथी बार विधायक चुने गए और पिछली सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे आदित्य ठाकरे ने किया। आदित्य शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं और चुनाव जीतकर किसी सदन में पहुंचने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं। उनके द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन पांच अन्य विधायकों ने किया और शिंदे विधायक दल के नेता चुन लिए गए। बैठक में दूसरी बार विधायक बने सुनील प्रभु को विधानसभा में शिवसेना का चीफ व्हिप भी चुना गया।

बैठक को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने दो दिन पहले आए देवेंद्र फड़नवीस के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें पत्रकारों को दिए गए दीवाली भोज के दौरान यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। उद्धव का आशय फड़नवीस के उस बयान से था जिसमें उन्होंने शिवसेना को ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद का कोई वादा नहीं करने की बात कही थी। उद्धव ने कहा कि किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि वह मुख्यमंत्री पद का अमरत्व प्राप्त करके आया है। लेकिन इस बयान के तुरंत बात उद्धव ने नरम रुख अख्तियार करते हुए यह भी कहा कि वह मित्रपक्ष को मित्रपक्ष ही समझते हैं, शत्रुपक्ष नहीं। हमें मिलकर स्थिर सरकार देने का प्रयास करना चाहिए।

शिवसेना नेता एवं नवनिर्वाचित विधायक आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में पार्टी विधायकों ने गुरुवार को राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। साथ में शिवसेना विधायक दल के नेता चुने गए एकनाथ शिंदे (बाएं से दूसरे) और अन्य। एएनआइ

सरकार गठन पर अंतिम फैसला उद्धव लेंगे : आदित्य

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद कहा कि सरकार गठन में देरी ठीक नहीं है। भाजपा से सरकार गठन की वार्ता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को भाजपा की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गठन पर कोई भी फैसला उनके पिता और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही लेंगे। आदित्य ने बताया कि राज्यपाल से उन्होंने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की।

राउत बोले, 50-50 फॉर्मूले की मांग नहीं छोड़ी

भाजपा के प्रति सदैव कड़ा रुख रखने वाले शिवसेना सांसद एवं पार्टी मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने एक बार फिर साफ किया कि शिवसेना ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद और 50-50 फॉर्मूले की मांग से पीछे नहीं हटी है।

भाजपा-शिवसेना सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं एकनाथ शिंदे

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

शिवसेना विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही एकनाथ शिंदे का सितारा चमक उठा है। जैसी की संभावनाएं हैं, यदि भाजपा-शिवसेना गठबंधन की सरकार बनी तो शिंदे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री भी बन सकते हैं।

चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लोगों की निगाह शिवसेना के विधायक दल नेता के चुनाव पर लगी थी। माना जा रहा था कि पहली बार चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचे ठाकरे परिवार के पहले सदस्य आदित्य ठाकरे को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। चुनाव परिणाम आने के अगले दिन ही ठाकरे निवास मातोश्री पर हुई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में कई विधायकों ने खुलकर आदित्य को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठाई थी। आदित्य के चुनाव क्षेत्र वरली और उनके निवास मातोश्री के बाहर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर भी उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताने की कोशिश हुई। शिवसेना अभी भी ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी हुई है। लेकिन राजनीतिक हलकों में एक विचार यह भी शुरू से चल रहा था कि उद्धव ठाकरे अपने पुत्र आदित्य पर अभी यह बड़ी जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। वह उन्हें कुछ समय सदन की रीति-नीति समझने का मौका देकर ही बड़ी जिम्मेदारी देंगे।

आदित्य के बाद अन्य वैकल्पिक नामों में ठाकरे परिवार के सबसे भरोसेमंद सुभाष देसाई और ठाणे से चौथी बार चुनकर विधानसभा में पहुंचे एकनाथ शिंदे के नाम शीर्ष पर थे। चूंकि शिवसेना इस बार मुख्यमंत्री पद पर अड़ी है। यदि वह न मिला तो उपमुख्यमंत्री पद मिलना तो तय माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में सुभाष देसाई का नाम दौड़ में आगे लग रहा था। लेकिन शिंदे ठाणे जनपद के जमीनी नेता हैं। 2014 के चुनाव के बाद जब तक शिवसेना सत्ता में शामिल नहीं हुई थी, तब तक एकनाथ शिंदे को ही शिवसेना विधायक दल का नेता बनने के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष भी बनने का मौका मिला था। सरकार में शामिल होने के बाद उन्हें पीडब्लूडी जैसा मंत्रालय भी दिया गया। वह जनाधार वाले नेता भी हैं। माना जाता है कि यदि उन्हें नजरअंदाज करके उद्धव कोई कदम उठाते तो वह भविष्य के नारायण राणे साबित हो सकते थे।

हरियाणा में कांग्रेस दिखाएगी सदन से सड़क तक तेवर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल बनी कांग्रेस ने सरकार गठन के साथ ही आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन से ही जहां कांग्रेस विधायक सरकार पर हमलावर नजर आएंगे, वहीं मंगलवार से पूरे प्रदेश में दिग्गज कांग्रेसी 10 दिन के लिए सड़कों पर उतरेंगे।

पिछले पांच साल में बिखरे विपक्ष और राजनीतिक गलतियों से सबक लेते हुए कांग्रेस अभी से भाजपा-जजपा के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गई है। हरियाणा कांग्रेस की प्रधान कुमारी सैलजा ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही पार्टी प्रभारी गुलाम नबी आजाद, राष्ट्रीय महासचिव मधुसूदन मिस्त्री भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की यह पहली बैठक है।

हरियाणा कांग्रेस का मौजूदा समय में कोई संगठन नहीं है। आपसी खींचतान के कारण पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर प्रदेश में कांग्रेस का ब्लॉक व जिला स्तर पर संगठन नहीं खड़ा कर सके थे। बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सैलजा ने तंवर द्वारा गठित प्रकोष्ठों व अन्य नियुक्तियों को निरस्त कर दिया। सैलजा ने अभी तक आधा दर्जन नियुक्तियां ही की हैं जिनमें मुख्य रूप से प्रवक्ता, संयोजक तथा कोषाध्यक्ष शामिल हैं।

चंडीगढ़ में बुलाई बैठक में चुनाव हारने वाले सभी प्रत्याशियों, जिला समन्यवकों के अलावा उन सभी नेताओं को बुलाया गया है जिन्होंने चुनाव में अहम भूमिका निभाई है। पार्टी द्वारा 5 से 15 नवंबर तक विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सदन से लेकर सड़क तक भाजपा-जजपा सरकार की घेराबंदी की जाएगी।

किरण चौधरी के बैठक में शामिल होने पर संशय

कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक में पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी के भाग लेने पर संशय है। हालांकि पहली बैठक होने और हाईकमान के इसमें शामिल होने के चलते किरण चौधरी का इसमें आना अनिवार्य है। पार्टी के अंदरूनी राजनीतिक हालातों पर अगर नजर डालें तो किरण चौधरी का हुड्डा गुट के साथ हमेशा छत्तीस का आंकड़ा रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर और किरण चौधरी द्वारा बुलाई गई अधिकतर बैठकों में हुड्डा गुट के विधायक शामिल नहीं हुए हैं। हुड्डा खुलकर तो कभी आगे नहीं आए, लेकिन जब किरण चौधरी ने खुद को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए विधानसभा स्पीकर के समक्ष दावा पेश किया था तो हुड्डा समर्थित सभी विधायकों ने इसका विरोध किया था।

न्यूज गैलरी

'देश चीन की तरह एक दलीय शासन की ओर बढ़ रहा'

नई दिल्ली : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कहा है कि भारत भी चीन की तरह एकदलीय शासन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन कर रही है, उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि जिनकी गोद में ये पार्टियां जा रही हैं, उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा के लोग देश को चला रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। चीन की तरह देश एक दलीय शासन की ओर जा रहा है। हरियाणा के चुनाव में 40 सीटें जीतने वाली भाजपा ने जजपा के साथ सरकार बनाई है। (एएनआइ)

मोदी का स्वच्छता अभियान महज दिखावा : तेज प्रताप

मथुरा : बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने नंदगांव में गंदगी पर नाराजगी जताई। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान महज दिखावा है। उन्होंने नंदगांव में कई स्थलों के दर्शन किए। गंदगी देख कहा कि प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण यहां विकास नहीं हो सका है। यहां परिवहन व्यवस्था नहीं है, गायों के लिए कोई चिकित्सालय नहीं। (जासं)

हरियाणा में नई सरकार चलाने को पुरानी कैबिनेट संग सीएम मनोहर लाल का मंथन

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

- मनोहर लाल ने हारे हुए सभी आठ मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया
- चुनाव जीते अनिल विज और डॉ. बनवारी लाल भी होंगे बैठक में शामिल

हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन की नई सरकार चलाने में पूर्व मंत्रियों की भी राय ली जाएगी। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी पुरानी कैबिनेट के चुनाव हार चुके सभी मंत्रियों को बातचीत के लिए शुक्रवार को चंडीगढ़ बुलाया है। मनोहर लाल की पुरानी कैबिनेट में अनिल विज और डा. बनवारी लाल ही चुनाव जीते हैं। इन दोनों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है।

सीएम निवास पर सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पुराने मंत्रियों के साथ नई सरकार के संचालन पर चर्चा करेंगे। मनोहर कैबिनेट में शामिल दो मंत्रियों विपुल गोयल और राव नरबीर को इस बार टिकट नहीं मिला था। इसलिए वह चुनाव नहीं लड़े, लेकिन विपुल व राव दोनों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। पुरानी मनोहर कैबिनेट के आठ मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओमप्रकाश धनखड़, कृष्ण पाल पंवार, कविता जैन, मनीष ग्रोवर, कृष्ण कुमार बेदी और कर्ण देव कांबोज चुनाव हार गए हैं। इन आठों मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। सीएम इस बैठक में पुराने मंत्रियों के साथ सरकार के संचालन, नए मंत्रियों की नियुक्ति, विधानसभा की कार्यवाही और भाजपा की सहयोगी पार्टी जजपा को कदम से कदम मिलाकर साथ लेकर चलने की तमाम स्थितियों पर चर्चा करेंगे। बैठक में मंत्रियों के चुनाव हारने के कारणों की भी समीक्षा होगी। इंद्री हलके से 2014 में चुनाव जीते कर्ण देव कांबोज का इस बार हलका बदलकर रादौर किया गया है। रादौर से श्याम सिंह राणा विधायक थे। उनका टिकट काटा गया है। रादौर से कर्ण देव चुनाव हार गए, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के मुद्दे भी सीएम के साथ होने वाली बैठक में उठाए जा सकते हैं।

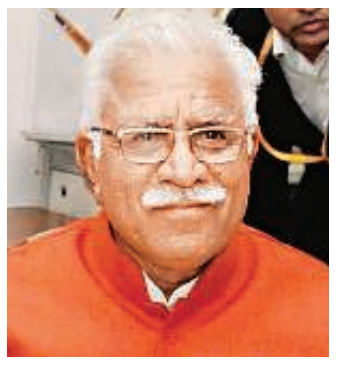

मुख्यमंत्री मनोहर लाल। फाइल

बैठक में मंत्री अपनी हार के कारण और भितरघात के साथ ही टिकट वितरण के तमाम पहलुओं पर खुलकर बातचीत करने वाले हैं। दूसरी तरफ हरियाणा सचिवालय की पांचवीं मंजिल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम की प्लेट लग चुकी है। यह पूरा फ्लोर डिप्टी सीएम के आफिस के लिए आवंटित हो चुका है। सीएम मनोहर लाल के नाम की प्लेट पहले ही लग चुकी है। मंत्रिमंडल का गठन छह नवंबर के बाद संभव है। मुख्यमंत्री कार्यालय में होने वाली नियुक्तियों पर भी चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। इस बार सीएमओ पूरी तरह से बदला हुआ होगा।

आज कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे। इसके बाद उनका विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

चंडीगढ़ में शुक्रवार को होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुड्डा को नेता चुन लिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा विधानसभा स्पीकर को एक पत्र लिखकर बैठक की कार्यवाही के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर द्वारा हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष के रूप में अधिसूचित कर दिया जाएगा। हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कु. सैलजा ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के विरुद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार करने को अलग से बैठक होगी। पहले दौर की बैठक सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कु. सैलजा के अलावा हाल ही में चुने गए सभी विधायक भाग लेंगे।

कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी प्रभारी गुलाम नबी आजाद और पार्टी महासचिव मधु सूदन मिस्त्री भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित जैन के अनुसार दूसरे दौर की बैठक में केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों के विरुद्ध आंदोलन चलाने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। काबिल-ए-गौर है कि इस बार हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत हासिल हुई है। चुने गए विधायकों में ज्यादातर हुड्डा गुट के हैं।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फाइल

भाजपा के समक्ष वोट प्रतिशत बरकरार रखने की चुनौती

झारखंड चुनाव

राज्य ब्यूरो, रांची

- लोकसभा चुनाव में पार्टी को झारखंड में मिले थे 50 प्रतिशत से अधिक वोट
- इसी प्रदर्शन के बूते पार्टी ने इस बार 65 प्लस का दिया है नारा

हरियाणा विधानसभा चुनाव के हाल ही में आए परिणामों ने प्रदेश भाजपा को एक बार फिर से मंथन के मोड में डाल दिया है। भाजपा की चुनौती पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिले वोट प्रतिशत को बरकरार रखने की है। लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत के आधार पर ही भाजपा ने इस बार 65 प्लस का नारा दिया है। हालांकि, यह नारा एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की साझा मुहिम को दिया गया है, लेकिन आजसू के साथ अभी से बन रही तनातनी की स्थिति से भाजपा फिलहाल असहज महसूस कर रही है।

विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे जुदा होते हैं। यही वजह है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने बूते पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई। हालांकि, वहां दोबारा सरकार बनाने में भाजपा जरूर कामयाब हो गई। लोकसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा को इस बार रिकार्ड मत मिले। 14 में से 12 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई और भाजपा का वोट प्रतिशत 50 फीसद को पार कर गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को इतनी ही सीटें हासिल हुईं थी और उसे करीब 41 फीसद वोट मिले थे। लेकिन, 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 31 फीसद से कुछ अधिक पर सिमट कर रह गया था। परिणाम स्वरूप, भाजपा को विधानसभा चुनाव में अपने बूते 37 सीटें हासिल हुई थीं। हालांकि, लोकसभा चुनाव के सापेक्ष वोट प्रतिशत में यदि 10 फीसद की गिरावट इस बार भी आती है, तो भी भाजपा पिछली बार से बेहतर स्थिति में होगी। लेकिन, यहां यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में सीटें गंवाने के बावजूद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है। जाहिर है कांग्रेस और झामुमो की संयुक्त ताकत विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेगी।

तृणमूल व माकपा ने घोषित किए उम्मीदवार

बंगाल उपचुनाव

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- करीमपुर सीट पर माकपा ने घोषित किया उम्मीदवार, शेष दो सीटों पर करेगी कांग्रेस का समर्थन
- माकपा-कांग्रेस गठबंधन पर मंत्री सुब्रत मुखर्जी का तंज, सब जानते हैं परिणाम

राज्य के तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को आगामी 25 नवंबर को मतदान होने हैं। इससे पहले इन सीटों के लिए राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी।

गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले की खड़गपुर सदर सीट से पार्टी ने प्रदीप सरकार को तो नदिया जिले की करीमपुर से विमलेंदु सिंह रॉय और उत्तर दिनाजपुर की कालियगंज सीट से तपन देव सिंह को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। वहीं क्षेत्र की जनता व पार्टी कर्मियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना भेदभाव किए विकास को हमेशा काम किया है। ऐसे में सभी एकजुट हो इन सीटों पर पार्टी को जीत दिला मुख्यमंत्री के हाथ को मजबूत करने का काम करें, ताकि क्षेत्र में और अधिक विकास हो सके।

वहीं कांग्रेस संग सीट बंटवारे पर मुहर लगने के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए वाममोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने करीमपुर सीट से माकपा उम्मीदवार के रूप में गुलाम रब्बी के नाम की घोषणा की। इस दौरान क्षेत्र के लोगों को भाजपा व तृणमूल के खिलाफ लामबंद हो माकपा व कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की तो वहीं तृणमूल के वरिष्ठ नेता व राज्य के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने वाममोर्चा अध्यक्ष की जनता से अपील पर तंज कसते हुए कहा कि परिणाम सबको पता है और सब यह भी जानते हैं कि माकपा-कांग्रेस गठबंधन व्यापक अंतर से पराजित होने जा रही है। दरअसल, अगले महीने पश्चिम मेदिनीपुर जिले की खड़गपुर सदर, नदिया जिले की करीमपुर और उत्तर दिनाजपुर की कालियगंज सीटों के लिए उपचुनाव को मतदान होने हैं।

बता दें कि कालियगंज सीट कांग्रेस विधायक प्रमथनाथ राय के निधन के बाद खाली हुई है, जबकि खड़गपुर सदर सीट से पिछली बार विधायक चुने गए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के लोकसभा सदस्य चुने जाने से रिक्त हुई है।

बंगाल में आगामी उपचुनाव हिंसा मुक्त होने चाहिए : राज्यपाल

जागरण संवाददाता, कोलकाता : राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि राज्य में 25 नवंबर को तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव 2019 में हुए लोकसभा चुनावों की यादों को मिटाने के लिए हिंसा मुक्त होने चाहिए। लोकसभा चुनावों ने राज्य की एक अलग तरह की छाप छोड़ी थी। आगामी उपचुनावों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उपचुनाव मील का पत्थर साबित होंगे और दुनिया को यह दिखाएंगे कि सबसे शांतिपूर्ण चुनाव बंगाल में होते हैं। हाल ही में राज्य सरकार के साथ बयानबाजी में उलझे राज्यपाल ने कहा कि उपचुनाव हिंसा मुक्त होने चाहिए। पिछले लोकसभा चुनावों ने एक अलग तरह की छाप छोड़ी थी। हमें उसे मिटाने की जरूरत है। राज्यपाल यहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि उपचुनाव हिंसा मुक्त होगा और प्रत्येक मतदाता को वोट देने का अधिकार मिलेगा।

भाजपा-जजपा सरकार की न्यूनतम कार्यक्रम समिति को चुनेंगे शाह

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

- समिति में भाजपा की तरफ से केंद्रीय पदाधिकारी की भी हो सकती है भागीदारी

हरियाणा में भाजपा और जजपा सरकार के गठन के साथ ही गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सबकी नजरें हैं। हालांकि सरकार चलाने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम दोनों दलों की एक कमेटी तय करेगी और इस कमेटी का गठन होना अभी बाकी है। माना जा रहा है कि बुधवार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो मुलाकात हुई है, उसमें समिति के खाके पर भी विचार किया गया है।

असल में जननायक जनता पार्टी के नेता भी फिलहाल केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अपना संरक्षक मान रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में चूंकि अमित शाह की तरफ से दुष्यंत चौटाला को अहमियत दी जा रही है इसलिए खुद दुष्यंत और उनके रणनीतिकार चाहते हैं कि यह समन्वय बना रहना चाहिए। इसलिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम की कमेटी का प्रारूप भी शाह के दरबार में ही तय होगा। शाह की मुहर के बाद ही कमेटी का प्रारूप सामने आएगा।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम कमेटी के अध्यक्ष पर होगी बड़ी जिम्मेदारी: भाजपा-जजपा सरकार सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम कमेटी के अध्यक्ष पर बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी होगी कि सरकार की सफलता के लिए दोनों दलों के बीच समन्वय का केंद्र यह कमेटी ही रहेगी। बेहतर समन्वय के साथ दोनों दलों के चुनावी घोषणा पत्र लागू हों और इसका भाजपा के केंद्रीय एजेंडे पर कोई असर नहीं पड़े।

असल में कमेटी की ही जिम्मेदारी साझा कार्यक्रम को पूरी तरह लागू करवाने की रहेगी। एक तरह से सरकार और दोनों दलों के संगठनों की यह कोर कमेटी होगी। इसमें भाजपा की तरफ से जहां खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो रहेंगे ही साथ ही पदेन रूप में प्रदेशाध्यक्ष, संगठन महामंत्री और भाजपा कोटे के वरिष्ठ मंत्री भी हो सकत हैं। जजपा की तरफ से खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उनके दो साथी इसमें शामिल किए जा सकते हैं।

निर्देश

अब संवेदनशील मुद्दों पर सधे कदम बढ़ाएगी कांग्रेस, अयोध्या पर शुरू किया होमवर्क, नफा-नुकसान देखकर दी जाएगी प्रतिक्रिया

हाईकमान की तय की गई लाइन पर बोलेंगे कांग्रेसी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अनुच्छेद-370 और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर नेताओं के वैचारिक भटकाव ने कांग्रेस की खूब किरकिरी कराई। इससे सबक लेकर पार्टी ने तय किया है कि अब किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर पहले ही होमवर्क कर पार्टी लाइन तैयार कर ली जाएगी। फिलहाल अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले के मुहाने पर खड़े उप्र के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इसका स्पष्ट संदेश दे दिया है।

लंबे समय से बिखरी-बिखरी नजर आ रही कांग्रेस अब प्रदेश में खुद को व्यवस्थित और अनुशासित बनाने का प्रयास कर रही है, जिसकी कमान खुद राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने थाम रखी है। प्रदेश कमेटी को छोटा और संतुलित बनाकर उन्होंने पदाधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी है। साथ ही पिछली खामियों और भविष्य की चुनौतियों पर भी उनकी नजर है।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि प्रियंका वाड्रा ने स्पष्ट कहा है कि मोदी सरकार अब संवेदनशील मामलों पर जो भी फैसला लेगी, उस पर प्रतिक्रिया का भटकाव नहीं होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक एक-एक कांग्रेसी का समान रुख होना चाहिए। इस संबंध में राष्ट्रीय नेतृत्व अब गंभीर है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इसे देखते हुए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है कि कांग्रेस का स्टैंड किस फैसले पर क्या होगा। यही नहीं, किसी भी गंभीर विषय पर पहले ही पार्टी लाइन तय कर कार्यकर्ताओं को बता दिया जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पहले मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 खत्म करने पर कांग्रेस अपना स्टैंड तय नहीं कर सकी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया सरीखे वरिष्ठ नेताओं ने फैसले के पक्ष में अपनी राय रखी थी, जबकि शीर्ष नेतृत्व इसके विरोध में था।

प्रियंका गांधी वाड्रा। फाइल

प्रियंका वाड्रा के ट्वीट पर स्मृति ईरानी का पलटवार

जासं, अमेठी : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन भी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका पर हमलावर रहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रियंका वाड्रा के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि वाकई में वह उनके प्रति आस्था रखती हैं तो देशभर में आयोजित रन फॉर यूनिटी में भागीदारी करतीं, न कि अपने ट्विटर एकाउंट पर बैठकर सरदार वल्लभ भाई पटेल व देश की जनता पर कटाक्ष करतीं। उनके पदचिह्नों पर चलकर अखंड भारत की कल्पना करना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल है, जिन्होंने संसद में धारा 370 हटाने का विरोध किया था।

छग की राज्यपाल ने की कमलनाथ की तारीफ, भाजपा नेता नाराज

नईदुनिया, छिंदवाड़ा (मप्र)

छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उईके द्वारा एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की तारीफ करना भाजपा नेताओं को नागवार गुजरा है। भाजपा नेता संतोष राय ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल उईके मप्र के छिंदवाड़ा जिले की मूल निवासी हैं। इन दिनों वे जिले के प्रवास पर हैं। बुधवार रात जिले के रोहना गांव में हुए कार्यक्रम में उन्होंने छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना के साथ मंच साझा किया। दीपक उनके बचपन के मित्र हैं। लिहाजा दोनों ने पुरानी यादें ताजा कीं। इस दौरान राज्यपाल ने मंच से मप्र के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि कमलनाथ जी मुझे सक्रिय राजनीति में लेकर आए हैं। दलगत राजनीति अपनी जगह है। मैं व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देती हूं। उन्होंने बताया कि दीपक सक्सेना और उनका घर आमने-सामने था। कार्यक्रम में पूर्व विधायक दीपक सक्सेना ने रोहना गांव की ओर से उईके को शॉल, श्रीफल देकर अभिनंदन किया। बदले में उईके ने भी अपने साथ छत्तीसगढ़ से लाया गया स्मृति चिह्न सक्सेना को भेंट किया। इस दौरे में यहां वे अपनी बचपन की सहेलियों से भी मिलीं।

भाजपा नेता ने यह की टिप्पणी: इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेता व नगरनिगम के सभापति संतोष राय ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि 'जिनसे हम दुश्मनी निभा रहे हैं, उनसे वो रिश्ते निभा रही हैं।' इस संबंध में राय ने कहा कि मुझे जो भी गलत लगता है, वो स्पष्ट रूप से कह देता हूं। मैंने सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त की है।

पहले भी हो चुका विवाद: जब उईके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष थीं, तब कमलनाथ पर लिखी एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में भी उन्होंने कमलनाथ की तारीफ की थी। जिस पर स्थानीय नेताओं ने विरोध जताया था। स्थानीय छोटा तालाब के सौंदर्यीकरण में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, तब कथित रूप से उईके ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे।

हरियाणा में विधायकों की शपथ में लगेंगे दो घंटे, पहले महिला एमएलए की शपथ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: हरियाणा की 14वीं विधानसभा के लिए नव निर्वाचित विधायकों के शपथ लेने में कम से कम दो घंटे का समय लगेगा। विधायक के नाते सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधानसभा में शपथ ग्रहण करेंगे। तीस

4231 पर्यटक आए हैं कश्मीर में 2019 में अगस्त से अक्टूबर के बीच। इनमें 928 विदेशी थे। वहीं, 1.61 लाख पर्यटक आए थे 2018 में।

साक्षात्कार

अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला : हीको मास

भारत दौरे पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता को कई लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे समय जब दुनिया में चीन का दबदबा बढ़ रहा है और नए सिरे से वैश्विक तालमेल पनप रहे हैं तब भारत व जर्मनी के रिश्तों को भी बहुत दिलचस्पी से देखा जा रहा है। द्विपक्षीय रिश्तों के तमाम पहलुओं पर जर्मनी के विदेश मंत्री **हीको मास** ने दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता **जयप्रकाश रंजन** को ईमेल पर सवालों का जवाब दिया।

जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास का फाइल फोटो।

● आप भारत-जर्मन संबंधों को कैसे वर्गीकृत करेंगे? मोदी-मर्केल युग में यह कैसे बदला है?

- जर्मनी और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी अद्वितीय है। यह 19 वर्ष पुरानी है। दक्षिण एशिया के किसी भी अन्य देश के साथ इस तरह का गठबंधन नहीं है, इस लिहाज से इसकी तुलना किसी दूसरे देश के साथ नहीं की जा सकती। हाल के वर्षों में, हमारे संबंध और गहरे हुए हैं। उदाहरण के लिए दोनों देशों ने 30 से अधिक परामर्श और संवाद प्रारूप बनाए हैं जो पिछले 19 वर्षों के दौरान हमारी साझेदारी को लेकर उपजे विश्वास का नतीजा हैं।

● चांसलर एंजेला मर्केल की यात्रा का क्या महत्व होगा? क्या दोनों देश कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं?

- हम संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के नेताओं ने इसे जो गतिशीलता दी उसे भी बनाए रखना चाहते हैं। यह यात्रा कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगी। उदाहरण के लिए, हम अपने स्टार्ट-अप के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौते करेंगे। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के क्षेत्र में भी हम सहयोग करना चाहते हैं। मर्केल अपनी यात्रा के दौरान एक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के साथ होंगी।

● जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, हम अपनी अर्थव्यवस्था साझेदारी को मजबूत करने के लिए और क्या कर सकते हैं?

- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से हम काफी प्रभावित हैं। यह वर्षों से बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। जर्मनी की तरह, भारत भी मुक्त, खुले और नियम-आधारित व्यापार के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि यूरोप और भारत के लिए यह अच्छा होगा यदि हम एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करें और इसे आगे की तरफ ले जाएं।

● जर्मनी के कौन से क्षेत्र भारत के साथ काम करने को इच्छुक हैं?

- मैं जर्मनी और भारत के बीच कई क्षेत्रों में अधिक से अधिक सहयोग की संभावनाएं देखता हूं। विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों से लड़ने में हमारा सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हम पहले से ही जलवायु और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय रूप से बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यदि हम जलवायु और पर्यावरण के मुद्दों पर और अधिक निकटता से सहयोग करने में सफल होते हैं और खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तो हम पेरिस में निर्धारित महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।

● भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी कैसे आगे बढ़ रही है... भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं?

- भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा नीति के मुद्दों में केंद्रीय भूमिका निभाता है, उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जारी पुनर्निर्माण और वहां चलाई जा रही शांति प्रक्रिया में जर्मनी भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है। दोहा में अंतर-अफगान वार्ता के साथ, जर्मनी ने अफगानिस्तान में भविष्य की शांति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्षेत्र के स्थायी शांति के लिए हमें भारत के प्रभाव की आवश्यकता है। मुख्य सुरक्षा नीतियों को लेकर जर्मनी और भारत को एक दूसरे के साथ चलने की जरूरत है।

● जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर जर्मनी का क्या रुख है?

- हमारे लिए यह भारत का एक आंतरिक मामला है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर से जुड़े फैसले हमेशा क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव डाल सकते हैं। मैंने हमेशा भारतीय और पाकिस्तानी दोनों पक्षों को अपनी बातचीत में इस बारे में बताया भी है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी पक्ष आग पर तेल ना डाले और संवाद के राजनयिक चैनल खुले रहें।

● भारतीय छात्र अब अध्ययन के लिए जर्मनी का चयन कर रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे जो भविष्य में वहां जाना चाहते हैं?

- हमें खुशी है कि भारतीय छात्रों के अध्ययन के लिए जर्मनी इतना लोकप्रिय स्थान है। दोनों देशों में उद्योग और अनुसंधान केवल इस विनिमय से लाभान्वित हो सकते हैं। बेशक, मैं उसी को प्रभावित कर सकता हूं जो भारत और जर्मनी के बीच अच्छे आर्थिक संबंधों और थोड़ी बहुत जर्मन भाषा सीखने के लिए जर्मनी में अध्ययन को इच्छुक हो।

● भारत व जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग की क्या स्थिति है और इसका भविष्य क्या है?

- फरवरी, 2019 में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देने को लेकर एक समझौता हुआ है। इसके अलावा हमने हाल ही में एक नया संवाद प्रारूप बनाया है जो मुख्य रूप से सैन्य नीति से जुड़े पहलुओं पर ध्यान देगा। मुझे उम्मीद है कि यह सब रक्षा व सुरक्षा नीति के मुद्दों पर हमारे सहयोग का एक अच्छा आधार तैयार करेगा।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बने केंद्र शासित प्रदेश

ऐतिहासिक क्षण ▶ जीसी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर और आरके माथुर ने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में ली शपथ

मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने श्रीनगर और लेह में दिलाई शपथ

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पूरे देश की उम्मीदें और आशाएं परवान चढ़ीं और गुरुवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसी के साथ श्रीनगर के राजभवन में जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू और लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर राधाकृष्ण माथुर को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। यह शपथ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने दिलाई। इसके साथ ही दोनों प्रदेशों में विकास का नया अध्याय भी शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण करने के बाद उपराज्यपाल जीसी मुर्मू नागरिक सचिवालय में अपना कार्यभार संभालने पहुंचे। जहां राज्य पुलिस के दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक सचिवों और विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ बैठक में जम्मू-कश्मीर में सरकारी कामकाज की जानकारी ली। आरके माथुर ने भी लद्दाख में पद संभालने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की और विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी ली।

श्रीनगर में हुआ शपथ ग्रहण समारोह : दोपहर करीब पौने एक बजे श्रीनगर के राजभवन में आयोजित एक सादे और भावपूर्ण समारोह में जीसी मुर्मू ने उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. निर्मल सिंह, भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा, पीडीपी के राज्यसभा सांसद नजीर अहमद लावे, निवर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सभी पांच सलाहकार, सेना की 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो, राज्य पुलिस महानिदेशक, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नागरिक प्रशासन, पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षाबल और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

लेह में समारोह : इससे पूर्व सुबह पौने आठ बजे लेह में मुख्य न्यायधीश ने आरके माथुर को लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के सीईसी ग्याल पी वांग्याल, विकास परिषद करगिल के सीईसी फिरोज अहमद खान, दोनों परिषदों के काउंसलर व लेह और कारगिल में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक और मजहबी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

सरदार पटेल की जयंती का चुना दिन : पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत ही अनुच्छेद-370 को समाप्त करते हुए एकीकृत जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में पुनर्गठित किया गया। लेकिन यह फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी हुआ। क्योंकि भारत-पाक विभाजन के समय करीब 565 रियासतों को भारत में शामिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इसी दिन होती है।

श्रीनगर में गुरुवार को गिरीश चंद्र मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। एएफपी

लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करने के बाद आरके माथुर। एएनआइ

'लद्दाख के पर्यावरण के अनुकूल विकास योजनाओं को लागू कराना, सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और विकास के अवसर पैदा करना, खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को बढ़ाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।'

-राधाकृष्ण माथुर, उपराज्यपाल, लद्दाख

दोनों जगहों में 18 जून से लागू राष्ट्रपति शासन हटा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के साथ ही गुरुवार को राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस संदर्भ में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत एकीकृत जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित हुआ है। एकीकृत जम्मू कश्मीर में 18 जून 2018 को महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के गिर जाने के बाद पहले राज्यपाल शासन फिर दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रपति शासन हटाने के संदर्भ में जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-356 के प्रावधान दो के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत मैं रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति भारत 19 दिसंबर 2018 को उपरोक्त अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अपने आदेश को वापस लेता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत ही जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

आपातकाल की अंतिम निशानी भी बनी इतिहास का हिस्सा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- नए जम्मू-कश्मीर में छह नहीं पांच साल का होगा विधानसभा का कार्यकाल
- 45 साल पहले आपातकाल के दौरान बढ़ाई गई थी अवधि

भारत के नक्शे पर गुरुवार को दो केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उभरने के साथ ही आपातकाल की अंतिम निशानी छह वर्ष की विधानसभा भी अब इतिहास का हिस्सा बन गई है। लद्दाख में विधानसभा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अब जो विधानसभा होगी उसका कार्यकाल पांच साल ही होगा।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का छह वर्षीय कार्यकाल 1975 में लागू हुए आपातकाल की देन है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू करने के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को छह साल किया था। इसके लिए भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किया गया। उस समय जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री स्व. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। उन्होंने यह कहकर कि जम्मू-कश्मीर भी पूरे भारत के साथ चलेगा, वह हिंदुस्तान की मुख्यधारा में है, इसलिए छह साल की विस का कार्यकाल उन्होंने राज्य संविधान में संशोधन के जरिए कर दिया।

आपातकाल हटने और इसके साथ ही केंद्र में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्व. मोरार जी देसाई ने जनता पार्टी के नेतृत्व में सत्ता संभालने पर संसद और विधानसभा का कार्यकाल फिर पांच साल कर दिया। पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो गई, लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल छह से पांच साल नहीं हुआ, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके बाद जिसने भी जम्मू-कश्मीर में सत्ता संभाली, सभी ने छह साल की विधानसभा को बनाए रखने को ही प्राथमिकता दी। संबंधित केंद्रीय कानून जो पांच साल के कार्यकाल की व्यवस्था करता है, उसे अनुच्छेद-370 की आड़ में कभी भी जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होने दिया गया।

अलगाववाद की भावना बनाए रखना था कारण

जम्मू-कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ डॉ. अजय चुरुंगू ने कहा कि एकीकृत जम्मू-कश्मीर में कश्मीर केंद्रित पार्टियों की एक वर्ग विशेष के तुष्टिकरण की जो सत्ता रही है, वह अनुच्छेद 370 के चुनिंदा इस्तेमाल का एक सुबूत है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल छह से पांच साल नहीं किया गया, इसके पीछे मंशा सिर्फ जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग रखने और लोगों में अलगाववाद की भावना को बनाए रखने की थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में जो विधानसभा होगी उसका कार्यकाल अब पांच साल ही होगा। वहीं, जब कभी जम्मू-कश्मीर दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करेगा, उस समय भी विधानसभा का कार्यकाल पांच साल ही रहेगा।

राज्य कार्य नियम पहले की तरह रहेंगे लागू

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने जारी किया पहला निर्देश
- सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 31 अक्तूबर, 2019 से इन्हें प्रभावी बना दिया

जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बावजूद एकीकृत जम्मू कश्मीर के जो राज्य कार्य नियम थे, वे केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू रहेंगे। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने पहला निर्देश दिया कि जम्मू व कश्मीर कार्य नियम के प्रावधान जो पूर्व में जम्मू व कश्मीर राज्य पर लागू थे, वे आगे भी सरकारी लेनदेन के कार्य में प्रभावी रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 31 अक्तूबर, 2019 से इन्हें प्रभावी बना दिया।

पुनर्गठन के विरोधी सांसद को समारोह में देख सभी हैरान : केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में पीडीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नजीर अहमद लावे को देख सभी हैरान रह गए। उन्होंने वहां आए अन्य गणमान्य नागरिकों से मुलाकात की और उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मिलकर उन्हें मुबारक भी दी।

यह वही नजीर लावे हैं जिन्होंने गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हालात सामान्य बनाने व राजनीतिक बंदियों की रिहाई का आग्रह किया था।

पूरी तरह शांत रही स्थिति : एकीकृत जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित राज्यों के रूप में अस्तित्व में आने पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ और आतंकी संगठनों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी व हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। इस साजिश का खुफिया तंत्र ने अलर्ट भी जारी किया था। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए लखनपुर से लेकर लेह तक सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया था। सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मजबूत बनाते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा व एलओसी के साथ सटे इलाकों में और आतंकग्रसत इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया था। कई जगह ड्रोन के जरिए भी स्थिति पर नजर रखी गई। अलबत्ता, स्थिति पूरी तरह शांत रही।

ये बड़े बदलाव

- जम्मू, श्रीनगर और लेह स्थित रेडियो कश्मीर के केंद्र अब आकाशवाणी जम्मू, आकाशवाणी श्रीनगर और आकाशवाणी लेह में बदल गए।
- केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय कानून प्रभावी हो गए।
- अब राष्ट्रभाषा हिंदी को केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में उर्दू के स्थान पर सरकारी भाषा का दर्जा दिया जा सकेगा।
- एकीकृत जम्मू कश्मीर को अपनी एक अलग पहचान और कश्मीर के वर्चस्व से मुक्ति मिल गई।
- भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को चुनौती देने वाला जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और अलग निशान भी अब पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया।
- राज्यपाल का पद भी समाप्त हो गया।

यूटी बनने की खुशी में खुलकर झूमे लद्दाखी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

सात दशक के लंबे इंतजार के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने का सपना साकार होने पर गुरुवार को लद्दाख खुशी से झूम उठा। लेह के मुख्य बाजार में पांच घंटे तक नाच-गाने के बीच केंद्र शासित प्रदेश बनने की खुशियां मनाई गईं। लेह में बसने वाले बौद्ध, शिया, सुन्नी मुस्लिमों के साथ क्रिश्चियन समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी इस जश्न में बराबर हिस्सा लिया।

लद्दाख के सांसद जामियांग सेरिंग नांग्याल के साथ लेह हिल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, काउंसिलरों के साथ कारिगल हिल काउंसिल के कई काउंसिलर व भाजपा की कारगिल जिला इकाई के नेता भी इस समारोह में शामिल हुए। नांग्याल ने कहा कि लद्दाख के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। आगे देखिए क्या-क्या होता है। लद्दाख के लोग पिछले 71 सालों सें बेसब्री के साथ इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उनका कहना था कि मोदी सरकार ने लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है।

लेह में उप राज्यपाल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम खत्म होने के बाद लेहवासी मुख्य बाजार में एकत्र होने लगे और सुबह नौ बजे के करीब यूटी की खुशी मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। पारंपरिक वेशभूषा में लेह के निवासियों का नाच, गाना दोपहर दो बजे तक जारी रहा। शुक्रवार को भी लद्दाख के यूटी बनने की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी रहेगा।

कारगिल का मुख्य बाजार बंद रहा: कारगिल में कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों के प्रभाव के चलते लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। कारगिल का मुख्य बाजार गुरुवार को भी बंद रहा। कश्मीर केंद्रित दलों के नेताओं की तरह कारगिल के कई नेता भी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विरोध कर रहे हैं। जिले के नेताओं का कहना है कि कारगिल वासियों की आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का फैसला उन्हें मंजूर नहीं है।

लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने पर स्थानीय लोगों ने इस तरह नाच-गाकर खुशी व्यक्त की। एपी

अब 'यह आकाशवाणी का जम्मू केंद्र' है...

अशोक शर्मा, जम्मू : यह आकाशवाणी का जम्मू केंद्र है... 72 साल बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को रेडियो स्टेशन से यह एनाउंसमेंट सुनने को मिली, जिससे उनमें संतोष और भारतीयता की लहर दौड़ पड़ी। लंबे समय से जम्मू-कश्मीर के लोग मांग करते रहे थे कि रेडियो कश्मीर जम्मू का नाम बदला जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश होते ही श्रोताओं की लंबित मांग पूरी हो गई।

केंद्र शासित प्रदेश बनते ही जम्मू-कश्मीर में काफी कुछ बदल रहा है। अब रेडियो कश्मीर जम्मू का नाम ऑल इंडिया रेडियो जम्मू के साथ रेडियो कश्मीर श्रीनगर का नाम ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर और लेह स्टेशन का नाम ऑल इंडिया रेडियो लेह होगा।

वरिष्ठ समाचार वाचक जगमोहन शर्मा का 'एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमा सुना करदेओ' और विजय बजाज का कहना 'एह आकाशवाणी जम्मू ए बडलै खबरें च तुंदा स्वागत' भी श्रोताओं के लिए एक नया अहसास था, जो 1971 से लेकर आज तक सुबह शाम क्षेत्रीय समाचार सुनते आ रहे हैं। उनके लिए भी यह सुखद अनुभव था। देश भर में दो ही स्टेशन ऐसे थे जो रेडियो कश्मीर जम्मू और रेडियो कश्मीर श्रीनगर कहलाते थे जबकि देश भर के दूसरे स्टेशनों से आकाशवाणी का केंद्र कहा जाता है। वैसे तो जम्मू-कश्मीर शुरू से ही भारत का अटूट अंग रहा है लेकिन देश के दूसरे रेडियो स्टेशनों की एनाउंसमेंट सुनने के बाद लगता था कि जम्मू-कश्मीर के रेडियो स्टेशनों के नाम में कुछ तो गलत है।

आकाशवाणी जम्मू की कार्यक्रम प्रमुख रेणु रैना ने कहा कि लंबे समय से लोग रेडियो कश्मीर जम्मू का नाम बदल कर देश के दूसरे स्टेशनों की तरह आकाशवाणी जम्मू रखने की मांग करते आए हैं। अनुच्छेद 370 के चलते महाराजा हरि सिंह के समय चल रहा नाम बदलना आसान नहीं था। अब केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद प्रसार भारती की उच्च स्तरीय बैठक में नाम बदलने का निर्णय लिया गया। आज से आदेश का पालन हुआ है।

नापाक इरादे

कुलगाम में पश्चिम बंगाल के पांच श्रमिकों की हत्या इसी साजिश का है हिस्सा, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद विकास प्रक्रिया से हताश है पाकिस्तान

आइएसआइ ने रची गैर कश्मीरियों की हत्या की साजिश

श्रीनगर/नई दिल्ली, एजेंसी: जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद कश्मीर में विकास योजनाओं को गति दिए जाने से हताश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ और उसके समर्थित आतंकी संगठनों ने हालात बिगाड़ने के लिए पूरी घाटी में विशेषकर दक्षिण कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोगों की हत्याओं की साजिश रची है। गत दिनों कुलगाम में पश्चिम बंगाल में पांच श्रमिकों की हत्या भी इसी साजिश का हिस्सा है। इस साजिश से कश्मीर में दूसरे राज्यों के 20 हजार से अधिक लोगों और श्रमिकों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

श्रीनगर स्थित खुफिया तंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया है कि इस्लामाबाद इस समय कश्मीर और गैर कश्मीरियों के बीच दूरी पैदा करना चाहता है। अब वह केंद्र शासित कश्मीर में भारत के अन्य हिस्सों के लोगों का आना पूरी तरह बंद कराना चाहता है। उन्होंने बताया कि बीते एक माह के दौरान एलओसी के पास आतंकियों के कई रेडियो संदेश पकड़े गए हैं। इनमें नवगठित केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने की पाकिस्तानी की खतरनाक साजिश का राजफाश हुआ है। इस साजिश को पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ ने मिलकर तैयार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कश्मीर में आतंकियों द्वारा दूसरे राज्यों के लोगों को निशाना बनाए जाने की रची गई साजिश 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं व उनके सामूहिक पलायन की याद दिलाती है।

कश्मीर में पांच सौ से अधिक आतंकी: खुफिया सूत्रों के मुताबिक, कश्मीर में 500 से अधिक आतंकी हैं। इनमें से अधिक 200 से ज्यादा पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी हैं। इनमें से अधिकांश विदेशी आतंकियों की अगुआई में अलग-अलग गुटों में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के चार जिलों शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग में ही सबसे ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं।

पाक खुफिया एजेंसी ने विदेशी आतंकियों को सौंपी कमान

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आइएसआइ ने अपनी साजिश को अमलीजामा पहनाने के लिए घाटी में विदेशी आतंकियों को विभिन्न संगठनों की कमान संभालने को कहा है। यह स्थानीय आतंकियों से कहीं ज्यादा क्रूर हैं। इससे पहले कि यह अपनी साजिश को और आगे बढ़ाएं, हमने उन्हें मार गिराने के लिए विशेष अभियान चला रखे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के डिवीजन कमांडर रियाज नायकू की भी तलाश तेज कर दी है। उसने ही जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के साथ मिलकर बाहरी ट्रक चालकों की हत्या की वारदातों को अंजाम दिया है। उसने ही कुछ समय पहले चेतावनी दी थी कि यदि कुछ बड़ी घटना घटी, तो उसके आदमी गैर-कश्मीरी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू करेंगे। उसने एक ऑडियो संदेश में कहा था कि 'कश्मीर में मौजूद बाहरी लोग हमारे निशाने पर होंगे।'

'कश्मीर में साजिश के तहत की गई बंगाल के श्रमिकों की हत्या'

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के पांच श्रमिकों की कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने पर केंद्र सरकार को घेरा है। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि श्रमिकों की हत्या प्री प्लान (पूर्व निर्धारित) साजिश थी।

उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में है। कश्मीर में यूरोपियन सांसदों के दौरे के मद्देनजर सभी सावधानी बरती गई थी। उसके बाद कैसे वहां श्रमिकों की हत्या हुई? इस वारदात के पीछे जम्मू-कश्मीर में केंद्र की गलत नीतियों का हवाला देते हुए ममता ने कहा कि एक ओर यूरोपियन सांसदों को केंद्र की मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर का दौरा करा रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं व सांसदों को वहां जाने से रोका जाना सरकार के दोहरे रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मारे गए राज्य के श्रमिक वहां रहने नहीं, बल्कि अपने काम को पूरा करने के बाद लौटने वाले थे। ऐसे में इनकी हत्या पूरी तरह से प्री प्लान थी और इस वारदात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना समय गंवाए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

धनखड़ बोले, हिंसा की निंदा करें, राजनीतिकरण नहीं

पांच श्रमिकों की हत्या मामले में गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि हिंसा चाहे जहां भी हो, इसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। धनखड़ ने गुरुवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने उक्त बातें कहीं।

25 आइएएस अधिकारियों को लगाया है पंजाब सरकार ने पराली की घटनाओं को रोकने के लिए। सूबे के 27 जिलों में इस साल 30 अक्टूबर तक पराली जलाने के 16732 मामले दर्ज किए गए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 1 नवंबर 2019

टीपू सुल्तान के अतीत और वर्तमान में खिंची तलवारें

कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर टीपू सुल्तान को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि उनकी सरकार टीपू सुल्तान के इतिहास से जुड़ी हर चीज हटाने जा रही है। पाठ्यक्रम की किताबों से भी टीपू से जुड़ी सामग्री हटाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार ने पूरे राज्य में 18वीं सदी के मैसूर के इस शासक की जयंती मनाई जाती थी। दूसरी सरकारों में उसकी महिमा के गीत गाए जाते थे। टीपू सुल्तान को लेकर भाजपा का नजरिया बिल्कुल अलग है। आइए यहां समझने की कोशिश करते हैं कि टीपू सुल्तान के इतिहास को लेकर इतना विवाद क्यों छिड़ा है?

जब जल उठा कोडगु

मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने वर्ष 2015 से राज्य स्तर पर टीपू सुल्तान जयंती मनाने की शुरुआत की थी। इसका भाजपा ने जमकर विरोध किया था और इसे सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला कदम बताते हुए वोटबैंक की राजनीति करार दिया था। इस समारोह के विरोध में कोडगु जिले में हिंसा शुरू हो गई थी जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समेत दो लोगों की मौत हो गई थी।

हिंदू विरोधी शासक की छवि

भाजपा टीपू सुल्तान को अत्याचारी और हिंदू विरोधी शासक बताती रही है। एक ऐसा राजा जिसने जबरन धर्मांतरण कराने के साथ मंदिरों को ध्वस्त किया। केरल-कर्नाटक की सीमा पर कोडगु वन क्षेत्र व केरल के कुछ हिस्सों में भी टीपू सुल्तान को नायक के रूप में नहीं देखा जाता है। दरअसल टीपू सुल्तान और उसके पिता **हैदर अली** की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं काफी अधिक थीं। इसी के तहत मैसूर से बाहर के कई इलाकों पर भी कब्जा किया गया। मालाबार, कोझीकोड, त्रिशूर, कोडगु व कोच्चि पर विजय प्राप्त कर इन्हें मैसूर शासन के अधीन लाया गया। इन सभी स्थानों पर टीपू सुल्तान को एक रक्तपिपासु शासक के रूप में देखा जाता है जिसने शहरों व गांवों को जला दिया। सैकड़ों मंदिरों व चर्चों को जमींदोज कर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। अब भाजपा टीपू के व्यक्तित्व के इसी पहलू को प्रचारित कर रही है ताकि इसी बहाने मजबूत राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा सके। भाजपा ने इस पर 2016-17 से ही काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि 2018 में विधानसभा चुनाव होने थे ताकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ हिंदुओं की सशक्त गोलबंदी की जा सके। उस समय के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों व पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर चुनावी रण में विजय पताका फहराने की रणनीति पर काम कर रहे थे।

मैसूर के शेर की उपाधि

भाजपा से इतर सोच रखने वाले टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में चित्रित करते हैं जो निडर व बहादुर था, जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ डटकर संघर्ष किया। टीपू सैनिक हैदर अली का बेटा था जो अपनी योग्यता व काबिलियत के बल पर वाडयार शासन के तहत सेना में ऊंचे ओहदे तक गया। बाद में वह 1761 में मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ और उसने 17 वर्ष की उम्र में ही पहला एंग्लो-मैसूर युद्ध लडा। दूसरे एंग्लो-मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मौत हो गई और टीपू सुल्तान ने 1782 में सत्ता संभाली। आम भारतीयों में टीपू की छवि एक साहसी योद्धा, कुशल प्रशासक व सैन्य रणनीतिकार के रूप में रही है जिसने अपने 17 वर्ष के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे कठिन चुनौती दी। टीपू ने 1767-99 के बीच पूरी बहादुरी से ईस्ट इंडिया कंपनी का चार बार सामना किया और गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस और वेलेस्ली को नाकों चने चबवा दिए। चौथी जंग में टीपू की मौत हो गई। इसके बाद मैसूर ईस्ट इंडिया के अधीन हो गया।

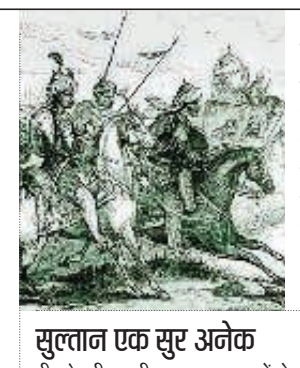

यूरोपीय सेना की तर्ज पर काम

टीपू सुल्तान ने यूरोपियन सेना की तर्ज पर नई तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी सेना को पुनर्गठित किया। टीपू की सेना में रॉकेट तक था। उसने कृषि क्षेत्र का विकास किया। नई भू राजस्व प्रणाली विकसित की। पुराने डैम को ठीक कराया तो सिंचाई के लिए आधारभूत संरचना तैयार की। मैसूर में चंदन, रेशम, चावल आदि का कारोबार होता था। इसे देखते हुए टीपू सुल्तान ने विदेश के साथ अपने क्षेत्र में 30 व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे।

सुल्तान एक सुर अनेक

टीपू के जीवन की सकारात्मक बातों से उसकी क्रूरता की कहानियां समाप्त नहीं होती हैं। टीपू एक ऐसा शासक था जिसके बारे में लोगों की अलग-अलग राय है। कांग्रेस व समाजवादी टीपू सुल्तान की राष्ट्रवादी छवि गढ़ते हैं क्योंकि उसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जंग किया था तो भाजपा उसे हिंदुओं व ईसाइयों के जबरन धर्मांतरण के कारण अत्याचारी कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में देखती है। टीपू ने फ्रांस के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया का मुकाबला किया ताकि दक्कन व कर्नाटक की राजनीति को नियंत्रित करने की ब्रिटिश कोशिशों को नाकाम किया जा सके। उसने कोडगु को अपने अधीन इसलिए किया ताकि मंगलौर बंदरगाह को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। टीपू ने क्षेत्र में बिना किसी जाति-धर्म की परवाह किए हर जंग को लड़ा। उसकी सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। जब उसने केरल में खून खराबा किया तो मरने वालों में मुसलमान भी बड़ी संख्या में थे। सिद्दरमैया की मानें तो यह कहना गलत होगा कि टीपू राष्ट्रवादी या धर्मनिरपेक्ष था। 18वीं सदी में ऐसी कोई विचारधारा ही नहीं थी। वहीं अगर इसके प्रमाण हैं कि टीपू ने मंदिरों को तोड़ा तो यह भी सच है कि उसकी ओर से मंदिरों तथा पुजारियों को दान व उपहार भी दिए गए। टीपू ने श्रृंगेरी मठ को संरक्षित किया।

कैप्टन की अगुआई में नहीं जाऊंगा करतारपुर : बाजवा

दो टूक ▶ कहा, अगर जत्थे की अगुआई मनमोहन सिंह करेंगे तो जाऊंगा

मुख्यमंत्री का जवाब, अकाली दल के जत्थे के साथ चले जाएं बाजवा

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

करतारपुर गुरुद्वारे में एक साथ मत्था टेकने को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्य सभा सदस्य व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा आमने-सामने हो गए हैं। बाजवा ने नौ नवंबर को कैप्टन की अगुआई में करतारपुर साहिब जाने वाले जत्थे में शामिल होने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि अगर जत्थे की अगुआई पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह करेंगे तो वह जाएंगे। कैप्टन ने भी बाजवा पर पलटवार करते हुए कहा है कि वह अकालियों के जत्थे में भी शामिल हो सकते हैं।

कैप्टन का कहना है कि बाजवा अगर नहीं जाना चाहते तो न जाएं। वह जिसके साथ जाना चाहते हैं, चले जाएं। अकाली दल का भी जत्था जा रहा है, वह उसके साथ भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ बाजवा ने कहा कि जो मुख्यमंत्री धार्मिक ग्रंथ की मर्यादा नहीं रखते, उनकी अगुआई में वह गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने नहीं जा सकते। कैप्टन ने गुटखा साहिब हाथ में लेकर नशे को खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया।

बाजवा ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह का सिख जगत में सबसे अधिक सम्मान है। वह कैप्टन से वरिष्ठ भी हैं और दो बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ऐसे में उनको ही जत्थे की अगुआई करनी चाहिए। बता दें कि 2002 की कैप्टन सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे बाजवा के संबंध बाद में मुख्यमंत्री के साथ ज्यादा खराब हो गए थे। दोनों के बीच लंबे समय से छत्तीस का आंकड़ा चल रहा है।

केंद्र व पंजाब सरकार और एसजीपीसी वहन करे 20 डॉलर का खर्च : करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से 20 डॉलर वसूलने की पाकिस्तान की शर्त पर बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान पर सिखों का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार भारत पर है। देश में हज यात्रियों के लिए पहले ही सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह सिख श्रद्धालुओं के लिए 20 डालर की शर्त को केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और एसजीपीसी मिलकर उठाए ताकि किसी पर भी अतिरिक्त बोझ न पड़े। खर्च भी उन्हीं लोगों का उठाया जाए जो गरीब हैं।

गुरुद्वारा श्री गुरु नानक प्याऊ दिल्ली से ननकाना साहिब जाने वाले अतंरराष्ट्रीय नगर कीर्तन के अमृतसर स्थित अटारी-वाघा सरहद के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करते समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर पुष्प वर्षा करती हुई संगत और सोने की पालकी को उठाकर सरहद पार ले जाते हुए सेवादार। जागरण

पासपोर्ट पर न लगे पाकिस्तान की मुहर

प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि केंद्र सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि पंजाब से जाने वाले श्रद्धालुओं के पासपोर्ट पर पाकिस्तान की मुहर न लगे। पंजाब के लोग विदेश में रोजगार की तलाश में जाते हैं। अगर उनके पासपोर्ट पर पाकिस्तान की मुहर लग जाती है तो कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों में उनके पासपोर्ट को संदिग्ध नजरों से देखा जाता है। अतः पाकिस्तान सरकार पासपोर्ट के साथ एक अतिरिक्त पेपर लगा सकती है। जब श्रद्धालु करतारपुर साहिब में मत्था टेककर वापस आएं तो उस कागज को फाड़ दिया जाए। इससे न तो पासपोर्ट पर पाकिस्तान की मुहर लगेगी और न ही युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत आएगी।

पाकिस्तान का दावा, सिद्धू ने स्वीकारा उसका आमंत्रण

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पाकिस्तान की सत्तारूढ़ तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने दावा किया है कि पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री इमरान खान का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इमरान ने सिद्धू को नौ नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। सिद्धू ने इमरान का धन्यवाद करते हुए कहा है कि वह इसके लिए आभारी हैं।

तहरीक-ए-इंसाफ के सीनेटर फैजल जावेद ने सिद्धू के साथ संपर्क करके उन्हें आमंत्रण दिया था। फैजले के मुताबिक सिद्धू ने कहा कि विश्व भर में फैले सिख समुदाय को बाबा नानक के इस कॉरिडोर के खुलने की अपार खुशी है। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने नवजोत सिद्धू द्वारा पाकिस्तान के आमंत्रण को स्वीकार करने पर कहा है कि पाकिस्तान ने जिनको न्योता दिया है, उनके लिए पॉलिटिकल क्लीयरेंस जरूरी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को 480 श्रद्धालुओं की सूची भेज दी है और हमें उसकी मंजूरी का इंतजार है।

सिद्धू पाक जाएंगे या नहीं, यह वही बताएंगे : कैप्टन

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि नवजोत सिद्धू पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, इसके बारे में वही बता सकते हैं। कैप्टन ने यह बात डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कही। उल्लेखनीय है कि कैप्टन से सिद्धू के संबंध अच्छे नहीं हैं। पिछली बार जब सिद्धू पाकिस्तान गए थे, तब भी कैप्टन ने नाराजगी जताई थी।

550वें प्रकाश पर्व पर अमृतसर से लंदन के लिए फ्लाइट शुरू

जासं, अमृतसर : श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर गुरुवार को अमृतसर से लंदन के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो गई। सप्ताह में तीन दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार तड़के लगभग तीन बजे यहां से लंदन के लिए उड़ान भरी जा सकेगी। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 164 यात्रियों को लेकर तड़के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अमृतसर से उड़ा। उड़ान से पहले एयरपोर्ट पर अरदास की गई। यात्रियों में शामिल क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि एयर इंडिया ने अपने विमानों की टेल पर एक-ओंकार का चिह्न लगाकर सिख श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया है।

30 हजार संगत के स्वागत के लिए डेरा बाबा नानक में तैयारी

बाल कृष्ण कालिया, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर)

30 एकड़ में बनी सुविधाओं से लैस टेंट सिटी

3500 श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए की है व्यवस्था

श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को लेकर ऐतिहासिक नगर डेरा बाबा नानक में आठ नवंबर से शुरू होने वाले चार दिवसीय समागमों में लगभग 30 हजार संगत रोजाना पहुंचेगी। संगत के ठहरने के 30 एकड़ पर सुविधाओं से लैस टेंट सिटी बनाई गई है। यहां 3500 संगत के ठहरने के प्रबंध हैं। टेंट सिटी में 544 टेंट यूरोपियन स्टाइल, 100 स्विस कोटेज और 20 दरबार स्टाइल की रिहायश है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को मुख्य समागम के लिए बनाए गए मुख्य पंडाल के साथ-साथ टेंट सिटी का भी निरीक्षण किया और प्रबंधों पर संतुष्टि जाहिर की। पंडाल में 30 हजार की संख्या में संगत एकत्रित होने की क्षमता है।

4.2 करोड़ रुपये की लागत से बनी टेंट सिटी : टेंट सिटी का प्रोजेक्ट 4.2 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। इसमें यूरोपियन तरीके की रिहायश भी बनाई गई है। इसमें छह-छह व्यक्ति ठहर सकते हैं। इस तरीके की रिहायश के साथ 140 अलग बाथरूम और 140 वॉशरूम भी बनाए गए हैं। प्रत्येक स्विस कोटेज में दो व्यक्ति ठहर सकते हैं। इसके साथ बाथरूम भी अटैच होगा।

श्रद्धालुओं को मिलेगा आरओ युक्त पानी : डीसी विपुल उज्जवल ने बताया कि एक हजार लीटर प्रति घंटे की क्षमता के साथ पानी संशोधन करने वाला एक आरओ और पानी मुहैया करवाने के लिए 18 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इससे संगत को साफ पानी मुहैया करवाना यकीनी बनाया जाएगा। इसी तरह बिजली की निर्विघ्न सप्लाई के लिए 125 किलोवॉट के सामर्थ्य वाले चार जेनरेटर भी लगाए जाएंगे।

दो को होगी ऑनलाइन बुकिंग : पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारा परिसर में जाने के लिए दो नवंबर को ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जा रही है। इसमें भारत का कोई भी श्रद्धालु इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद ऑनलाइन सिस्टम में अप्रूवल मिलने के बाद श्रद्धालु को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा साहिब के दर्शनों के लिए अनुमति मिलेगी।

श्रद्धालुओं की मदद करेगी एसजीपीसी

जासं अमृतसर : पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के खोले गए रास्ते के माध्यम से दर्शन को जाने वाली संगत की एसजीपीसी की ओर से आवश्यक मदद की जाएगी। एसजीपीसी श्रद्धालुओं की सूचियां तैयार करके अगली प्रक्रिया के लिए भी मदद करेगी। इसके लिए एसजीपीसी अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने सभी गुरुद्वारों के मैनेजरों को आदेश जारी कर दिए हैं। एसजीपीसी के प्रवक्ता कुलविंदर सिंह रमदास ने कहा कि जो भी श्रद्धालु पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वे एसजीपीसी के प्रबंधों के अधीन चलने वाले गुरुद्वारों के मैनजरों और प्रबंधकों के पास पहुंच सकते हैं। इस संबंध में मैनेजरों को एक पत्र भी जारी किया जा रहा है।

जवाहर पंडित हत्याकांड में करवरिया बंधु दोषी करार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▶ **एडीजे कोर्ट में अब चार नवंबर को सुनाई जाएगी सजा, 13 अगस्त 1996 को एके-47 से की गई थी तीन लोगों की हत्या**

प्रयागराज के विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड के मुकदमे में करवरिया बंधु दोषी करार दे दिए गए। खचाखच भरी अदालत में अपर जिला जज (एडीजे) बद्री विशाल पांडेय ने पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके भाई पूर्व विधायक उदयभान, पूर्व एमएलसी सूरज भान तथा रामचंद्र मिश्रा उर्फ कल्लू को दोषी करार दिया। 23 साल पुराने इस मामले में चार नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।

कोर्ट ने 31 अक्टूबर की तिथि फैसले के लिए निर्धारित की थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई होने से पहले ही कोर्ट में तमाम अधिवक्ता और अभियुक्तों के समर्थक पहुंच गए। दोपहर करीब दो बजे अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो मुल्जिम करवरिया बंधु कोर्ट में मौजूद थे। अपर जिला जज ने 224 पेज के निर्णय में खुली अदालत में कहा कि अभियोजन ने अपने अभियोग को पूर्णतः साबित किया है। लिहाजा सभी आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 302, 149, 307/149 व 7 सीएलए एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है। सजा के बिंदु पर आगामी चार नवंबर को सुनवाई होगी और उसी दिन फैसला आएगा। करीब एक घंटे तक अभियुक्त कोर्ट में मौजूद रहे और फिर साढ़े तीन बजे के लगभग उन्हें वापस नैनी जेल भेज दिया गया।

घटना 13 अगस्त 1996 को हुई थी। शाम को प्रयागराज सिविल लाइंस में एके 47 से गोली मारकर विधायक जवाहर पंडित समेत तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। फायरिंग में दो राहगीर भी जख्मी हुए थे। जवाहर के भाई सुलाकी यादव की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा लिखा गया था। सीबीसीआइडी लखनऊ ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था, जिस पर अब तक सुनवाई चल रही थी। इधर, सुनवाई के बीच में ही प्रदेश सरकार ने करवरिया बंधुओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की संस्तुति की थी, जिसे डीएम के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। इस पर तत्कालीन अपर जिला जज रमेश चंद्र ने सुनवाई की और निष्कर्ष में पाया कि मामले में गवाही पूर्ण हो चुकी है। इस स्तर पर मुकदमा वापस करने की अर्जी विचारनीय नहीं है। इसी आधार पर तब अर्जी खारिज कर दी गई थी।

शाह बोले, पटेल के प्रयास से बना देश का वर्तमान मानचित्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ गृहमंत्री ने इंडिया गेट पर रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी

▶ अनुच्छेद 370 व 35ए हटाने को बताया सरदार पटेल का सपना

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके योगदान को याद किया। कहा कि हमारे सामने आज जो भारत का मानचित्र दिखाई पड़ता है, इसमें एक भारत की जो झलक दिखाई देती है, यह केवल सरदार पटेल के प्रयासों के कारण है। अंग्रेजों ने देश को 550 से अधिक रियासतों में बांटने का काम किया। पूरी दुनिया मानती थी कि भारत को आजादी तो मिलेगी, लेकिन वह बिखर जाएगा। महात्मा गांधी ने पूरे भारत को एक संघ के रूप में स्थापित करने का काम सरदार पटेल का सौंपा, जिसे उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कर दिखाया।

गृह मंत्री शाह ने इस अवसर पर इंडिया गेट पर आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो अमर जवान ज्योति पर जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, खेल मंत्री किरण रिजिजू, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी व दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के अलावा खेल जगत की कई हस्तियां मौजूद रहीं।

शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पटेल ने आजादी के बाद देश को एक किया, लेकिन जम्मू-कश्मीर को एक करने की कसक बाकी रह गई थी। अनुच्छेद 370 व 35ए के कारण जम्मू-कश्मीर हमारे लिए एक समस्या बनकर रह गया। 70 साल में किसी सरकार ने इसे छूना मुनासिब नहीं समझा। देश की जनता ने भाजपा सरकार को चुना और मोदी ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 व 35ए को हटाकर सरदार पटेल का अधूरा सपना पूरा कर दिया। ये दोनों ही अनुच्छेद देश के लिए आतंकवाद का प्रवेश द्वार बने हुए थे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद शाह ने कहा कि सरदार पटेल को देश की आजादी के बाद उचित सम्मान नहीं मिला। चाहे वह भारत रत्न देने की बात हो या फिर उनकी याद में कोई बड़ा स्मारक बनवाने की, यहां तक की उन्हें भुलाने के भी प्रयास किए गए। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए देश के करोड़ों किसानों से उनके खेतों में इस्तेमाल किए गए औजारों व मिट्टी को इकट्ठा करने की शुरुआत की। आज गुजरात में 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनवाकर दुनिया के सामने उनके काम को रखने का कार्य किया है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नई दिल्ली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को रवाना करते गृहमंत्री अमित शाह। जागरण

युवा आइएएस से बोले प्रधानमंत्री देश के लिए मिलकर काम करें

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

केवडिया (गुजरात), प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को युवा आइएएस अधिकारियों से देश के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अकेले-अकेले काम करने या पदानुक्रम से व्यवस्था को मदद नहीं मिलती।यहां अपनी तरह के पहले कॉमन फाउंडेशन कोर्स 'आरंभ' में हिस्सा ले रहे नौकरशाहों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत को 2024-25 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को साकार करने की दिशा में काम करें। बता दें कि 'आरंभ' एक राष्ट्र केंद्रित और भविष्य केंद्रित कोर्स है। इसका मकसद प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव लाना है ताकि लोग अकेले काम करने की प्रवृत्ति छोड़ दें। मोदी ने आगे कहा कि नौकरशाही की किसी भी पोस्टिंग को दंड के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, 'आइए हम चीजों को देखने का नजरिया बदलें। कई बार शब्दावली बदलने से भी मदद मिलती है। पहले लोग कहा करते थे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स (पिछड़े जिले)। आज हम कहते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स (आकांक्षी जिले)।' इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सिविल सर्विसेज के विकास में देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के योगदान को भी याद किया।

फर्जीवाड़ा

इंदौर में सड़क हादसे में मारे गए सेना के सफाई कर्मी के लैपटॉप ने उगले कई राज, क्राइम ब्रांच, पुलिस और सेना की पड़ताल जारी, अन्य लोगों के भी शामिल होने का शक

सेना में फर्जी भर्ती के लिए बना ली थी वेबसाइट

नईदुनिया, इंदौर

मध्य प्रदेश के इंदौर-देवास बायपास पर सड़क हादसे में मृत सेना के सफाईकर्मी और फर्जी लेफ्टिनेंट जयप्रकाश झा के लैपटॉप और मोबाइल की जांच में चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। उसने सेना में भर्ती के लिए फर्जी वेबसाइट भी बना ली थी। वह किसी प्रशिक्षण अकादमी की तरह भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय से संबंधित कर्मचारियों की कथित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लेकर परीक्षा और प्रशिक्षण भी आयोजित करवाता था। इस जानकारी के बाद सैन्य अधिकारियों ने जयप्रकाश से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि आर्मी वॉर कॉलेज (महू) में पदस्थ सफाईकर्मी 24 वर्षीय जयप्रकाश झा की कार मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें न केवल जयप्रकाश बल्कि उसके बेटे और माता-पिता के साथ ही दो साथियों की जान चली गई थी। पत्नी और साली की हालत गंभीर बनी हुई है। सड़क हादसे के बाद पुलिस को पड़ताल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कार में लेफ्टिनेंट की नेम प्लेट भी मिली थी। झा को लेफ्टिनेंट समझ जांच कर रही पुलिस उस वक्त हैरान गई जब महू स्थिति सैन्य छावनी के अफसरों ने यह बताया कि वह लेफ्टिनेंट नहीं, बल्कि सफाईकर्मी था। अफसरों ने उसके पास मिले कार्ड को फर्जी बताया और संदेह जताया कि झा फर्जीवाड़े में लिप्त था। अफसरों ने कार में मिले सामान की छानबीन की तो दो स्टार लगी वर्दी मिली।

इंदौर की तेजाजीनगर थाना पुलिस के अनुसार जयप्रकाश की कार से मिले लैपटॉप में चार जीबी डेटा मिला था। बुधवार रात तकनीकी जांच के लिए लैपटॉप क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। उसमें अधिकारियों को एक फ्लेक्स (होर्डिंग) का फोटो मिला। इस पर ज्वाइंट रिक्रूटमेंट ग्रुप (जेआरजे) लिखा हुआ था। उसमें एक वेबसाइट बनाए जाने की जानकारी भी मिली। सेना के अधिकारियों ने वेबसाइट खोली तो उसमें सेना का लोगो, फोटो और रक्षा मंत्रालय से जुड़ी जानकारी मिली। जांच में शामिल एक कर्नल के अनुसार प्रारंभिक पड़ताल में यह स्पष्ट हो चुका है कि जयप्रकाश सेना में भर्ती के नाम पर बेरोजगारों को ठग रहा था। कुछ लोग वेबसाइट के जरिये आवेदन करते थे। उसके लैपटॉप में सेना भर्ती संबंधित दस्तावेज और सवाल-जबाव भी मिले हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वालों की वह फर्जी परीक्षा भी आयोजित करवाता था। बाद में उन्हें वह प्रशिक्षण भी देता था। हालांकि, अभी तक की जांच में उसके द्वारा एलडीसी, माली, कारपेंटर, सफाईकर्मी, पेंटर और इलेक्ट्रिशियन आदि पदों के लिए आवेदन लेने की ही जानकारी मिली है। पुलिस को शक है कि फर्जीवाड़े में अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार जयप्रकाश के बैंक खातों की जानकारी मांगी गई है। कॉल डिटेल के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि वह किसका कॉल था, जिससे बात होने पर जयप्रकाश बिहार की अपनी यात्रा रद कर 200 किमी से वापस महू के लिए लौटने लगा। हालांकि, महू पहुंचने से पहले ही हादसे में उसकी मौत हो गई।

जेआरजे ग्रुप के लिए सेना भी कर चुकी है अलर्ट : ज्वाइंट रिक्रूटमेंट ग्रुप (जेआरजे) की जानकारी मिलने पर सेना भी अलर्ट जारी कर चुकी है। सेना ने कहा कि यह भ्रामक विज्ञापन और संस्था है। लोग बहकावे में न आएं और इस पर कोई आवेदन नहीं करें। साथ में सेना ने एक लिंक देकर बताया है कि भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय से संबंधित आधिकारिक भर्ती के लिए इसी लिंक का उपयोग करें।

टेरर फंडिंग : पीएम आवास योजना के आवेदकों के खातों की होगी जांच

जागरण संवाददाता, बरेली

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए खुलवाए गए बैंक खातों के जरिये टेरर फंडिंग की आशंका है। इसे लेकर डूडा के परियोजना अधिकारी ने योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदनकर्ताओं के बैंक खातों की जांच के लिए कहा है। इस बाबत उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को पत्र भेजा है।

बरेली के मकरंदपुर सरकार निवासी किरन ने 21 अक्टूबर को एसएसपी शैलेश पांडेय से शिकायत की थी कि कर्मचारीनगर में रहने वाले मोहित, सुधार व शुभम ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का झांसा देते हुए 11 महिलाओं का बैंक खाता खुलवाया था। कुछ खाते नगरिया परीक्षित की एक सरकारी बैंक शाखा और कुछ खाते डीएम आवास के पास एक निजी बैंक में खोले गए। इन खातों में सात से बीस लाख रुपये तक आए और तुरंत ट्रांसफर कर दिए गए। बाकी महिलाएं तो समझ ही नहीं सकीं। किरन ने मोबाइल पर मैसेज आने के बाद बैंक में संपर्क किया तो लेन-देन का पता चला। तीनों युवकों से शिकायत की तो उन्होंने धमकी दी। एसएसपी से शिकायत पर 22 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर, इन महिलाओं के आवेदन डूडा कार्यालय में भी चेक कराए गए, लेकिन आवेदन नहीं मिले। यानी, इन खातों का उपयोग सिर्फ रुपयों के लेन-देन के लिए हो रहा था।

खुल सकते हैं टेरर फंडिंग के विदेशी लिंक

लखनऊ : नेपाल के जरिये टेरर फंडिंग की रकम उत्तर प्रदेश में भेजने वाले गिरोह के बड़ों तक पहुंचने के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) शुक्रवार से नए सिर से कसरत शुरू करेगा। मुंबई से पकड़े गये नाइजीरिया निवासी दोनों आरोपितों को एटीएस पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू करेगी। माना जा रहा है कि दोनों आरोपितों से टेरर फंडिंग के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शनों की कुंडली पता चलेगी। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 11 अक्टूबर को नेपाल से लाखों रुपये लेकर आये उम्मेद अली, संजय अग्रवाल, एराज अली व समीर सलमानी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया था। चारों के तार टेरर फंडिंग से जुड़े थे। एटीएस ने बरेली से मास्टर माइंड सिराजुद्दीन व फहीम को पकड़ा था, जिन तक नेपाल से लाई गई रकम पहुंचाई जाती थी। इसके बाद एटीएस ने मुंबई से नाइजीरिया के रहने वाले चिनवेउबा एमेका माइकल, पीटर हरमन अस्सेंगा व अर्जुन अशोक खराडे को गिरफ्तार किया था। तीनों से शुरुआती पूछताछ में सामने आया था कि कई देशों से ऑनलाइन फ्राड की रकम नेपाल के खातों में पहुंचाई जाती थी। विवेचना में विभिन्न खातों में 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर (1.75 करोड़ रुपये) ट्रांसफर करने के तथ्य सामने आने के बाद ही ए

84 साल बाद बस शुरू होने के ट्रेन पहुंची है मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में। इस रेललाइन का शिलान्यास फरवरी 2008 में हुआ था। ट्रेन पहुंचने पर लोगों ने उसका आतिशबाजी कर स्वागत किया।

सड़क से नहीं हटेंगे कमर्शियल वाहन

पहल ▶ आइआइपी ने ईंधन वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की दिशा में बढ़ाए कदम

प्रयोग के तौर पर संस्थान के दो वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला

सुमन सेमवाल, देहरादून

कोलकाता में आयोजित होने वाले विज्ञान महोत्सव में होगा नई तकनीक का प्रदर्शन। प्रतीकात्मक

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आइआइपी) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की उस चिंता का समाधान खोजने में जुट गया है। जिससे 10 साल की अवधि पूरी करने वाले कमर्शियल वाहनों को भविष्य में सड़कों से हटाने की नौबत आ गई है। आइआइपी ऐसे शोध की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे ईंधन वाले वाहनों को आसानी से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में तब्दील किया जा सकेगा। प्रयोग के तौर पर संस्थान के दो पुराने वाहनों को ईवी में बदल भी दिया गया है और इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। इसी के साथ संस्थान के वैज्ञानिक अब शोध को बाजारी प्रतिस्पर्धा के हिसाब से परिष्कृत करने में जुट गए हैं।

गुरुवार को जागरण से बातचीत में आइआइपी के निदेशक डॉ. अंजन रे ने बताया कि पांच से आठ नवंबर को कोलकाता में पांचवां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। वहां ईवी तकनीक का भी विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी वाहन को इलेक्ट्रिक मोड में लाने के लिए उसके इंजन और फ्यूल टैंक को निकाल दिया जाता है। उसकी जगह उसमें मोटर, कंट्रोलर और बैटरी को फिट किया जाता है। इसके साथ ही कुछ आवश्यक बदलाव और संयोजन के बाद वाहन का इलेक्ट्रिक माध्यम से संचालन किया जा सकता है। अभी यह शोध शुरुआती अवस्था में है, लिहाजा आइआइपी निदेशक ने ईवी को लेकर अधिक तकनीकी जानकारी देने से इन्कार कर दिया।

संस्थान के वाहन में लगी एक किलोवाट की बैटरी : आइआइपी ने जिस ईंधन वाहन को ईवी में तब्दील किया है, उसमें एक किलोवाट की बैटरी लगाई गई है। वर्तमान में यह वाहन एक बार चार्ज करने पर 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसकी अधिकतम स्पीड भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया कि उच्च क्षमता की बैटरी लगाकर इसकी क्षमता को उसी अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह भी है कि अभी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों में जिन बैटरियों का चलन है, वह चीन से मंगाई जाती हैं। जबकि इस प्रयोग में मेक इन इंडिया के तहत बैटरियों का निर्माण कराया जाएगा।

बदलाव की लागत 1.7 लाख : ईंधन वाहन को इलेक्ट्रिक रूप देने के लिए करीब 1.7 लाख रुपये खर्च आ रहा है। हालांकि, यह लागत अभी प्रयोगशाला स्तर की है और कमर्शियल स्तर पर इसकी लागत और कम हो जाएगी।

चुनौती से निपटने वाला यह प्रयोग क्रांतिकारी : आइआइपी के निदेशक अंजन रे ने बताया कि जिस तरह से देशभर में 10 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों को सड़क से बाहर करने की बात कही जा रही है, उससे ऐसे वाहनों का निस्तारण किसी चुनौती से कम नहीं। क्योंकि अभी देश में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में बाहर होने वाले वाहनों का उचित निस्तारण किया जा सके। लिहाजा, इस चुनौती से निपटने के लिए किया जा रहा यह शोध किसी क्रांति से कम साबित नहीं होगा।

उत्तराखंड में चार नवंबर को लाया जा रहा प्रस्ताव : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद उत्तराखंड में भी 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को सड़कों से बाहर करने का प्रस्ताव आगामी चार नवंबर को होने वाली संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में लाया जा रहा है। इसी के साथ वाहन स्वामियों की चिंता भी बढ़ गई है।

मेजर जनरल कैडेट्स को भेजता था अश्लील वीडियो, होगा कोर्ट मार्शल

नई दिल्ली, एएनआइ : सेना के एक मेजर जनरल पर एनसीसी की महिला कैडेट्स ने अश्लील वीडियो भेजने के आरोप लगाए हैं। अब इस सैन्य अफसर को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा। सेना के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया, 'अधिकारी देश के पश्चिमी हिस्से में तैनात था। वहां उसके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की महिला कैडेट्स की देखरेख की जिम्मेदारी थी। अपनी तैनाती के दौरान कथित तौर पर वह महिला कैडेट्स के साथ अश्लील वीडियो साझा किया करता था।' सूत्रों ने बताया कि अधिकारी से अश्लील वीडियो मिलने के बाद छात्रा ने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की। इसके बाद मामले की जांच के आदेश जारी हुए।

सूत्रों ने कहा, 'अधिकारी जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाला है। लेकिन, आर्मी एक्ट की धारा 123 के तहत उसे सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यवाही का सामना करना होगा।' गौरतलब है कि जनरल बिपिन रावत के सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद इस प्रकार के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने एक महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी का कोर्ट मार्शल किया था।

योगी जी, बीएसएनएल की बिजली न काटें : संचार मंत्री

प्रमोद यादव, प्रयागराज

- मोबाइल टॉवरों के विद्युत कनेक्शन काटे जाने पर रविशंकर प्रसाद ने लिखी चिट्ठी
- बीएसएनएल नहीं जमा कर पा रहा है बकाया बिजली का बिल
- चार त्रैमासिक किस्तों में किया जाएगा बकाये बिल का भुगतान

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। बिजली का बिल जमा न कर पाने से मोबाइल टॉवरों और दूरसंचार केंद्रों का कनेक्शन काटा जा रहा है। इससे संचार सेवा ठप होने लगी है। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि 31 मार्च 2020 तक बकाया बिल पर कनेक्शन न काटें। चार त्रैमासिक किस्तों में बकाये बिल का भुगतान करा देंगे।

प्रयागराज में दूरसंचार केंद्रों, मोबाइल टॉवरों और कार्यालयों का हर महीने का बिजली का बिल करीब 80 लाख रुपये होता है। बीएसएनएल इसे हर महीने जमा नहीं कर पाता है, क्योंकि इनकी महीनेभर की कमाई करीब दो से ढाई करोड़ है। वह भी दिनोंदिन कम होती जा रही है। इस कमाई से उसे अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। निगम होने के बावजूद वह बिजली के बिल, वेतन व अन्य खर्चे के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। बिल जमा न हो पाने के कारण पिछले दिनों दर्जनभर दूर संचार केंद्र और दो दर्जन से अधिक मोबाइल टॉवर ठप हो गए थे।

फिलहाल अब कुछ का बिल जमा हुआ है। फिर भी करीब दर्जनभर टॉवर बंद हैं। ऐसी स्थिति देशभर में बीएसएनएल की है। इसलिए 24 अक्टूबर को संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में बीएसएनएल का ही नेटवर्क है और इसकी बिजली कटने पर दूर दराज के उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। इस समय निगम की माली हालत ठीक नहीं है, वह इसे पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पत्र को मुख्यमंत्री ने यूपीपीसीएल के सीएमडी के पास भेजा है। उम्मीद है कि जल्द ही सीएमडी की सहमति के बाद मोबाइल टॉवरों के कनेक्शन कटने बंद हो जाएंगे।

फैसले के लिए खुद को तैयार कर रहा संघ

अयोध्या की पुकार

- पक्ष में निर्णय आने को लेकर आशान्वित है आरएसएस, बनाई जा रही रणनीति
- संघ ने कहा, किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे सौहार्द

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर किसी भी फैसले के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) खुद को तैयार कर रहा है। संघ आशान्वित है कि नवंबर के मध्य तक आने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में होगा। हालांकि, विपरीत फैसला आने की स्थिति के लिए भी वह अपनी रणनीति को पुख्ता कर लेना चाहता है। इसलिए छतरपुर में चल रही संघ परिवार की तीन दिवसीय बैठक में गुरुवार को दूसरे दिन भी राममंदिर का मुद्दा छाया रहा। इसमें सर संघचालक मोहन भागवत, संघ के शीर्ष पदाधिकारी और आनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दूसरे दिन भी बैठक में हिस्सा लिया। वहीं, उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल विशेष रूप से बुलाए गए।

संघ के एक पदाधिकारी के मुताबिक, 'हम फैसला अपने पक्ष में आने को लेकर आशान्वित हैं। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मंदिर स्थान को तीन बराबर भागों में बांटने का आदेश दिया था। ऐसे में हर फैसले को लेकर खुद को तैयार किया जा रहा है और उसके अनुसार रणनीति तैयार की जा रही है। संघ नहीं चाहता है कि फैसले के बाद किसी भी प्रकार देश का सौहार्द बिगड़े।' बैठक में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। बैठक में अनुषांगिक संगठनों के लिए कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है।

फतवे की तरह मस्जिदों से जारी होगा प्रशासन का संदेश

जागरण संवाददाता, अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट के बहुप्रतीक्षित फैसले को लेकर मुसलमानों ने शांति व्यवस्था के लिए अनोखी पहल की है। जुमा की नमाज के दौरान फतवे की तरह प्रशासन के संदेशों को प्रसारित किया जाएगा। बुधवार को शांति वार्ता के लिए डीएम अनुज झा ने बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने मुसलमानों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग मांगा था। तब बात उठी कि ऐसे मौकों पर अफवाहें फैलाकर अशांति फैलाई जाती है। इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। मौलवियों व अन्य मुस्लिम प्रतिनिधियों ने कहा कि यह जिला अशांति फैलाने वालों का नहीं है। स्थिति तब खराब होती है, जब बाहर से लोग यहां आते हैं। शिया व सुन्नी प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखा कि जनहित संबंधी सूचना को मस्जिदों से फतवे की तरह प्रशासन प्रसारित करा सकता है। अधिकांश मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। इससे फायदा हो सकता है।

संतुलन कायम रखने की जरूरत

प्रथम पृष्ठ से आगे

न्यायपालिका में पारदर्शिता के मुद्दे पर जस्टिस बोबडे का कहना है कि संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। सभी मामलों में एक समान मानदंड नहीं हो सकते। मामले के हिसाब से यह अलग-अलग हो सकता है। यह केस दर केस निर्भर करेगा। वह मानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनौतियां है और वह उनसे निपटेंगे।

मुकदमों के त्वरित निपटारे पर विचार : जस्टिस बोबडे का लोगों को संदेश है कि वे न्यायपालिका में अपना भरोसा बनाए रखें। वह लंबित मुकदमों के त्वरित निपटारे पर कहते हैं कि कमेटी इस पर विचार कर रही है। उसकी सिफारिशें आने के बाद लागू की जाएंगी। वह मानते हैं कि न्यायपालिका पहले से मजबूत है। इसे और मजबूत करने की जरूरत नहीं। बहुत से सुधार हुए हैं और हो रहे हैं।

एनफील्ड बुलेट चलाने के शौकीन हैं भावी सीजेआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जस्टिस एसए बोबडे ने उन्हें अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सूचना सबसे पहले अपनी माता जी को दी और उनसे आशीर्वाद लिया। जस्टिस बोबडे को मोटर साइकिल चलाना अच्छा लगता है और वह एनफील्ड बुलेट चलाते थे। न्यायाधीश के रूप में लंबा सफर तय कर चुके जस्टिस बोबडे तीन पूर्व न्यायाधीशों को अपना रोल मॉडल मानते हैं और जूनियर जज के तौर पर उनके साथ पीठ साझा करने को अपना सौभाग्य समझते हैं। ये तीन न्यायाधीश हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा, जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा और जस्टिस सीके ठक्कर। हालांकि वह मानते हैं कि इनके अलावा और भी बहुत से काबिल न्यायाधीश हुए हैं और हैं। 17 महीने के लिए सीजेआइ नियुक्त होने वाले जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल, 2021 को रिटायर होंगे।

मुस्लिम भी बुलंद करते रहे हैं राममंदिर की आवाज

रघुवरशरण, अयोध्या

मंदिर-मस्जिद विवाद हिंदुओं-मुस्लिमों का विवाद नहीं है। यह सच्चाई उन मुस्लिमों से बयां है, जो लंबे समय से मंदिर के हक में आवाज बुलंद करते रहे हैं। 1857 की क्रांति के दौर में ही हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए मुस्लिमों ने विवादित जमीन हिंदुओं को देने की योजना तैयार की थी। हालांकि ब्रिटिश हुक्मरानों की साजिश के चलते इस योजना पर पानी फिर गया और इस योजना के सूत्रधार मौलवी अमीर अली को बाबा रामशरणदास के साथ फांसी की सजा दे दी गई।

अयोध्या जामा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष मरहूम सैयद असगर अब्बास रिजवी गत दशक के पूर्वार्ध में सौहार्द-संवाद से यह मसला हल करने के लिए आगे आए। रिजवी का मानना था कि जहां रामलला विराजमान हैं, उस स्थल से मुस्लिमों को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। हालांकि वे कामयाब नहीं हो सके और इसके पीछे वे ताकतें निर्णायक थीं, जो इस विवाद को जिंदा रखकर अपनी दुकानदारी चलाए रखना चाहती थीं।

सितंबर 2010 में लखनऊ हाई कोर्ट का निर्णय आने के परिदृश्य में सौहार्द की मुहिम के साथ बाबरी मस्जिद के मुद्दई मरहूम हाशिम अंसारी तक ने रामलला के मंदिर को लेकर चिंता जताई। अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष और हनुमानगढ़ी से जुड़े शीर्ष महंत ज्ञानदास के साथ मिलकर वह यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि रामलला जहां विराजमान हैं, वहां मंदिर बने और मस्जिद अन्यत्र बने। 20 जुलाई 2016 को इंतकाल के वक्त तक हाशिम राम मंदिर के प्रति नरमी के पर्याय बने रहे।

फैसला जो भी आए, अमन कायम रखें : मुस्लिम धर्मगुरु

जुनैद अहमद, लखनऊ

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के साथ भाईचारा कायम करने की मिसाल बन रहे लखनऊ के मौलाना

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरु समेत तमाम मौलाना सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने न केवल कोर्ट का फैसला स्वीकार करने का संदेश दिया है, बल्कि लोगों को भी ऐसा करने को कह रहे हैं।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, वह सभी को कुबूल होगा। फैसला जिनके पक्ष में आए वे खुशी में कोई ऐसा काम न करें, जिससे दूसरे पक्ष का दिल दुखे और न ही जिनके खिलाफ आए, वे विरोध करें। हर इंसान को देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। इसी एकता और भाईचारे को कायम रखने के लिए मस्जिदों से अमन व भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। जुमे की नमाज के खुतबे में भी इसका जिक्र होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि फैसले के बाद किसी तरह का विरोध और नारेबाजी न की जाए। सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी न करें।

> हम लोग शुरू से एकता और भाईचारे के पैरोकार हैं। बेहतर होगा कि अयोध्या का फैसला जल्द आए और इस पर कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को भी इस मुद्दे पर सियासत नहीं करनी चाहिए।
> **– मौलाना कल्बे जवाद, शिया धर्मगुरु**

> हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए, उसका स्वागत करें। सोशल मीडिया समेत सड़कों पर कुछ ऐसी हरकत न करें, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें इस मुल्क के अमन-चैन के बारे में सोचना होगा। अयोध्या में मंदिर बने या मस्जिद, लेकिन किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए।
> **–मौलाना सैफ अब्बास, शिया धर्मगुरु**

> देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला हर हिंदुस्तानी को मानना चाहिए। हम सभी कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। देश की एकता और भाईचारे के लिए हम अमन व शांति का संदेश देते हैं।
> **– इरफान मियां फरंगी महली, शहर काजी**

इस्लामिक स्टेट से जुड़े मामले में तमिलनाडु में एनआइए के छापे

- कोयंबटूर, शिवगंगा समेत पांच जिलों में छह जगहों की ली तलाशी
- दो लैपटॉप, आठ मोबाइल समेत कई सिम कार्ड और अहम दस्तावेज बरामद

जांच एजेंसी ने छह लोगों के खिलाफ दायर किया है आरोप पत्र। प्रतीकात्मक

चेन्नई, प्रेट्र : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने इस्लामिक स्टेट (आइएस) से जुड़े मॉड्यूल के मामले में गुरुवार को तमिलनाडु में कई जगहों पर छापे मारे और तलाशी ली। इस कार्रवाई में कई अहम इलेक्टॉनिक्स गजट और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एनआइए कोयंबटूर में हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की साजिश के मामले की जांच कर रही है।

एजेंसी ने बताया कि कोयंबटूर, शिवगंगा, तिरुचिरापल्ली, नागपट्टिनम और तूतीकोरिन जिलों में छह जगहों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान दो लैपटॉप, आठ मोबाइल फोन, पांच सिमकार्ड, एक एसडी कार्ड और 14 दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एनआइए के प्रवक्ता के मुताबिक इस्लामिक स्टेट से जुड़े कोयंबटूर मामले की जांच के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। जांच एजेंसी ने इस मामले में छह लोगों और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपितों ने इस्लामिक शासन की स्थापना के इरादे से कोयंबटूर में कुछ खास हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या करने की साजिश रची थी। प्रवक्ता ने बताया कि इन आरोपितों को राज्य पुलिस ने पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था और एनआइए ने इस साल फरवरी में इनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। इनके खिलाफ राज्य में दहशत और दंगा फैलाने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। एनआइए के मुताबिक आरोपित श्रीलंका में चर्चों और ईसाइयों पर हमला करने वाले आतंकी गिरोह के सरगना जहरान हाशिम से प्रभावित थे। सोशल मीडिया पर उसके भाषण सुनते और वीडियो देखते थे। गुरुवार को उन लोगों के ठिकानों पर छापे मारे गए, जिनपर आरोपितों के साथ संपर्क में रहने का शक है।

कोयंबटूर में एनआइए ने दो जगहों की तलाशी ली। शहर के जीएम नगर में निसार और लोरीपेट इलाके में सौरीद्दीन नामक संदिग्धों के घर पर पांच सदस्यीय दल ने छापे मारे थे। एजेंसी ने इस्लामिक स्टेट से संपर्क रखने की आशंका में 21 सितंबर को भी राज्य के तिरुनेलवेली जिले में एक व्यक्ति के घर पर छापा मारा था।

खास बातें

- हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की साजिश की जांच कर रही है राष्ट्रीय जांच एजेंसी
- इस मामले में आइएस से जुड़े छह आरोपितों की हुई है गिरफ्तारी
- आरोपितों से संपर्क रखने वालों के घरों की हुई तलाशी

नहीं रहे भाकपा के वयोवृद्ध नेता गुरुदास दासगुप्ता

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताया शोक

गुरुदास दासगुप्ता। फाइल

भाकपा के वयोवृद्ध नेता व पूर्व सांसद गुरुदास दासगुप्ता का गुरुवार को निधन हो गया। 83 वर्षीय नेता ने एक गैरसरकारी अस्पताल में सुबह छह बजे अंतिम सांस ली। वह किडनी और दिल की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे थे। उनको अगस्त माह में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लोकसभा और राज्यसभा मिला कर पांच बार सांसद रहे गुरुदास दासगुप्ता यूपीए शासनकाल में हुए 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए गठित संयुक्त कमेटी के सदस्य रहे थे।

उधर, उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीटर पर शोक संदेश पोस्ट करते हुए लिखा- श्री गुरुदास दासगुप्ता प्रतिवद्ध और मुखर प्रस्तावक थे। संसद में वे हमेशा मुखर रहते थे। उनके विचारों को सभी ध्यान से सुनते और ग्रहण करते थे। उनके निधन से मुझे काफी दुख हुआ है। मैं उनकी आत्म की शांति की कामना करता हूं। वहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शोक जताया। कहा- गुरुदास दासगुप्ता के निधन से दुखी हूं। सांसद और श्रमिक नेता के रूप में उनके योगदान को पूरा देश याद रखेगा।

गुरुदास दासदुप्ता का सफरनामा : तीन नवंबर 1936 को बांग्लादेश (तत्कालीन अभिभाजित हिंदुस्तान) के बरिशाल में जन्मे गुरुदास दासगुप्ता 1985 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे।

2000 तक लगातार राज्यसभा से तीन बार सदस्य बने। इसके बाद 2001 में भाकपा की श्रमिक संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआइटीआइसी) के महासचिव चुने गए। इसके बाद 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में पांशकुड़ा लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद 2009 में घाटाल लोकसभा सीट से दोबारा लोकसभा सदस्य चुने गए। इसी साल लोकसभा में भाकपा दल के नेता भी चुने गए थे।

मोनिका बेदी के फर्जी पासपोर्ट मामले में फैसला सुरक्षित

नईदुनिया, जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम की महिला मित्र रही अभिनेत्री मोनिका बेदी उर्फ फौजिया उस्मान के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। मोनिका के वकील ने पासपोर्ट जब्ती को लेकर सवाल उठाए तो सरकार की ओर से कार्रवाई को उचित बताया गया। जस्टिस वीपीएस चौहान की एकलपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर बाद में सुनाने के निर्देश दिए।

यह अपील राज्य सरकार ने भोपाल की निचली अदालत से मोनिका को बरी किए जाने के खिलाफ दायर की है। प्रकरण के अनुसार फर्जी पासपोर्ट कांड को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहेफिजा थाने में मोनिका बेदी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी। मोनिका पर आरोप था कि उसने खुद को अबु सलेम की पत्नी बताते हुए फौजिया उस्मान के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। 2006 में भोपाल की निचली अदालत ने मोनिका बेदी को बरी कर दिया। सेशन कोर्ट से भी सरकार की अपील 16 जुलाई 2007 को खारिज हो गई। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने यह पुनरीक्षण याचिका हाई कोर्ट में दायर की। 2007 में ही एक अन्य याचिका इसी संबंध में दायर की गई। मप्र हाई कोर्ट ने भी 2008 में स्वतः संज्ञान लेकर एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

परंपरा

ओंकारेश्वर मंदिर में भक्तों ने पुष्प और अक्षत से किया डोली का स्वागत, मंगलवार को बंद हुए थे धाम के कपाट

शीतकाल के लिए ऊखीमठ में विराजमान हुए बाबा केदार

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग

रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की डोली के दर्शन करते श्रद्धालु। जागरण

दो पड़ावों पर रात्रि विश्राम करने के बाद गुरुवार को भगवान केदारनाथ अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गए। अब अगले छह महीने केदार बाबा की नित्य पूजाएं ऊखीमठ में ही संपन्न होंगी। इससे पूर्व, गुप्तकाशी से ऊखीमठ पहुंचने पर सैकड़ों भक्तों ने बाबा की उत्सव डोली का फूल व अक्षत से जोरदार स्वागत किया।

मंगलवार को भैयादूज पर्व पर धाम के कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की उत्सव डोली रात्रि विश्राम के लिए अपने प्रथम पड़ाव रामपुर पहुंची थी। बुधवार को डोली अपने दूसरे पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची। गुरुवार सुबह ठीक आठ बजे धाम के मुख्य पुजारी केदार लिंग ने विशेष पूजा-अर्चना के बाद बाबा की पंचमुखी भोगमूर्ति को भोग लगाया। यहां से जैसे ही डोली अपने अंतिम पड़ाव के लिए रवाना हुई, भक्तों की जयकार और जम्मू-कश्मीर इन्फेंट्री की बैंड धुनों से पूरी केदारघाटी शिवमय हो गई। उत्सव डोली भैंसारी और विद्यापीठ होते हुए 10:45 बजे जैबीरी पहुंची। यहां स्थानीय लोगों ने डोली को अर्घ्य लगाया। जबकि, देवदर्शनी पहुंचने पर भक्तों ने फूल मालाओं से डोली का स्वागत किया। ठीक 11:45 बजे डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ऊखीमठ परिसर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची। यहां मुख्य मंदिर की परिक्रमा करने के बाद डोली को गद्दीस्थल ले जाया गया और फिर धाम के रावल भीमाशंकर लिंग, केदार लिंग और शिवशंकर लिंग की मौजदूगी में बाबा की पंचमुखी भोगमूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया।

ओंकारेश्वर मंदिर का किया गया शुद्धीकरण : बाबा केदार की डोली के ऊखीमठ पहुंचने से पूर्व केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग की देख-रेख ओंकारेश्वर मंदिर का शुद्धीकरण किया गया। दरअसल, ओंकोरश्वर मंदिर में विभिन्न स्थानों पर बीते 31 अगस्त को 19 ताम्रपत्र मिले थे। इनमें मंदिर पर हक-हकूक की बात अंकित थी। इस मामले में कार्रवाई न होने से गुस्साए रावल ने बुधवार शाम चेतावनी दी थी कि बाबा की डोली को मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जाएगा।

इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सभी ताम्रपत्र मंदिर से हटा दिए और एक सप्ताह के भीतर मामले में ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रशासन ने यह भी कहा था कि मंदिर के शुद्धीकरण के बाद ही डोली को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा।

लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दिव्यांग उपकरण घोटाला

जागरण संवाददाता, एटा

दिव्यांग उपकरण वितरण घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी। सलमान खुर्शीद के डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट ने केंद्रीय योजना के तहत 2010 में अलीगंज में दिव्यांग उपकरण वितरण के लिए शिविर लगाया था।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 71.50 लाख रुपये आवंटित किए थे। इसकी जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने की। ट्रस्ट ने 21 लाभार्थियों की सूची सत्यापन रिपोर्ट जांच के साथ एजेंसी को सौंपी थी। सत्यापन रिपोर्ट की जांच में तत्कालीन तहसीलदार और सीएमओ के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए थे। इस पर जांच एजेंसी ने 15 जून 2017 को अलीगंज थाने में ट्रस्ट की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद सहित तीन के खिलाफ एफआइआर दर्ज करा दी। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। जांच एजेंसी की सक्रियता बढ़ते देख लुईस ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका अदालत में प्रस्तुत की।

याचिका पर बुधवार को प्रथम अपर जिला जज अशोक कुमार नवम की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई थी। शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांग उपकरण घोटाला मामले में अदालत ने गुरुवार को अग्रिम जमानत याचिका रद कर दी है।

16 अन्य जिलों में भी दर्ज है घोटाले की रिपोर्ट : ट्रस्ट की तरफ से दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, संत रविदास नगर व इलाहाबाद व दो अन्य जिलों में भी लगाए गए थे। इन सभी जिलों में घोटाला पाया गया और एफआइआर दर्ज कराईं गईं थी।

दैनिक जागरण

शांति के समान कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई धर्म नहीं

जीने के अधिकार पर आघात

दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के साथ उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण का विकराल रूप यही बता रहा है कि उस पर नियंत्रण पाने के दावे थोथे साबित हुए। ये दावे इसलिए थोथे साबित हुए, क्योंकि जिन पर भी वायुमंडल को दूषित होने से बचाने की जिम्मेदारी है उन्होंने कुछ न करना ही बेहतर समझा। यह देखना दयनीय है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें और उनकी तमाम एजेंसियों के साथ एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक प्रदूषण पर लगाम लगाने के जतन करते रहे, लेकिन सब को नाकामी ही मिली। ऐसा लगता है कि प्रदूषण नियंत्रण के मामले में ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने की एक बड़ी वजह यह है कि उसके मूल कारणों को समझने और उनका निवारण करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। ऐसा तब है जब बीते करीब एक दशक से वायु प्रदूषण एक खतरे के रूप में चित्रित हो रहा है। यह शासन व्यवस्था की नाकामी का नमूना ही है कि वायु प्रदूषण की चिंता केवल सर्दियों में ही की जाती है। क्या शेष समय उत्तर भारत का वायुमंडल साफ-सुथरा रहता है? जो भी हो, तमाम कवायद के बाद भी वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर एक तरह से जीने के अधिकार पर आघात ही है।

जब हरियाणा और पंजाब के साथ देश के कुछ अन्य हिस्सों में फसलों के अवशेष जलाए जाने लगते हैं तब इसकी चिंता की जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक इस सवाल की तह तक जाने की दिखावटी कोशिश होती है तब तक फसलों के बचे-खुचे अवशेष भी जलाए जाने लगते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। यह लज्जा की बात है कि हरियाणा और पंजाब की सरकारें एक बार फिर ऐसे प्रबंध नहीं कर सकीं कि किसान पराली न जलाने पाएं। इन दोनों राज्य सरकारों के नाकारापन के सामने केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कुल मिलाकर असहाय ही साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल फसलों के अवशेष जलाने से ही प्रदूषण की समस्या सिर उठाती हो, लेकिन जब उनका धुआं सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और वाहनों के उत्सर्जन से मिलता है तो वह सेहत के लिए जानलेवा स्मॉग में तब्दील हो जाता है। निःसंदेह दीपावली के दौरान पटाखे दागे जाने के कारण भी वायुमंडल खराब होता है, लेकिन केवल उन्हें ही जिम्मेदार ठहराना समस्या का सरलीकरण करना ही है। इस बार कहीं कम पटाखे दगे, लेकिन प्रदूषण का स्तर कहीं अधिक गंभीर हो गया। स्पष्ट है कि समस्या की जड़ में शासन-प्रशासन का निठल्लापन ही है।

बांग्लादेशी कैदियों का मुद्दा

राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर बंगाल में भाजपा नेताओं एवं तृणमूल के बीच जुबानी जंग जारी है। इन सबके बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों में बंगाल में सबसे अधिक विदेशी कैदी होने का दावा किया गया है। इनमें से सर्वाधिक बांग्लादेशी नागरिक हैं। ऐसे में एनसीआरबी की रिपोर्ट से भाजपा नेताओं को राज्य में एनआरसी लागू करने की वकालत करने के लिए एक और ठोस वजह मिल गई है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में बंगाल में एनआरसी, घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टीकरण को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। उसे राज्य की 42 में से 18 सीटें हासिल हुई थीं और अब इन आंकड़ों को भी वह चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। एनसीआरबी के 2017 के आंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों की तुलना में बंगाल में सबसे अधिक विदेशी कैदी हैं। उसके अनुसार 1,379 विदेशी कैदी बंगाल की जेलों में बंद हैं, जो कि देश में बंद कुल विदेशी कैदियों का 61.9 फीसद है। इस माह की शुरुआत में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इसके बाद करीब सात फीसद विदेशी कैदी महाराष्ट्र, 6.8 फीसद उत्तर प्रदेश में बंद हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक बांग्लादेशी विदेशी कैदी बंद हैं। कुल 1,403 बांग्लादेशी भारतीय जेलों में बंद है, जिसमें से 1,284 बंगाल में बंद हैं। एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह देश में भारतीय दंड संहिता और विशेष तथा स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध के आंकड़ों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने का काम करता है। इस बीच इसे चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर रही भाजपा की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि बांग्लादेश से लगातार हो रही अवैध घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न हो रहे खतरे को दर्शाती है। इस आंकड़े से हमारी एनआरसी लागू करने की मांग को ठोस आधार मिलेगा। बांग्लादेश और बंगाल 2,216.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसके बड़े हिस्से में बाड़ नहीं लगा है। वहीं नदियां एवं जंगल भी हैं। इसके अलावा सीमा पर ऐसे स्थान भी हैं जहां दोनों ही ओर गांव हैं। ऐसा मालदा जिले में है। जिसके चलते इन सीमाओं से घुसपैठ एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यह तो 2017 के आंकड़े हैं। 2018 के बाद अब समाप्त होने वाले वर्ष 2019 के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो संख्या और अधिक हो जाएगी। इसीलिए बंगाल सरकार ने अब ऐसे विदेशी खासकर बांग्लादेशी कैदी जिनकी सजा पूरी हो चुकी है और डिपोर्ट नहीं होने की वजह से जेल में ही हैं, उनके लिए सुरक्षित आशियाना बनाने का निर्णय लिया है।

गुलाम कश्मीर की कसक

आर विक्रम सिंह

जम्मू-कश्मीर में नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह जरूरी है कि गुलाम कश्मीर की वापसी के सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठाए जाएं

अवधेश राजपूत

जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही एक देश-एक विधान का वह सपना साकार हुआ जो लंबे अर्से से देखा जा रहा था, लेकिन यह सपना सही तरह से तब पूरा होगा जब गुलाम कश्मीर भी भारत-भूमि का हिस्सा बनेगा। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर प्रत्येक भारतीय के मन की व्यथा को कुरेदा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की कसक उनके मन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात राजौरी में सैनिकों के साथ दीपावली मनाते समय कही। राजौरी के उत्तर में ही पुंछ है। 1947 में हमारी सेनाओं ने पुंछ कस्बे को तो आजाद करा लिया, लेकिन युद्धविराम की जल्दी में पूरे जिले को मुक्त नहीं कराया जा सका। उत्तर दिशा में हाजीपीर दर्रे से होकर जाने वाली सड़क पुंछ को उड़ी से जोड़ती है। पुंछ से उड़ी जाने का जो रास्ता 30 किमी लंबा हुआ करता था वह अब कहीं अधिक लंबा हो गया है। इसका कारण यह है कि हाजीपीर दर्रे के साथ यह रास्ता पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका है। 1947 में यह रास्ता हमारे नियंत्रण में था। दरअसल 161 इन्फैंट्री बिग्रेड की मोर्चेबंदी में अनायास ही ऐसे परिवर्तन किए गए जिनका लाभ उठाकर पाकिस्तानी सेना हाजीपीर दर्जे पर काबिज हो गई थी। यह तत्कालीन ब्रिगेडियर एंडरसन के नाकारापन का परिणाम था जो आगे चलकर लेफ्टिनेंट जनरल बने। इसके कारण एक तो कश्मीर की रक्षा व्यवस्था और नाजुक हो गई और दूसरे, पश्चिमी कश्मीर के पंजाबी, गोजरी भाषी इलाके भी दो भागों में विभाजित हो गए। कुपवाड़ा, उड़ी एक तरफ और राजौरी, पुंछ दूसरी तरफ रह गए। इससे उनकी राजनीतिक शक्ति बनने की संभावनाएं क्षीण पड़ गईं।

हमारे तत्कालीन शासकों ने भागते हुए कबायलियों का पीछा कर रही भारतीय सेना को उड़ी में ही रोक दिया जबकि मुजफ्फराबाद का रास्ता पूरी तरह खुला हुआ था। उड़ी के दक्षिण में सैन्य अभियान चलाकर पाकिस्तानी घेरे को उत्तर की दिशा से तोड़कर पुंछ तक जोड़ा जा सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता कि नेहरू और माउंटबेटन ने इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? जो इलाके अभी गुलाम कश्मीर का हिस्सा हैं उन्हें हमारे तत्कालीन नेतृत्व ने एक तरह से पाकिस्तान को तश्तरी में रखकर परोस दिया। इसके पीछे दो उद्देश्य दिखते हैं। भारत विभाजन के बाद के हालात में गुलाम कश्मीर के दस जिलों के अलावा उत्तर में स्थित गिलगित-बाल्टिस्तान अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया था। यह इलाका चीन-पाकिस्तान-रूस-अफगानिस्तान की सीमाओं से लगा ऐसा क्षेत्र था जिसकी पहाड़ियों से रूस-चीन की गतिविधियों पर निगाह रखी जा सकती थी। भारत की आदर्शवादी नीतियों के चलते इस क्षेत्र का ब्रिटिश-अमेरिकी हितों के लिए उपयोग हो पाना संभव नहीं था। भारतीय ब्रिटिश सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल लॉकहर्ट और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का दायित्व ब्रिटेन के हितों की रक्षा करना भी था। गिलगित एजेंसी ब्रिटिश नियंत्रण में थी। अंग्रेज सरकार उसे आजादी के वक्त भारत को दे सकती थी, लेकिन उसने वह क्षेत्र 30 जुलाई, 1947 को कश्मीर के महाराजा को हस्तगत कर दिया।

महाराजा की सेना के ब्रिटिश मेजर ब्राउन ने एक नवंबर, 1947 को महाराजा के मुस्लिम सैनिकों से विद्रोह कराकर गिलगित पाकिस्तान को सौंप दिया। लेह-लद्दाख तो भारतीय सेनाओं ने अपनी जीवटता से अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन बाल्टिस्तान में हमारी सेनाओं को कोई सहयोग नही मिल सका। कर्नल शेर सिंह थापा सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ महीनों तक स्कर्दू का मोर्चा संभाले रहे। मजबूरी में उन्हें पीछे हटना पड़ा। गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए कोई अभियान न चलाया जाना ब्रिटिश षड्यंत्र की ओर स्पष्ट इशारा करता है। यह भी नजर आता है कि शेख अब्दुल्ला की स्थानीय राजनीति को निष्कंटक बनाने के लिए गुलाम कश्मीर को अस्तित्व में आने दिया गया। गुलाम कश्मीर के इलाके और खासकर नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, भिंबर आदि कश्मीरी नहीं, बल्कि पंजाबी, पहाड़ी और गोजरी भाषी हैं। इन इलाकों पर कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला का जादू नहीं चला, क्योंकि वे अपनी सांस्कृतिक-भाषाई पहचान की दृष्टि से जम्मू के डोगरा-पंजाबी हिंदू राजपूत बिरादरी के ज्यादा निकट थे। यदि संपूर्ण कश्मीर मुक्त करा लिया गया होता तो पंजाबी, पहाड़ी और डोगरा समाज का समीकरण आबादी का सबसे बड़ा वर्ग होने के चलते सत्ता का स्वाभाविक दावेदार हो सकता था। ऐसा होता तो शेख साहब की राजनीति का सूरज सदा के लिए अस्त हो जाता। गुलाम कश्मीर की 45 लाख की आबादी, जम्मू क्षेत्र की 45 लाख की आबादी के साथ मिलकर करीब 90 लाख हो जाती। यदि इनमें भारतीय पश्चिमी कश्मीर के राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा जिले के अलावा उड़ी और बुनियार तहसीलें भी मिला लें तो कुल आबादी एक करोड़ से अधिक हो जाती जो कश्मीर घाटी की 60-70 लाख जनसंख्या से कहीं अधिक होती। चूंकि शेख की सत्ता के लिए कश्मीर का बंटवारा जरूरी था इसलिए हमारे नेतृत्व ने सैन्य अभियान पर उड़ी में ही विराम लगा दिया और इस तरह गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ में बने रहने दिया गया।

अपनी पुस्तक 'द ब्लंडर्स एंड वे आउट' में कश्मीरी नेता भीम सिंह ने लंदन में माउंटबेटन से 1970 में हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया है। उन्होंने माउंटबेटन से पूछा था कि जब सेनाएं जीत रही थीं तब आपने एकतरफा युद्धविराम क्यों स्वीकार कर लिया? इस पर माउंटबेटन का जवाब था, 'युद्धविराम तो भारत और कश्मीर के प्रधानमंत्रियों ने लागू कराया था।' गुलाम कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे में जाते ही शेख अब्दुल्ला का कश्मीर में एकछत्र राज कायम हो गया। हाजीपीर दर्रे और उड़ी-पुंछ मार्ग पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाना शेख अब्दुल्ला की राजनीति के लिए फायदेमंद रहा।

हालांकि 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय सेनाओं ने पहले ही हमले में हाजीपीर दर्रे को कब्जे में लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले मार्ग को खोल दिया था, लेकिन उसकी वापसी ताशकंद वार्ता का एक बड़ा मुद्दा बनी। फिर हमें उसे वापस करने के लिए बाध्य होना पड़ा। कुछ इसी तरह की गलती 1971 के युद्ध के बाद की गई थी। समझना कठिन है कि इस युद्ध के दौरान गुलाम कश्मीर की वापसी सुनिश्चित क्यों नहीं की गई?

उड़ी की सीमावर्ती चौकियों से हाजीपीर दर्रा साफ दिखाई देता है। अपने सैन्य जीवन के दौरान मैं इन चौकियों पर चहलकदमी कर चुका हूं। हम हाजीपीर दर्रे तक पहुंचने के लिए हमेशा बेचैन रहते थे। यह अच्छा है कि अब यही बेचैनी हमारे शीर्ष नेतृत्व में भी दिख रही है। गुलाम कश्मीर की वापसी दिवास्वप्न नहीं रहनी चाहिए।

(लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

बेरोजगारी की समस्या का सामना

सृजन पाल सिंह

तकनीक के इस दौर में आइआइटी के साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे आइटीआइ भी विश्वस्तरीय बनें

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े यह कहते हैं कि भारत में 2018 में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत थी। इसे बीते 45 वर्षों में सबसे अधिक बताया गया। बेरोजगारी दर से मतलब होता है कामकाजी आयु वर्ग में से कितने लोग एक तय समय में रोजगार की तलाश कर रहे थे, पर उन्हें काम नहीं मिल सका। 2018 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 10.8 प्रतिशत शहरी महिलाओं में पाई गई। इसके बाद यह शहरी भारत में पुरुषों में 7.1 प्रतिशत, ग्रामीण पुरुषों में 5.8 प्रतिशत और ग्रामीण महिलाओं में 3.8 प्रतिशत पाई गई। देखा जाए तो ये आंकड़े स्वयं में भ्रामक हैं, क्योंकि भारत में न तो कड़ाई से न्यूनतम मजदूरी दर लागू होती है और न ही काम करने के घंटे पर कोई अंकुश होता है। पूर्णतः बेरोजगार लोगों के अलावा भारत का एक और बड़ा हिस्सा वह भी है जो बहुत कम मजदूरी या फिर अनुबंध पर काम करता है। इसके अलावा वह तबका भी है जो उचित रोजगार के अभाव में कम समय के लिए किसी न किसी व्यावसायिक इकाइयों से जुड़ जाता है। यह भी एक आंशिक बेरोजगारी है जो औपचारिक आंकड़ों में नहीं दिखती। यहां यह भी बताना आवश्यक है कि बेरोजगारी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि कई विकसित देशों की भी समस्या है। फ्रांस में बेरोजगारी दर 8.8 प्रतिशत, इटली में 10.7 प्रतिशत, स्पेन में 18.6 प्रतिशत और अमेरिका में 4.4 प्रतिशत है। हालांकि यह दर चीन में 3.6 प्रतिशत और जापान में 2.6 प्रतिशत है। इसकी एक वजह यह है कि जापान और चीन में युवाओं का प्रतिशत भारत की तुलना में कम है।

वैसे तो बेरोजगारी के कई कारण हैं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि बेरोजगारी की समस्या की जड़ हमारी शिक्षा प्रणाली है, चाहे वह औपचारिक शिक्षा हो या अनौपचारिक। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हर साल सबसे अधिक संख्या में इंजीनियर तैयार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि 82 प्रतिशत भारतीय इंजीनियरों के पास वह मूलभूत कौशल नहीं है जिसकी आज के तकनीकी युग में आवश्यकता है। बेरोजगारी की समस्या में हमारी अर्थव्यवस्था की भी भूमिका है। हमारा आर्थिक विकास मॉडल कुछ महानगरों पर केंद्रित है। देश के चुनिंदा 8-10 महानगरों के अलावा अन्य इलाकों में नौकरियों के बहुत कम अवसर पैदा हो रहे हैं। इसकी वजह से छोटे शहरों से निकलने वाले युवाओं को भी अपनी पहली नौकरी महंगे महानगरों में ढूंढनी पड़ती है। बढ़ती बेरोजगारी का एक बड़ा कारण हमारे गांवों की स्थिति भी है। हमारा कृषि क्षेत्र मंदी के लंबे दौर से गुजर रहा है। 1993 से 2016 तक किसानों की आय में दो प्रतिशत से भी कम की सालाना बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कृषि रोजगार का एक बड़ा जरिया है, लेकिन कृषि क्षेत्र में चल रही निरंतर मंदी के कारण शायद ही कोई युवा उसे करियर के रूप में चुनना चाहेगा। जाहिर है कि निराश युवा किसान भी बेरोजगारी के आंकड़ों में दिखेंगे। बेरोजगारी का एक अन्य कारण तकनीकी बदलाव भी है। पिछले तीन-चार दशकों में तकनीक के क्षेत्र में काफी तेज विकास हुआ है। आज अधिकतर कंपनियां अपने कॉल सेंटरों पर इंसान नहीं, कंप्यूटर का प्रयोग कर रही हैं। टैक्सी बुक करने से लेकर खाना और सामान मंगाने का कार्य एप से हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमेशन या एक रोबोट छह इंसानों का काम अकेले कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक विश्व भर में 80 करोड़ लोगों की नौकरियां रोबोट द्वारा ले ली जाएंगी। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों जैसे कि जर्मनी और अमेरिका में एक तिहाई कर्मचारियों की नौकरी रोबोट के हाथों में चले जाने का अनुमान है। यही प्रवृत्ति भारत और अन्य विकासशील देशों में भी दिखेगी।

आज इस सवाल से दो-चार होने की जरूरत है कि क्या हम बदलती तकनीक के साथ कदम से कदम मिलकर चल पा रहे हैं? ध्यान रहे कि भारत में इलेक्ट्रिक कारों का आगमन हो चुका है। अनुमान है कि 2030 तक भारत में पेट्रोल या डीजल की कारें नहीं बिकेंगी। आने वाले वक्त में स्वचालित कारें आएंगी जिसमें स्टीयरिंग भी नहीं होगा। इसका असर यह होगा कि टैक्सी ड्राइवर का कार्य करने वाले लोगों की नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही कम शिक्षा स्तर वाले लाखों मोटर मैकेनिकों के रोजगार पर भी संकट आ सकता है। जाहिर है कि हमें वक्त के साथ हो रहे बदलाव के ढांचे में खुद को ढालना पड़ेगा। हमें युवाओं के कौशल पर ध्यान देना होगा और रोजगार के नए अवसर भी तलाशने होंगे। सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को कौशल विकास पर केंद्रित करना होगा। इसके साथ ही नए प्रयोग करने पर भी ध्यान देना होगा। देश में लाखों शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन सरकार केवल कुछ अच्छे संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, जिसकी वजह से कौशल विकास का केंद्रीकरण हो गया है। यह आवश्यक है कि आइआइटी का स्थान विश्व में अच्छा हो, मगर यह अति आवश्यक है कि हमारे छोटे शहरों में स्थित आइटीआइ भी विश्व स्तरीय हों।

तकनीकी परिवर्तन के कारण रोजगार में गिरावट का सामना करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने रोबोट टैक्स लगाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि जिस भी उद्योग में एक रोबोट से लोगों की नौकरियां जाएं वहां सरकार एक विशेष कर लगा सकती है। इस कर का उपयोग बेरोजगार हुए व्यक्तियों के कौशल विकास और जीवनयापन के लिए किया जा सकता है। भारत जैसे देश को इस सुझाव पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि रोबोट की चुनौती का सामना करने के लिए युवाओं में रचनात्मक कौशल और संवेदना के स्तर को विकसित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि रोबोट के पास इसका अभाव होता है। बेशक नए आविष्कार तमाम दरवाजे खोल सकते हैं, परंतु रचनात्मकता और मानवीय संवेदना का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम आने वाले युग में अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो हमें रचनात्मकता और संवेदना पर ध्यान देना होगा। हमें इसकी शुरुआत स्कूलों और घरों से करनी होगी और बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा का विकास करना होगा।

(एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

पुरुषार्थी जीवन

सफल एवं सार्थक जीवन के लिए पुरुषार्थ एवं कर्मशीलता जरूरी है। पुरुषार्थ जीवन की अनिवार्य शर्त है। पैरों में गति होती है तो मन में मति होती है। गति और मति से मानव-जीवन सफल और सार्थक होता है। यही कारण है कि हमारे सभी संत और मनीषियों ने जीवन को गतिमान बनाए रखने की प्रेरणा दी है। गति दो प्रकार की होती है-एक निरुद्देश्य, दूसरी सोद्देश्य। निरुद्देश्य गति में मनुष्य को यह पता नहीं होता कि उसे कहां जाना है, जैसे कोल्हू का बैल आंखें बंद किए एक दायरे में घूमता रहता है। वह चलता है, किंतु उसका चलना उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। वास्तव में वह चलकर भी चलता नहीं। उसका यह कार्य कितना उत्पादक माना जाएगा?

सोद्देश्य चलने में व्यक्ति को पता रहता है कि उसे कहां जाना है। उसकी मंजिल होती है। चलने का उद्देश्य होता है। ऐसा आदमी प्रत्येक क्षण का मूल्य जानता है और वह उस क्षण का भरपूर उपयोग करता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य तुलसी आदि ने कभी प्रमाद को पास फटकने नहीं दिया। खूब काम किया और इतना काम किया कि उसे देखकर लोग चकित रह गए। गतिशीलता का एक विशेष महत्व है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उसमें अनेक विकृतियां जमा होती रहती हैं। जिस प्रकार घिरे हुए पानी में कूड़ा-करकट और काई इकट्ठी हो जाती है, सड़ांध आ जाती है, उसी प्रकार निष्क्रिय व्यक्ति का जीवन भांति-भांति की बुराइयों से भर जाता है। नदी की जल-धारा के प्रवाह में बह जाने वाली गंदगी की तरह आदमी का चैतन्ययुक्त मन मैल को निकाल फेंकता है और निर्मल हो जाता है।

जापान में पौधों के विकास को रोक कर उन्हें छोटा कर देते हैं। इससे मोटे-मोटे तनों के पेड़ एक छोटे से गमले में समा जाते हैं। वे बौने हो जाते हैं। यही बात मनुष्य के साथ है। मनुष्य एक विकासशील प्राणी है। उसका विकास रुक जाता है तो वह बौना रह जाता है। जीवन की सार्थकता उसकी सक्रियता में है। उन्हीं उदात्त क्षणों में महान कार्य हुए हैं। स्वस्थ और सक्रिय मन में ही सृजन के बीज जन्म लेते हैं और पनपते हैं।

बेला गर्ग

संकट में रेगिस्तान का जहाज

देवेंद्रराज सुथार

ऊंट बेहद उपयोगी पशु है और यह रेगिस्तानी संस्कृति से भी जुड़ा है। ऊंटों की संख्या में आ रही कमी चिंताजनक है

रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की तादाद में तेजी से गिरावट आ रही है। राजस्थान में ऊंट केवल एक पशु नहीं, बल्कि यहां की परंपरा और संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। ढोला-मारू, पाबूजी, बाबा रामदेव, खिमवाजी और महेंद्र-मूमल जैसे लोकगीत तो ऊंटों को आधार मानकर ही रचे गए हैं। राजस्थानी काव्य और पहेलियों में भी ऊंटों का अहम स्थान देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान की यह शान अब संकट में है। कहने को तो राजस्थान सरकार ने ऊंटों की तेजी से कम होती संख्या को देखते हुए 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया। वहीं हाल ही में एक कानून बनाकर ऊंट को मारने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया, लेकिन इसके बावजूद ऊंटों की संख्या घटने पर है।

20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना नामक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में ऊंटों की संख्या पिछले सात वर्षों में लगभग 35 फीसद कम हुई है। वर्ष 2012 में जहां राजस्थान में 3.26 लाख ऊंट थे, जो वर्ष 2019 में घटकर 2.13 लाख हो गए हैं। वहीं गुजरात में ऊंटों की संख्या 30 हजार से घटकर 28 हजार, उत्तर प्रदेश में 8 हजार से घटकर 2 हजार, हरियाणा में 19 हजार से घटकर 5 हजार हो गई है। बीएसएफ को 1276 ऊंटों की जरूरत है, लेकिन उसके पास केवल 531 ऊंट ही हैं। ऊंट संख्या में विश्व में कभी तीसरे स्थान पर रहने वाला भारत आज नौवें स्थान पर आ गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से स्थापित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार ऊंटों की संख्या में कमी का मुख्य कारण चरागाहों की कमी, प्रजनन की कमी, युवाओं की ऊंट पालन से विमुखता, चारे की अनुपलब्धता और महंगाई भी है। वहीं ऊंटों की घटती संख्या के लिए ऊंटों का अवैध रूप से वध भी जिम्मेदार है। ऊंटों की कम होती संख्या के लिए रूढ़िवादिता भी एक कारण है। ऊंट पालने वाले राइका समाज में ऐसी मान्यता है कि ऊंटनी का दूध बेचना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता के कारण ऊंट के दूध का व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ऊंट के मांस की मांग बढ़ने के कारण इनकी निर्मम हत्या की जाने लगी है। राजस्थान के कई जिलों में बलिदान के रूप में भी ऊंट मारा जा रहा है। कृषि और यातायात साधनों ने ऊंट को हाशिये पर धकेल दिया है।

हालांकि राजस्थान सरकार ने ऊंटों की संख्या को बढ़ाने के लिए ऊंट विकास योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत हर ऊंटनी के प्रसव पर ऊंट पालक को 10 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती है, लेकिन केवल इस योजना से ऊंटों की संख्या में कमी को रोक पाना संभव नहीं है। हमें समझना होगा कि एक पशु के रूप में ऊंट राजस्थान के कई लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इसका दूध कई बीमारियों के उपचार में काम आता है। अतः ऊंटों का बचाव अत्यंत जरूरी है। सरकार को ऊंट को एक डेयरी पशु के रूप में विकसित करते हुए इसके लिए उन्नत चरागाहों के विकास पर भी काम करना चाहिए। ऊंट के प्रजनन में वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल होना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

पटेल के गुणों का अनुसरण जरूरी

केसी त्यागी द्वारा लिखित 'भारत को एक करने वाले सरदार' नामक लेख पढ़ने के बाद यह स्पष्ट है कि भारत के गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस भूमिका का निर्वाह किया वह अद्वितीय है। पटेल की सूझबूझ, योगदान एवं त्याग को याद किए जाने को राजनीतिक दृष्टिकोण से कदापि नहीं देखा जाना चाहिए। उनसे प्रेरणा लेकर उनके जैसा राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने की आज भी उतनी ही आवश्यकता है। आज भी किसानों, मजदूरों व शोषितों के लिए संघर्ष की उतनी ही जरूरत है जितनी सरदार पटेल के समय थी। आज भी पटेल से प्रेरणा ग्रहण करते हुए पद को वैसे ही त्यागने की दरकार है जैसे महात्मा गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री का पद उन्होंने त्याग दिया था। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा पेश किए गए लोभ के पद को वैसे ही ठुकराने का समय है जैसे पटेल ने ठुकराया था और अपनी उच्च शिक्षा को देश के हवाले कर दिया। राष्ट्रीय हितों के लिए आज पटेल जैसे योग्य वकीलों को भारत मां वैसे ही पुकार रही है जैसे स्वाधीनता आंदोलन के समय पुकारी थी। विभाजन के समय पटेल द्वारा मुस्लिमों को हिंदू अतिवादियों से बचाने के लिए जो यत्न किया गया था उस यत्न की भी आज सख्त जरूरत है। स्वयं पं. नेहरू ने पटेल को दूर दृष्टिकोण वाला बड़ा नेता माना है। अपने कर्तव्य का पालन करने की नसीहत देने वाले पटेल के इन गुणों का अनुसरण यदि हम नहीं कर सकते हैं तो उनकी जयंती मनाने का हमें नैतिक अधिकार नहीं है।

डॉ. हरिप्रसाद राय, बालडिह, आजमगढ़

विरोध बुद्धिमानी नहीं

विपक्ष में खास तौर पर कांग्रेस, इस बात पर बेहद गुस्से का इजहार कर रही है कि मोदी ने यूरोपीय सांसदों को जम्मू कश्मीर बुलाकर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण किया है। वे लोग, जिनके नेता 1948 में कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में ले गए, उनके मुंह से ऐसे आरोप शोभा नहीं देते। कांग्रेस को यह भी देखना चाहिए कि ये यूरोपीय सांसद कम से कम भारत का समर्थन तो कर रहे हैं। इसका नुकसान तब होता जब ये भारत के खिलाफ बोलते। पहली बार ये नेतागण विश्व को समझा रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंक द्वारा कश्मीर को भारत से तोड़ने की फिराक में है। यह तो हमारे हित में है। इसके बावजूद इस कदम का विरोध कहां की बुद्धिमानी है?

poonammittal124@gmail.com

सोच बदलने की जरूरत

यह हमारी सोच का दिवालियापन ही है कि हमें स्वस्थ तंदुरुस्त बेटा तो चाहिए पर जो बेटी उस पुत्र को जन्म देगी उसके स्वास्थ्य, लालन-पालन व शिक्षा के प्रति घोर उदासीनता बरती जाती है। हमें यह क्यों समझ नही आता कि अस्वस्थ, बीमार बेटियां क्या स्वस्थ बेटा पैदा कर सकती हैं? कभी नहीं। हमें बेटियों के प्रति अपनी इस पुरानी घटिया सोच को तुरंत तिलांजलि देकर उनके जन्म और उनके लालन पालन को एक उत्सव के रूप में अपनाना होगा तभी हमारी अगली पीढ़ियां बलशाली होंगी ।

सतीश त्यागी काकड़ा, इंदिरापुरम, गाजियाबाद

भ्रामक एक्जिट पोल

महाराष्ट्र और हरियाणा के विधान सभा चुनावों के परिणामों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विभिन्न टी वी चैनलों के एक्जिट पोल सर्वे अविश्वसनीय होते हैं। इन सर्वे में परिणाम तक पक्षपात पूर्ण तरीके से पहुंचा जाता है। कई न्यूज चैनलों ने भाजपा के पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की रिपोर्ट दी थी। इससे न्यूज चैनलों की विश्वसनीयता घटी है। या तो सर्वे करने वाले अनाड़ी हैं या उनकी नीयत में खोट है।

dharmendranath.rastogi@gmail.com

शिक्षित बेरोजगार

देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली की स्थिति बेहद चिंताजनक है। हमारे यहां अभी भी थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, शोध व प्रयोग पर नहीं। जहां थोड़ा बहुत ध्यान दिया भी जाता है वहां उपकरण कई साल पुराने होते हैं। इससे भी बच्चों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ शिक्षा का उद्देश्य नौकरी तो है, लेकिन अधिकतर बच्चे विषय की गहराई में नहीं जाते हैं। यही कारण है कि आज देश के ज्यादातर युवा साक्षर तो हैं, मगर शिक्षित नहीं।

25 प्रतिशत तक कम हुआ दिल्ली में हवा में मौजूद प्रमुख प्रदूषित कारक पीएम 2.5 पार्टिकल का स्तर, वर्ष 2012-14 के मुकाबले वर्ष 2016-18 के दौरान, संबंधित विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार।

आजकल

सावरकर पर दृष्टिकोण बदलने की जरूरत

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

इसे देश और देश के नायकों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि वर्ष 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र के अस्तित्व में आने के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अंग्रेज शासकों की मानसिकता से लिखा गया। इतना ही नहीं, वामपंथी इतिहासकारों ने आक्रांताओं को महिमामंडित किया और भारत के मूल निवासी आर्यों को हमलावर बताया। इस दृष्टि से हमें विनायक दामोदर सावरकर पर न केवल तथ्यपरक दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है, बल्कि समूचे भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की भी दरकार है, ताकि भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण को कायम किया जा सके

देश भर में सावरकर को 'भारत रत्न' देने की मांग के बीच यह बहस तेज हो गई है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को उतना महत्व नहीं दिया गया जिसके वे हकदार हैं। हालांकि सावरकर का एक वीर योद्धा और इतिहास लेखक के रूप में सम्मान इंदिरा गांधी भी करती थीं। मई 1970 में इंदिरा गांधी ने सावरकर पर डाक टिकट जारी करते हुए कहा था, 'हम सावरकर के खिलाफ नहीं हैं। वे जीवन भर जिस हिंदुत्ववादी विचार का समर्थन करते रहे, हम उसके जरूर खिलाफ हैं।'

हमें यह समझना होगा कि वह सावरकर ही थे, जिन्होंने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। सावरकर ने ही लंदन में पहली बार सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन संगठित कर सक्रिय किया। बाल गंगाधर तिलक और श्याम कृष्ण वर्मा ने उन्हें बैरिस्टर की शिक्षा लेने के बहाने 1906 में क्रांतिकारी आंदोलन को हवा देने की दृष्टि से लंदन भेजा था। तिलक उनसे इसलिए प्रभावित थे, क्योंकि सावरकर 1904 में ही 'अभिनव भारत' नाम से एक संगठन अस्तित्व में ले आए थे। लंदन जाने से पहले इसका दायित्व उन्होंने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर को सौंप दिया था।

लंदन में सावरकर ने भारतीय छात्रों को एकत्रित किया और उनमें राष्ट्रवाद का अलख जगाया। 1906 में सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता समर पुस्तक लिखने का संकल्प लिया। 10 मई 1907 को इस संग्राम की लंदन के इंडिया हाउस में 50वीं वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया। इस हेतु सावरकर ने 'फ्री इंडिया सोसायटी' के नेतृत्व में एक भव्य आयोजन की रूपरेखा बनाई। फिरंगी हुकूमत को जब इसकी भनक लगी तो उसने इस आयोजन पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु सावरकर के वाक्चातुर्य के चलते अंग्रेज प्रशासन रोक नहीं पाया। इसी दिन सावरकर ने इसे तार्किक रूप में सैन्य विद्रोह अथवा गदर के रूप में खारिज किया और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का पहला सशस्त्र युद्ध घोषित किया। इस पहली लड़ाई को 'संग्राम' का दर्जा देने वाले वे पहले भारतीय थे।

इसी बीच सावरकर ने मराठी व अंग्रेजी में '1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' शीर्षक से इतिहास-पुस्तक लिखी। भारतीय दृष्टिकोण और ऐतिहासिक सच्चाइयों को तथ्य, साक्ष्य व घटनाओं के साथ किसी भारतीय इतिहास लेखक द्वारा लिखी यह पहली इतिहास-पुस्तक थी। इसी कालखंड में सावरकर और मैडम कामा ने मिलकर 'राष्ट्रीय-ध्वज' बनाया। दरअसल जर्मनी के स्टूटगार्ट में समाजवादियों का वैश्विक सम्मेलन आयोजित था। सावरकर की इच्छा थी कि इसमें कामा द्वारा भारत के ध्वज का ध्वजारोहण किया जाए। सावरकर इस उद्देश्य की पूर्ति में सफल हुए। इस समय तक सावरकर तिलक के बाद सबसे ज्यादा ख्यातिलब्ध क्रांतिकारी हो गए थे। इसी कालखंड में खुदीराम बोस समेत तीन अन्य क्रांतिकारियों को दी गई फांसी से सावरकर बहुत विचलित हुए और उन्होंने इन फांसियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी एडीसी कर्जन वायली से बदला लेने की ठान ली। मदनलाल ढींगरा ने उनकी इस योजना में जान हथेली पर रखकर शिरकत की। सावरकर ने उन्हें रिवॉल्वर हासिल कराई। एक कार्यक्रम में मौका मिलते ही ढींगरा ने कर्जन के मुंह में पांच गालियां उतार दीं और आत्मसमर्पण कर दिया। इस जानलेवा क्रांतिकारी गतिविधि से अंग्रेज हुकूमत की बुनियाद हिल गई। इस घटना के फलस्वरूप समूचे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध माहौल बनने लगा।

इस बीच कुछ अंग्रेज भक्त भारतीयों ने इस घटना की निंदा के लिए लंदन में आगा खां के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की। इसमें आगा खां ने कहा कि 'यह सभा आम सहमति से एक स्वर में मदनलाल ढींगरा के कृत्य की निंदा करती है।' किंतु इसी बीच एक हुंकार गूंजी, 'नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।' यह हुंकार थी वीर सावरकर की। इस समय तक आगा खां सावरकर को पहचानते नहीं थे। तब उन्होंने परिचय देने को कहा। सावरकर बोले, 'जी मेरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं।' अंग्रेजों की धरती पर उन्हीं के विरुद्ध हुंकार भरने वाले वे पहले भारतीय थे।

देश की आजादी के लिए संघर्षरत सावरकर को 24 सितंबर 1910 को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी गई और उन्हें अंडमान-निकोबार की कालापानी जेल भेज दिया गया। यहां की काल-कोठरी में अमानवीय अत्याचार भोगते हुए उन्होंने करीब एक दशक यातनापूर्ण जीवन गुजारा। तत्पश्चात माफीनामा लिखकर उन्होंने जेल से मुक्ति पाई। इस कोठरी पर भी कालजयी साहित्य की वे रोजाना नई पंक्तियां लिखते थे और उन्हें कंठस्थ करने के बाद मिटाकर फिर नई पंक्तियां लिखते थे। यह माफीनामा उन्होंने केवल अपने जीवन की सुरक्षा के लिए ना लिखकर, जेल से बाहर आने का बहाना ढूंढने के लिए लिखा था। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और सावरकर इसमें भागीदारी करके आजादी का रास्ता तलाशने के इच्छुक थे। शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने आठ मई 2021 को 'यंग इंडिया' में लिखा था, 'यदि भारत इसी तरह सोया रहा तो मुझे डर है कि उसके दो निष्ठावान पुत्र विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश हाथ से चले जाएंगे। लंदन में मुझे सावरकर से भेंट करने का सौभाग्य मिला था। वे बहादुर हैं, चतुर हैं और देशभक्त क्रांतिकारी हैं। ब्रिटिश प्रणाली की बुराइयों को उन्होंने बहुत पहले ही ठीक से समझ लिया था।'

याद रहे नजरबंद सुभाषचंद्र बोस को भारत से बाहर जाकर ब्रिटेन के शत्रु देशों से सैनिक सहयोग लेने की सलाह सावरकर ने ही दी थी। बोस का देश से पलायन और फिर आजाद हिंद फौज के सेनापति के रूप में सामने आना भी, ऐसा एक बड़ा कारण था, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया था।

ऐसे समर्थ राष्ट्रभक्त पर तथाकथित वामपंथी क्षमा-पत्र का सहारा लेकर उनके कद को बौना करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जबकि ज्यादातर वामपंथी स्वतंत्रता आंदोलन से ही दूर रहे थे। सावरकर ने वर्ष 1906 से 1910 तक ब्रिटेन में रहकर स्वतंत्रता के लिए जो अलख जगाया और वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर जो किताब लिखी, उनके इस राष्ट्रीय योगदान के लिए ही उन्हें याद किया जाना चाहिए और आज इन कार्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

राजनीति के शिकार स्वतंत्रता सेनानी

राजीव गुप्ता

कोई भी व्यक्ति अपनेआप में पूर्ण नहीं है। कार्यशैली, विचार और व्यवहार के कारण प्रत्येक व्यक्ति के समर्थक और विरोधी दोनों होते हैं। सावरकर के भी समर्थक और विरोधी दोनो हैं। सावरकर समर्थकों का मानना है कि वह सबसे अधिक शिवाजी महाराज से प्रेरित थे, अतः उनकी ही युद्धकला से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ तरह तरह की रणनीति बनाकर उसे कार्यान्वित करते रहते थे, जिस कारण वे अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बने रहते थे। लंदन स्थित इंडिया हाउस से अंग्रेजों के खिलाफ उनकी विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां इसका प्रमाण हैं। सावरकर के जीवन का एक तथ्य यह भी है कि 1857 के महासमर की, जिसे अंग्रेज 'गदर' व 'लूट' बताकर बदनाम करते आ रहे थे, को मुहतोड़ जवाब देने के लिए श्याम कृष्ण वर्मा ने सावरकर की सहायता से 10 मई 1907 को लंदन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर भारत में अंग्रेजों की क्रूरता की पोल खोल दी थी। इस कार्यक्रम का वहां रह रहे भारतीयों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि भारतीय देशभक्त युवक कैंब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में वर्ष 1857 के महासमर की स्वर्ण जयंती का स्टीकर लगाकर गए। लंदन की गलियों में वंदेमातरम गूंजने लगा।

सावरकर के क्रांतिकारी जीवन का एक दूसरा उदाहरण भी मिलता है कि लंदन में मदनलाल ढींगरा के पक्ष में 'टाइम्स' में एक लेख लिखकर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक मदनलाल ढींगरा का केस अदालत में है, उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। सावरकर ने अपने लेखों में मदनलाल ढींगरा को सच्चा देशभक्त और अमर शहीद स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार की उन मंशाओं पर पानी फेर दिया, जिनमें वे मदनलाल ढींगरा को अर्धविक्षिप्त और वहशी सिद्ध करने में जुटे थे। इसी प्रकार सावरकर को विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के उपरांत उन्हें जब 'मोरिया' नामक जहाज से भारत लाया जा रहा था तो रास्ते में ही वह अंग्रेज सिपाहियों की आंखों में धूल झोंकते हुए जहाज से बीच समुद्र में कूद गए और तैरते हुए फ्रांस के तट पर जा पहुंचे, परंतु दुर्भाग्य से अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें फिर से पकड़ लिया और वापस जहाज में लाया गया। वहीं दूसरी तरफ सावरकर विरोधी लोगों का तर्क है कि सावरकर वास्तव में वीर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और अदालत द्वारा महात्मा गांधी की हत्या का अभियुक्त उन्हें भी माना गया था, परंतु साक्ष्य के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था।

किसी भी ऐतिहासिक घटना की विवेचना करने के लिए हमें उस घटना के संदर्भ को जरूर जांचना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि काकोरी कांड को अंजाम देने वाले लोग हमारे लिए क्रांतिकारी हैं तो अंग्रेजों के लिए वे लुटेरे हैं। इसी प्रकार भगत सिंह हर भरतीय के लिए एक महान क्रांतिकारी हैं और भारत का हर बच्चा भगत सिंह जैसा बनने की इच्छा रखता है तो अंग्रेजों की नजर में भगत सिंह एक आतंकवादी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अतीत की हर घटना को जांचने-परखने का अपना अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण होता है। इसके साथ, साथ हमें यह समझना चाहिए कि भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए कभी भी किसी भी क्रांतिकारी के अमूल्य योगदान को तुलनात्मक रूप से नहीं आंकना चाहिए। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाने के लिए खुदीराम बोस जैसे नवयुवक का योगदान भी महात्मा गांधी के योगदान से कम नहीं था। आज हमारे लिए खुदीराम बोस जैसा नवयुवक भी वंदनीय है और महात्मा गांधी भी वंदनीय हैं। हम कह सकते हैं कि भारत को स्वाधीन करवाने में विभिन्न क्रांतिकारियों ने अपने अपने ढंग से आजीवन प्रयत्न किया और यह भी एक तथ्य है कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। परंतु यह देश का दुर्भाग्य है कि इतिहासकारों के पूर्वाग्रह और उनकी भेदभावपूर्ण नीति के चलते इतिहास के पन्नों पर मात्र कुछ क्रांतिकारियों की स्वर्णिम गाथा लिखी गई, जबकि कई गुमनाम क्रांतिकारी उनकी स्वर्णिम गाथा की चमक में कहीं खो गए और उन्हें इतिहास के पन्नों पर वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। सावरकर समेत अनेक गुमनाम क्रांतिकारी भी भारत रत्न प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, परंतु यह निर्णय हमें भारत सरकार पर छोड़ देना चाहिए कि वह किसे भारत रत्न देने का फैसला लेते हैं और किसे नहीं।

खरी-खरी

ओए बगदादी, तू मर नहीं सकता!

पीयूष पांडे

ओए बगदादी, तू हमारे देश के टीवी पत्रकारों को यूं बेरोजगार कर मर नहीं सकता। हमने तुझे अब तक कई बार मारा। जब-जब हमारे पास कोई खबर नहीं हुई, हमने तेरी स्टोरी चलाकर तुझे मौत के घाट उतारा। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति की गवाही सामने है, इसलिए हमें तेरी और हमारे रोजगार की चिंता है।

बगदादी तू सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था। तू हमारे देश की टीवी इंडस्ट्री की टीआरपी का चिराग था रे! ऐसा चिराग, जिसे जितना रगड़ो उतनी टीआरपी आती थी। हमने तेरी कितनी लानत-मलानत की। अपनी खोपड़ी को रचनात्मक ऊंचाइयां देते हुए तेरे बारे में ना जाने क्या-क्या कहानियां गढ़ीं, तेरी मौत की झूठी कथाओं को खूब तोड़ा-मरोड़ा, लेकिन तूने कभी हमारी बात का खंडन नहीं किया। हम अब किसे मारेंगे रे? तेरा मरना टीआरपी के एक स्वर्णिम युग का खत्म हो जाना है। तू कई न्यूज चैनलों का संकट मोचक था।

ओए बगदादी, तुझे नहीं मालूम कि तेरा जाना न्यूज चैनलों के दफ्तर में कैसा शून्य भर गया है। टीआरपी खेंचू कई बाबागणों पर तो स्वयं राहु-केतु विराजमान हैं और वो जेल में चक्की पीस रहे हैं। अपनी मौत की भविष्यवाणी करने वाले आदरणीय कुंजीलाल का भी अभी-अभी निधन हो गया है। ना जाने क्यों उन्होंने भी कभी दोबारा भविष्यवाणी नहीं की? वे दोबारा भविष्यवाणी करते। हम दोबारा लाइव टेलीकास्ट दिखाते। खूब तमाशा होता तो 'पीपली लाइव रिटर्न्स' बनाकर निर्देशक-एक्टर थोड़ा पैसा कूट लेते।

ओए बगदादी, अब बिना ड्राइवर की कार वाली खबरें चलाकर दर्शकों को रोमांचित करने का जमाना नहीं रहा, क्योंकि कार कंपनियों ने ऐसी कारें लांच कर दी हैं। बेचारे टीवी वाले मंगल पर पहुंचा यान भी कब तक दिखाएं! बीच-बीच में डब्बू अंकल के शानदार नृत्य वाले वीडियो अवश्य आते हैं, लेकिन ये सब क्षणभंगुर हैं रे! तेरे मरने की खबर शाश्वत थी। हाल यह था कि एंकर बदलकर साल भर पुराना प्रोग्राम भी हमारे टीवी वालों ने कई बार चला दिया, लेकिन दर्शक पांच बार तेरी मौत देखने के बाद छठी बार भी पर्याप्त चौंके थे रे!

ओए बगदादी, तेरे मरने में दहशत, रोमांच, खुशी...सब कुछ था रे! अब तू सचमुच मर गया है तो चैनलों द्वारा लिए गए उत्तेजना के ठेके का क्या होगा? अब अगला बगदादी पैदा होने तक दाऊद, हाफिज से ही काम चलाना पड़ेगा रे!

ट्वीट-ट्वीट

आखिरकार भारत का पूर्ण संवैधानिक एकीकरण संपन्न हुआ। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश-एक निशान और एक संविधान वाली व्यवस्था सुनिश्चित हुई। इसे संभव बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार।
अभिनव प्रकाश@Abhina_Prakash

दिल्ली में 15 वर्ष हो गए और अब यहां से जाने का मन हो रहा है। पिछले तीन साल से यही सुन रहा हूं कि प्रदूषण से निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, मगर हालात जस के तस बने हुए हैं। दुनिया के किसी दूसरे शहर में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक होता तो वहां जनजीवन ठप हो गया होता।
अमन शर्मा@AmanKayamHai_ET

एक अध्ययन में सामने आया है कि भारतीयों के मस्तिष्क का आकार कुछ देशों खासकर पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले छोटा होता है। यानी हमारे लिए वक्त आ गया है कि हम उस कहावत को चरितार्थ करके दिखाएं कि-आकार बिल्कुल मायने नहीं रखता।
आनंद महिंद्रा@anandmahindra

पर्यावरण अनुकूल दिल्ली की दिशा में एक प्रयास

शाहान सूद
स्वतंत्र टिप्पणीकार

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का प्रयास निरंतर जारी है। दुनिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से सात भारत में ही हैं, जहां हम यह देख रहे हैं कि यातायात-जनित प्रदूषण का दुष्प्रभाव दिनों-दिन कितना बढ़ता जा रहा है, और राजधानी दिल्ली तो दुनिया में छठे सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है जिससे यहां स्वास्थ्य जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है।

हालांकि कई अध्ययनों में यह दर्शाया गया है कि वर्ष 2012-14 के मुकाबले वर्ष 2016-18 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु में प्रमुख प्रदूषित कारक पीएम 2.5 पार्टिकल का स्तर 25 प्रतिशत तक कम हुआ है, लेकिन महज इतने सुधार से काम नहीं चलने वाला है और इसे मौजूदा स्तर से 65 प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर देश भर में वायु की औसत गुणवत्ता के समान लाया जा सके।

ऑड-इवेन यानी सम-विषम योजना को इसी कवायद के तहत तीसरी बार फिर से आगामी चार नवंबर से लागू करने की तैयारी चल रही है, जो इसके समाधान की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है। हालांकि विगत वर्षों दिल्ली में जब दूसरे चरण में सम-विषय योजना को लागू किया गया था, उसके बाद सीपीसीबी और डीपीसीसी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर की समीक्षा की थी तो उसमें यह पाया गया कि इसे समुचित तरीके से नहीं लागू करने या फिर आधी-अधूरी तैयारी के साथ लागू करने के कारण इस समयावधि के दौरान न केवल प्रदूषण के स्तर में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, बल्कि यह निष्प्रभावी भी रहा। चूंकि इस योजना को पूरी तरह से प्रभावी नहीं बनाया गया और बहुत तरह के वाहनों चालकों को इस नियम से छूट दी गई, लिहाजा यह अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री द्वारा महज राजनीतिक रूप से नफा-नुकसान के आधार पर इस संबंध में निर्णय लेने से इसके असल लक्ष्य को हासिल करना सुनिश्चित किया जा सकता है?

प्रतीकात्मक

यदि हम इसे सतह पर जाकर देखें, और इस सम-विषम योजना के तहत ठोस फार्मूले के आधार पर आगे बढ़ा जाए तो इसके लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने पहली बार चार दिसंबर 2015 को इस स्कीम को लागू किया था, और पांच दिसंबर 2015 से 10 जनवरी 2016 के बीच दिल्ली में चार पहिया वाहनों की बिक्री इसी अवधि में इसके पिछले वर्ष के 7,679 के मुकाबले बढ़कर 8,298 तक पहुंच गई। इससे पिछले चार वर्षों के दौरान भी चार पहिया वाहनों की औसत बिक्री दर कमोबेश इतनी ही रही थी, जबकि इस समयावधि के दौरान ऑटो सेक्टर में सुस्ती का दौर देखा जा रहा था। यह इस बात को रेखांकित करता है कि सम-विषम योजना के कारण अधिकांश लोगों ने अपने उपयोग के लिए एक अतिरिक्त वाहन भी खरीदा ताकि उनके पास सप्ताह के सभी दिनों के लिए इस्तेमाल में लायक एक निजी वाहन उपलब्ध हो सके।

सड़कों पर नियंत्रित तादाद में वाहनों को उतारने की इस योजना को कार्यान्वित करने के बारे में बीते दिनों कुछ अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से भी सीखा गया है और तीसरे चरण में लागू होने वाली सम-विषय योजना में इसका उपयोग किया जाएगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सम-विषम योजना के साथ-साथ इस बार अन्य कई उपाय भी अमल में लाए जाएंगे जिसमें एन-95 एंटी-पॉलूशन मास्क बांटने समेत पौधरोपण पर जोर देना और सड़कों पर पानी का छिड़काव करने जैसे उपाय इस दिशा में 'अल्प प्रभावी' कहे जा सकते हैं, क्योंकि समस्या का प्रभावी समाधान करने के लिए यह नजरिया समुचित नहीं प्रतीत हो रहा है।

मौजूदा समय राजनीतिक बयानबाजी में फंसने का नहीं है। तात्कालिक उपायों के जरिये इस समस्या का समाधान तलाशने का मतलब यह होगा कि हम राजधानी को स्वच्छ वायु में सांस लेने युक्त शहरों में शामिल करने में देरी करेंगे। इससे दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने का प्रयास भी कामयाब नहीं हो पाएगा।

वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हमारे सतत प्रयास को सुनिश्चित करने का समय इस वर्ष आखिरी दौर में है। ऐसे में हमें सम-विषम योजना के साथ परिवहन नीतियों को प्रभावी तौर पर लागू करना होगा और लोगों को सस्ता व सुगम सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हो सके इसे सुनिश्चित करना होगा, ताकि आगामी पांच वर्षों में दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। इसके लिए धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया जाना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन का ढांचा अधिक से अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों पर उतारने पर रणनीतिक रूप से जोर दिया जा सकता है। इसके लिए दिल्ली सरकार एक नीति का प्रारूप भी तैयार कर रही है जिसे लागू करने से राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिल सकती है।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या आप मुकेश अंबानी से सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती अस्थाई है?

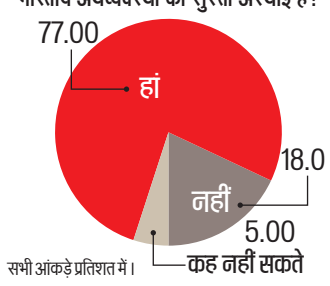

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या देश में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

शिवसेना जैसे मिलें राजनीति में मित्र,
तो विपक्ष का काम क्या स्थिति रहे विचित्र।
स्थिति रहे विचित्र चले फिर कैसे सत्ता,
सत्ता के दो पक्ष करें जब गुत्थमगुत्था।
सीटें आधी पाय चाहती पूरा लेना,
बैठे नहीं गंवाय कहीं सबकुछ शिवसेना!
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

हृदय रोग उपचार की रणनीति पर हो विचार

डॉ. विवेक कुमार
चिकित्सा विशेषज्ञ

देश में हृदय रोग का जोखिम निरंतर बढ़ता जा रहा है लिहाजा इसके उपचार के एक प्रमुख फैक्टर स्टेंट की आवश्यकता बढ़ रही है। ऐसे में इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि हमें किस तरह के स्टेंट पर जोर देना चाहिए ताकि वह अधिक कारगर हो

भारत में पिछले कुछ वर्षों में हृदय से जुड़े स्टेंट के बाजार में व्यापक वृद्धि हुई है। लगभग 6.15 करोड़ भारतीयों के हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त होने के साथ हम जल्द ही वैश्विक तौर पर इस बीमारी से ग्रस्त सर्वाधिक संख्या वाला देश बन जाएंगे। मेडिकल उपकरणों से जुड़ी अपनी 80 फीसद जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहने वाले भारत जैसे बाजार के लिए सरकार हृदय में लगने वाले स्टेंट के देशी संस्करण को प्रोत्साहित कर रही है। जब भारत ने 'मेक इन इंडिया' का बिगुल बजाया, तब इसने घरेलू मेडिकल उद्योग को आबादी की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पाद निर्मित करने को जरूरी प्रोत्साहन दिया।

यह वास्तव में एक प्रशंसनीय प्रयास है, लेकिन इसके बावजूद यह सुनिश्चित करने की अत्यधिक जरूरत है कि खासकर जीवन रक्षक उपकरणों और सुरक्षा से संबंधित मामलों और अध्ययन के मामलों में हमारे पास सशक्त बुनियादी ढांचा, गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मानक व्यवस्थित ढंग से मौजूद हों।

हालांकि घरेलू विनिर्माताओं का किसी उद्योग में अपनी पहचान बनाना उत्साहवर्धक है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल कागजी नीतियों से कुछ नहीं होता, किसी मेडिकल उपकरण के लिए सबसे जरूरी है उसकी गुणवत्ता और क्षमता। एक स्टेंट के निर्माण में उपयोग में लाए गए विज्ञान, अनुसंधान और तकनीक जैसे कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि हृदय में लगने वाले स्टेंट जैसे मेडिकल उपकरण के मामले में क्या उसके उत्पादन का स्थान ही एकमात्र विचारणीय विषय हो सकता है।

इस बारे में हमें विचार करना होगा कि ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों और आंकड़ों के अभाव में हम लाखों लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि हमारे स्टेंट कहां से आए हैं, बल्कि यह होना चाहिए कि उपचार के नजरिये से वे किस स्तर के हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उन उत्पादों को अपनाएं, जो स्वयं किए जा रहे दावों के समर्थन में एक सशक्त नैदानिक जांच के नतीजों को पेश कर सकें। किसी प्रकार के पक्षपात और गलत जानकारी से बचने के लिए और स्टेंट के कामयाब होने की दर के निर्धारण के लिए यह जरूरी है कि एक नियंत्रित माहौल में पर्याप्त संख्या में रोगियों पर जांच की गई हो।

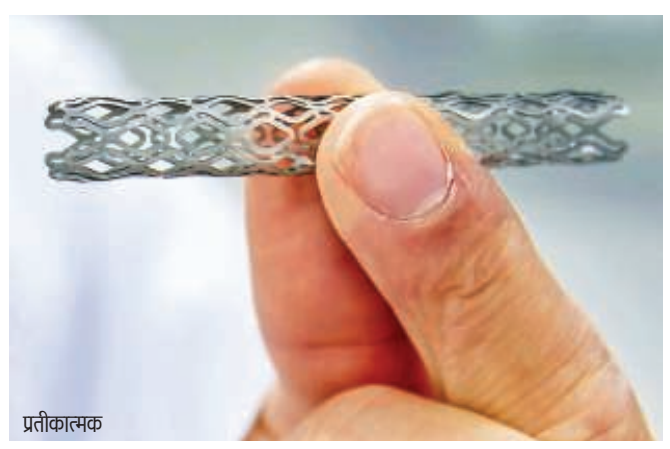
प्रतीकात्मक

इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। घरेलू स्तर पर निर्मित होने वाले स्टेंट के पक्ष में गर्माती बहस के साथ हम एसएमटी के सूप्राफ्लेक्स जैसे उदाहरण देखते हैं जो जाइंस के समतुल्य होने का दावा करती है। सूप्राफ्लेक्स का परीक्षण सात यूरोपीय देशों के 23 केंद्रों के केवल 1,435 रोगियों पर किया गया। सूप्राफ्लेक्स के लिए कराए गए एक परीक्षण में डीईएस सूप्राफ्लेक्स को गोल्ड स्टैंडर्ड वाली डीईएस जाइंस की तुलना में परखा गया और इस नतीजे पर पहुंचा गया कि एक वर्ष के भीतर स्टेंट में आने वाली किसी भी खामी के संदर्भ में दोनों ही समान हैं। जबकि जाइंस के पास पूरी दुनिया में एक करोड़ से ज्यादा रोगियों के उपचार के आंकड़े व क्षमता के मामले में दस वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। हालांकि यूरोपीय एसोसिएशन ऑफ परक्यूटेनस कार्डियोवैस्कुलर इंटरवेन्शंस यूरो पीसीआर 2019 में प्रदर्शित नैदानिक अपडेट में बताया गया कि सूप्राफ्लेक्स, जाइंस से कमतर नहीं है, लेकिन जाइंस की तुलना में इसमें होने वाली मौतों की संख्या ज्यादा है और डिवाइस की कामयाबी की दर कम है।

प्रतिष्ठित जर्नल कैथ सीवीआइ में प्रकाशित एक अन्य उदाहरण में 701 रोगियों ने शोध के निष्कर्षों को महत्वपूर्ण माना जिसमें साफ तौर पर यूकोन च्वॉइस के साथ हृदय से जुड़े गंभीर मामलों की दर ऑफ लेबल उपयोग (दिए गए निर्देशों का पालन न करते हुए) के मामले में महत्वपूर्ण ढंग से ज्यादा थी।

इसके अलावा यूकोन च्वॉइस पीसी या फिर अन्य उपलब्ध उत्पादों को भारतीय रोगियों पर नहीं परखा गया था, इसलिए भारतीय रोगी समूह के संदर्भ में सुरक्षा और क्षमता को साबित करने का कोई डाटा उनके पास नहीं है। स्टेंट का उनके निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए और निर्देशों से परे उनके उपयोग से बचना चाहिए।

इस संबंध में स्वयं से पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नैदानिक प्रमाणों के मामले में केवल स्टेंट के निर्माण होने की जगह की तुलना में क्या हमें गुणवत्ता और बेहतर संसाधनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।

जिन रोगियों ने बेहतर गुणवत्ता वाले स्टेंट के प्रति भरोसा जताया है, उन्होंने कभी हृदय की धमनियों के संकरा होने या रक्तस्राव जैसी जटिलताओं की शिकायत नहीं की है। इन-स्टेंट थ्रांबोसिस के उच्च खतरे वाले रोगियों के लिए जाइंस जैसे प्रमाणित स्टेंट विभिन्न परीक्षणों में ज्यादा सुरक्षित पाए गए हैं।

मेडिकल के क्षेत्र में हुए इनोवेशन ने ऐसे स्टेंट के साथ मुमकिन बनाया है जो रोगियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए न केवल प्रोफाइल व प्रदर्शन के मामले में बेहतर हैं, बल्कि साक्ष्य-आधारित नतीजों द्वारा भी समर्थित हैं।

कोरोनरी शिरा रोग की बढ़ती जटिलताओं से निपटने के लिए भारत को नवाचारों में निवेश करना चाहिए। हमारे रोगियों में जो भी डिवाइस उपयोग में लाई जाए, भले ही वह स्थानीय तौर पर निर्मित हो या फिर दुनिया में कहीं और, सुरक्षा व दीर्घ अवधि के लिए बेहतर नतीजों का आंकड़ा उसके साथ होना चाहिए। और ऐसा होने की दशा में ही हम देश भर में तमाम हृदय रोग से पीड़ितों के लिए मुकम्मल इलाज का इंतजाम कर पाएंगे।

233 वन्य जीव हैं नैनीताल के गोविंद बल्लभ पंत उच्चस्थलीय प्राणी उद्यान में। यहां पर सर्दियों को देखते हुए चिड़ियाघर के मेन्यू में बदलाव किया गया है। भारत में कुल 164 चिड़ियाघर हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 1 नवंबर 2019

युवाओं को रोजगार दे रही मुरादाबादी बिरयानी

इसी तरह बड़े-बड़े शहरों में भी जगह-जगह मुरादाबादी बिरयानी बिक रही है। जागरण

मुस्लेमीन, रामपुर

- अब सिर्फ मुरादाबाद तक सीमित नहीं रही मुरादाबादी बिरयानी
- दिल्ली, मुंबई सहित देश के अनेक शहरों में पहुंचे क्षेत्रीय युवाओं ने बनाया रोजगार का जरिया

बिरयानी का नाम सुनते ही नॉनवेज के शौकीनों के मुंह में पानी आ जाता है। वैसे तो बिरयानी कई तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मुरादाबादी बिरयानी की अपनी पहचान है। यह अब सिर्फ मुरादाबाद तक सीमित नहीं रह गई है। जिले के कई युवाओं ने मुरादाबादी बिरयानी को रोजगार का साधन बना लिया है।

दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, चंडीगढ़, पटना व अजमेर... अनेक शहरों में मुरादाबादी बिरयानी खूब बिक रही है। बड़े-बड़े शहरों में जगह-जगह मुरादाबादी बिरयानी के सेंटर खुले हैं। रामपुर (उप्र) के हजारों युवाओं ने मुरादाबादी बिरयानी को रोजगार का साधन बना लिया है। खासकर टांडा नगर, डौंकपुरी टांडा, खेड़ा टांडा, नगलिया आकिल, टांडा बादली के करीब पांच हजार युवा देश के कोने-कोने में बिरयानी बना रहे हैं। इनमें किसी ने दुकान में होटल खोल रखा है तो कोई ठेले पर ही बिरयानी बेच रहा है।

जनसंख्या नियोजन

इनकी मानें तो इस काम में मुनाफा भी खूब है, जबकि लागत कम है। इस कारोबार से रोजाना दो से पांच हजार रुपये तक कमा लेते हैं। नवाबों के शहर रामपुर में मुरादाबादी चिकन बिरयानी के करीब तीन दर्जन सेंटर हैं। युवाओं ने सड़क किनारे की दुकानों में होटल बना रखे हैं। रेलवे स्टेशन के सामने हाईवे पर और शहर की खास सड़कों पर जगह-जगह बिरयानी सेंटर नजर आते हैं।

नगलिया आकिल के प्रधान सरफराज कहते हैं कि उनके गांव में 10 हजार वोटर हैं और करीब एक हजार युवा दूसरे शहरों में बिरयानी बेच रहे हैं। यहीं के इब्राहिम अपने गांव में ही राइस मिल चला रहे हैं, जबकि उनके तीन बेटे आसिफ, आरिफ और मुन्ना पंजाब के मोहाली में बिरयानी बेच रहे हैं। आसिफ बताते हैं कि तीनों भाई साथ मिलकर होटल चला रहे हैं। दो किला चावल की बिरयानी पककर 10 किलो बन जाती है, जिसे 180 रुपये किलो बेचते हैं। एक पतीले में करीब एक हजार रुपये बच जाते हैं। जहां ज्यादा डिमांड है, वहां रोज 50 किलो चावल की बिरयानी भी बिक जाती है। डौंकपुरी और खेड़ा टांडा की आबादी करीब 20 हजार है और इसके एक-एक परिवार से चार-चार युवा दूसरे शहरों में बिरयानी बेचने का काम कर रहे हैं। गांव के प्रधान मौलाना फारूख बताते हैं कि उनके गांव के हजार से ज्यादा युवा दूसरे शहरों में बिरयानी बेच रहे हैं। इससे युवाओं को रोजगार भी मिला है और उनकी माली हालत भी काफी सुधरी है।

कम तेल, स्वाद उम्दा... : बिरयानी की खास वैरायटीज की बात होती है तो इसमें मुरादाबादी चिकन बिरयानी का भी नाम आता है। लखनवी बिरयानी का फ्लेवर लिए मुरादाबादी बिरयानी उतनी ही लजीज है, जितनी नवाबों के शहर लखनऊ की बिरयानी। रामपुर के मशहूर बाबर्ची बाबू भाई बताते हैं कि बासमती चावल, चिकन, नींबू, हरी मिर्च, प्याज, अदरक और मसालों जैसे हींग, इलायची, लौंग, जीरा, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर से तैयार इस बिरयानी की सुगंध दूर से ही आने लगती है। खास बात यह है कि इसमें कम से कम तेल का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से बिरयानी का अलग ही स्वाद आता है। हैदराबादी और लखनवी बिरयानी में तेल और मसाले ज्यादा पड़ते हैं। सेहत के लिए मुरादाबादी बिरयानी उनके मुकाबले बेहतर है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

फूलों के खेतों में लिविंग कॉटेज से लेकर स्वीमिंग पूल तक

जागरण विशेष ▶ 'पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ गन्ना की खेती' के मिथक को तोड़ रहा यह प्रगतिशील किसान

विनय विश्वकर्मा, मेरठ

'पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ गन्ना की खेती' के मिथक को प्रगतिशील किसान ने तोड़ दिया। फल-फूल और सब्जियों की खेती के अलावा खेतों में ही सुंदर नेचर पार्क भी बनाया, जिसमें पर्यटकों की भीड़ जुटती है।

रजपुरा ब्लाकक्षेत्र के गांव कुनकुरा निवासी किसान प्रद्युम्न चौधरी कहते हैं, खेती के मायने अब सिर्फ शारीरिक श्रम से नहीं, बल्कि यह पेशा तकनीक और दिमाग की जुगलबंदी का है। मैंने इस सूत्र को समझा, परखा और अपनाया भी। गन्ना का रकबा घटाया और फल-फूल व सब्जियों की खेती पर फोकस किया। मेहनत रंग लाई और शुगर बाउल में लिलियम, जरबेरा खिलखिला उठे।

देसी-विदेशी सजावटी फूलों की खेती करके उन्होंने इस इलाके में खेती का कारगर विकल्प दिया। यही नहीं, कृषि भूमि से अतिरिक्त कमाई कैसे हो सकती है, यह भी प्रद्युम्न ने कर दिखाया। मेरठ, उप्र में एनएच-119 से 3.5 किमी. दूर अपनी 100 बीघा कृषि भूमि में प्रद्युम्न ने नेचर पार्क भी विकसित किया है। यहां पॉली हाउस में फूलों की खेती के साथ बागवानी भी हो रही है। लीची की बुआई हो चुकी है। कुछ जैविक सब्जियां तैयार हो रही हैं। इसी परिसर में स्वीमिंग पूल, लिविंग कॉटेज, योग केंद्र, खेल का मैदान, लिविंग एरिया, एडवेंचर झूले और गोशाला भी हैं। प्रद्युम्न कहते हैं, उनका प्रयास लोगों को ग्राम्य जीवन के नजदीक लाना और खेती की इस शैली को समझाना है। लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं और इसे महसूस करने यहां चले आते हैं। फार्म में लोगों के लिए चूल्हे की रोटी, हांडी की दाल, देशी गाय का दूध, घी, लस्सी सहित अनेक देसी व्यंजन निर्धारित दरों पर उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेत में बना पॉली हाउस। जागरण

अपने पॉली हाउस में फूलों की खेती दिखाते प्रद्युम्न चौधरी। जागरण

जिला उद्यान अधिकारी आरएस राठौर कहते हैं, गन्ने की अपेक्षा सब्जियों व फूलों से सालभर में दस गुना अधिक उत्पादन ले रहे प्रद्युम्न चौधरी क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल हैं। वहीं, सहायक निदेशक कृषि प्रबोध कुमार का कहना है कि प्रद्युम्न का प्रयास कृषि विविधीकरण, आय व उत्पादन बढ़ाने के साथ ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देते दिखता है, जो अनुकरणीय है।

मुनाफे का सौदा... : प्रद्युम्न ने बताया कि वह अक्टूबर माह में लिलियम फूल की पौध लगाते हैं। लिलियम नीदरलैंड्स से मंगाया जाता है। एक एकड़ में करीब 12 लाख रुपये लागत आती है। चार माह में 25-30 लाख रुपये का उत्पादन होता है। वहीं, जरबेरा का पौधा पांच साल तक फूल देता है। एक एकड़ में शुरुआती लागत (सब्सिडी के अलावा) 15 लाख रुपये आती है जबकि प्रति एकड़ प्रतिवर्ष आठ-दस लाख रुपये आमदनी होती है। जरबेरा और लिलियम मेरठ मंडी और दिल्ली की गाजीपुर मंडी में जाते हैं। यहां से ये सजावटी फूल दिल्ली के अनेक पांच सितारा होटलों के अलावा विदेशी होटलों में भी पहुंचते हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

'वायरलेस' के लिए चोरी करती रही सरकार, मरते रहे बाघ

मध्य प्रदेश का मामला ▶ बीते 10 साल में 170 बाघों की मौत के पीछे बड़ी वजह बनी यह लापरवाही

जागरण पड़ताल

36 करोड़ शुल्क न चुकाने के कारण दूरसंचार विभाग ने रोक दी थी वायरलेस फ्रीक्वेंसी

मनोज तिवारी, भोपाल

मध्य प्रदेश के वन विभाग और केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के बीच चल रहा वायरलेस फ्रीक्वेंसी विवाद दस साल बाद सुलझ गया है, लेकिन विभाग को पुरानी देनदारी, जो 36 से बढ़कर 70 करोड़ रुपये हो गई, देनी ही पड़ेगी। दूरसंचार मंत्रालय ने इसी शर्त के साथ नया लाइसेंस दिया है। उधर, इतने सालों तक वन विभाग चोरी की फ्रीक्वेंसी से संरक्षित क्षेत्रों (टाइगर रिजर्व, अभयारण्य) में बाघों सहित अन्य वन्यप्राणियों की हिफाजत करता रहा। जबकि सामान्य वनमंडलों में हाल और भी बदतर था।

इन क्षेत्रों में वायरलेस का इस्तेमाल नहीं हो सका। हालांकि दावा तो यह भी है कि फ्रीक्वेंसी बंद हो जाने के बाद मप्र वन विभाग ने वायरलेस का विकल्प पीडीए मोबाइल को बनाया। प्रदेशभर में मैदानी कर्मचारियों को मोबाइल दिए गए। लेकिन ये कारगर साबित नहीं हुए क्योंकि घने वन क्षेत्रों में किसी भी सेल्युलर कंपनी का नेटवर्क नहीं था। लिहाजा, यह व्यवस्था भी जल्द ही हाशिए पर आ गई थी।

साफ है कि बीते दस सालों तक मप्र वन विभाग का समूचा सुरक्षा व सूचना तंत्र बुरी तरह प्रभावित था और लगभग ठप था। इस बीच यहां 170 बाघों की मौत हुई, जिनमें से 41 शिकार के चलते मारे गए। लेकिन जिम्मेदार विभाग इन मौतों के लिए इस विवाद को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि दूरसंचार मंत्रालय से चोरी-छिपे वह संरक्षित क्षेत्रों में वायरलेस की मदद से बाघों की हिफाजत करता रहा।

दरअसल, वन्यप्राणियों और जंगलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने वर्ष 1991 में दूरसंचार मंत्रालय से वायरलेस फ्रीक्वेंसी का लाइसेंस लिया था, लेकिन शुल्क नहीं चुकाया गया। वन विभाग के अफसरों का कहना था कि जंगल और वन्यप्राणियों की हिफाजत भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है, इसलिए दूरसंचार विभाग द्वारा शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन दूरसंचार मंत्रालय का कहना था कि मप्र वन विभाग उपभोक्ता है, लिहाजा शुल्क देना होगा। इस विवाद के बीच वर्ष 2006 तक दूरसंचार विभाग फ्रीक्वेंसी देता रहा, लेकिन तब तक ब्याज समेत इसका शुल्क 36 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। 2006 में फ्रीक्वेंसी का लाइसेंस रद कर दिया गया। 2006 से लेकर अब तक मप्र वन विभाग का सुरक्षा-सूचना तंत्र बुरी तरह प्रभावित रहा है। इधर, बकाया भी बढ़कर 70 करोड़ रुपये हो गया।

बंगाल टाइगर का प्रतीकात्मक चित्र (फाइल फोटो)।

- फ्रीक्वेंसी की चोरी कर और जुगाड़ पर चल रहा था समूचे बाघ संरक्षित वन्यक्षेत्र का सुरक्षा तंत्र, सामान्य वनमंडल था भगवान भरोसे
- मप्र में बीते 7 साल में 31 बाघों का हुआ शिकार, 142 में से सिर्फ 80 मौतें सामान्य

मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक... : जिम्मेदारों ने बताया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए वनमंत्री और मुख्यमंत्री स्तर से प्रयास किए गए, लेकिन शुल्क माफ नहीं हुआ। इस दौरान इस मामले में तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों जयराम रमेश, प्रकाश जावड़ेकर और स्व. अनिल माधव दवे ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो बार और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यभार संभालते ही दूरसंचार मंत्री को पत्र लिखकर विवाद सुलझाने को कहा था।

मामले में एक बार प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा गया। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य के वन मंत्रियों की हर मीटिंग में वायरलेस फ्रीक्वेंसी मुद्दा बना रहा। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मप्र के अफसरों और दूरसंचार मंत्रालय के अफसरों के बीच सालों तक बैठकों का दौर चला, लेकिन कुछ हुआ नहीं।

शुक्र है, टाइगर जिंदा है...

देशभर में मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों का शिकार हो रहा है। यहां बीते 7 साल में 31 बाघों को शिकार कर मार दिया गया। बाघों की मौत के मामले में भी राज्य अव्वल रहा है। यहां 2012 से अब तक 142 बाघों की मौत हुई, इनमें से सिर्फ 80 मौतें सामान्य हैं। यह खुलासा नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी द्वारा जारी टाइगर मोर्टेलिटी रिपोर्ट (2012-18) में हुआ है। एनटीसीए अफसरों के मुताबिक मध्यप्रदेश में भोपाल, होशंगाबाद, पन्ना, मंडला, सिवनी, शहडोल, बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा के जंगल शिकारियों की पनाहगाह बन गए हैं। सिलसिला थमा नहीं है। दिसंबर 2018 से 27 जून 2019 तक मध्य प्रदेश में 17 बाघों की मौत हुई है। इनमें से 3 बाघों की मौत शिकार की वजह से हुई जबकि 5 बाघों की मौत करंट लगने से हुई है।

मामला सुलझने के बाद मप्र वन विभाग को हाल ही में वायरलेस फ्रीक्वेंसी का नया लाइसेंस मिला है। विभाग अब 1500 सेट खरीदेगा, जो संरक्षित क्षेत्रों में दिए जाएंगे। दूसरे चरण में सामान्य वनमंडलों के लिए सेट खरीदे जाएंगे। विभाग की संरक्षण शाखा वायरलेस सेट चयन करने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही करेगी।

– डॉ. यू. प्रकाशम, वन बल प्रमुख एवं प्रभारी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, मप्र

वाराणसी का केला, पपीता और भिंडी खाएंगे विदेशी

जागरण संवाददाता, वाराणसी

- एपीडा ने विदेश में निर्यात के लिए चयनित की फल व सब्जी, निर्यात से पहले जांच को काशी में बनेगी लैब

आम, अमरूद, आंवला और केले के साथ ही काशी का पपीता, भिंडी, हरी मिर्च, लौकी, प्याज, बींस और मटर भी विदेशी खा सकेंगे। एपीडा (एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने निर्यात के लिए फल व इन सब्जियों का चयन किया है ताकि काशी सहित पूर्वांचल के किसानों को एक बेहतर विश्व बाजार मिल सके।

इसके लिए प्रदेश सरकार से सहयोग की स्वीकृति भी मिल गई है। विदेशों में निर्यात से पहले जांच के लिए काशी में लैब बनाने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की नई दिल्ली एवं वाराणसी में दो चरणों की बैठक भी हो चुकी है। अब फल-सब्जी उगाने एवं निर्यातकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतिम निर्णय के लिए मंथन होने जा रहा है।

काशी को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए राजातालाब में पेरिशेबल कार्गो सेंटर भी स्थापित किया गया है। इसके साथ ही काशी अब जल-थल व नभ हर ओर से निर्यात के लिए तैयार है। इसे लेकर पहली बैठक 27 जुलाई को नई दिल्ली एवं दूसरी बैठक 22 अगस्त को वाराणसी में हुई थी। अब सीधे निर्यातकों एवं उत्पादकों के बीच एक नवंबर को बैठक होने जा रही है। एपीडा के के महाप्रबंधक उपेंद्र कुमार वत्स बताते हैं कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, इंग्लैंड, अमेरिका में पूर्वांचल की सब्जी व फल को निर्यात करने की योजना बनाई गई है। इसमें भिंडी, हरी मिर्च, प्याज, बींस, मटर, अमरूद, आंवला, केला, आम व पपीता शामिल हैं।

गुणवत्ता से समझौता नहीं

वत्स ने बताया कि विदेशों में उन सब्जी या फल की डिमांड है जो बिना कीटनाशक या कम रासायनिक खाद से तैयार किए गए हैं। वैसे फिलहाल वाराणसी में इसकी जांच की उचित व्यवस्था नहीं है। इसके लिए ईरी से लैब तैयार करने के लिए कहा गया है। साथ ही एक निजी संस्था से भी संपर्क साधा जा रहा है। ताकि निर्यात से पहले फल व सब्जी की गुणवत्ता की जांच की जा सके।

किसानों के लिए लखटकिया ई-ट्रैक्टर बना रहे हैं सीएमईआरआइ के वैज्ञानिक

हृदयानंद गिरि, दुर्गापुर

देश के किसानों की सुविधा के लिए केंद्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) की बंगाल के दुर्गापुर स्थित सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमईआरआइ) के विशेषज्ञ ई-ट्रैक्टर बनाने में जुटे हैं। मकसद यही कि छोटे व महिला किसानों को भी ट्रैक्टर सहज उपलब्ध हो। इसके साथ-साथ डीजल से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम कर पर्यावरण संरक्षण भी हो सके। ट्रैक्टर की लागत करीब एक लाख आएगी। इस लखटकिया ट्रैक्टर को वैज्ञानिक 6-8 माह में तैयार कर लेंगे।

पिछली सदी के सातवें दशक में इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने 20 एचपी (हॉर्स पावर) का स्वराज ट्रैक्टर तैयार किया था। जो कृषि क्षेत्र में क्रांति लाया था। उसके बाद सीएमईआरआइ वैज्ञानिकों ने बड़े आकार के 35 एचपी वाले सोनालिका ट्रैक्टर को तैयार किया। वर्ष 2014 में 12 एचपी का छोटे आकार का कृषि शक्ति ट्रैक्टर बनाया। डीजल से चलने वाला यह ट्रैक्टर भी किसानों को खूब भाया। अब कृषि शक्ति के मॉडल पर ही ई-ट्रैक्टर बनाने में वैज्ञानिकों की टीम लगी है। जो बैटरी से चलेगा।

प्रतीकात्मक

- 6 से 8 माह में वैज्ञानिक तैयार कर लेंगे ई-ट्रैक्टर
- 10 एचपी की होगी क्षमता, 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी का होगा प्रयोग, सौर ऊर्जा से भी होगी चार्ज
- पर्यावरण का होगा संरक्षण, महिला व छोटे किसान कर सकेंगे इसका आसानी से प्रयोग

इन खूबियों से लैस होगा ई-ट्रैक्टर : सीएमईआरआइ के वैज्ञानिक जिस ई-ट्रैक्टर को बनाने में जुटे हैं वह 10 एचपी क्षमता का होगा। इसमें 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी का उपयोग होगा। बैटरी के एक बार चार्ज होने पर ट्रैक्टर एक घंटा तक खेत में दौड़ सकेगा। बैटरी को सौर ऊर्जा से भी चार्ज किया जा सकेगा। इस बेहद शानदार खूबी के कारण इसका प्रयोग कम जमीन रखने वाले किसान भी कर सकेंगे। ट्रैक्टर की रफ्तार 25 किमी प्रति घंटा तक होगी। इसका वजन 300-400 किलो होगा।

ऊर्जा की बचत के साथ छोटे एवं मध्यम श्रेणी के किसानों को खेती में सुविधा देने के लिए ई-ट्रैक्टर तैयार कर रहे हैं। यह कृषि शक्ति जैसा ही होगा। सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2020 के मध्य तक इसे बनाकर ट्रायल भी कर लेंगे। महिला किसान भी इसे आसानी से चला सकेंगी।

– हरीश हिरानी, निदेशक, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल

संक्रमित सिरिंज से पंजाब में बढ़े 370 फीसद एचआइवी मरीज

प्रतीकात्मक

वर्ष	मरीज
2014	671
2015	780
2016	1196
2017	1488
2018	2567
2019	3134

जगदीश कुमार, जालंधर

- नशे के आदी एक ही सिरिंज से नशा कर दे रहे बीमारी को निमंत्रण
- ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप भी एक ही सिरिंज से कई मरीजों को देते दवा

एचआइवी और एड्स पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद पंजाब में एचआइवी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण है संक्रमित सिरिंज और सुइयों का इस्तेमाल करना। इससे राज्य में पांच वर्षों में एचआइवी मरीजों की संख्या 370 फीसद बढ़ गई है। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के मुताबिक वर्ष 2014 में संक्रमित सिरिंज के इस्तेमाल से सामने आने वाले एचआइवी मरीजों की संख्या 671 दर्ज की गई थी।

वर्ष 2017 में इनकी संख्या बढकर 1,488 हो गई थी। वर्ष 2018 में 70 फीसद इजाफे के साथ यह संख्या 2,567 तक पहुंच गई। वहीं, इस साल मरीजों की संख्या में पिछले आठ माह में 25 फीसद इजाफा हुआ है। एचआइवी मरीजों की संख्या अब 3,134 है। इसका कारण यह है कि एक ही सिरिंज से एक से अधिक लोग नशा करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप उपचार के दौरान एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। इससे एचआइवी होने का खतरा बढ़ जाता है। उपचार के दौरान असावधानी बरतने से पैरामेडिकल स्टाफ के भी एचआइवी की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है।

ओएसटी सेंटरों से आधे से ज्यादा नशेड़ी हुए गायब : बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. पीएल गर्ग बताते हैं कि सेहत विभाग ने सिरिंज से नशा करने वालों को एचआइवी व एड्स से बचाने को उन्हें ओरल मेडिसिन पर शिफ्ट करने के लिए 30 ओएसटी सेंटर खोले हैं। इसमें धीरे-धीरे उनका नशा भी छुड़ाया जाता है। ओएसटी सेंटरों में राज्य भर से करीब 28,700 नशे के आदी लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है। इनमें से करीब 21 हजार लोगों का इलाज चल रहा है। इलाज करवाने वालों में दस हजार ही दवा खाने आ रहे हैं। आधे से ज्यादा मरीज गायब हो चुके हैं। सेहत विभाग ने उन्हें ढूंढने की जहमत ही नहीं उठाई। गायब हुए लोग ही संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल कर एचआइवी की दर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार हैं।

पंजाब एड्स कंट्रोल सोसायटी की एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. मनप्रीत कौर छतवाल का कहना है कि सिरिंज की सप्लाई केवल अस्पतालों व पंजीकृत डॉक्टरों को ही उनके लेटर पैड पर आवेदन के बाद करने के आदेश हैं। राज्य में पंजाब एड्स कंट्रोल सोसायटी के साथ ही 62 स्वयंसेवी संगठन सिरिंज से नशा करने वालों को ढूंढ कर उन्हें ओएसटी सेंटरों में ला रहे हैं।

झोलाछापों पर शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार : राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार असुरक्षित सिरिंज से नशा करने वालों में 12 फीसद एचआइवी मरीज सामने आए हैं। इस मामले को लेकर विभाग फर्जी डॉक्टरों पर शिंकजा कसने की तैयारी कर रहा है। सेहत विभाग को केंद्र सरकार ने सिरिंज से नशा करने वाले 13,350 लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य दिया था। विभाग की टीमें 13,992 लोगों तक पहुंची हैं। इन्हें एचआइवी से बचाने के लिए विभाग की ओर से स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से मुफ्त सिरिंज मुहैया करवाई जाती हैं। पुरानी सिरिंज लेने के बाद ही उन्हें नई सिरिंज दी जाती हैं। इसके बाद इन्हें ओएसटी सेंटरों में शिफ्ट किया जाता है, जहां उनका इलाज होता है। स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर डॉ. अवनीत कौर बताती हैं कि एचआइवी सहित अन्य संक्रामक रोगों से बचाव के लिए इलाज के दौरान इंजेक्शन का कम से कम इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है।

तैयारी

वन विभाग ने फूलों की घाटी में किया है सात प्राकृतिक गुफाओं का संरक्षण, अत्यधिक बर्फबारी व शीत में भी इन गुफाओं में सुरक्षित रह पाएंगे दुर्लभ वन्य जीव

फूलों की घाटी में सुरक्षित रहेंगे दुर्लभ वन्यजीव

रणजीत सिंह रावत, जोशीमठ (चमोली)

शीतकाल के दौरान फूलों की घाटी में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वन विभाग ने घाटी में सात प्राकृतिक गुफाओं (उड्यार) का संरक्षण किया है। ये प्राकृतिक आवास हिमालयन काला भालू, हिमालयन भूरा भालू, हिमालयन थार, कस्तूरा मृग, हिम तेंदुआ, भरल, घुरड़ आदि दुर्लभ जीवों के लिए बनाए गए हैं।

केंद्र सरकार की समेकित वन्य जीव प्राकृतिक वास (आइडीडब्ल्यूएच) योजना के तहत फूलों की घाटी में जो सात गुफाएं संरक्षित की गई हैं, वो बामणधोण, द्वारीपुल, धंसा धार व मैरी की कब्र के पास हैं। इन गुफाओं की बाउंड्री वॉल बनाने के साथ ही भीतरी हिस्सों का समतलीकरण कर वहां घास-फूस बिछाई गई है। इसके अलावा एप्रोच मार्ग भी दुरुस्त किए गए हैं। यह भी ध्यान रखा गया है कि गुफाओं में हवा का वेग नियंत्रित रहे। इससे वन्य जीव अत्याधिक शीत में भी सुरक्षित रह सकेंगे। वन क्षेत्राधिकारी फूलों की घाटी बृजमोहन भारती का कहना है अत्याधिक बर्फबारी और ठंड होने पर दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव इन गुफाओं में अपना आशियाना बनाएंगे। दरअसल, शीतकाल के दौरान अत्याधिक बर्फबारी होने पर दुर्लभ वन्य जीव निचले स्थानों पर आ जाते हैं। जहां शिकारियों की निगाहें उन पर गड़ी रहती हैं। इसी को देखते हुए वन विभाग ने यह पहल की है।

चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। फाइल

पर्यटकों के लिए बंद हुई घाटी

जागरण संवाददाता, चमोली : नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी बुधवार पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई। इस साल 17 हजार से अधिक सैलानी फूलों की घाटी के दीदार को पहुंचे, जो कि एक रिकार्ड है। अब सैलानी अगले साल जून में घाटी की सैर कर सकेंगे। समुद्रतल से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली फूलों की घाटी जैव विविधिता का खजाना है। यहां दुर्लभ प्रजाति के फूल, वन्य जीव-जंतु, जड़ी-बूटियां और पक्षी पाए जाते हैं।

1931 में फूलों की घाटी की खोज ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रेंक स्मिथ ने की थी। उन्होंने वैली ऑफ फ्लॉवर नाम की पुस्तक भी लिखी। 1982 में घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और वर्ष 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दिया। घाटी में 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन भारती ने बताया कि इस साल फूलों की घाटी में रिकॉर्ड 17,424 सैलानी पहुंचे, जबकि वर्ष 2018 में यह आंकड़ा करीब 14742 था।

घाटी में लगेंगे 12 कैमरा ट्रैप : सर्दियों में फूलों की घाटी की सुरक्षा के लिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन पुख्ता व्यवस्था करने जा रहा है। इसके तहत घाटी में 12 कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन भारती ने बताया कि इसके अलावा घाटी में गश्त भी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 14 वन कर्मियों की टीम बनाई गई है।

एक देश नहीं, पूरे विश्व की समस्या है ग्लोबल वार्मिंग

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: जर्मनी से तीर्थनगरी पहुंचे योग जिज्ञासुओं के दल ने गुरुवार को परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज व जीवा की अंतरराष्ट्रीय महासचिव साध्वी भगवती सरस्वती से मुलाकात की। दल ने उनसे योग के अलावा पर्यावरण व जल प्रदूषण और इसके समाधान पर भी चर्चा की।

दल ने परमार्थ निकेतन का भ्रमण करने के साथ ही योग और ध्यान की कक्षाओं में सहभाग कर अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। इस दौरान स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि जलवायु परिवर्तन व जल प्रदूषण जैसी समस्याएं किसी एक राष्ट्र नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की हैं। इसलिए इनके समाधान को भी मिल-जुलकर प्रयास किए जाएं तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बताया कि पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने न्यूयॉर्क में आयोजित यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट-2019 में अपनी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया। इसी तरह विश्व का युवा अगर अपनी जागरुकता दिखाए तो पर्यावरणीय समस्याओं को कम किया जा सकता है।

दैनिक जागरण
सबरंग
प्लान वीकेंड के
नई दिल्ली, शुक्रवार, 1 नवंबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीर के साथ क्यों न एक यादगार फोटो हो जाए। जागरण

कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित जश्न-ए-विरासत-ए-उर्दू फेस्टिवल में प्रस्तुति देतीं वंदना मिश्रा व अन्य कलाकार। जागरण

इस बार यहां चलें

अकबर द ग्रेट नहीं रहे

कॉमिक शेड के साथ यह हिंग्लिश प्ले है। आज के भारत में अकबर की महानता पर सवाल उठाए जाने पर क्या होता है? वह स्वर्ग में अशोक से लेकर अलेक्जेंडर व अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन पाते हैं, लेकिन, पृथ्वी पर मीडिया मुगल की जरूरत है। वह कौन होगा? इसके लिए नाटक देखना होगा।

- **कहां** : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली
- **कब** : 1 नवंबर, शाम छह बजे
- **प्रवेश** : ऑनलाइन बुकिंग, 100 से 1000 रुपये टिकट

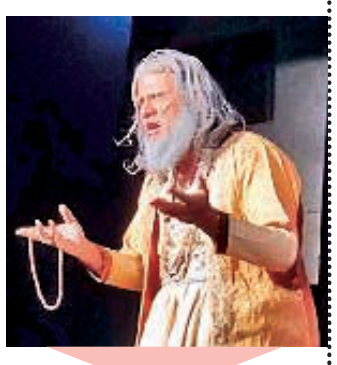

औरंगजेब की आखिरी रात

औरंगजेब ने एक साम्राज्य बनाया लेकिन जब वह गिर गया तो उसके अपने साम्राज्य के पत्थर ने उसे उड़ा दिया। उनकी मरणासन्न आवाज पृथ्वी के चेहरे से मिट गई। वह क्षमा और सहानुभूति के लिए तरस गया। औरंगजेब की आखरी राट वह गाथा है जो उन सभी लम्हों के बारे में बताती है जो उनके निधन से पहले थे।

- कहां : श्रीराम सेंटर ऑडिटोरियम, मंडी हाउस, नई दिल्ली
- कब : 2 नवंबर, शाम पांच बजे
- प्रवेश : ऑनलाइन बुकिंग द्वारा। 100 से 750 रुपये टिकट।

इथीरिअल हारमनी

पॉप कल्चर, जिसने दुनिया को एक गूंज में समां दिया है, उसकी खूबसूरती कैनवस पर सजाकर तनु यादव दर्शको के बीच आ रही हैं। 'इथीरिअल हारमनी' के क्यूरेटर मोहन सिंह है। तनु कहती हैं पॉप कल्चर मेरे लिए प्रेरणा है। इसकी लाइफस्टाइल को पेंटिंग में उतरना मेरे लिए काफी रोमांचक था।

- कहां : त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली
- कब : 1-11 नवंबर, सुबह 11 से रात 8 बजे तक
- प्रवेश : निश्शुल्क

लैटिन अमेरिका महोत्सव

दिल्ली तीसरे लैटिन अमेरिका महोत्सव के आगाज के लिए तैयार है। बोलिविया और कोलंबिया के कलाकारों की शानदार प्रस्तुति आपका मन मोह लेगी। बोलिविया से जेडी कर्डेनस-कैपिहुआरस और प्रेम शक्ति कंपनी-अंटोनिना कनाल डायरेक्टर हिस्सा लेंगे।

- कहां : कमानी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस, नई दिल्ली
- कब : 4-5 नवंबर, शाम साढ़े छह बजे
- प्रवेश : निश्शुल्क

जश्न-ए-विरासत-ए-उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल

शाम ने विदा ली तो रात शायर बन गई

शाम पंख सिकोड़ कर विदा ले रही थी और बादलों पर छाती अंधेरी, रात होने की गवाही दे रही थी। बहुत खास था, यूं शाम का खुलेआम रात से मिलना चूंकि उर्दू की शायरी इस माहौल का शृंगार कर रही थी। यूं तो महफिल दिन में भी सजी थी। पर कलाकारों ने समां...बांध दिया था...श्रोताओं का भी उत्साह पूरे शबाब पर था। संगीत की धमनियों पर थिरकते गजल-शायरी के बोल मनों में घुले जा रहे थे। हर श्रोता को भरी भीड़ में तन्हा किए जा रहे थे...अपने मन से मिलन का मौका दिए जा रहे थे। सबरंग के इस अंक में बुधवार 30 अक्टूबर से शुरू हुए ऐसे जश्न-ए-विरासत-ए-उर्दू हेरिटेज उत्सव से रूबरू करा रहे हैं **संजीव कुमार मिश्र** :

शाम का इतराना वाजिब था, रात का इठलाना लाजिमी था। दोनों को दिल्ली जी ही इस अंदाज में रही थी। सुरों की महफिल रोशनी में नहाई थी। दर्शकों फरमाइश पर कलाकारों की आजमाइश जारी थी। एक के बाद एक हो प्रस्तुति से माहौल सज चुका था। अमरोहा से आए कलाकारों ने पहली ही प्रस्तुति में समा बांध दिया था। उस्ताद यासिन खलीफा परवाज ने चाहरबैत की प्रस्तुति दी। बकौल यासिन यह चाहरबैत अफगानिस्तान में प्रचलित था। डेढ़ हजार साल पुरानी इस कला की पहली जुबान पश्तो या फिर फारसी हुआ करती थी। बाद में हिंदुस्तानी जुबान में कही जाने लगी। अब तो हिंदी में भी चाहरबैत कही जाने लगी। इस कड़ी में रामपुर रियासत का जिक्र आना भी जरूरी है। रामपुर के नवाब को लतीफा बहुत पसंद था, उन्होंने इसे संरक्षित किया और फैलाया भी। चाहरबैत छह से सात लोग गाया करते हैं। जिनमें एक कलाकार नुमाया होता है जबकि बाकि हमनमा होते हैं। इस टीम को अखाड़ा कहा जाता है। आमतौर पर अखाड़े से मतलब लोग गांव-देहात के अखाड़े से लगाते हैं जहां कुश्ती-दंगल होता है। लेकिन चाहरबैत में भी अखाड़ा होता है। अखाड़े का खलीफा ही मुख्य किरदार होता है। इसकी शायरी दर्शकों के दिल में उतर जाती है। बकौल खलीफा इसमें साज के नाम पर सिर्फ डफली का प्रयोग होता है। खलीफा परवाज की पहली ही प्रस्तुति 'हिंदुस्तान' ने सेंट्रल पार्क का माहौल देशभक्ति वाला कर दिया। उन्होंने जब मिसरे गाए....

एलान है, एलान है, एलान हमारा
जन्नत का नमूना है, हिंदुस्तान हमारा
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या इसाई
आजादी की शम्मा है सबने मिलके जलाई।।
आपस में रहे इस तरह, जैसे कि हों भाई।।

अगली प्रस्तुति और भी उम्दा थी। इसके बोल दर्शकों के दिल में उतर गए...

ए हवा अदब से चलना, मेरे यार की गली है
ये तो मानता हूं कि तू भी किसी हुक्म से चली है।।

वहीं एक अन्य आशिकाना प्रस्तुति...

ये तो तुमने कह दिया, कि हमसे मत बोला करो
तो, खिड़कियां कमरे की अपने, तुम भी मत खोला करो।।

उत्सव का अगला पड़ाव था महफिल-ए-गजल। जिसमें हैदराबाद से आई पूर्वा गुरु ने अपनी दिलकश आवाज में गजल सुनाई। उनकी प्रस्तुति भी कुछ यूं थी...

नसीं में सुबह ए गुलशन में
गुलों से मिलती होगी।।

एक अन्य गजल-हजारों मंजिले, फिर भी मेरी मंजिल है तू ही तू... को दर्शकों ने तालियां बजाकर सराहा। दर्शकों ने खड़े होकर अभिवादन किया।

पहले दिन की तीसरी प्रस्तुति वंदना मिश्रा की थी। वंदना ने सूफी महफिल कुछ ऐसी सजाई कि दर्शक सुरधारा में बह गए।

...मैं तो जोगन बन गई गाया। इस गाने पर वंदना संग दर्शक भी झूम उठे।

आतिक हुसैन बंदानवाज की कव्वाली के साथ महफिल-ए-कव्वाली की शुरुआत होती है। इन्होंने पहले पहल...

अपना क्या है, तमाम उनका है
सुनसान जंगलों में, ऊंची पहाड़ियों में
उर्वा की झोपड़ी में इशरत की महफिलों में

अपना क्या है, तमाम उनका है।। सुनाया तो दर्शकों ने कव्वाली का साथ दे रहे तबले की थाप पर थिरकना शुरू कर दिया।

पहले दिन की आखिरी प्रस्तुति प्रख्यात गजल गायक तलत अजीज की थी। तलत अजीज को सुनने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर से लोग आए थे। तलत अजीज जब मंच पर आए तो दर्शकों ने खड़े होकर तालियों से उनका अभिवादन किया।

...मौत की सच्ची खबर उड़ाने वाला झूठा है : खय्याम साहब का हाल ही में इंतकाल हुआ। तलत उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि वो मेरे वालिद की तरह थे। उन्होंने ही पहली बार मुझे फिल्मों में मौका दिया। उमराव जान में गजल गवाई। जिंदगी जब भी तेरी बज में लाती है गाई। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, सारी रस्में मैंने की। इस मौके पर निदा फाजली द्वारा लिखा एक नज्म मैंने उन्हें बतौर श्रद्धांजलि आयोजित सभा में पढ़ा। था। निदा फाजली द्वारा अपने वालिद के इंतकाल पर लिखा था। जिसे मैंने थोड़ा बदला था। जिसके बोल थे-

तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आया
मुझे मालूम था कि तुम मर नहीं सकते।
तुम्हारी मौत की सच्ची खबर
जिसने उड़ाई थी
वो झूठा है
वो तुम कब थे
कोई सूखा हुआ पत्ता, हवा से हिलकर टूटा।।

इसके बाद...

जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें
ये जमीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें।।

इसके बाद फैयाज हाशमी साहब का नगमा सुनाया- आज जाने की जिद ना करो...।

दिखेगा छात्रों की अदाकारी : जश्न-ए-विरासत में छात्रों समेत फैकल्टी का भी जलवा दिखेगा। यहां ऐसे कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों का हुनर दिखेगा। एक नवंबर को बैतबाजी मुकाबला होगा। जिसमें जामिया के छात्र हिस्सा लेंगे। जामिया के खालिद कहते हैं कि यह अंताक्षरी की तरह होता है। हालांकि इसमें शेर पढ़ा जाता है। बकौल खालिद इसमें हमदर्द, इंद्रप्रस्थ, जेएनयू के छात्र भी शिरकत करेंगे। पढ़ाई के साथ बैतबाजी की रिहर्सल के सवाल में खालिद कहते हैं कि जामिया में कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं। जिसमें हमे शेर पढ़ने का मौका मिलता है। इसके अलावा जामिया के छात्र गजल भी पढ़ेगे। लेकिन एक कार्यक्रम जो बहुत ही खास है वो है तमसीली मुशायरा। आयोजन से जुड़े जावेद कहते हैं कि यह बहुत ही दिलचस्प होता है। तसलीमी मुशायरे में हम प्रसिद्ध शायरों की नकल करते हैं। उन्हीं के अंदाज में शेर पढ़ते हैं। यहां तक की उन्हीं की तरह वेशभूषा भी होती है। चाल-ढाल भी उन्हीं की तरह होता है। इसमें जामिया के फैकल्टी भाग लेंगे। इसकी रिहर्सल करीब 20 दिन से लगातार हो रही है। वसीम बरेलवी, जेहरा निगाह, आदिल लखनवी, पापुलर मेरठी, जौन एलिया आदि पर तसलीमी मुशायरा प्रस्तुत किया जाएगा। 4 नवंबर को दोपहर दो बजे प्रस्तुति होगी।

गजल गायक तलत अजीज

- **आयोजन**-जश्न-ए-विरासत-ए-उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल
- **कहां** : सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस
- **कब** : सुबह दस से रात आठ बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क
- **नजदीकी मेट्रो स्टेशन** : राजीव चौक

अस्तित्व की तलाश में अर्धनारीश्वर के वंशज

नृत्य नाटिका

कुर्सी पर शांतचित्त बैठे लोग, हर मन में उत्सुकता है, उधेड़बुन भी कैसी होती होगी किन्नरों की जिंदगी, क्या वे भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीते हैं। अचानक मंच पर चीख-पुकार की आवाज से उनकी तंद्रा टूटती है। ये क्या चार लोग एक शव को कंधे पर लेकर आ रहे हैं। यह तो एक किन्नर की अंतिम यात्रा है। इतना भावुक क्षण कि दर्शक भी भाव विह्वल हुए बिना नहीं रह सके। 23 अक्टूबर को श्रीराम सेंटर ऑडिटोरियम में किन्नर की जिंदगी की एक एक कहानियां नृत्य के जरिए प्रस्तुत की जातीं रहीं। इस नृत्य नाटिका के जरिये दर्शक भावना और असल जिंदगी के मायने समझते रहे। जब यह दृश्य नृत्य के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा था तब वायस ओवर दर्शकों को कहानी बयां करता है। जिसमें कहा जाता है-ये अर्ध नारीश्वर का अंश है। इनको इंसान की तरह समझो। इनके पूर्वज अर्ध नारीश्वर थे।

खुशी का पल मातम में बदल गया : चंद मिनटों बाद ढोल की आवाज के बीच बच्चे की किलकारी गूंजती है। दर्शकों का मन भी आनंदित हो उठता है। कलाकार समूह में मंच पर आते हैं। एक दूसरे को बधाई देते हैं। बच्चे के जन्म पर अभिभावकों की खुशी देखते ही बनती है। खुशी के इस मौके पर किन्नरों का एक समूह भी घर पर आ धमकता है। वे गाना गाते है, बच्चे को खूब दुआएं देते हैं। तभी एक किन्नर को पता चलता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वह भी किन्नर है। खुशी का यह पल मातम में बदल जाता है। मायूसी के बीच एक बच्चे की आवाज दर्शकों का ध्यान खींचती है। मेरी किलकारियों ने सन्नाटे को शोर बना दिया, दूसरे ही क्षण देखने वालों की होड़ लग गई। लेकिन मां....वो तो अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए है। वह बेटे को पुरुषों की मानिंद रहना सिखाती है। लड़का भी मां की बात मानता है और वह सब करता है, जो मां उसे कहती है। लेकिन कहीं न कहीं उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है। और अंत में वह टूट ही जाता है। और एक दिन पुरुषों के कपड़े उतार, महिलाओं के कपड़े पहन लेता है।

कोरियोग्राफर बसु शर्मा कहती हैं कि एक किन्नर जिसे अर्धनारीश्वर कहकर पूजा जाता है, उन्हीं के वंशज समाज में खुद के होने का अस्तित्व ढूंढते हैं। इस नृत्य नाटिका के माध्यम से हम दर्शकों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते थे कि किन्नरों के साथ भी मानवीय व्यवहार करें। इस प्रस्तुति के लिए कलाकारों ने तीन महीने से भी ज्यादा समय तक परिश्रम किया। किन्नरों के हाव भाव, पहनावे का अध्ययन किया। कई कलाकार ट्रैफिक सिग्नल पर गए, उनसे बात की। रिहर्सल के दौरान किन्नर की तरह ताली बजाने में दिक्कत हो रही थी। मैंने कलाकारों से गुजारिश की कि वे किन्नरों से मिलकर सीखें। 10 दिन तक सभी कलाकार ताली बजाने की प्रैक्टिस करते रहे। नृत्य नाटिका में ट्रैफिक सिग्नल वाले दृश्य में ताली का भी जिक्र है।

किन्नरों के जीवन को कलाकारों ने मंच पर कुछ यूं जीवंत बना दिया। जागरण

जब अपने भी मुंह फेर लेते हैं : मंच पर इस दृश्य का मंचन इतना आसान नहीं था, लेकिन कलाकार अनुराग ने अपनी भाव-भंगिमा से इसे आसान बना दिया। नृत्य करते हुए कपड़े बदलने के दृश्य और उसके बाद लड़के के जीवन में आए बदलाव ने तो दर्शकों का दिल जीत लिया। लड़के ने कपड़े क्या बदले मानों उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया हो। माता-पिता को भी बेटे से मुंह फेरना पड़ता है। आस पड़ोस के लोग कल तक जिसे लड़का मान बातें करते थे अब उसे देखना भी नहीं चाहते। समाज से मिले इस तिरस्कार के बाद युवक को किन्नरों का समूह ज्वाइन करना पड़ता है।

इंसान हैं हम ठुकराना बंद करो : किन्नरों की पीड़ा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और एक वाक-इन-इंटरव्यू दृश्य का भी मंचित किया गया। तकनीक के सहारे ट्रैफिक सिग्नल का दृश्य इतनी खूबसूरती के साथ दिखाया गया मानो सचमुच शोर-शराबे के बीच ट्रैफिक पर खड़े हों। इसे दिखाने का मकसद यही था कि ट्रैफिक सिग्नल पर किस तरह किन्नर जिंदगी की जंग लड़ता है। कोई उसे धमकाता है तो कोई गाली देता। सबसे मार्मिक दृश्य नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान देखने को मिला। इंटरव्यू देने वालों की लाइन लगी है। तभी एक किन्नर भी वहां नौकरी के लिए पहुंचता है, लेकिन लोग उसे धक्के देकर भगा देते हैं। किन्नर पढ़ा लिखा है, लेकिन समाज उसे नौकरी नहीं करने देता। कार्यक्रम के अंत में किन्नर अपनी व्यथा सुनाते हुए कहता है कि इंसान है हम, छूआछूत की बीमारी नहीं, बंद करो हमें परखना, भीख देना, लाचार समझना, इंसान है हम, ठुकराना बंद करो। कलाकार अनुराग, दीपक वर्मा, प्रीति दास, शिखा राणा, राकेश कुमार, ताहिर अली, दिशा शर्मा और आकाश के शानदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

-संजीव कुमार मिश्र

विशुद्ध मारवाड़ी स्वाद की पूरी होती अभिलाषा

शेफ अभिलाषा मशहूर फूड क्रिटिक मरियम एच रेशी के साथ

जायका

गुरुग्राम में विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े लोग रहते हैं लेकिन यहां के फूड कल्चर पर विदेशी जायके का प्रभाव है। ऐसे में लोगों को वह पारंपरिक टेस्ट या तो अपने घरों पर मिलता है या फिर चुनिंदा रेस्त्रां और पंचतारा होटलों में। यानी यह जायका हर किसी की पहुंच में नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभिलाषा जैन राजस्थानी भोजन को लोगों तक पहुंचा रही हैं। राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन वह खुद तैयार करती हैं और लोगों तक पहुंचाती हैं। उन्होंने मारवाड़ी खाना नाम से फेसबुक पेज भी बनाया है।

संयुक्त परिवार के प्रभाव में सीखी पाक कला : अभिलाषा मूल रूप से भीलवाड़ा की हैं। उनका बचपन संयुक्त परिवार में बीता जहां उन्होंने दादी, चाची और मां को बेहतरीन भोजन पकाते देखा। ऐसे में बचपन से ही उन्हें रसोई से आकर्षण होने लगा और वे कुछ न कुछ बनाने लगीं। धीरे-धीरे कम उम्र में ही उनके हाथ की बनी चीजों की तारीफ होने लगी तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने राजस्थानी, खास तौर पर मारवाड़ इलाके के भोजन को बनाने में महारथ हासिल कर ली। अभिलाषा ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी नौकरी नहीं की। शादी के बाद पति के साथ स्कॉटलैंड गईं जहां कि उन्हें कहीं भी भारतीय भोजन नहीं मिल पाता था। ऐसे में उन्होंने सबसे ज्यादा कुकिंग वहां की और फिर जब गुरुग्राम आईं तो उन्होंने सोचा कि क्यों न लोगों को उनकी पसंद का पारंपरिक भोजन पहुंचाया जाए। और अब उनकी रेसिपीज सोशल मीडिया पर खूब हिट्स तो बटोर ही रही हैं। शेयर भी हो रही हैं साथ ही अच्छे फीडबैक भी मिल रहे हैं।

नाश्ते, मेनकोर्स में मारवाड़ की खुशबू : गुरुग्राम में राजस्थानी मूल के लोगों के अलावा ऐसे लोग फूड प्रेमी भी हैं जिन्हें राजस्थानी भोजन से विशेष लगाव है। ऐसे में वे उन्हें दाल-बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्जी, काली दाल के साथ मक्की के ढोकले, लेहसुन की चटनी व फली ढोकली का वही मारवाड़ी स्वाद तैयार करती हैं। दाल बाटी को राजस्थानी खुशबूदार देसी घी में बनाती हैं तो गट्टे की सब्जी में पड़े मसालों का स्वाद ही मुंह में पानी ला देता है। इसके अलावा मक्के के आटे से बने ढोकले की प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त होती है कि उसकी हर बाइट में राजस्थानी खुशबू व स्वाद हमेशा के लिए जुबां पर छा जाता है। लेहसुन की चटनी वे उसी अंदाज में राजस्थान से लाए मसालों से बनाती हैं। लोगों के स्वाद के अनुसार वे मसालों में बदलाव भी करती हैं। नाश्ते से लेकर मेनकोर्स मेन्यू और मिठाइयों में बदाम से लेकर सूजी का हलवा व अन्य चीजें बनाती हैं।

- प्रियंका दुबे मेहता

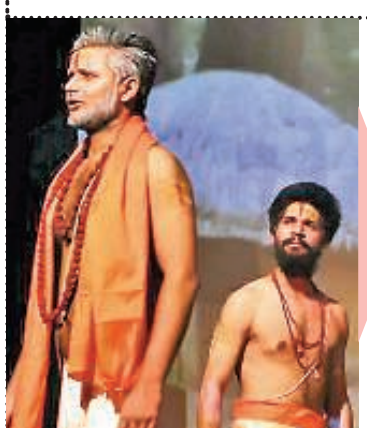

परशुराम-छठा अवतार

यह परशुराम के जिंदगी की रोमांचक कहानी है। जो उनकी जिंदगी को संघर्ष के आईने में दिखाती है। परशुराम को श्री हरि विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। लेकिन परशुराम, एक पुत्र, एक संत, एक योद्धा, एक अनुनायक और भी बहुत कुछ थे, जिसके बारे में दुनिया को जानने की जरूरत है।

- कहां : श्रीराम सेंटर, मंडी हाउस, नई दिल्ली
- कब : 2 नवंबर, शाम साढ़े सात बजे
- प्रवेश : ऑनलाइन बुकिंग द्वारा

एक्सक्यूज मी बॉस

नॉर्थ इंडियन, यूरोपीयन और चाइनीज फूड के शौकीन हैं और एक ही छत के नीचे इन्हें खाने की चाहत रखते हैं तो एक्सक्यूज मी बॉस जरूर जाएं। वैसे तो यहां का जायका लाजवाब है, लेकिन यहां पिज्जा, दाल मखनी, काकटेल, मोजिटो और पास्ता का सुस्वाद लेना ना भूलें।

- कहां : एफ, मिडिल सर्किल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
- कब : दोपहर 12 से रात 12 बजे तक
- शुल्क : 1800 रुपये प्रति दो व्यक्ति

ढाबा एक्सप्रेस

मुगलई, सी फूड और चाइनीज खाने वालों के लिए ढाबा एक्सप्रेस से बेहतर क्या हो सकता है। लाइट म्यूजिक के बीच लजीज जायकों का स्वाद दोगुना हो जाता है। यहां का बटर नान, कुरकुरे मोमोज, चाप, दाल मखनी, बटर चिकन, चिकन तंदूरी, चिकन कुरकुरी बेमिसाल है।

- कहां : पंचकुइयां रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
- कब : दोपहर 12 से रात साढ़े ग्यारह बजे तक
- शुल्क : 650 रुपये प्रति दो व्यक्ति

बजाज-टीवीएस ने किया पेटेंट मामले का निपटारा

नई दिल्ली, प्रेट्र : बजाज ऑटो और टीवीएस ने कहा है कि उन्होंने अपने एक दशक पुराने पेटेंट उल्लंघन के मामले का निपटारा कर लिया है। दोनों कंपनियों ने शेयर बाजारों को बताया कि एक स्पार्क प्लग के पेटेंट से जुड़े इस मामले में सुलह हो गई है। इस सुलह में टीवीएस द्वारा बजाज ऑटो पर किया गया मानहानि का मामला भी शामिल है। इसके अलावा दोनों कंपनियों ने अलग-अलग अदालतों में चल रहे इससे संबंधित सभी मामलों का निपटारा कर लिया गया है। इन्होंने श्रीलंका और मेक्सिको में दर्ज मामलों को भी इसी समझौते के तहत रफा-दफा कर दिया है।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी को 1,807 करोड़ रुपये का इनवेंट्री लॉस हुआ है। इस दौरान कंपनी की रिफाइनिंग मार्जिन पर भी चोट पड़ी है। इनका असर वित्तीय नतीजों पर दिखा है।
— संजीव सिंह, चेयरमैन, आइओसी

सेंसेक्स	40,129.05	77.18	निफ्टी	11,877.45	33.35	सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 39,017	₹115	चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 47,490	₹95
$ डॉलर	₹ 70.97	₹ 0.07	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 59.90							

कारपोरेट हलचल

गेल को कॉस्ट मैनेजमेंट अवार्ड

गेल (इंडिया) लिमिटेड ने एक बार फिर से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का उत्कृष्टता अवार्ड हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। यह अवार्ड कंपनी की पटना स्थित पेट्रोकेमिकल यूनिट ने जीता है। एक समारोह में कंपनी के निदेशक (फाइनेंस) ने वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर से यह अवार्ड ग्रहण किया।

रुद्रपुर में ईएसआइ अस्पताल का उद्घाटन

श्रम व रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में 100 बिस्तरों वाले ईएसआइ अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार में श्रम सेवायोजन मंत्री हरक सिंह रावत भी उपस्थित थे। इस अस्पताल का निर्माण पांच एकड़ भूमि पर 97.72 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। अस्पताल ईएसआइ सुविधा का लाभ उठाने वाले करीब दो लाख स्थानीय लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएगा।

उरे सतर्कता जागरूकता सप्ताह

उत्तर रेलवे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से दो नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य कार्यक्रम उत्तर रेलवे के मुख्यालय बड़ौदा हाउस में आयोजित हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त शरत कुमार मुख्य अतिथि थे। उनके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे की सतर्कता स्मारिकाओं का विमोचन भी हुआ।

एएआइ में सतर्कता जागरूकता सप्ताह

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में क्षेत्रीय निदेशक एम. सुरेश ने इसका उद्घाटन किया। सुरेश ने इस मौके पर कर्मचारियों व अधिकारियों को शपथ भी दिलाई। इस मौके पर संयुक्त महाप्रबंधक (सतर्कता) श्रीमती अमृता वर्मा भी उपस्थित थीं।

एनबीसीसी में सतर्कता सप्ताह

एनबीसीसी में एक सप्ताह तक चलने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह में हाल में कंपनी के सीएमडी बने पीके गुप्ता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सप्ताह के दौरान कंपनी ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

एपल ने भारत में की रिकॉर्ड बिक्री

कैलीफोर्निया, आइएएनएस : दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एपल इंक ने कहा है कि चौथी तिमाही के दौरान उसके भारतीय कारोबार से रिकॉर्ड बिक्री हासिल हुई है। इसके अलावा कंपनी ने अपने मैक डेस्कटॉप बिजनेस से भी रिकॉर्ड राजस्व जुटाया है।

हालात ▸ सोमवार को बैंकॉक में आरसेप पर शीर्ष बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी, भारत में किसान संगठनों का प्रदर्शन

आरसेप पर फैसले से पहले भारत कशमकश में

अंतिम चरण तक वार्ता खिंचने की उम्मीद, भारत के बगैर आगे बढ़ सकते हैं सदस्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

तीन दिन बाद यानी अगले सोमवार को आसियान के 10 देशों समेत 16 देशों के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते यानी आरसेप पर अंतिम फैसला होना है। लेकिन भारत अभी भी इस समझौते में शामिल होने को लेकर कशमकश में है। सभी 16 सदस्य देशों के अधिकारियों के बीच बैंकॉक में जबरदस्त विमर्श का दौर जारी है और भारत इस बात का प्रयास कर रहा है कि कृषि उत्पादों और सेवा उद्योग को लेकर उसकी चिंताओं को अंतिम मसौदे में शामिल किया जाए। लेकिन बैंकॉक से जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक अगर भारत आरसेप में शामिल होने से इन्कार करता है तब भी शेष 15 देश इस समझौते को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पिछले वर्ष भारत की वजह से ही इस समझौते पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया था।

पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को बैंकॉक में होने वाली रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को देर शाम रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी वहां रविवार को आसियान-भारत शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। जबकि अगले दिन मंगलवार को वे ईस्ट एशिया शिखर बैठक में शिरकत करेंगे और बाद में आरसेप शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। मोदी के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ वरिष्ठ नौकरशाहों का एक बड़ा दल जा रहा है।

विदेश मंत्रालय की सचिव (ईस्ट) विजय ठाकुर सिंह से जब यह पूछा गया कि भारत की क्या मांग है तो उनका जवाब था कि कुछ मुद्दों को लेकर भारत की अपनी चिंताएं है जिस पर बातचीत हो रही है। भारत पूरी गंभीरता से इसमें शामिल हो रहा है ताकि सभी के हितों की रक्षा करने वाले एक पारदर्शी समझौते पर सहमति बन जाए। मेरा मानना है कि जब तक समझौतों को लेकर अंतिम सहमति नहीं बन जाए, हमें इंतजार करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के अन्य दूसरे अधिकारियों ने भी यह तो नहीं बताया कि भारत किन मुद्दों पर अड़ा हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा कृषि उत्पादों से जुड़ा है। जिस तरह से आरसेप आने के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों से दुग्ध उत्पादों समेत गेहूं व अन्य मोटे अनाजों के आयात का रास्ता खुलने का डर है, उसको लेकर भारत सबसे ज्यादा चिंतित है। ऐसे में भारत इनके सस्ते आयात को रोकने के लिए अपने पास कुछ अधिकार चाहता है ताकि वह अपने घरेलू उद्योग व किसानों के हितों की रक्षा कर सके। अब देखने वाली यह होगी कि अगर भारत इसके लिए तैयार होता है तो उसे बदले में किस क्षेत्र में अवसर देने की कोशिश होती है। दूसरी तरफ सरकार को यह भी मालूम है कि आरसेप को लेकर घरेलू स्तर पर विरोध बढ़ रहा है और विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा है।

दूसरी तरफ बैंकॉक में आरसेप में शामिल होने वाले अन्य सभी सदस्य देशों के बीच लगभग यह सहमति बन रही है कि अगर भारत शामिल नहीं होता है तब भी बाकी देश इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। चीन का मत है कि भारत के लिए एक वर्ष तक इंतजार किया जा चुका है और अब आगे बढ़ना चाहिए।

सरकार की चुप्पी से किसान संगठनों में आक्रोश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सोलह देशों के बीच रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) की बैठक में भारत की ओर से लगातार साधी जा रही चुप्पी पर किसान संगठनों ने सख्त नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मुक्त व्यापार समझौते पर भारत ने दस्तखत किया तो घरेलू किसानों की कमर टूट जाएगी। लगभग 10 करोड़ छोटे व भूमिहीन किसानों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। चार नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में जिन वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात निर्यात पर फैसला होने वाला है, उनमें कृषि उत्पाद प्रमुख हैं। नाराज किसान संगठनों ने आरसेप की बैठक में संधि पत्र पर होने वाले दस्तखत के दिन चार नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का एलान किया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष वीएम सिंह का करना है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे डेयरी उत्पादक देशों से घरेलू बाजार में डेयरी उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी, जो हमारे किसानों की आजीविका पर सीधा हमला होगा। संकट के दौर से गुजर रहे किसानों के हित संरक्षण के लिए किसान संगठन चुप नहीं बैठेंगे। किसान नेता आयोजित एक प्रेसवार्ता में बोल रहे थे। किसान शेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने कहा कि ज्यादातर छोटे व भूमिहीन किसानों की रोजी-रोटी पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से होती है। ऐसी संधि से तो हमारे किसानों का बहुत नुकसान होगा, जिसका अंदाजा सरकार को नहीं है। किसान नेता जितेंद्र ने कहा कि आरसेप को लेकर सरकार की ओर से बरती जा रही गोपनीयता से संदेह पुख्ता होता जा रहा है। अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव राजाराम सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है और अब बाजार में बाहर के उत्पादों की आवक से उनकी हालत और पस्त होगी।

हिस्सेदारी बेचकर 8,500 करोड़ रुपये जुटाएगा यस बैंक, शेयरों में बड़ी तेजी

नई दिल्ली, प्रेट्र : निजी क्षेत्र के अग्रणी कर्जदाता यस बैंक ने कहा है कि उसे 120 करोड़ डॉलर (करीब 8,500 करोड़ रुपये) के विदेशी निवेश का ऑफर मिला है। बैंक अपनी शेयर हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से यह रकम जुटाएगा। इस सूचना के बाद गुरुवार को बैंक के शेयरों में तेज उछाल देखा गया। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर बैंक के बोर्ड, पूंजी बाजार नियामक और शेयर होल्डर्स की अनुमति मिलना बाकी है। इसके अलावा विदेशी और घरेलू निवेशकों से हो रही बातचीत विशेष चरण में है। इससे पहले बैंक ने शेयर बाजारों को बताया था कि कई घरेलू और विदेशी निवेशक इसके कारोबार में निजी इक्विटी और रणनीतिक निवेश को लेकर इच्छा जता रहे हैं। संकट से गुजर रहे इस निजी बैंक ने अगस्त में करीब 1,930 करोड़ रुपये संस्थागत निवेशकों के माध्यम से जुटाए थे।

गुरुवार को इंट्रा-डे में बैंक के शेयर 38 परसेंट तक ऊपर चले गए। लेकिन बाद में कुछ नरमी के चलते 24 परसेंट उछाल के साथ बंद हुए। बीएसई के सेंसेक्स में बैंक का शेयर 70.45 रुपये के भाव पर बंद हुआ। वहीं एनएसई में इसके शेयर 23.77 परसेंट उछाल के साथ 70.30 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बंद हुए।

एयरटेल, वोडाफोन देनदारी चुकाने में सक्षम, सरकार बहकावे में न आए : जियो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ **अपील - सरकार इन्हें राहत के बजाय टैक्स व जीएसटी क्रेडिट के मुद्दे सुलझाए**

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार से राहत पाने की बाट जोह रहीं टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर रिलायंस जियो ने एक और प्रहार किया है। कंपनी ने संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र लिखकर कहा है कि फैसले के बाद दोनों कंपनियों के प्रयास असल में सरकार की आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। जियो का कहना है कि दोनो कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पूरा बकाया अदा करने में सक्षम हैं। इसलिए सरकार को उन पर कोई दरियादिली नहीं दिखानी चाहिए।

इससे पहले इस मसले पर रिलायंस जियो ने बुधवार को टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सीओएआइ से विरोध जताया था। गुरुवार को प्रसाद को लिखे पत्र में जियो ने कहा है कि वैसे तो दोनो कंपनियों के बंद होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन यदि ऐसा हो ही जाता है तो भी उससे टेलीकॉम क्षेत्र की स्थिति खराब होने वाली नहीं है। इसकी वजह यह है कि मुकाबले के लिए पीएसयू (बीएसएनएल) के अलावा नई कंपनियों के आने का रास्ता खुला होगा।

जियो ने सीओएआइ के इस नजरिये से भी असहमति जताई है कि अगर सरकार से राहत नहीं मिली तो टेलीकॉम क्षेत्र चरमरा जाएगा। कंपनी के मुताबिक सरकार को सीओएआइ के पत्र को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह संपूर्ण उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के बजाय केवल दो कंपनियों के सुर में सुर मिलाता है। सरकार से अपनी बात कहने का उसका तरीका डराने और ब्लैकमेल करने वाला है। सीओएआइ के पत्र से साफ पता चलता है कि उसका दृष्टिकोण जियो के प्रति पूर्वाग्रह से भरा है तथा दोनो कंपनियां मौजूदा हालात के लिए जियो को जिम्मेदार मानती है। जबकि इसके लिए वे स्वयं दोषी है। उन्होंने आधुनिकीकरण पर कोई निवेश नहीं किया। जबकि जियो ने इस पर पौने दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सरकार को इनकी प्रबंधकीय विफलता का बोझ अपने सिर नहीं लेना चाहिए।

स्पर्धियों पर परोक्ष प्रहार करते हुए जियो ने उन्हें कानून से लगातार बचने का प्रयास करने वाला बताया है। इसकी पुष्टि के लिए जियो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वे अंश भी पत्र में उद्धृत किए हैं जिनमें सीओएआइ के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की गई हैं। जियो ने सरकार को सुझाव दिया है कि सीओएआइ की अनुचित मांगों पर ध्यान देने के बजाय उसे विभिन्न शुल्क, टैक्स तथा जीएसटी क्रेडिट जैसे मुद्दे सुलझाने की कोशिशें करनी चाहिए। शामिल हैं। सरकार को इन वास्तविक मुद्दों के साथ अपनी राहत संबंधी मांग का घालमेल करने की सीओएआइ को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

गोल्ड एमनेस्टी स्कीम का कोई इरादा नहीं

नई दिल्ली : सोने में निवेश किया गया कालाधन वापस लाने के लिए सरकार फिलहाल कोई गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लाने पर विचार नहीं कर रही है। इससे पहले खबरें आई थीं कि सरकार गोल्ड एमनेस्टी स्कीम पेश करने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मीडिया में चल रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, आयकर विभाग ऐसी किसी योजना की तैयारी नहीं कर रहा है। प्रेट्र

जीडीपी में ऑटो सेक्टर का योगदान गिरने की आशंका

नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में ऑटो सेक्टर का योगदान घटकर सात परसेंट रह जाने की आशंका जताई गई है। इससे पहले 2018-19 के दौरान जीडीपी में इसका योगदान 7.5 परसेंट रहा था। चालू वित्त वर्ष में ऑटो सेक्टर का राजस्व छह परसेंट तक सिकुड़ने की आशंका है। गौरतलब है कि भारत का ऑटो सेक्टर पिछले कुछ समय से खपत में कमी से जूझ रहा है। एक स्टडी के मुताबिक इस वर्ष कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री में 6-7 परसेंट गिरावट की आशंका है। पिछले वर्ष के दौरान 2.5 करोड़ यूनिट वाहनों की बिक्री हुई थी। प्रेट्र

भारत में पहला डिजिटल शोरूम खोलेगी एमजी मोटर

बेंगलुरु : एमजी मोटर इंडिया ने कहा है कि वह भारत में अपना पहला डिजिटल शोरूम खोलने जा रही है। बेंगलुरु में खोले जाने वाले इस शोरूम में कोई कार नहीं रखी जाएगी। कंपनी ने बताया कि पारंपरिक कार शोरूम का परिचालन खर्च काफी ज्यादा होता है। इस नए तरीके से खर्च में बचत के साथ कारोबार को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही कंपनी ने बताया कि यह उसका पायलट प्रोजेक्ट है और डिजिटल होते कारोबार के लिए भविष्य का शो-केस है। कंपनी ने बताया कि यह एआइ पर आधारित शोरूम होगा जहां कर्मचारी टूल की मदद से कार का डिसप्ले करेंगे। प्रेट्र

बैंकों के बड़े राजस्व में सेंध लगाएंगे डिजिटल पेमेंट माध्यम

मुंबई : भुगतान परिदृश्य में आने वाले बदलावों के चलते भारतीय बैंकों द्वारा अगले छह वर्षों में करीब 63,000 करोड़ रुपये का राजस्व गंवाने की आशंका है। एक कंसल्टेंसी फर्म ने बताया कि आने वाले समय में भुगतान का तरीका अधिक तेज, पारदर्शी और मुफ्त होता जाएगा। इससे बैंकों को राजस्व का नुकसान होना सुनिश्चित है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान डिजिटल पेमेंट में बहुत तेज इजाफा हुआ है। इस स्टडी में कहा गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में भुगतान राजस्व 10.7 परसेंट की गति से बढ़ेगा। प्रेट्र

हांगकांग की इकोनॉमी मंदी के दौर में

हांगकांग : हांगकांग ने मान लिया है कि लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों और यूएस-चीन में जारी ट्रेड-वार से बुरी तरह प्रभावित होकर उसकी इकोनॉमी मंदी के दौर में चली गई है। यहां के नागरिक पिछले करीब पांच महीनों से लोकतंत्र की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे शहर की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसके कारण शहर का पर्यटन पूरी तरह से ठप हो चुका है। एएफपी

आरबीआइ डिप्टी गवर्नर के लिए सात उम्मीदवार मैदान में

नई दिल्ली : कैबिनेट सचिव अगले सप्ताह आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर पद के लिए सात उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेंगे। आरबीआइ की यह पोस्ट विरल आचार्य के इस्तीफे से खाली हुई थी। आचार्य ने अपना कार्यकाल पूरा होने के छह महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस पद के लिए सात चिन्हित उम्मीदवारों को सात नवबंर को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। प्रेट्र

सितंबर में तेजी से गिरा बुनियादी उद्योगों का उत्पादन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की स्थिति इस वर्ष सितंबर में बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। इस महीने कोयले के उत्पादन में तेज गिरावट के बाद समूचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योग के उत्पादन में 5.5 परसेंट की कमी दर्ज की गई है। अलबत्ता चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में इस क्षेत्र की विकास दर 1.3 परसेंट रही है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2018 में आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की विकास दर 4.3 परसेंट रही थी। अगस्त में यह 0.1 परसेंट रह गई थी। इस वर्ष सितंबर में सबसे खराब प्रदर्शन कोयला क्षेत्र का रहा। इस अवधि में कोयले के उत्पादन में 20.5 परसेंट की कमी दर्ज की गई है। इसी तरह रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में भी 6.7 परसेंट की कमी आई है।

पिछले कुछ महीनों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे स्टील उद्योग की स्थिति भी सितंबर में खराब हुई है। इस अवधि में इसका उत्पादन 0.3 परसेंट कम रहा। हालांकि सितंबर में एकमात्र फर्टिलाइजर के उत्पादन में 5.4 परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई।

जीएसटी का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ **गैस और एटीएफ को जीएसटी में लाने पर विचार, खाद्यान्न भी संभावित उत्पादों की सूची में**

जीएसटी से मिलने वाले रेवेन्यू के लगातार एक लाख करोड़ रुपये से नीचे रहने के बाद अब सरकार इसका दायरा बढ़ाने पर विचार करने लगी है। इसकी शुरुआत प्राकृतिक गैस और विमानों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन यानी एटीएफ से हो सकती है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों को भी जीएसटी के दायरे में लाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श का दौर शुरू हो गया है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जीएसटी को अगले चरण में ले जाने की तैयारियों के बीच सरकर जहां दरों की संख्या घटाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही कुछ ऐसे उत्पादों को शामिल करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं जिनसे राजस्व बढ़ सके। इसके तहत पांच पेट्रोलियम उत्पादों में से गैस और एटीएफ को सर्वाधिक संभावित लक्ष्य माना जा रहा है। हालांकि इसका फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में ही होगा। सूत्र बताते हैं कि बहुत संभव है कि इन दोनों उत्पादों पर काउंसिल में सहमति बन जाएगी।

इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने अगले दौर की बातचीत की तैयारी शुरू कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय पहले ही इन दोनों उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव रख चुका है। जीएसटी की शुरुआत के वक्त सरकार ने पांचों पेट्रोलियम उत्पादों - पेट्रोल, डीजल, गैस, एटीएफ और कच्चे तेल को बाहर रखा था।

इसके अतिरिक्त सरकार खाद्यान्नों को भी जीएसटी के दायरे में लाने की संभावना तलाशने में जुट गई है। राजस्व वृद्धि पर अधिकारियों की समिति ने इस तरह के

प्रतीकात्मक

उत्पादों पर विचार करना आरंभ कर दिया है। जीएसटी से पूर्व वैट के समय में खाद्यान्नों पर व्यापारियों को राज्यों में परचेज टैक्स अदा करना होता था। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद परचेज टैक्स समाप्त हो गया। अब अधिकारियों का समूह इस संभावना की तलाश कर रहा है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिये इन उत्पादों पर जीएसटी लागू किया जा सकता है या नहीं। ऐसा होने पर रजिस्टर्ड कंपनियां गैर-पंजीकृत कारोबारियों के आधार पर जीएसटी का भुगतान कर सकती हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अभी यह केवल शुरुआती चर्चा में आया है। इस पर विस्तृत चर्चा होनी बाकी है।

गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद इस वर्ष केवल अप्रैल में इस मद में राजस्व एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर पाया है। सितंबर में जीएसटी संग्रह 91,916 करोड़ रुपये के साथ 19 महीनों में सबसे कम रह गया था।

क्रैश टेस्ट में वैगनआर, सेंट्रो का प्रदर्शन लचर

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में सुरक्षित वाहनों को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत किए गए सुरक्षा परीक्षण में मारुति सुजुकी इंडिया की लोकप्रिय हैचबैक वैगनआर और ह्युंडई की सैंट्रो को केवल दो स्टार मिले। वाहन सुरक्षा समूह ग्लोबल एनसीएपी ने गुरुवार को बताया कि एंट्री लेवल की कारों पर किए गए इस परीक्षण में दात्सुन के रेडीगो को महज एक स्टार रेटिंग मिली।

क्रैश टेस्ट में किसी भी मॉडल को पांच स्टार रेटिंग नहीं मिल सकी। हालांकि मारुति सुजुकी के दो एयरबैग वाले मल्टी परपस व्हीकल (एमपीवी) एर्टिगा को परीक्षण में 3-स्टार रेटिंग मिली है। ग्लोबल एनसीएपी ने कहा, 'भारत के लिए सुरक्षित वाहन मुहिम के छठे दौर के लिए एर्टिगा, वैगनआर, सैंट्रो और रेडीगो के एंट्री लेवल संस्करण को चुना गया। परीक्षण से पता चला कि केवल एर्टिगा में ही दो एयरबैग दिए गए हैं, जबकि अन्य वाहनों में केवल चालक के लिए एक एयरबैग है।'

एर्टिगा का प्रदर्शन बेहतर : ग्लोबल एनसीएपी के प्रेसिडेंट व सीईओ डेविड वार्ड ने कहा, 'वाहनों के हालिया सुरक्षा परीक्षण में मिश्रित प्रदर्शन देखने को मिला। निराशाजनक तौर पर किसी भी वाहन ने 5-स्टार प्रदर्शन नहीं किया।' उन्होंने कहा कि एर्टिगा ने व्यस्कों और बच्चों दोनों के लिए तीन-तीन स्टार रेटिंग प्राप्त की। वैगनआर और सैंट्रो को बच्चों और व्यस्कों के लिए 2-2 स्टार मिले। रेडीगो को व्यस्कों के लिए एक स्टार और बच्चों के लिए 2-स्टार रेटिंग मिली।

तेजी

लगातार पांचवे सत्र में बढ़त के साथ रिकॉर्ड स्तर की ओर बाजार, आइटी और बैंक के शेयरों में देखा गया सबसे तेज उछाल

लगातार पांचवें सत्र में बढ़त, रिकॉर्ड की ओर बाजार

मुंबई, प्रेट्र : गुरुवार को लगातार पांचवे सत्र में प्रमुख भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ रिकॉर्ड की ओर अग्रसर हुए। इंट्रा-डे में सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान आइटी और बैंक के शेयरों में तेजी का रुख रहा। इंट्रा-डे में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 40,392.22 के स्तर की नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अंत में 77.18 अंक यानी 0.19 परसेंट सुधार के साथ 40,129.05 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के निफ्टी ने 33.35 अंक का इजाफा दर्ज किया। यह 11,877.45 के पर बंद हुआ।

गुरुवार के कारोबार में सेंसेक्स में सबसे ज्यादा 24.03 परसेंट की तेजी यस बैंक के शेयरों ने दर्ज की। इसके अलावा एसबीआइ, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक और एचडीएफसी के शेयरों में 7.69 परसेंट तक की तेजी देखी गई। वहीं दूसरी ओर टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइसीआइसीआइ बैंक के शेयरों में 2.09 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई।

शेयरखान के सीनियर वीपी और कैपिटल मार्केट स्ट्रैटेजी एंड इन्वेस्टमेंट्स हैड गौरव दुआ

प्रतीकात्मक

के मुताबिक बेहतर तिमाही नतीजों, त्योहारी सीजन में बढ़ी खपत और सरकार द्वारा नीतिगत सुधार की उम्मीद में सेंसेक्स इंट्रा-डे में सर्वकालिक उच्च स्तर तक गया। इसके अलावा यूएस फेड रिजर्व द्वारा इसकी प्रमुख ब्याज दरों में कटौती का भी असर देखा गया। बीएसई में टेक, टेलीकॉम, आइटी, रियल्टी और हेल्थकेयर सेक्टर के शेयरों में 1.97 परसेंट का इजाफा दर्ज किया गया। हलांकि मेटल, एनर्जी और कैपिटल गुड्स के शेयरों में 0.51 परसेंट की गिरावट देखी गई।

एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग, सियोल और टोक्यो के शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि शंघाई में गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के शेयर बाजारों में सत्र के शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई।

इन शेयरों में रही खास गहमागहमी

युनाइटेड बैंक : मजबूत तिमाही नतीजों के चलते इसके शेयरों में करीब 13 परसेंट का इजाफा दर्ज किया गया। बीएसई में इस सरकारी बैंक के शेयर 12.81 परसेंट उछाल के साथ 10.04 रुपये के हिसाब से बिके। वहीं एनएसई में इसके शेयर 13.48 परसेंट उछाल के साथ 10.36 रुपये के भाव पर बंद हुए। इससे पहले बैंक ने शेयर बाजारों को बताया था कि उसे जुलाई-सितंबर की तिमाही में 123.88 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।

जेके टायर : गुरुवार को जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के शेयरों में आठ परसेंट का उछाल देखा गया। बीएसई में कंपनी के शेयर 7.62 परसेंट की तेजी के साथ 75.60 रुपये के भाव पर बंद हुए। वहीं एनएसई में इनकी कीमत में 8.90 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार को कंपनी ने बताया था कि उसके शुद्ध मुनाफे में तीन गुना इजाफा हुआ है। वैसे, ऑटो सेक्टर में मंदी का असर टायर कंपनियों पर भी दिखा है।

क्वैश कॉर्प : बेहतर तिमाही नतीजों के चलते निवेशकों ने क्वैश कॉर्प के शेयरों में रुचि दिखाई। दिन के कारोबार में कंपनी के शेयरों में नौ परसेंट का इजाफा देखा गया। बीएसई में इसके शेयर 9.51 परसेंट उछाल के साथ 519.10 रुपये के स्तर पर बंद हुए वहीं एनएसई में इसके शेयर 8.97 परसेंट की तेजी के साथ 516.55 रुपये के भाव पर बंद हुए। बुधवार को जारी नतीजों के मुताबिक कंपनी का शुद्ध मुनाफा 5.49 परसेंट की दर से बढ़कर 65.03 करोड़ रुपये रहा।

सराफा बाजारों में तेजी जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : गुरुवार को सोने-चांदी के भाव में इजाफा दर्ज किया गया। दिन के कारोबार में सोना 115 रुपये बढ़त के साथ 39,017 प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। इससे पहले बुधवार को यह 38,902 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 95 रुपये की मामूली बढ़त के साथ 47,490 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई।

सराफा बाजार की गुरुवार की चाल के बारे में एचडीएफसी सिक्युरिटीज के सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल ने कहा कि मजबूत अंतरराष्ट्रीय कीमत और रुपये में गिरावट के कारण सोने के भाव में इजाफा दर्ज किया गया। इसके अलावा अमेरिका के फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती का असर भी देखा गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना 1,500 डॉलर प्रति औंस और चांदी 18 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के भाव पर बिके।

27 अप्रैल, 1942 को 32 नौसैनिकों समेत 44 लोगों को लेकर रवाना हुई यू श्रेणी की पनडुब्बी एचएमएस अर्ज को भूमध्य सागर स्थित माल्टा के पास पाया गया है। ब्रिटिश नौसेना की यह पनडुब्बी द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान लापता हो गई थी।

कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने किया वियना संधि का उल्लंघन

- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी रिपोर्ट में उजागर की पाकिस्तान की करतूत
- कहा- मामले में लागू होता है संधि का अनुच्छेद 36, काउंसलर एक्सेस के अधिकारों का भी किया उल्लंघन

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के अध्यक्ष जज अब्दुलकावी यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में वियना संधि का उल्लंघन किया। यूसुफ ने 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को पेश अपनी रिपोर्ट में जाधव मामले में पाकिस्तान की करतूतों को उजागर किया। उन्होंने यह भी कहा कि जाधव को वियना संधि के तहत सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

यूसुफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था ने गत 17 जुलाई को दिए अपने फैसले के संदर्भ में पाया कि पाकिस्तान ने वियना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया।' जज यूसुफ ने महासभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते समय जाधव मामले में कोर्ट के फैसले के कई पहलुओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को इस बात का परीक्षण करना था कि वियना संधि के अनुच्छेद 36 के

कुलभूषण जाधव। फाइल

तहत काउंसलर एक्सेस (राजनयिक संपर्क) की जो बात कही गई है, क्या उस अधिकार से जासूसी के संदिग्ध को बाहर रखा जा सकता है। इस संबंध में कोर्ट ने पाया कि वियना संधि में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे जासूसी या इस तरह के मामले में काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाए। इसलिए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि जाधव मामले में भी वियना संधि का अनुच्छेद 36 लागू होता है। कोर्ट ने पाया कि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस के अधिकारों का उल्लंघन किया।

17 जुलाई को आया था फैसला

आइसीजे ने गत 17 जुलाई को जाधव मामले में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि पाकिस्तान जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा और पुनर्विचार करे। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के झूठे आरोपों में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इस फैसले को आइसीजे में चुनौती दी थी। भारत ने दलील दी थी कि भारतीय नागरिक को काउंसलर एक्सेस से इन्कार किया जा रहा है। यह वियना संधि का सरासर उल्लंघन है।

बगदादी को मार गिराए जाने का वीडियो जारी

अमेरिका की गोलाबारी में आइएस सरगना का ठिकाना तबाह होने की तस्वीरें आईं सामने

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका ने दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के सरगना अबू बकर अल-बगदादी को सीरिया में मार गिराने के सैन्य अभियान की पहली तस्वीरें जारी की हैं। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने सीरिया के इदलिब में छुपे बगदादी को गत शनिवार को मार गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले दिन बगदादी के मारे जाने का एलान करते समय कहा था कि वह इस मिशन के कुछ वीडियो जारी करने पर विचार कर रहे हैं।

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बुधवार को इस अभियान का पहला वीडियो जारी किया। इस एरियल ब्लैक एंड ह्वाइट वीडियो में अमेरिकी विशेष बल एक परिसर को घेरते और हेलीकॉप्टर से आतंकियों पर गोलीबारी करते दिखे। वीडियो में एक जगह बगदादी के परिसर पर बमबारी के बाद काले धुंए का गुबार उठता दिखा।

अमेरिकी सेना की मध्य कमान के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने पेंटागन में पत्रकारों से कहा, 'यह सुनिश्चित करने के लिए इस परिसर को नेस्तनाबूद कर दिया गया ताकि इस जगह को यादगार स्थान ना बनाया जा सके।' उन्होंने बताया कि बगदादी सीरिया में जिस परिसर में

आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल-बगदादी को मार गिराने के अमेरिकी सैन्य अभियान की वीडियो फुटेज। इसमें सीरिया के इदबिल के एक गांव में छिपे परिसर में बगदादी की घेराबंदी करते विशेष बल के जवान नजर आ रहे हैं। एपी

रहता था, वह तुर्की की सीमा से महज छह किलोमीटर दूर था। इस इलाके में दबदबा रखने वाले दूसरे आतंकी संगठनों को शायद इसका आभास नहीं था कि बगदादी उनके इतना करीब था। मैकेंजी ने आइएस सरगना के अंतिम क्षणों के बारे में कहा, 'मैं आपको यह बता सकता हूं कि वह दो छोटे बच्चों के साथ एक सुरंग में रेंगकर जा रहा था और बच्चों के साथ उसने खुद को बम से उड़ा दिया था।'

आइएस ले सकता है बदला : मैकेंजी ने आशंका जताई कि आइएस बगदादी के मारे जाने का बदला ले सकता है। उन्होंने कहा, 'हमें आशंका है कि वे बदला लेने के लिए हमले का प्रयास करेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं।'

ट्रंप ने उजागर किया खोजी कुत्ते का नाम

समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, ट्रंप ने बगदादी को मार गिराने के अभियान में शामिल रहे खोजी कुत्ते का नाम उजागर कर दिया है। उन्होंने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, 'अभियान में घायल कोनन अभी पश्चिम एशिया में ही है। वह अगले हफ्ते ह्वाइट हाउस आएगा।' ट्रंप ने गत सोमवार को उसकी तस्वीर साझा की थी

लेकिन उसका नाम नहीं बताया था। कोनन ने ही सुरंग में बगदादी का पीछा किया था, जिसके बाद आतंकी सरगना ने खुद को बम से उड़ा दिया था।

न्यूज गैलरी

प्रेमदासा ने श्रीलंका में किया सत्ता विकेंद्रीकरण का वादा

कोलंबो : श्रीलंका में सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के राष्ट्रपति उम्मीदवार सजित प्रेमदासा ने वादा किया है कि चुनाव जीतने पर वह सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे। इसके तहत श्रीलंका की संसदीय प्रणाली में एक और सदन सीनेट को फिर बहाल किया जाएगा। यूएनपी के चुनाव घोषणापत्र में इसका जिक्र करते हुए कहा गया है कि सीनेट के सदस्य देश के विभिन्न प्रांतों से चुनकर आएंगे। श्रीलंका की संसदीय प्रणाली में 1971 तक सीनेट का अस्तित्व था। लेकिन 1972 के संविधान के तहत इसे हटा दिया गया था। श्रीलंका में इस महीने की 16 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। देश के शीर्ष पद के लिए कुल 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला सजित प्रेमदासा और पूर्व रक्षा मंत्री गोतबाया राजपक्षे के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। घोषणापत्र में प्रेमदासा की पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर श्रीलंका अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते मजबूत बनाने पर भी ध्यान देगी। श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिल समुदाय काफी समय से सत्ता विकेंद्रीकरण की मांग उठाता रहा है। (प्रेट्र)

राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल का पड़ा था असर : ब्रेनन

वाशिंगटन : अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए के पूर्व निदेशक जॉन ब्रेनन ने कहा है कि 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी मदताताओं पर रूसी दखल का असर पड़ा था। वाशिंगटन स्थित नेशलन प्रेस क्लब में ब्रेनन ने बुधवार को कहा, मैं यह नहीं जानता कि अमेरिकी मतदाताओं पर रूसी दखल का कितना असर पड़ा, लेकिन यह असर प्रभावी था। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल के मुद्दे पर उनका यह बयान अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और सांसदों के आधिकारिक निष्कर्ष से अलग है। गत वर्ष सांसदों ने रिपोर्ट जारी कर कहा था कि इस चुनाव में रूस की दखलंदाजी को लेकर कोई प्रमाण नहीं मिला। वर्ष 2013 से 2017 तक सीआइए के निदेशक रहे ब्रेनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े आलोचकों में हैं। गत वर्ष ट्रंप ने ब्रेनन द्वारा तैयार एक सुरक्षा व्यवस्था को निराधार बताते हुए रद कर दिया था। (रायटर)

दो हफ्ते में भूकंप से तीसरी बार दहला फिलीपींस

किदापवान : फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में गुरुवार को आए तेज भूकंप से पांच लोगों की मौत हो गई। करीब दो हफ्ते के भीतर देश में भूकंप की यह तीसरी बड़ी त्रासदी है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र कोटाबाटो प्रांत के तुलुनन शहर से 28 किलोमीटर दूर व सतह से छह किलोमीटर अंदर था। बीते मंगलवार को भी आए भूकंप से आठ लोगों की मौत हो गई थी। पिछले 16 अक्टूबर को रिक्टर पैमाने पर 6.3 की तीव्रता वाले भूकंप से सात लोगों की मौत हो गई थी। (एपी)

पाकिस्तान में चलती ट्रेन में खाना बनाते समय धमाका, 74 की मौत

लापरवाही ▶ कराची से लाहौर जा रही थी ट्रेन, तीन बोगियां हुईं खाक

मारे गए ज्यादातर लोग थे तब्लीगी जमात के सदस्य

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुरुवार सुबह चलती ट्रेन में आग लगने से 74 यात्रियों की मौत हो गई। यह हादसा कराची से लाहौर जा रही तेजगाम एक्सप्रेस में खाना बनाते समय गैस सिलेंडरों के फटने से हुआ। 40 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे के शिकार ज्यादातर लोग तब्लीगी जमात से जुड़े थे और एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने लाहौर जा रहे थे। प्रधानमंत्री इमरान खान ने घटना पर दुख जताते हुए इसकी जांच के निर्देश दिए हैं।

ट्रेन जब लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर रहीम यार खान शहर के पास लियाकतपुर से गुजर रही थी, तभी उसमें आग लग गई। आग तेजी से तीन बोगियों में फैल गई, जिनमें 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। इससे ट्रेन में अफरातफरी मच गई और लोग आग से बचने के लिए चलती ट्रेन से कूदने लगे। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की दस गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों और झुलसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। लियाकतपुर अस्पताल के चिकित्सा

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुरुवार को कराची से लाहौर जा रही तेजगाम एक्सप्रेस में लगी आग के बाद उठती लपटें (वीडियो ग्रैब)। रायटर

अधीक्षक नदीम जिया के अनुसार, शवों की पहचान डीएनए जांच से ही हो पाएगी। जिला आपातकालीन अधिकारी आरवाईके बकीर हुसैन ने बताया कि ज्यादातर यात्रियों की मौत ट्रेन से कूदने के कारण हुई। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन आग लगने के दो किलोमीटर बाद रुकी थी।

रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर तब्लीगी जमात (इस्लामिक उपदेशक) के सदस्य हैं। सभी लाहौर के पास रायविंड में आयोजित होने वाले सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि नियमों के खिलाफ यात्रियों द्वारा लाए गए दो छोटे गैस सिलेंडर और स्टोव पर नाश्ता बनाते समय धमाका हो गया, जिससे ट्रेन में भीषण आग लग गई। उन्होंने रेलवे प्रशासन की चूक स्वीकार करते हुए कहा कि गैस सिलेंडरों की जांच की जानी चाहिए थी। तब्लीगी जमात के पदाधिकारियों ने हालांकि इसका खंडन करते हुए कहा कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी।

ट्रेन हादसे के कारण पाकिस्तान में एक दिन टला आजादी मार्च

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक प्रभावशाली मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में आजादी मार्च को गुरुवार को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। यह फैसला लाहौर में ट्रेन हादसे के कारण लिया गया।

दक्षिणपंथी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआइ-एफ) की ओर से यह मार्च 27 अक्टूबर को दक्षिणी सिंध से शुरू किया गया है। इसे 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचना था। मार्च के जरिये इमरान खान के त्यागपत्र की मांग की जा रही है। इमरान पर 2018 के आम चुनाव में धांधली के जरिये जीतने का आरोप लगाया गया है।

रहमान का यह भी आरोप है कि प्रधानमंत्री इमरान आर्थिक कुप्रबंधन के दोषी हैं और उनमें शासन चलाने की काबिलियत नहीं है। इस मार्च के कारण इमरान पर दबाव काफी बढ़ गया है। जेयूआइ-एफ के वरिष्ठ नेता अकरम दुर्रानी ने एक रैली में बताया कि अब यह मार्च शुक्रवार को नमाज के बाद शुरू होगा और इसमें कई वरिष्ठ विपक्षी नेता भी भाग लेंगे।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के नेता अहसन इकबाल ने भी कहा कि विपक्षी दलों ने ट्रेन हादसे के कारण अपनी रैली स्थगित करने का फैसला किया है। इमरान खान ने पद से त्यागपत्र देने से इन्कार किया है। हालांकि वह और उनकी पार्टी चुनावी सिस्टम या शासन संचालन के तौर-तरीकों में सुधार के लिए किसी भी अन्य मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार है।

चीन में लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही कम्युनिस्ट सरकार

- नैतिक गुणवत्ता में सुधार के लिए जारी किए दिशा निर्देश
- राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति वफादारी पर जोर

बीजिंग, एएफपी : चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने नागरिकों के नैतिक गुणवत्ता में सुधार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सामाजिक दायित्वों से लेकर राष्ट्रभक्ति व मातृभूमि के प्रति वफादारी और बच्चों की परवरिश के लिए माता-पिता को क्या-क्या करना चाहिए, जैसी तमाम बातें दी गई हैं।

देश के भविष्य की दिशा पर चर्चा करने के लिए इस हफ्ते यहां बंद कमरे में हुई कम्युनिस्ट सरकार के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के साथ ही ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए। सरकार ने लोगों को बताया है कि नए युग में उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और दिखावे से दूर रहना चाहिए।

नए दिशा निर्देशों में नागरिकों को इंटरनेट के इस्तेमाल, बच्चों की परवरिश, सार्वजनिक छुट्टियां मनाने और विदेश यात्रा के दौरान सभ्य व्यवहार के तौर-तरीके बताए गए हैं।

चीनी भावना, चीनी मूल्यों और चीनी शक्ति की स्थापना पर जोर दिया गया है। राष्ट्र ध्वज उठाने और राष्ट्र गीत गाते समय उचित शिष्टाचार का पालन करने की ताकीद की गई है। लोगों की वैचारिक जागरूकता और नैतिक मानक में सुधार के लिए लाइब्रेरी और यूथ सेंटर जैसे सरकारी संस्थानों को लक्षित नैतिक शिक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं।

'सेंट्रल कमीशन फॉर गाइडिंग कल्चरल एंड एथिकल प्रोग्रेस' की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग के अधिकारी झांग झियांग के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग

खास-खास दिशा निर्देश

- चीनी भावना, चीनी मूल्य और चीनी शक्ति की स्थापना पर जोर
- माता-पिता बच्चों को स्वच्छता की बातें बताएं
- ऑनलाइन पॉन से दूर रहें, ढंग से कपड़े पहनें
- विदेश यात्रा के दौरान सभ्य और शालीन व्यवहार करें
- राष्ट्रीय ध्वज उठाने और राष्ट्रगीत गाने में जरूरी शिष्टाचार का पालन करें

से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्थानीय सरकारों से बड़ों के साथ बुरा बर्ताव, आडंबरपूर्ण वैवाहिक आयोजन जैसे खराब रीति-रिवाज को खत्म करने को कहा गया है।

चीन में नैतिकता को लेकर दिशानिर्देश इससे पहले 2001 में जारी किए गए थे। उसमें धन की लोलुपता, सुखवाद, और अति व्यक्तिवाद में वृद्धि की बात कही गई थी। अट्ठारह साल बाद जारी नए दिशानिर्देशों में भी तमाम पुरानी बातें शामिल हैं।

अब अमेरिका में नहीं उड़ सकेंगे चीन में बने ड्रोन

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- संवेदनशील सरकारी परियोजनाओं में उपयोग को लेकर जताई गई है चिंता

वाशिंगटन : अमेरिका के गृह विभाग ने एलान किया है कि उसके बेड़े में शामिल चीन निर्मित सभी ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेंगे। चीन में बने ड्रोन पर भले यह अस्थायी रोक लगाई गई है, लेकिन यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब चीनी तकनीक और संवेदनशील सरकारी परियोजनाओं में इनके उपयोग को लेकर खतरे की चिंता जताई गई है। जासूसी के संदेह में ट्रंप प्रशासन चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे समेत कई प्रौद्योगिकी कंपनियों पर पहले ही रोक लगा चुका है।

अमेरिकी गृह विभाग ने बुधवार को कहा कि यह आदेश आपात मकसद जैसे जंगलों में लगी आग, राहत और बचाव के अभियानों में तैनात ड्रोन पर लागू नहीं होगा। चीन निर्मित ड्रोन की उड़ान पर रोक विभाग के ड्रोन प्रोग्राम की समीक्षा के तहत उठाया गया है। गृह विभाग ने आपात अभियानों समेत आपदा पर निगरानी के लिए हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में ड्रोन खरीदे हैं। पिछले साल आई एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के गृह विभाग के पास 531 ड्रोन हैं।

ड्रोन को लेकर यह चिंता

अमेरिका में चीनी ड्रोन को लेकर यह चिंता जताई जा रही है कि इनके जरिये चोरी-छुपे डाटा जुटाकर चीन की खुफिया एजेंसियों के पास भेजा जा सकता है।

अमेरिकी सेना चीनी ड्रोन पर लगा चुकी है रोक

अमेरिका की सेना ने साल 2017 में ही चीनी कंपनी डीजेआइ द्वारा निर्मित ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने गत मई में देश की कंपनियों को आगाह किया था कि चीन निर्मित ड्रोन संवेदनशील फुटेज तीसरे पक्ष को मुहैया करा सकते हैं।

अमेरिका के 42 राज्यों और क्षेत्रों में इनकी दस हजार से ज्यादा उड़ानें हो चुकी हैं। रिपोर्ट में हालांकि यह नहीं बताया गया कि विभाग के पास चीन निर्मित कितने ड्रोन हैं।

बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी नेता के मृत्युदंड पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी के शीर्ष नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम की मौत की सजा को बरकरार रखा है। इस्लाम को युद्ध अपराधों की सुनवाई करने वाले इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (आइसीटी) ने 30 दिसंबर, 2014 को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे उसने देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश महमूद हुसैन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की चार सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को इस्लाम की याचिका खारिज कर दी।

जमात-ए-इस्लामी के पूर्व सहायक महासचिव इस्लाम ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। उस पर 1400 से ज्यादा लोगों की हत्या, कई महिलाओं से दुष्कर्म, अपहरण और यातनाएं देने के आरोप थे। इस्लाम को काशिमपुर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। बांग्लादेश में युद्ध अपराधों के तहत अब तक छह दोषियों की मौत की सजा पर अमल हो चुका है। इनमें से पांच जमात-ए-इस्लामी के सदस्य और एक विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का नेता था।

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ी

- प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग प्रक्रिया को औपचारिक रूप प्रदान किया
- जांच के अगले चरण में हाउस इंटेलीजेंस कमेटी में होगी खुली सुनवाई

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच सार्वजनिक सुनवाई की ओर बढ़ गई है। अमेरिकी संसद कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में सदस्यों ने गुरुवार को पहली बार मतदान के जरिए महाभियोग प्रक्रिया को औपचारिक रूप प्रदान किया।

स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा, 'आज सदन एक कदम आगे की ओर बढ़ा है जहां हमने सदन की खुफिया समिति द्वारा संचालित खुली सुनवाई के लिए प्रक्रिया स्थापित की है ताकि जनता अपने लिहाज से तथ्यों को देख सके।' सदन ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए 196 के मुकाबले 232 मतों से मंजूरी दी। जांच के अगले चरण में हाउस इंटेलीजेंस कमेटी में खुली सुनवाई होगी। इसमें गवाह और दस्तावेजी सबूत पेश किए जाएंगे तथा रिपब्लिकनों को साक्ष्यों को चुनौती देने की अनुमति मिलेगी। इसके बाद मामला हाउस ज्यूडिशरी कमेटी में जाएगा जहां ट्रंप और उनके वकील साक्ष्यों को चुनौती दे पाएंगे।

यदि ट्रंप के खिलाफ मामले में मजबूती पाई जाती है तो कमेटी उनके खिलाफ औपचारिक आरोप-महाभियोग संबंधी अनुच्छेद तय करेगी जिस पर पूरा सदन मतदान करेगा। प्रक्रिया इस साल के अंतिम महीनों में पूरी हो सकती है। डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा में आरोप संबंधी अनुच्छेदों को मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। इसके बाद मामला ट्रंप को हटाने के लिए सीनेट में जाएगा जहां रिपब्लिकन बहुमत में हैं।

इस बीच, रूस और यूरोपीय मामलों पर ट्रंप के पूर्व शीर्ष सलाहकार टिम मोरिसन भी गुरुवार को इस मामले में गवाही के लिए संसद की समिति के सामने पहुंचे। हालांकि, उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक दिन पहले ही अपना पद छोड़ा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने खिलाफ महाभियोग जांच को सार्वजनिक सुनवाई की ओर ले जाने के डेमोक्रेट्स के प्रयासों के बीच गुरुवार को अपने रिपब्लिकन साथियों से अपने साथ खड़े रहने को कहा।

जापान में 600 साल पुराना ऐतिहासिक महल आग से तबाह

टोक्यो, एएफपी : जापान के दक्षिणी द्वीप ओकिनावा पर स्थित ऐतिहासिक शूरी महल में गुरुवार को भीषण आग लग गई। विश्व धरोहर में शुमार इस महल का बड़ा हिस्सा इस आग में तबाह हो गया। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने साल 2000 में इस महल समेत रयूकू साम्राज्य के विभिन्न स्थलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिया था।

माना जाता है कि शूरी महल का इस्तेमाल करीब 1400 ईसवी से हो रहा है। रयूकू साम्राज्य 12वीं से लेकर 17वीं सदी तक था। महल के मौजूदा ढांचे के ज्यादातर हिस्से का मूल योजना और पुरानी तस्वीरों के आधार पर पुनर्निर्माण किया जा रहा था। स्थानीय दमकल विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि आग महल परिसर के 4,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैल गई थी। दमकल विभाग के एक अन्य प्रवक्ता दैसुक फुरुगेन ने कहा, 'सभी (तीन) मुख्य इमारतें जल गईं और कुछ नहीं बचा। आग बहुत भीषण थी। दमकलकर्मियों को इस पर काबू पाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।' अधिकारियों को महल में आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

नई जंग

सोशल मीडिया साइट के सीईओ जैक डॉरसी को इसके लिए अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेट्स की मिल रही वाहवाही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चढ़ीं त्योरियां

ट्विटर पर नवंबर से राजनीतिक विज्ञापन बंद, फेसबुक पर रहेंगे जारी

- डारसी ने कहा, 22 नवंबर से लागू होगी नई नीति
- कहा, राजनीतिक संदेश की पहुंच अर्जित होनी चाहिए न कि खरीदी हुई
- जुकरबर्ग ने कहा, लोकतंत्र के लिए नहीं है ठीक

सैन फ्रांसिस्को, एजेंसियां : सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को लेकर एक नए किस्म की जंग शुरू है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने जहां अगले महीने से अपने प्लेटफार्म पर विश्व भर में राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का एलान किया है। अमेरिकी कंपनी के सीईओ जैक डॉरसी को इसके लिए अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेट्स की वाहवाही मिलनी शुरू हो गई है, जबकि रिपब्लिकन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से त्योरियां चढ़ीं हैं। दूसरी ओर, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने से इन्कार करते हुए कहा कि यह विज्ञापन उम्मीदवारों और उनके समर्थक समूहों की आवाज होते हैं।

अमेरिकी कंपनी ट्विटर के सीईओ जैक डॉरसी ने गुरुवार को बताया कि उनकी कंपनी थोड़ी छूट के साथ अपनी अंतिम नीति आगामी 15 नवंबर को साझा करेगी। इस दौरान मतदाताओं के पंजीकरण संबंधी विज्ञापनों आदि की छूट रहेगी। लेकिन नई नीति को 22 नवंबर से लागू किया जाएगा। डॉरसी ने राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध को उचित ठहराते हुए कहा कि उनकी कंपनी का

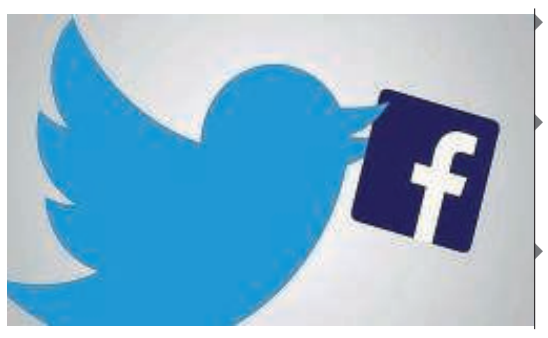

मानना है कि राजनीतिक संदेश की पहुंच अर्जित होनी चाहिए, खरीदी हुई नहीं। जब लोग किसी एकाउंट को फॉलो करते हैं या रीट्वीट करते हैं तो एक राजनीतिक संदेश की पहुंच अर्जित होती है। लेकिन उस संदेश के लिए रकम चुकाने से वह फैसला नदारत हो जाता है।

42 वर्षीय डॉरसी ने कहा कि इंटरनेट के विज्ञापन बेहद सशक्त और प्रभावशाली होते हैं। लेकिन इस शक्ति के साथ राजनीति के क्षेत्र में बड़ा खतरा आ जाता है। चूंकि इससे वोटों को प्रभावित करके लाखों लोगों के जीवन पर असर डाला जाता है। दूसरी ओर, इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धी कंपनी फेसबुक के सीईओ ने राजनीतिक विज्ञापनों को अपनी सोशल मीडिया साइट पर बंद न करने का बचाव करते हुए कहा, 'मेरे विचार से लोकतंत्र में यह उचित नहीं कि निजी कंपनियों को यह अधिकार है कि वह राजनेताओं या खबरों को बाधित करें। हालांकि पहले हमने इस बात पर विचार किया कि ऐसे विज्ञापनों को नहीं लिया जाए। पर फिलहाल हमने राजनीतिक विज्ञापनों को जारी रखने का फैसला लिया है।' उन्होंने गूगल, यूट्यूब, केबिल नेटवर्क और राष्ट्रीय प्रसारणकर्ताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि वह भी अपने यहां ऐसे विज्ञापन देते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों और उनके समर्थक समूहों से भी आने वाला संदेश अहम है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कारोबार के लिहाज से भी राजनीतिक विज्ञापनों का प्रतिशत बेहद कम है। हमारे हिसाब से अगले साल राजनीतिक विज्ञापनों से मिलने वाला राजस्व 0.5 फीसद से भी कम होगा।

भारत में ट्विटर यूजर	करीब 3.5 करोड़
अमेरिका में ट्विटर यूजर	4.86 करोड़
विश्व में ट्विटर यूजर	33 करोड़
भारत में फेसबुक यूजर	**30.38 करोड़**
अमेरिका में फेसबुक यूजर	16.95 करोड़
विश्व में फेसबुक यूजर	100 करोड़

फेसबुक बनाम ट्विटर

जिस तरह से भारत में फेसबुक आम जनता (मासेज) और ट्विटर प्रबुद्ध वर्ग (क्लासेज) पर अपनी पकड़ रखता है। अमेरिका समेत पूरे विश्व में इन दोनों सोशल नेटवर्किंग साइटों की कमोबेश यही स्थिति है। इसी साल 24 अप्रैल को जारी किए गए पीईडब्लू के शोध के अनुसार ट्विटर का इस्तेमाल 22 फीसद वयस्क अमेरिकी ही करते हैं। जबकि प्रमुख सोशल नेटवर्क कंपनी फेसबुक का इस्तेमाल 69 फीसद अमेरिकी करते हैं। अमेरिका में ट्विटर यूजर युवा अधिक हैं और ज्यादातर डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक हैं। वह अधिक शिक्षित और अधिक आय वाले लोग हैं। जबकि भारत में फरवरी 2019 तक पूरी आबादी के 22 फीसद भारतीय फेसबुक पर हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक फेसबुक यूजर्स इसी देश में हैं। इन यूजर्स में पुरुष (77.8 फीसद) अधिक हैं। फेसबुक यूजर्स में अधिकांश का आयुवर्ग 25 साल से 34 साल के बीच है। भारत में सोशल मीडिया साइटों का उपयोग ज्यादा होने का एक कारण यहां की जनसंख्या भी है।

लोगों तक विज्ञापन के जरिए पहुंचाए गए अत्यधिक आशावादी संदेश असल में थोपे जाते हैं। हमारा मानना है कि इन फैसलों में धन के बल पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
-जैक डॉरसी, सीईओ ट्विटर

राजस्व के लिए हम राजनीतिक विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। बेहतर होगा कि काम में पारदर्शिता बढ़ाई जाए। फेसबुक पर विज्ञापन किसी भी और जगह से अधिक पारदर्शी हैं।
-मार्क जुकरबर्ग, सीईओ फेसबुक

मेरा कोई भी सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है। मेरे नाम से फेक अकाउंट बनाए गए हैं।
— विनोद राय, सीओए के प्रमुख

सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया की बार्टी

शेनझेन (चीन), आइएएनएस : विश्व नंबर-एक ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने दो बार की विंबलडन चैंपियन चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा को हराकर डब्ल्यूटीए फाइनल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। फ्रेंच ओपन चैंपियन बार्टी ने एक घंटे 29 मिनट तक चले मुकाबले में क्वितोवा को 6-4, 6-2 से मात दी। बार्टी को सिडनी ओपन के फाइनल और ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में क्वितोवा से हार का सामना करना पड़ा था।

प्रदूषण के साथ टी-20

- दो साल में भी विनोद राय की अगुआई वाली सीओए नहीं बदल पाई थी अपनी नीति
- दिल्ली में प्रदूषण के बीच रविवार को होने वाले मैच को देखने वालों को भी होगी परेशानी

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

दो साल पहले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) को पत्र लिखकर प्रदूषण की स्थिति में यहां मैच नहीं कराने को कहा था। इसके बाद बीसीसीआइ ने कहा था कि हम इसको लेकर नई नीति बनाएंगे जिससे प्रदूषण के समय खिलाड़ियों को मैदान में नहीं उतरना पड़ा लेकिन विनोद राय की अध्यक्षता वाली सीओए ने इसको लेकर कुछ नहीं किया और बीसीसीआइ से विदा हो गई। अब सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाले बोर्ड को इस दिशा में काम करना होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में पहला टी-20 मुकाबला खेला जाएगा।

वायु प्रदूषण की वजह से कई पर्यावरणविद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मैच को लेकर चिंता जताई थी और इसे दिल्ली की जगह कहीं ओर कराने की मांग की थी। बीसीसीआइ के एक पूर्व पदाधिकारी ने कहा कि 2017 में दिसंबर में भारत और श्रीलंका के बीच तत्कालीन फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में टेस्ट मैच हुआ था और उस दौरान ही दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अलावा कई डॉक्टरों ने बीसीसीआइ को ईमेल लिखकर परिस्थितियों से अवगत कराया था। उन्होंने बताया था कि ऐसी परिस्थितियों में दिल्ली में मैच खेलना खिलाड़ियों के लिए बेहद हानिकारक है। उस समय सीओए ही बीसीसीआइ का प्रशासन देख रहा था और दुर्भाग्यवश उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया और ऐसे ही समय दिल्ली एवं क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को मैच आयोजित कराने को दे दिया जब देश की राजधानी में प्रदूषण प्रचंड रूप धारण कर लेता है। निश्चित तौर पर यह बड़ी चूक है और अब स्थितियां ऐसी हैं कि हम मैच को कहीं स्थानांतरित भी नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए ही परेशानी का सबब नहीं है बल्कि हजारों दर्शक जो यहां मैच देखने आएंगे उनके लिए भी तकलीफदेह है। देखिये क्या होता है। दिवाली में पटाखे जलाने और हरियाणा-पंजाब में पराली जलाए जाने के बाद दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।

अभ्यास के वक्त मास्क पहने नजर आए लिटन दास

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की हवा इस समय बेहर गंभीर स्थिति में है और गुरुवार को फिरोजशाह कोटला में बांग्लादेश टीम के पहले अभ्यास सत्र में उनके बल्लेबाज लिटन दास को मास्क पहनकर अभ्यास करते देखा गया लेकिन भारतीय टीम के मौजूदा टी-20 कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि तीन नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टी-20 मुकाबले में वायु प्रदूषण कोई समस्या खड़ी करेगा। रोहित ने कहा कि मैं अभी आया हूं और मेरे पास आकलन करने का समय नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि यह मुकाबला तीन नवंबर को खेला जाएगा और हम खेल रहे हैं। रोहित ने कहा कि जब हमने श्रीलंका के खिलाफ यहां टेस्ट मैच खेला था तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मुझे भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई थी। रोहित 2017 में खेले गए टेस्ट की बात कर रहे थे, जहां श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने मास्क पहनकर मैच खेला था। वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंचने की वजह से 20 मिनट तक खेल रोक भी दिया गया था। गुरुवार को बांग्लादेश टीम के पहले अभ्यास सत्र में लिटन ने 10 मिनट तक मास्क पहना। हालांकि इस दौरान किसी अन्य खिलाड़ी ने मास्क नहीं पहना। स्टेडियम में धुएं की हल्की परत को आसानी से देखा जा सकता था। लिटन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्होंने कोई मास्क नहीं पहना था।

अरुण जेटली स्टेडियम में अभ्यास करते मुस्तफिजुर रहमान। प्रेट्र

मुझे कुछ निजी समस्या थी, इसी वजह है मैंने मास्क पहना था। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। हमारी टीम मजबूत है और टीम में शाकिब अल हसन के रहने की कमी महसूस नहीं होगी।
लिटन दास, बांग्लादेशी बल्लेबाज

प्रदूषण का स्तर खतरनाक

नई दिल्ली: बांग्लादेशी टीम जिस समय स्टेडियम में अभ्यास कर रही थी, उस वक्त वहां वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक था। उस समय एयर इंडेक्स 400 के पार था जो फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है।

बांग्लादेश के पास भारत को हराने का अच्छा मौका : लक्ष्मण

मुंबई: भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश के पास अपनी बल्लेबाजी में गहराई की बदौलत रविवार से शुरू होने वाली टी-20 सीरीज में मजबूत भारत को हराने का बढ़िया मौका है। सीरीज का शुरुआती मैच दिल्ली में खेला जाएगा, जिसके बाद राजकोट में सात नवंबर को और नागपुर में 10 नवंबर को मैच होंगे। टी-20 सीरीज के बाद दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें ईडन गार्डेंस में मेजबान भारत 22 नवंबर से गुलाबी गेंद से ऐतिहासिक डे-नाइट मैच खेलेगा। लक्ष्मण ने कहा कि बांग्लादेश के लिए यह भारत को उसकी सरजमीं पर हराने का सर्वश्रेष्ठ मौका है, क्योंकि उनका बल्लेबाजी लाइन-अप काफी मजबूत है। हालांकि उनके गेंदबाजी विभाग में दबाव सबसे ज्यादा मुस्तफिजुर रहमान पर होगा, क्योंकि टीम में स्पिनरों की तुलना में तेज गेंदबाजी लाइन-अप थोड़ा अनुभवहीन लगता है। उन्होंने कहा कि मुस्तफिजुर को अहम भूमिका निभानी होगी और नई गेंद से जल्दी विकेट चटकाने होंगे। टीम में विराट कोहली नहीं है तो मध्य क्रम में थोड़ा अनुभव कम होगा। लक्ष्मण ने कहा कि टीम इंडिया में अब समय युवाओं के लिए जिम्मेदारी निभाकर मैच जीतने के बाद भारत के लिए सीरीज जीतने का है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर और युजवेंद्रा सिंह चहल भारत के गेंदबाजी विभाग के लिए अहम होंगे, क्योंकि जहां मैच खेले जाने हैं वे स्थल स्पिनरों के मुफीद हैं। इस गेंदबाजी लाइन अप में इतना अनुभव नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि युजवेंद्रा तीनों मैच में खेलेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अन्य युवा खिलाड़ियों जैसे क्रुणाल पांड्या के लिए भी कठिन ओवर में बेहतर करके मैच जीतने का यह अच्छा मौका होगा। लक्ष्मण ने सीरीज में नतीजे के बारे में कहा कि मुझे लगता है कि यह 2-1 से भारत के पक्ष में होगा। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल अच्छी फॉर्म में हैं और शिखर धवन भी खुद को स्थापित करने में लगे हैं इसलिए मैं इस सीरीज को जीतने के लिए भारतीय बल्लेबाजी का समर्थन कर रहा हूं।

गुलाबी गेंद से खेलने का अनुभव काम आएगा : रोहित शर्मा

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम 22 से 26 नवंबर तक कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डेंस स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ दिन-रात का अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। भारतीय खिलाड़ियों में विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और मुहम्मद शमी को ही घरेलू क्रिकेट में दिन-रात टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है। दोनों खिलाड़ी 2016 में ईडन गार्डेंस में सीएबी के सुपर लीग फाइनल में दिन-रात क्रिकेट खेल चुके है लेकिन अब टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा है कि उन्हें दलीप ट्रॉफी में गुलाबी गेंद से खेलने का अनुभव हासिल है और उनका यह अनुभव आगामी दिन-रात टेस्ट मैच में मदद करेगा।

रोहित ने गुरुवार को कहा कि मैं दिन-रात टेस्ट मैच को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं दलीप ट्रॉफी में गुलाबी गेंद से एक मैच खेल चुका हूं और मुझे इसका अच्छा अनुभव हासिल हुआ था। अब मौका फिर से आया है तो मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा और हम मैच जीतेंगे।

बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज से कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है और रोहित को टीम की कमान सौंपी गई है। रोहित ने कहा कि टीम का नेतृत्व करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि ये चीजें हमारे हाथ में नही हैं। एक हो या 100, यह सम्मान की बात है।

घरेलू दलीप ट्रॉफी में गुलाबी गेंद से डे-नाइट मुकाबला खेल चुके हैं शर्माए कहा कप्तानी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूं

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा • एएनआइ

मैं पहले भी टीम की कप्तानी कर चुका हूं और मुझे इसका अच्छा अनुभव है। मैं यह नहीं सोचता कि मुझे कितने समय तक कप्तान बने रहना है। जब भी मुझे टीम की कप्तानी करने का मौका मिलता है तो मैं इसका आनंद लेता हूं। रोहित ने साथ ही महेंद्र सिंह धौनी के भविष्य पर भी कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। आप ही इन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं।

भविष्य में दिवाली के बाद उत्तर भारत को मैच देने पर करेंगे विचार : गांगुली

कोलकाता, प्रेट्र: बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि राजधानी में वायु की गुणवत्ता खराब होने के बावजूद बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआती टी-20 मैच को रद नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में दिवाली के बाद मैचों के आयोजन के लिए उत्तर भारत के स्थलों पर विचार नहीं किया जाएगा। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के साथ दिवाली पर पटाखे जलाने से हर साल एनसीआर में हवा की गुणवत्ता का स्तर खराब होता है।

गांगुली ने ईडन गार्डेंस में कहा कि अब बहुत देर हो गई है क्योंकि मैच की तैयारियों के लिए काफी चीजें की जाती हैं जैसे टिकट बिक्री और दर्शक, सब कुछ इसलिए अंतिम समय में मैच रद करना संभव नहीं है। गांगुली ने कहा कि भविष्य में वह ज्यादा व्यावहारिक रहेंगे। हम चर्चा करेंगे। भविष्य में जब हम कार्यक्रम बनाएंगे, विशेषकर सर्दियों के दौरान उत्तरी हिस्से में तो हमें और ज्यादा व्यावहारिक होना होगा। हमने पिछले दो दिन में दिल्ली में अधिकारियों से बात की। वे मैच के होने की उम्मीद कर रहे हैं। मैच पहले ही तय कर दिया गया था इसलिए हमें इसे अंतिम समय में रद नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने 23 अक्टूबर को ही पद संभाला था। मैं जानता हूं कि दिवाली के बाद उत्तर भारत में थोड़ी मुश्किल होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबकुछ ठीक रहे। मैंने मैदानकर्मियों से बात की और उन्होंने कहा कि एक बार धूप आ जाएगी तो यह ठीक हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के दिनों में वह मेरा मैदानकर्मी था। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, उसने कहा कि सब ठीक होगा। हम इस मैच को कराना चाहते हैं।

झटका

- कहा, कम समय में दिल्ली से मैच शिफ्ट करना नहीं था मुमकिन
- भारतीय कोच शास्त्री को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने की बात की

शास्त्री को एनसीए में जिम्मेदारी दी जाएगी: गांगुली ने कहा कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में एक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि मुख्य कोच रवि शास्त्री ज्यादा से ज्यादा समय इसमें बिता सकें। बीसीसीआइ बेंगलुरु में ही एक बड़े भू-भाग पर एक शानदार क्रिकेट अकादमी बना रहा है। गांगुली ने एनसीए के अधिकारियों के साथ उस प्रस्तावित भूमि का भी मुआयना किया जहां एनसीए की नई अकादमी बनने वाली है।

प्रधानमंत्री मोदी, सचिन को बुलाने का प्रयास जारी : कोलकाता टेस्ट के लिए गांगुली ने कहा कि यह मैच भारत के लिए खास है और इसके लिए खास लोगों को कोलकाता बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियां शामिल हैं। हम इसे एक शानदार इवेंट के तौर पर तब्दील करेंगे। 3-4 दिनों में आपको पूरा खाका मिल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। गांगुली ने कहा कि इस मैच के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। साथ ही बंगाल क्रिकेट संघ साल 2000 में बांग्लादेश के साथ पहला टेस्ट खेलने वाली टीम के सदस्यों को भी सम्मानित करेगा। इनमें सचिन भी हैं।

नवंबर में हो सकती है एजीएम: गांगुली ने कहा कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में बोर्ड की एजीएम हो सकती है। अंतिम तारीख की पुष्टि होना बाकी है। सीओए प्रमुख विनोद राय ने कहा था कि एजीएम 23 अक्टूबर को होगी लेकिन अब गांगुली को इस संबंध में अंतिम फैसला लेना है। संभावना है कि एजीएम का आयोजन कोलकाता में होगा क्योंकि भारत को 22 से 26 नवंबर तक कोलकाता में ही बांग्लादेश के साथ अपना पहला दिन-रात का टेस्ट मैच खेलना है।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना आज रूस से

भुवनेश्वर, प्रेट्र: भारतीय पुरुष हॉकी टीम को शुक्रवार को यहां निचली रैंकिंग की रूस की टीम के खिलाफ होने वाले दो चरण के ओलंपिक क्वालीफायर में आत्ममुग्धता से बचना होगा, जबकि महिला टीम को अमेरिका की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा।

दोनों भारतीय टीमें टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट कटाने से महज दो मैच दूर हैं। मनप्रीत सिंह की अगुआई वाली टीम को हालांकि 22वीं रैंकिंग की रूस के रूप में आसान प्रतिद्वंद्वी से भिड़ना है, जबकि महिलाओं को एफआइएच ओलंपिक क्वालीफायर के अंतिम दौर में अमेरिकी टीम का सामना करना है। दोनों टीमें शुक्रवार और शनिवार को लगातार दो मैच खेलेंगी। दो मैचों के क्वालीफायर में विजेता टीम (पुरुष और महिला टीम में से) 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए अपना स्थान सुनिश्चित कर लेगी।

पांचवीं रैंकिंग पर काबिज भारतीय पुरुष टीम को रूस के खिलाफ आसान मुकाबले की उम्मीद है, लेकिन कोच ग्राहम रीड इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि एक खराब दिन से भारत का ओलंपिक सपना टूट सकता है। इसलिए आत्ममुग्धता से भारतीय टीम को अगले दो दिन तक बचना होगा। पिछले 12 महीनों में भारतीय टीम ने रीड के मार्गदर्शन में रक्षात्मक पहलू में काफी सुधार किया है। सुरेंद्र कुमार और जूनियर विश्व विजेता टीम के सदस्य हरमनप्रीत सिंह की बदौलत हाल में भारतीय टीम का डिफेंस मजबूत दिखता है। वहीं, बैकलाइन में ड्रैगफ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह और बीरेंद्र लाकड़ा की वापसी से मजबूती मिलेगी। मिडफील्ड में कप्तान मनप्रीत के साथ हार्दिक सिंह, नीलकांत शर्मा व विवेक सागर प्रसाद मौजूद होंगे, जबकि गोल करने की जिम्मेदारी मंदीप सिंह, आकाशदीप सिंह, एसवी सुनील, रमनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय और सिमरनजीत सिंह पर होगी। अनुभवी पीआर श्रीजेश और कृष्ण बहादुर पाठक गोलकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

महिला टीम के लिए स्थिति बिलकुल उलट है, क्योंकि उन्हें दुनिया की 13वें नंबर की टीम अमेरिका से भिड़ना है, जिसके खिलाफ उनका जीत-हार का रिकॉर्ड 4-22 का है। रानी के अलावा ड्रैगफ्लिकर गुरजीत कौर, युवा फॉरवर्ड लालरेमसियामी व गोलकीपर सविता के प्रदर्शन पर टीम का भाग्य निर्भर होगा।

ओलंपिक क्वालीफायर

- मनप्रीत की अगुआई वाली टीम को आत्ममुग्धता से बचना होगा
- रानी की अगुआई वाली महिला टीम के सामने होगी अमेरिका की चुनौती

बीसीसीआइ लोकपाल के सामने 12 नवंबर को द्रविड़ की पेशी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: बीसीसीआइ के लोकपाल डीके जैन ने पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को उनके खिलाफ लगाए गए हितों के टकराव के मामले में 'आगे की सुनवाई और स्पष्टीकरण' के लिए 12 नवंबर को दूसरी बार निजी तौर पर पेश होने को कहा है। 46 वर्षीय पूर्व भारतीय कप्तान द्रविड़ ने इससे पहले 26 सितंबर को मुंबई में निजी सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा था।

एमपीसीए के आजीवन सदस्य संजय गुप्ता ने द्रविड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख के रूप में उनकी मौजूदा भूमिका और इंडिया सीमेंट्स का अधिकारी होने के कारण हितों के टकराव का आरोप लगाया था। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने बताया कि जैन ने बुधवार रात द्रविड़ को पत्र लिखकर उन्हें नई दिल्ली में 12 नवंबर को सुनवाई के लिए पेश होने को कहा। गुप्ता का पक्ष भी सुना जाएगा। द्रविड़ फिलहाल एनसीए में निदेशक हैं। इसके अलावा वह इंडिया सीमेंट्स समूह के उपाध्यक्ष भी हैं। इंडिया सीमेंट्स के पास आइपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स का स्वामित्व है। एनसीए में भूमिका मिलने से पहले द्रविड़ भारत-ए और अंडर-19 टीमों के मुख्य कोच भी रहे।

अनुष्का ने कड़वी की इंजीनियर की चाय

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पूर्व भारतीय विकेटकीपर फारुख इंजीनियर ने दावा किया है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली की पत्नी व भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा चयनकर्ताओं के साथ बैठती हैं और एक चयनकर्ता ने इस साल विश्व कप के दौरान उन्हें चाय परोसी। इंजीनियर के इस दावे के बाद गुस्साई अनुष्का ने इसे 'इरादतन बोला गया झूठ' बताया, जबकि चयनसमिति के एक सदस्य ने इसे 'दुर्भावनापूर्ण' कहा है।

भारत के लिए 46 टेस्ट खेलने वाले 82 साल के इंजीनियर ने एक अखबार से बातचीत के दौरान एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली भारत की पांच सदस्यीय चयनसमिति की साख का उपहास उड़ाया, जिसमें शरनदीप सिंह, जतिन परांजपे, गगन खोड़ा और देवांग गांधी भी शामिल हैं। इंजीनियर ने दावा किया था कि उन्होंने इन पांच लोगों में से एक को इंग्लैंड में विश्व कप के दौरान अनुष्का को चाय परोसते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने किसी का नाम जाहिर नहीं किया।

चयनसमिति के एक सदस्य से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने इस दावे का खंडन किया, जबकि अनुष्का ने एक लंबा बयान जारी किया, जिसमें लिखा कि वह भारतीय क्रिकेट से जुड़े विवादों में अपना नाम अब और नहीं घसीटने देंगी। चयनसमिति के एक सदस्य ने कहा, 'विश्व कप के दौरान वहां बॉक्स में कोई भी चयनकर्ता नहीं बैठा हुआ था जहां भारतीय कप्तान की पत्नी बैठी थीं और यह निश्चित रूप से बकवास है।

कप्तान विराट कोहली की पत्नी अनुष्का व पूर्व विकेटकीपर फारुख इंजीनियर • ट्विटर

अनुष्का तो अपने बयान में और ज्यादा उग्र हो गईं। उन्होंने कहा, 'इरादतन बोले गए झूठ का यह ताजा मामला है कि मुझे विश्व कप मैच के दौरान चयनकर्ता ने चाय परोसी थी। मैं विश्व कप के दौरान सिर्फ एक मैच के लिए गई थी और फैमिली बॉक्स में बैठी थी, ना कि चयनकर्ताओं के बॉक्स में। यदि आप चयनसमिति पर और उनकी योग्यता पर सवाल उठाना चाहते हैं तो कृपया ऐसा करें क्योंकि यह आपकी राय है, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं घसीटें, अपने दावे की पुष्टि करें और अपनी राय को सनसनीखेज बनाएं। मैं इस तरह की बातचीत में किसी को भी अपने नाम का इस्तेमाल करने की स्वीकृति नहीं देती हूं।' अनुष्का ने उन पिछले विवादों का भी जिक्र किया, जिनमें वह उलझी रही थीं। उन्होंने कहा, 'मैं हर बार चुप रही। मुझे मेरे ब्वॉयफ्रेंड और अब मेरे पति विराट कोहली के प्रदर्शन के लिए दोष दिया गया और साथ ही भारतीय क्रिकेट से जुड़ी सबसे ज्यादा आधारहीन चीजों के लिए भी मुझे ही दोष दिया गया।'

अनुष्का ने एक पिछली रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें दावा किया गया था कि बीसीसीआइ ने उनके कार्यक्रम के आधार पर खिलाड़ियों की पत्नियों और पार्टनरों के लिए रोस्टर तय किया। अनुष्का ने कहा कि वह कोहली के साथ रहने के लिए अपनी फ्लाइट की टिकट खुद खरीदती हैं। कोहली ने भी पूर्व में अपनी पत्नी पर लगे आरोपों को शर्मनाक बताया था। अनुष्का ने एक और मीडिया रिपोर्ट की खिंचाई की, जिसमें पिछले साल यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त के साथ उनके टीम इंडिया की ग्रुप तस्वीर का हिस्सा बनने के लिए बीसीसीआइ की आलोचना की गई थी।

अनुष्का ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में उन्हें विवादों से जोड़ने वाली सभी खबरें 'पीछे की ओर ले जाने वाली, भयानक, दुर्भावनापूर्ण और विद्वेषपूर्ण' हैं। उन्होंने कहा, 'मैं ना तो किसी के विचार या विश्वास या एजेंडा द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मोहरा हूं और ना होऊंगी। अगली बार जब आप किसी व्यक्ति या बोर्ड या यहां तक कि मेरे पति को बदनाम करने के लिए मेरे नाम का उपयोग करना चाहते हैं तो इसे तथ्यों और प्रमाणों के साथ करें। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन हो, क्योंकि मैं एक आत्मनिर्भर व स्वतंत्र महिला हूं, जो सिर्फ एक क्रिकेटर की पत्नी बनती है और रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि मैं कॉफी पीती हूं।'

विवाद

- पूर्व विकेटकीपर ने कहा था, अनुष्का को चाय पिला रहा था चयनकर्ता
- भारतीय कप्तान की पत्नी ने इन दावों को झूठा बताया

वेस्टइंडीज में बिना भत्ते के फंसी भारतीय महिला टीम

नई दिल्ली, जेएनएन: तीन वनडे और पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेलने गई भारतीय महिला टीम दैनिक भत्ता न मिलने के कारण वेस्टइंडीज में फंस गई। इसके बाद बीसीसीआइ के नए अधिकारी जल्द ही हरकत में आए और मिताली राज एवं उनकी टीम के खाते में भत्ते जमा कराए।

जहां महिला क्रिकेट के प्रभारी सबा करीम के रवैए के कारण लड़कियों को बिना भत्ते के कारण सीरीज खेलने जाना पड़ा तो वहीं नए अधिकारियों ने बुधवार को जल्द से जल्द खिलाड़ियों के खाते में राशि जमा कराकर परेशानी का हल निकाला। एक बीसीसीआइ अधिकारी ने कहा कि सीओए के तहत काम को लेकर बहुत बातें हुई। उसके बावजूद ऐसा दिन देखना पड़ा जब हमारी लड़कियां बिना पैसों के विदेशी सरजमीं पर मौजूद थीं। इसका कौन जिम्मेदार है? यदि पूरी वित्तीय प्रक्रिया 18 सितंबर को शुरू की गई थी, तो दस्तावेजों के पूरा होने में 24 अक्टूबर तक का समय क्यों लगा? नए पदाधिकारियों ने मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो लड़कियों को बिना भत्ते के संघर्ष करते हुए देखते।

समस्या ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट के हर दिन का आखिरी सत्र हो सकता है गेंदबाजों के लिए मुश्किलों भरा

कैब की चिंता, कहीं होश न उड़ा दे ओस

विशाल श्रेष्ठ • कोलकाता

यूं तो टेस्ट मैच के हर दिन के आखिरी सत्र को गेंदबाजों को विकेट दिलाने वाला माना जाता है लेकिन ईडन गार्डेंस स्टेडियम में भारत-बांग्लादेश के बीच 22 नवंबर से शुरू होने वाले ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट के प्रत्येक दिन का आखिरी सत्र गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला साबित हो सकता है। वजह है ओस। भारतीय क्रिकेट में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ने जा रहे इस टेस्ट मैच की तैयारियों में जुटा बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) भले लाख दावा करे कि मैच के दिनों में ओस को लेकर कोई समस्या नहीं होगी लेकिन अंदरखाने उसे भी यह चिंता सता रही है कि कहीं ओस उसके होश न उड़ा दे। इसे लेकर कैब में बैठकों का दौर चल रहा है। कैब मैच के हर दिन का खेल जल्दी शुरू कराने की कोशिश में है ताकि यह ज्यादा रात तक न खिंच पाए। इस बाबत बीसीसीआइ से अनुरोध भी किया जाएगा।

चूंकि बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ईडन के हालात से भली-भांति वाकिफ हैं, ऐसे में मैच जल्दी शुरू कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगने में देरी की संभावना नहीं है। गौरतलब है कि ईडन में डे-नाइट वनडे मैचों के समय ओस को लेकर पहले भी काफी समस्या हो चुकी है। मैदानकर्मियों को रस्सियों के जरिये ओस सुखाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। गेंदबाज बॉल पर ग्रिप बनाने के लिए उसे पोछते देखे गए हैं। ऐसे में डे-नाइट टेस्ट में रात के समय किसी भी गेंदबाज के लिए लंबा स्पेल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

कैब के सचिव अभिषेक डालमिया ने कहा कि डे-नाइट वनडे की तरह डे-नाइट टेस्ट दोपहर 2.30 बजे से शुरू नहीं कराया जाएगा। इसे दोपहर 1.30 बजे से शुरू कराने की कोशिश है ताकि रात 8.30 बजे तक दिन का खेल खत्म कराया जा सके। इससे स्टेडियम आने वाले दर्शकों को घर लौटने में भी सहूलियत होगी।'

ईडन गार्डेंस के क्यूरेटर सुजन मुखर्जी ने भी कहा कि मैच जल्दी शुरू कराया जाएगा, जिससे दिन का खेल जल्दी खत्म भी होगा इसलिए ओस को लेकर ज्यादा समस्या नहीं होगी। सुजन ने कहा कि अगर ओस को लेकर समस्या होगी भी तो उससे निपटने के लिए स्टेडियम में ट्रीटमेंट स्प्रे और मोपिंग जैसी उन्नत व्यवस्था है। ओस हटाने के लिए सुपर-सोपर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बंगाल के पूर्व कप्तान संबरन बनर्जी ने कहा कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि नवंबर में ओस को लेकर समस्या नहीं होगी।

...तो घाटे में रहेंगे अश्विन-जडेजा

कोलकाता: ईडन में अगर ओस की समस्या होती है तो रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा जैसे भारतीय स्पिनर सबसे ज्यादा घाटे में रहेंगे। ओस की वजह से गीली गेंद पर ग्रिप बनाना उनके लिए आसान नहीं होगा, जिससे उनकी गेंदबाजी पर असर पड़ेगा। अश्विन और जडेजा अंतिम सत्र में विकेट चटकाने में माहिर हैं।

अगर ओस ना हो तो डे-नाइट टेस्ट शानदार : तेंदुलकर

नई दिल्ली, प्रेट्र: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भारत का पहला डे-नाइट टेस्ट तभी सफल होगा जब ईडन गार्डेंस में ओस से प्रभावी तरीके से निपटा जाएगा। उन्हें अंदेशा है कि ओस से तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तेंदुलकर ने भारत में टेस्ट मैच दूधिया रोशनी में कराने का स्वागत करते हुए कहा कि यह 'अच्छा कदम' है और दर्शकों को इस पारंपरिक प्रारूप की ओर खींचकर लाएगा।

तेंदुलकर ने कहा कि जब तक ओस मैच को प्रभावित नहीं करती तब तक यह अच्छा कदम है लेकिन अगर ओस का प्रभाव पड़ता है तो तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि एक बार गेंद गीली हो गई तो ना तो तेज गेंदबाज अधिक कुछ कर पाएंगे और ना ही स्पिनर।

ओस की बड़ी भूमिका: ईडन पर डे-नाइट वनडे मैचों के दौरान ओस की समस्या रही है और तेंदुलकर की परेशानी का कारण यही है। तेंदुलकर ने कहा कि मुझे लगता है कि यहां ओस बड़ी भूमिका निभाएगी। देखने की जरूरत है कि कितनी ओस पड़ेगी। ओस फैसला करेगी कि दोनों टीमें किस हद तक प्रतिस्पर्धा पेश करेंगी। हालात का किसी चीज पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

दर्शकों को आकर्षित करेगा: तेंदुलकर बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली से सहमत हैं कि यह प्रयोग स्टेडियम में दर्शकों को वापस खींचने के लिए अच्छा विचार है। उन्होंने कहा कि यह अच्छा नजरिया है, क्योंकि लोग काम के बाद डे-नाइट टेस्ट देख पाएंगे। लोग शाम को आकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। खिलाड़ियों के नजरिए से देखा जाए तो गुलाबी गेंद से खेलना और यह देखना कि यह पारंपरिक लाल गेंद से किस तरह अलग व्यवहार करती है, बुरा विचार नहीं है।

गेंद के बर्ताव के हिसाब से रणनीति बनाएं: शोएब अख्तर हों या शेन वॉर्न, किसी भी गेंदबाज का सामना करने के लिए तेंदुलकर पूरी तैयारी के साथ उतरते थे और उन्होंने नेट सत्र के लिए भारतीय बल्लेबाजों को टिप्स भी दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बल्लेबाजों को नेट पर अलग-अलग तरह की गेंदों के साथ अभ्यास करने की जरूरत है। नई गुलाबी गेंद, 20 ओवर पुरानी गुलाबी गेंद, 50 ओवर पुरानी गुलाबी गेंद और 80 ओवर पुरानी गेंद। देखना होगा कि नई गेंद, थोड़ी पुरानी और पुरानी गेंद किस तरह बर्ताव करती है। इसके अनुसार अपनी रणनीति बनाओ। इस साल दलीप ट्रॉफी डे-नाइट नहीं होने के कारण तेंदुलकर ने भारतीय टीम से अपील की कि

मैं नहीं कह सकता हूं कि अगले टी-20 विश्व कप में मैं फिनिशर की भूमिका निभाता दिखूंगा।
– इयोन मॉर्गन, इंग्लैंड के कप्तान

इंग्लैंड ने डॉरेन गफ को सलाहकार चुना

क्राइस्टचर्च : इंग्लैंड ने अगले महीने से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम के साथ तेज गेंदबाजी सलाहकार के रूप में पूर्व तेज गेंदबाज डॉरेन गफ को जोड़ा है। गफ पांच नवंबर को ऑकलैंड में टेस्ट टीम से जुड़ेंगे और 18 नवंबर तक तेज गेंदबाजों के साथ काम करेंगे। टीम के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड ने गफ के टीम से जुड़ने पर कहा कि मुझे खुशी है। मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं।

आइओसी ने मेरी कॉम को टोक्यो ओलंपिक के लिए खिलाड़ी दूत समूह में शामिल किया

उपलब्धि ▸ मुक्केबाजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 सदस्यीय समूह में जगह मिली

नई दिल्ली, प्रेट्र : छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मेरी कॉम को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के खेल के लिए कार्यबल ने अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम्स से पहले मुक्केबाजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 सदस्यीय खिलाड़ी दूत समूह में शामिल किया है।

मेरी कॉम इस समूह में एशियाई मुक्केबाजों का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस समूह में दो बार के ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता यूक्रेन के दिग्गज वासिल लामाचेनको (यूरोप) और पांच बार के विश्व चैंपियन एवं 2016 ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जूलियो सेजार ला क्रूज (अमेरिका) जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। मेरी कॉम ने कहा, 'यह एक बड़ा सम्मान है, एक उपलब्धि की तरह है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी है क्योंकि मुझे अपने साथी एथलीटों की मदद करने की दिशा में काम करना है। मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करूंगी।'

भारत की 36 साल की मेरी कॉम हाल में विश्व चैंपियनशिप के इतिहास की सबसे सफल मुक्केबाज बनी थीं जब उन्होंने रूस में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के पिछले सत्र में कांस्य पदक के रूप में अपना आठवां पदक जीता था। मेरी कॉम 51 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कांस्य पदक जीतने के अलावा पांच बार की एशियाई चैंपियन हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीते हैं।

आइओसी ने कहा, 'प्रत्येक क्षेत्र से एक महिला और एक पुरुष दूत मुक्केबाजी समुदाय से निजी और डिजिटल रूप से जुड़ने की भूमिका निभाएंगे। वे टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 के मुक्केबाजी टूर्नामेंट और क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं की योजना बनाने के लिए खिलाड़ियों के सुझावों को मुक्केबाजी कार्यबल (बीटीएफ) तक पहुंचाने में मदद करेंगे।'

आइओसी ने इसी साल अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआइबीए) से ओलंपिक स्पर्धा के आयोजन का अधिकार छीन लिया था और पूरी क्वालीफाइंग प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लिया। आइओसी का कहना है कि प्रशासनिक अखंडता और वित्त प्रबंधन के मामले में एआइबीए सभी चीजों को सही करने में नाकाम रहा है।

भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम। फाइल फोटो

खिलाड़ी दूत समूह इस प्रकार है

पुरुष : लुकमो लावल (अफ्रीका), जूलियो सेजार ला क्रूज (अमेरिका), जियांगयुआन असियाहु (एशिया), वासिल लामाचेनको (यूरोप), डेविड निका (ओसिनिया)।

महिला : खदीजा मार्दी (अफ्रीका), मिकाइला मायर (अमेरिका), एमसी मेरी कॉम (एशिया), सारा ओरोमोने (यूरोप) और शेली वाट्स (ओसिनिया)।

लक्ष्य, मिथुन और राहुल प्री-क्वार्टर फाइनल में

सारब्रकेन (जर्मनी), प्रेट्र : उदीयमान भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने यहां कड़े मुकाबले में फिनलैंड के एतु हेइनो को हराकर सारलोरलक्स ओपन सुपर टूर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

सितंबर में बेल्जियम इंटरनेशनल में खिताबी जीत के दौरान हेइनो को हराने वाले आठवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य ने बुधवार रात फिनलैंड के इस खिलाड़ी को 56 मिनट तक चले मुकाबले में 21-18, 18-21, 22-20 से शिकस्त दी। इसी महीने डच ओपन के रूप में अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब जीतने वाले लक्ष्य अगले दौर में जर्मनी के लार्स स्कैंजलर का सामना करेंगे। उत्तराखंड के 18 वर्षीय लक्ष्य को पहले दौर में बाई मिली थी। इस टूर्नामेंट में लक्ष्य को आगामी मुकाबलों में कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है।

मिथुन मंजूनाथ और बीएम राहुल भारद्वाज ने भी सीधे गेम में जीत दर्ज करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिथुन ने मलेशिया के चोंग यी हान को 21-15, 21-14 से हराया। अब उनका सामना इंग्लैंड के पांचवीं वरीयता प्राप्त टॉबी पेंटी से होगा। वहीं, राहुल ने जर्मनी के काई स्कैफर को 21-13, 21-15 से मात दी। वह अब अगले दौर में आयरलैंड के नहात नगुयेन से भिड़ेंगे। पहले ही प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुके किरन जॉर्ज गुरुवार को नीदरलैंड्स के जोरान क्विकल का सामना करेंगे।

शाकिब ने सटोरिये को गंभीरता से नहीं लिया : अशरफुल

क्रिकेट डायरी

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुहम्मद अशरफुल का मानना है कि शाकिब अल हसन पर लगा प्रतिबंध सिस्टम के लिए चौंकाने वाली घटना है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) में 2013 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में पांच साल का प्रतिबंध झेलने वाले अशरफुल अब प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अब अगले 12 महीने शाकिब के लिए काफी मुश्किल होने वाले हैं। अशरफुल ने कहा कि हमारे मामले अलग हैं। उन्होंने सट्टेबाजी की जानकारी प्रशासन को नहीं दी जबकि मैं पूरी तरह से स्पॉट फिक्सिंग में शामिल था लेकिन यह सिस्टम के लिए एक चौंकाने वाली घटना है। हम क्रिकेट से प्यार करते हैं। शाकिब ने जो कुछ भी किया है, उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि यहां उनके बारे में कोई ज्यादा खबर नहीं है। 35 वर्षीय अशरफुल ने आगे कहा कि वह यह देखकर दुखी हैं कि उनके बाद के खिलाड़ी भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। मेरा मानना था कि मेरे बाद कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर इस तरह की परेशानियों में नहीं पड़ेगा। हम दोनों के मामले अलग हैं।

पूर्व कप्तान मुहम्मद अशरफुल। फाइल फोटो

मानसिक स्वास्थ्य के लिए ब्रेक पर गए मैक्सवेल

मेलबर्न : ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों के कारण श्रीलंका के खिलाफ जारी टी-20 सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने इस समस्या के कारण क्रिकेट से भी कुछ समय तक ब्रेक लेने का निर्णय लिया है। मैक्सवेल को श्रीलंका के खिलाफ हुए पहले दो टी-20 मैचों के लिए 11 खिलाड़ियों में भी शामिल किया था। उन्होंने पहले मैच में 27 रनों की तेज पारी भी खेली थी। उनकी जगह डी आर्वी शॉर्ट को शुक्रवार को होने वाले आखिरी टी-20 मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है। मनोचिकित्सक डा. लॉयड ने बताया कि ग्लेन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

शिव व रानी ने ओलंपिक टेस्ट इवेंट में जीते स्वर्ण

टोक्यो, प्रेट्र : शिव थापा (63 किग्रा) और पूजा रानी (75 किग्रा) ने गुरुवार को यहां मुक्केबाजी के ओलंपिक टेस्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीते, जबकि आशीष (69 किग्रा) को फाइनल में हार के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा। चार बार के एशियाई पदक धारक थापा ने कजाखिस्तान के राष्ट्रीय चैंपियन और एशियाई कांस्य पदक विजेता सनाताली तोलतायेव को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। थापा गत राष्ट्रीय चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के पूर्व कांस्य पदक विजेता हैं।

एशियन गेम्स की पूर्व कांस्य पदक विजेता रानी ने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। रानी ने इस साल एशियन चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता था।आशीष को हालांकि फाइनल में जापान के सेवोन ओकोजावा के खिलाफ शिकस्त के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे से उतरेगा भारत

योगेश शर्मा, दुबई

भारतीय टीम शुक्रवार को यहां रेड बुल कैंपस क्रिकेट टूर्नामेंट के वर्ल्ड फाइनल्स के एलिमिनेटर मैच में पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे से उतरेगी। इस टूर्नामेंट में सात बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ हैं जिसमें भारत सभी मैच में जीता हैं।

भारतीय टीम का ग्रुप के मैचों में प्रदर्शन अच्छा रहा है और पाक के खिलाफ भी उससे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। भारत ने ग्रुप-ए में अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 103 रनों से शिकस्त दी थी। इसके बाद उसने इंग्लैंड को 33 रन से हराया था। हालांकि, भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से 62 रन से हार गई थी। भारत अपने ग्रुप में चार अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय टीम की बल्लेबाजी ट्रेयाश बाली और कप्तान मयंक चौधरी पर निर्भर है। पहले मैच में मयंक ने पचासा (63) जड़ा था और टीम को जीत दिलाई थी। इंग्लैंड के खिलाफ बाली (94) का बल्ला खूब चला, लेकिन वह शतक से चूक गए थे। दोनों बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं चल पाए थे और टीम को हार का सामना करना पड़ा था। अगर भारतीय टीम को पाक के खिलाफ मैच जीतना है तो इन दोनों बल्लेबाजों को चलना होगा।

वहीं, पाकिस्तान ने ग्रुप-बी में दो मैच खेले हैं। पहले मैच में उसने मेजबान यूएई को 104 रन से रौंदा था, लेकिन दूसरे मैच में उसे श्रीलंका ने सात विकेट से हराया था। पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोज्जम मलिक को उम्मीद है कि उनकी टीम भारत को हराने में जरूर सफल होगी। पाकिस्तान ग्रुप में दो अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। इस टूर्नामेंट में खेल रही भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी डीएवी चंडीगढ़ कॉलेज की क्रिकेट टीम के हैं।

टी-20 विश्व कप की ट्रॉफियों का अनावरण करेंगी करीना

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर खान मेलबर्न में पुरुष और महिला टी-20 विश्व कप की ट्रॉफियों का अनावरण करेंगी। आइसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2020 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में अगले साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक किया जाएगा। महिला टी-20 विश्व कप भी 2020 में 21 फरवरी से आठ मार्च तक खेला जाएगा।

करीना ने कहा कि इस प्रतिष्ठित शाम का हिस्सा बनकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं उन सभी महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहती हूं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने देश के लिए खेल रही हैं। वे सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दिवंगत ससुर भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से खेलने वाले महानतम क्रिकेटरों में से एक थे और ट्रॉफी का अनावरण करना मेरे लिए सम्मान की बात है।

लेग्नेस को हरा दूसरे स्थान पर पहुंची मैड्रिड

मैड्रिड, आइएएनएस : रीयल मैड्रिड ने दमदार प्रदर्शन करते हुए यहां खेले गए स्पेनिश लीग के 10वें दौर के मैच में लेग्नेस को 5-0 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही रीयल की टीम 21 अंकों के साथ तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। शीर्ष पर काबिज एफसी बार्सिलोना के 22 अंक हैं।

इस करारी शिकस्त के बाद लेग्नेस पांच अंकों के साथ 20 टीमों की लीग में आखिरी पायदान पर बनी हुई है। मैच की शुरुआत से ही रियल की टीम ने दमदार प्रदर्शन किया जो आखिरी मिनट तक कायम रही। सातवें मिनट में रियल के लिए पहला गोल रोर्डिगो ने दागा। इसके एक मिनट बाद ही रियल अपनी बढ़त को दोगुना करने में कामयाब रही। मिडफील्डर टॉनी क्रूस ने रियल का दूसरा गोल किया। पहला हाफ समाप्त होने से पहले रियल की टीम मुकाबले का तीसरा गोल करने में भी कामयाब रही। 24वें मिनट में उसे पेनाल्टी मिली और कप्तन सर्जियो रामोस ने गेंद को गोल में डोलने में कोई गलती नहीं की। मैच का दूसरा हाफ भी पूरी तरह से रीयल के नाम रहा। रीयल को 69वें मिनट में एक और पेनाल्टी मिली। इस बार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने प्रयास किया और बिना कोई गलती करते हुए गोल करने में कामयाब रहे। लेग्नेस ने वापसी की कोशिश की, लेकिन वह एक गोल भी नहीं कर पाई। इंजुरी टाइम (91वें मिनट) में मैच का आखिरी गोल रीयल के स्ट्राइकर लूका योविक ने किया। क्लब के लिए योविक का यह पहला गोल है। वह इस सत्र की शुरुआत से पहले रीयल में शामिल हुए थे।

जीत के बाद जश्न मनाते मैड्रिड के खिलाड़ी। रायटर

विविध

मांसाहार करेंगे तो हो सकते हैं नरभक्षी : गोपाल भार्गव

नईदुनिया, भोपाल

▸ आंगनबाड़ी केंद्र में अंडे बांटने के प्रस्ताव पर सियासत जारी

▸ महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा- हमें किसी विरोध की परवाह नहीं

मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन में अंडा परोसने के प्रस्ताव पर सियासत जारी है। प्रस्ताव का विरोध करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा है कि हम यदि बचपन से ही मांसाहार करेंगे तो नरभक्षी भी हो सकते हैं। सनातन संस्कृति में मांसाहार निषेध है। वहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का कहना है कि हमें विरोध की परवाह नहीं है।

भार्गव ने सवाल उठाया है कि हम एक कुपोषित सरकार से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये लोग उन्हें भी अंडा बांट रहे हैं, जो मांसाहारी नहीं हैं। यह गलत है। हम लोगों को जबरिया कुछ भी खाने को नहीं कह सकते। भार्गव के ही समर्थन में भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि सरकार और कांग्रेस द्वारा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, मानो जिसने अंडा नहीं खाया, वह कुपोषण का शिकार हो गया। जबकि विकल्प में अंडा एक है, एकमात्र नहीं है। अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि व्यक्तिगत तौर पर कोई अंडा खाए या मांस, या फिर शाकाहारी हो, यह उसका अपना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार के नाते अंडा को शाकाहारी बताकर मासूम बच्चों को परोसना निश्चित रूप से उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना है। प्रस्ताव के समर्थन में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने गुरुवार को मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने सलाह दी तो बच्चों को अंडा देंगे। मप्र से कुपोषण को खत्म करना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे। मंत्री ने कहा कि बस सरकार और मुख्यमंत्री कमलनाथ की सहमति का इंतजार है।

गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा और यदि यह मंजूर हुआ तो अगले वित्तीय वर्ष से आदिवासी बहुल जिलों के आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को नाश्ते में अंडा दिया जाएगा। आंगनबाड़ियों में प्रोटीन के विकल्प के रूप में अंडा परोसने पर विचार पहली बार नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार में यह प्रस्ताव खारिज हो चुका है।

नाग के फन पर थिरके मोहन

देवाधिदेव महादेव की नगरी वाराणसी में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी की शाम द्वापर उतर आया। गंगा ने कालिंदी का रूप लिया और लीलापति ने कालिया का दर्प भंग किया। नटवर नागर भगवान ने अत्याचारी नाग के फन नाथ नृत्य मुद्रा में वंशी बजाते दर्शन दिया। इस दिव्य नजारे की गवाह बनी रामचरित मानस की रचना की गवाह तुलसीघाट की सीढ़ियां, जहां गोस्वामी तुलसीदास ने 450 वर्ष पूर्व प्रभु श्रीकृष्ण की इस लीला का श्रीगणेश किया। इस अवसर पर काशीराज परिवार के अनंत नारायण सिंह ने परंपरानुसार गिन्नी प्रदान की। उत्तम राय चौधरी

'मैनेजमेंट गुरु' थे प्रभु राम, उनके गुर सीखेंगे आइआइएम के छात्र

जागरण संवाददाता, लखनऊ

▸ आइआइएम लखनऊ में पहली बार होगा रामायण का मंचन, गूंजेगा 'जय श्रीराम'

▸ वार्षिक सांस्कृतिक समारोह मेनफेस्ट में पहली बार शामिल

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) लखनऊ में प्रभु राम के चरित्र और प्रबंध कौशल को रामायण मंचन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। संस्थान के वार्षिक सांस्कृतिक समारोह मेनफेस्ट में पहली बार रामायण का भव्य मंचन होगा। समारोह में देशभर के विभिन्न आइआइएम संस्थानों के साथ ही अन्य शैक्षिक संस्थान के छात्र भी शिरकत करेंगे।

आधुनिक दुनिया के इस बेहतरीन प्रबंधन संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों ने न केवल त्रेतायुग में जन्मे राम को माना है, बल्कि उन्हें प्रबंधन का महारथी बताते हुए उनके गुर सीखने का फैसला किया है। इसके लिए रास्ता भी राममय चुना है। हर पात्र में छात्र ही दिखेंगे, जिसके लिए उन्होंने युद्धस्तर पर तैयारी की है।

आइआइएम जैसे उच्च स्तरीय प्रबंधन संस्थान में रामायण के किरदारों का मंचन...? आयोजक छात्रों की ओर से इस सवाल का जवाब बेहद तार्किक आया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम विश्व के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु रहे हैं। उन्होंने हर जाति धर्म, जीव-जंतु से सामान रूप से व्यवहार करते हुए उनके अनुरूप दायित्व सौंपा। मर्यादित आचरण, कुशल नेतृत्व व कारगर नीति से ही राम प्रभु राम कहलाए। वक्त कोई भी हो, राम का चरित्र हर युग में अनुकरणीय है। प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े हर छात्र के लिए महान उदाहरण हैं।

आइआइएम लखनऊ। फाइल

15 से 17 के बीच गूंजेगा 'जय श्रीराम' : आइआइएम छात्रों की इस पहल को इसलिए भी चर्चा मिल रही है, क्योंकि जल्द ही अयोध्या में राममंदिर को लेकर फैसला आने वाला है। हालांकि, वे इस आयोजन को इससे इतर बताते हैं। उनका कहना है कि हर साल आइआइएम में मेनफेस्ट होता है। इस वर्ष 15 से 17 नवंबर तक कार्यक्रम होगा, जिसमें रामायण मंचन को भी शामिल किया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से इस आयोजन के लिए ढाई लाख रुपये का बजट भी मुहैया कराया गया है। मेनफेस्ट में प्रभु राम पर क्विज प्रतियोगिता भी होगी।

नेपाल में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मचा बवाल दो पक्षों की झड़प में भारतीय युवक की मौत

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर

नेपाल के सीमाई कस्बा कृष्णानगर स्थित झंडेनगर में गुरुवार को लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के लिए निकली शोभायात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। दो पक्षों के बीच हुई झड़प और पथराव में कई लोग घायल हो गए। इस दौरान उपद्रवियों पर चलाई गई नेपाली पुलिस की गोली से भारतीय सीमा क्षेत्र के सिद्धार्थनगर जिला निवासी सूरज पांडेय (22) की मौत हो गई। वह झंडेनगर में चाट की दुकान चलाते थे। घटना को लेकर दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

सीमा पर आवागमन पूरी तरह ठप है। कृष्णानगर बाजार से सटे आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मार्ग को लेकर विवाद बुधवार रात से शुरू हुआ। रास्ता रोके जाने पर दो पक्षों के बीच झड़प हुई और जमकर ईंट-पत्थर चले। मौके पर तैनात पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस पर उपद्रवियों ने सड़कों पर जलते हुए टायर और बोतलें फेंकीं। जवाब में पुलिस ने नौ राउंड फायरिंग की। तब उपद्रवियों ने ट्रैफिक पुलिस व पुलिस बूथ को आग के हवाले कर दिया।

नेपाल के कृष्णानगर में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा व आगजनी का दृश्य। जागरण

ताजमहल देखे बगैर लौटे सैकड़ों पर्यटक, हंगामा

जागरण संवाददाता, आगरा

ताजमहल के दीदार के लिए गुरुवार को भीड़ उमड़ी। टिकट विंडो और टर्न स्टाइल गेट पर लाइनें लगीं। पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, शाम को टिकट विंडो बंद होने पर टिकट नहीं मिलने से पर्यटकों को मायूस होकर लौटना पड़ा। पर्यटकों ने हंगामा भी किया, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई।

गुरुवार को पूर्वी व पश्चिमी गेट स्थित टिकट विंडो और टर्न स्टाइल गेट पर भीड़ उमड़ी। सूर्यास्त (5:36 बजे) से 45 मिनट पूर्व शाम 4:51 बजे नियमानुसार टिकट विंडो बंद हो गई, लेकिन उस समय पर भी पूर्वी गेट पर 500 से अधिक और पश्चिमी गेट पर करीब एक हजार पर्यटक टिकट लेने को लाइन में लगे हुए थे। टिकट विंडो बंद होने के बाद टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने हंगामा भी किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि ताजमहल में 10 मिनट देर तक पर्यटकों को प्रवेश दिया गया है। देर से आने वाले पर्यटकों को ही टिकट नहीं मिल सका है। वो ऑनलाइन टिकट बुक कर लाइन में लगने से बच सकते हैं।

क्वॉइन की रही समस्या : दोपहर 3:30 बजे के करीब ताज पूर्वी गेट स्थित टिकट विंडो पर पर्यटकों को टिकट के साथ दिए जाने वाले मैग्नेटिक क्वॉइन कम पड़ गए। क्वॉइन की स्कैनिंग में भी समस्या रही। हालांकि, विभागीय अधिकारी इससे इन्कार कर रहे हैं।

टिकट की स्थिति

भारतीय	23476
विदेशी	3386
सार्क	432
कुल	27294

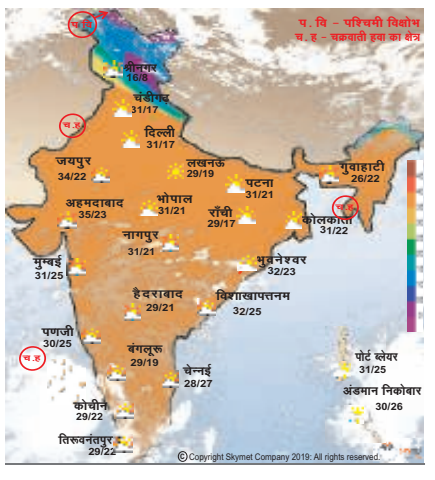

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर बना रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। पंजाब और हरियाणा में धुंध या बादलों के साथ मौसम आरामदायक होगा। बादलों में हल्की वृद्धि संभव है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	29/24/आंबा	अहमदाबाद	30/23/व
कोलकाता	31/22/सा	बड़ौदा	31/23/सा
चेन्नई	32/25/व	नागपुर	30/20/आंबा
हैदराबाद	29/21/सा	इन्दौर	29/21/आंबा
बंगलूरू	30/20/सा	राँची	29/17/आंबा
त्रिवेन्द्रम	31/23/आंबा	पटना	29/18/आंबा
गुवाहाटी	27/18/व	जमशेदपुर	32/24/आंबा
जंगटोक	12/-1/व	पुणे	27/21/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 1 नवंबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

भारत में भाप से चलने वाले पहले रेल इंजन का निर्माण हुआ

1950 में आज ही भारत में भाप से चलने वाले पहले रेल इंजन का निर्माण हुआ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चितरंजन रेल कारखाना और नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी ने इसे बनाया। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसे स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास को समर्पित किया।

दुनिया के पहले हवाई हमले में चार बम गिराए गए

1911 में आज ही इटली और तुर्की के बीच युद्ध के दौरान इटली के विमान चालक सेकेंड लेफ्टिनेंट गियूलिओ गैवोटी ने एटरिक टॉबे नामक विमान से लीबिया में तुर्की सेना के दो शिविरों पर चार बम गिराए। ये दुनिया का पहला हवाई हमला था।

सुंदरता और अदाकारी का बेजोड़ संगम हैं ऐश्वर्या

देश और दुनिया में अपनी खूबसूरती और दमदार अदाकारी के लिए मशहूर भारतीय फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन 1973 में आज ही के दिन मेंगलुरु में पैदा हुई थीं। 1994 में विश्व सुंदरी का खिताब हासिल करने के बाद 1997 में फिल्मों में पर्दापण किया। कई सफल अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में भी अभिनय किया। 2009 में पद्मश्री से सम्मानित हुईं। 2012 में फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय ने भी प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कही जाने वाली ऐश्वर्या ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की। उनकी एक बेटी आराध्या है।

इधर-उधर की

124 साल पुराना प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्र

लंदन, एजेंसी : जाने-माने विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाना अगर आज भी आसान नहीं है तो पहले भी यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए नाको चने चबाने पड़ते थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ट्रिनिटी कॉलेज कैंब्रिज का एक ऐसा ही प्रवेश परीक्षा प्रश्न-पत्र लोगों को सोचने पर विवश कर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल एंड आर्किटेक्चरल हिस्ट्री के प्रोफेसर विलियम वायटे ने इसे ट्विटर पर पोस्ट किया है। प्रवेश परीक्षा का यह प्रश्नपत्र 1895 का है। विभिन्न मामलों पर इसमें कुल 12 सवाल पूछे गए हैं। छात्रों को निर्देश दिया गया है कि सिर्फ नौ का ही वे उत्तर दें। इन सवालों को जो ध्यान से पढ़ रहा है तो उसका सिर घूम जा रहा है। अब उसे अहसास हो रहा है कि पहले भी पढ़ाई आसान नहीं हुआ करती थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस प्रश्न-पत्र को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

शोध अनुसंधान

ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाके में रहने से स्ट्रोक का खतरा

सड़कों पर बढ़ते वाहन हमारी सेहत के लिए कई तरह की समस्या भी खड़ी कर रहे हैं। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाके में रहने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इंवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, उच्च ट्रैफिक वाले इलाके में रहने वाले व्यक्तियों में स्ट्रोक का खतरा ज्यादा पाया गया है। यह निष्कर्ष अधेड़ उम्र के करीब एक लाख 15 हजार स्वस्थ लोगों पर 20 साल से ज्यादा समय तक किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि लंबे समय तक भारी ट्रैफिक की वजह से लोगों में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। प्रमुख शोधकर्ता पीटर लजंगमैन ने कहा, 'अध्ययन में स्ट्रोक के खतरे के तौर पर स्थानीय ट्रैफिक की पहचान की गई है।' -एएनआइ

बचपन में मोटापे के नए कारणों का पता चला

जंक फूड और ज्यादा कैलोरी वाले खाने को मोटापे का प्रमुख कारण माना जाता है। लेकिन एक नए अध्ययन ने बचपन में होने वाले मोटापे के नए कारणों पर रोशनी डाली है। ओबेसिटी रिव्यू जर्नल में छपे इस अध्ययन के अनुसार, गट (आंत) बैक्टीरिया व इम्यून सेल्स के साथ इसकी परस्पर क्रिया और फैट टिश्यू समेत मेटाबोलिक अंगों की बचपन के मोटापे में अहम भूमिका पाई गई है। ना सिर्फ आंत बल्कि मां की सेहत, आहार, एक्सरसाइज का स्तर, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग भी बच्चों में मोटापे का कारण बन सकते हैं। अमेरिका के वेक फॉरेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर हरिओम यादव ने कहा, 'पिछले दशक में किए गए कई अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी आंत में रहने वाले माइक्रोब्स का ना सिर्फ मोटापे से जुड़ाव है बल्कि वे इस समस्या के कारणों में भी शुमार हैं।' -एएनआइ

मुंबई और हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल

पेरिस, आइएएनएस : भारत के मुंबई और हैदराबाद समेत विश्व के 66 शहरों को यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन) की क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। मुंबई का चयन सिनेमा की दुनिया में योगदान जबकि हैदराबाद का पाक कला के लिए किया गया। दोनों शहर अब 246 सदस्यों वाले क्रिएटिव सिटी संगठन के नेटवर्क का हिस्सा होंगे।

यूनेस्को के अनुसार, यह नेटवर्क उन शहरों को एक साथ लाता है, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के दम पर विकास किया है। इनमें संगीत, कला, लोक शिल्प, डिजाइन, सिनेमा, साहित्य, डिजिटल कला और पाक कला आदि क्षेत्र शामिल हैं। यूनेस्को महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने गुरुवार को कहा कि क्रिएटिव सिटीज अपने विकास की रणनीति के केंद्र में संस्कृति को रखती हैं और अपने उत्तम अभ्यासों को साझा करती हैं।

मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है।

चारमीनार हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। दोनों फाइल

246 सदस्यों वाले क्रिएटिव सिटी संगठन का हिस्सा होंगे दोनों शहर

66 शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है विश्व के

सूची में शामिल अन्य शहर

- **संगीत :** अंबोन (इंडोनेशिया), हवाना (क्यूबा), पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद एवं टोबैगो), रामल्ला (फलस्तीन) आदि।
- **साहित्य :** बेरुत (लेबनान), लाहौर (पाकिस्तान), नानजिंग (चीन) आदि।
- **शिल्प व लोक कला :** बंदर अब्बास (ईरान), शारजाह (यूएई), त्रिनिदाद आदि।
- **डिजाइन :** हनोई (वियतनाम), सैन जोस (कोस्टारिका), फोर्टलेजा (ब्राजील) आदि।
- **मीडिया आर्ट्स :** कार्लजूए (जर्मनी), सैंटियागो डे कैली (कोलंबिया) और विबोर्ग (डेनमार्क)।
- **फिल्म :** पॉट्सडैम (जर्मनी), सराजेवो (बोस्निया व हर्जेगोविना), वलाडोलिड (स्पेन) और वेलिंगटन (न्यूजीलैंड)।

मात्र 10 मिनट में चार्ज हो सकती हैं इलेक्ट्रिक कारें

तकनीक ▶ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने तैयार किया बैट्री का नया डिजाइन

एक बार चार्ज करने के बाद आसानी से तय कर सकेंगे 322 किलोमीटर का सफर

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बैट्री का एक ऐसा डिजाइन विकसित किया है, जिससे केवल 10 मिनट में ही इलेक्ट्रिक कारें चार्ज हो सकती हैं और लोग 322 किलोमीटर का सफर आराम से तय कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है नई तकनीक ई-वाहनों की सबसे बड़ी चिंता को दूर कर सकती है। बता दें कि वर्तमान में ई-कारों को चार्ज होने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है।

पेंसिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जूल नामक जर्नल में बताया है- 'इतनी तेज चार्ज दर के लिए बैट्री को तुरंत 400 किलोवाट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्तमान पीढ़ी की बैट्रियां अभी इसके लिए सक्षम नहीं हैं क्योंकि इन बैट्री में लिथियम प्लेटिंग (क्षरण) का खतरा रहता है। इसके एनोड के आसपास मेटलिक लिथियम का निर्माण होने लगता है, जिससे बैट्री के खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। इस समस्या से पार पाने के लिए शोधकर्ताओं ने चार्जिंग के दौरान अपनी प्रयोगात्मक बैट्री का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया, लेकिन उपयोग के दौरान उसका तापमान सामान्य ही रखा।

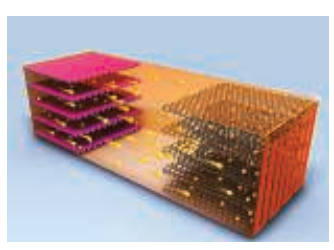

प्रतीकात्मक

पेंसिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियर और इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक चाओ-यांग वांग ने कहा, 'इस तरीके से चार्जिंग के दौरान बैट्री का तापमान सीमित रखने में मदद मिलती है और उसकी लाइफ भी बढ़ाई जा सकती है।'

अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सदस्य रिक सचलेबेन ने बताया कि बैट्री का नया डिजाइन है तो प्रभावी पर इसे तैयार करने और बाजार में लाने में अभी एक दशक का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माताओं को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इसमें तेजी से तापमान बढ़ाना सुरक्षित है और ज्यादा ऊर्जा हस्तांतरित करने पर इसमें विस्फोट नहीं होगा।

सचलेबेन ने कहा, तेज चार्जिंग इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी क्योंकि उन्हें डीजल-पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ई-वाहनों को चार्ज होने के लिए लगभग 30 मिनट लगते हैं। यदि यह डिजाइन कारगर रहा तो ई-वाहनों के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा।

एक से अधिक डिवाइस पर चला सकेंगे वाट्सएप

प्रतीकात्मक

सैन फ्रांसिको, आइएएनएस : फेसबुक के स्वामित्व वाला वाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिसके माध्यम से यूजर एक से अधिक डिवाइस पर एक ही वाट्सएप अकाउंट का उपयोग कर सकेंगे। वेब ईटीए इंफो की रिपोर्ट के अनुसार, वाट्सएप एक ऐसी सुविधा विकसित कर रहा है, जो लोगों को एक ही समय में विभिन्न उपकरणों पर उनके अकाउंट का उपयोग करने की अनुमति देगा। इसके लिए वाट्सएप एक नया तरीका विकसित कर रहा है।

वर्तमान में वाट्सएप यूजर पंजीकृत डिवाइस पर केवल एक ही अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी अन्य डिवाइस में लॉग इन करने की कोशिश की जाती है तो पिछले डिवाइस पर खाता लॉग आउट करना होता है। लेकिन नए फीचर के सफल परीक्षण के बाद यह परेशानी नहीं आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा वाट्सएप आइओएस यूजर्स के लिए एक नए बीटा अपडेट का परीक्षण कर रहा है, जो हाइड म्यूट स्टेटस अपडेट, स्प्लैश स्करीन जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा।

फिल्म रिव्यू

एक्शन के साथ इमोशन का तड़का

टर्मिनेटर : डार्क फेट

निर्देशक : टिम मिलर
प्रमुख कलाकार : अर्नाल्ड श्वार्जनेगर, लिंडा हेमिल्टन, मैकेंजी डेविस, गेब्रियल लूना
अवधि : 2 घंटे 8 मिनट

हॉलीवुड साइंस फिक्शन फ्रेंचाइजी 'द टर्मिनेटर' की खासियत इंसान और मशीन के बीच की लड़ाई और एक्शन दृश्य रहे हैं। हॉलीवुड फिल्म 'स्टार वार्स : द फोर्स अवेकेंस' की तरह इस बार 'टर्मिनेटर' की छठी किस्त 'टर्मिनेटर : डार्क फेट' में नई पीढ़ी के पात्रों को जोड़ते हुए लोकप्रिय पुराने पात्रों को पुनर्जीवित किया गया है।

'टर्मिनेटर' की पहली फिल्म वर्ष 1984 में रिलीज हुई थी। वह फिल्म अर्नाल्ड श्वार्जनेगर के करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। पहली और दूसरी किस्त में साहसी सारा कॉनर का किरदार निभाने वाली वाली लिंडा हेमिल्टन ने इस सीरीज में वापसी की है। करीब 28 साल के अंतराल के बाद इस फ्रेंचाइजी में वह अर्नाल्ड के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। दोनों वर्ष 1991 में रिलीज 'टर्मिनेटर : जजमेंट डे' में आखिरी बार स्क्रीन पर एकसाथ नजर आए थे।

कहानी वर्ष 2020 में मैक्सिको सिटी में आरंभ होती है। डानी (नतालिया रेयेस) ऑटो फैक्ट्री में काम करती है। उसकी जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है, जब उस पर हमला होता है। दरअसल, भविष्य से दो मशीनें अतीत में वापस आ जाती हैं। 'टर्मिनेटर' की पिछली फिल्मों की तरह एक उसे मारने के लिए और दूसरी उसकी रक्षा हेतु। दानी को रेव 9 (गेब्रियल लूना) फैक्ट्री में मारने का प्रयास करता है, तब तक उसकी रक्षा के लिए सुपर सैनिक ग्रेस (मैकेंजी डेविस) पहुंच जाती है। वहां से भागते हुए उनका सामना फिर रेव 9 से होता है। तब सारा कॉनर दानी की रक्षा करती है। सारा टर्मिनटर यानी टी 800 (अर्नाल्ड श्वार्जनेगर) की खोज में है। वह ग्रेस और दानी के साथ मिशन में जुड़ जाती है। वहीं टी 800 अब कार्ल के तौर पर रिटायर जिंदगी जी रहा है। अब उसका परिवार है। हालांकि उन्हें नहीं पता कि वह मशीन है। सारा और टी 800 के बीच मतभेद हैं, फिर भी वे मिलकर रेव 9 से दानी की रक्षा करते हैं।

यह फिल्म 'जजमेंट डे' के बाद 'टर्मिनेटर' फ्रेंचाइजी की तीन फिल्मों को नजरअंदाज करती है। काफी हद तक पहली किस्त की कहानी को दोहराती-सी लगती है। लेखकों ने उन बिंदुओं पर फोकस किया है, जिनकी वजह से पहली दो किस्तों को पसंद किया गया था।

पहली फिल्म की कहानी का सार है कि मशीनी दुनिया के लिए भविष्य में घातक साबित हो सकने वाले शख्स को मारने के लिए अतीत में एक टर्मिनेटर आता है। वहीं एक दूसरी मशीन उसकी रक्षा के लिए आती है। लब्बोलुआब यह है कि फिल्म भविष्य से ज्यादा वर्तमान की बात करती है। इस बार इमोशन का भी तड़का है।

सीरीज की तीसरी फिल्म के बाद जेम्स कैमरून बतौर निर्माता और सहलेखक इससे जुड़े हैं। 'डेडपूल' जैसी फिल्म बना चुके टिम मिलर पर जेम्स कैमरून का प्रभाव खास नजर आता है। बहरहाल, इस बार तीन महिला पात्रों को धुआंधार एक्शन करने का मौका मिला है। लिंडा और मैकेंजी पूरे दमखम के साथ गैब्रियल से लोहा लेती हैं। रेव 9 के साथ ग्रेस के लड़ाई के दृश्य टी 800 के साथ बांधे रखते हैं।

63 वर्षीय लिंडा उम्र के इस पड़ाव पर भारी भरकम हथियार चलाते हुए आकर्षित करती हैं। पेचीदा दृश्यों में उनके साथ मैकेंजी डेविस और नतालिया रेयेस जैसी नई पीढ़ी की कलाकार हैं। अर्नाल्ड 72 साल की उम्र में भी एक्शन करते हुए जंचे हैं। रेव 9 को इस बार अधिक शक्तिशाली दर्शाया गया है। गेब्रियल रेव 9 की भूमिका में निष्ठुर मशीन के तौर पर प्रभावित करते हैं। अर्नाल्ड के साथ उनके लड़ाई के दृश्य ज्यादा नहीं हैं। फिल्म का वीएफएक्स प्रभावित करता है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

नौ मिनट में छह किलो का बर्गर खाने का चैलेंज

बर्गर खाने के शौकीनों को थाइलैंड की राजधानी बैंकाक के एक चर्चित रेस्टोरेंट के मालिक ने बर्गर खाने के साथ-साथ इनाम जीतने का खुला चैलेंज दिया है। लेकिन चैलेंज स्वीकार करने से पहले ठहरिए. यह कोई आम बर्गर नहीं है। तले हुए प्याज, बेकन और मियोनीज स्टफ वाले इस बर्गर का वजन छह किलोग्राम है और इसे सिर्फ नौ मिनट में खाना है। इनाम में पच्चीस हजार रुपये नगद मिलेंगे। क्रिस स्टेक एवं बर्गर रेस्टोरेंट के मालिक कोमडेच कॉन्गसुवान के अनुसार, देश के इस सबसे बड़े बर्गर को खाने के लिए प्रतिदिन ग्राहक आते हैं, लेकिन अब तक एक भी चैलेंज पर खरा नही उतर पाया है। रायटर

सांपों की तस्वीरें खींच कर वैज्ञानिकों की मदद कर रही हैं बुजुर्ग महिलाएं

फ्रांसीसी क्षेत्र के न्यू कैलेडोनिया में समुद्र की गहराइयों में उतरकर खतरनाक सांपों की तस्वीर खीचकर वृद्ध महिलाओं का एक ग्रुप वैज्ञानिकों को समुद्री पारिस्थितिकी को और बेहतर ढंग से समझने में उनकी मदद कर रहा है। इस ग्रुप में साठ से सत्तर वर्ष की सात महिलाएं हैं। शौकिया फोटोग्राफी करने वाली यह महिलाएं अक्सर समुद्री कछुओं की तस्वीरें अपने कैमरे में उतारती थी। इसी दौरान उन्हें करीब डेढ़ मीटर लंबा दुर्लभ प्रजाति का विषैला सर्प नजर आया। बाद में महिलाओं ने कैलेडोनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से संपर्क साधा तो पता चला है कि यह सर्प समुद्री इको सिस्टम का अहम हिस्सा हैं। इन महिलाओं ने अब ऐसे सर्पों की खोज करने का बीड़ा उठाया है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

मां ने दिया क्लैप, आमिर खान ने शुरू की शूटिंग

लगातार बन रही रीमेक फिल्मों के बीच अब आमिर खान ने भी अपनी आगामी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग शुरू कर दी है। 'लाल सिंह चड्ढा' वर्ष 1994 में रिलीज हुई टॉम हैंक्स अभिनीत अमेरिकन हॉलीवुड फिल्म 'फॉरेस्ट गंप' की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। आमिर खान इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म के आइडिया पर एक साल से काम कर रहे थे। एक साल बाद फिल्म फ्लोर पर उतर चुकी है। करीबी सूत्रों के मुताबिक, आमिर खान की मां जीनत हुसैन ने क्लैप देकर फिल्म की शूटिंग का शुभारंभ किया। 'लाल सिंह चड्ढा' का निर्देशन फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' के निर्देशक अद्वैत चंदन करेंगे। फिल्म में आमिर खान एक सिख युवक की भूमिका में होंगे, जबकि करीना कपूर खान उनकी प्रेमिका का किरदार निभाएंगी। आमिर और करीना की साथ में यह दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले दोनों ने '3 इडियट्स' फिल्म में साथ काम किया था। फिल्म में विजय सेतुपति और योगी बाबू सहित कई कलाकार होंगे। खबरें हैं कि फिल्म की कहानी में स्वर्ण मंदिर नरसंहार और इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में भी दिखाया जाएगा। 31 अक्टूबर 1984 के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसे संयोग कहा जा सकता है कि फिल्म की शूटिंग भी 31 अक्टूबर से ही शुरू हुई है। आमिर खान ने इसी साल अपने 53वें जन्मदिन पर 'लाल सिंह चड्ढा' फिल्म को बनाने की घोषणा की थी। खबरें यह भी हैं कि आमिर खान से पहले 'फॉरेस्ट गंप' फिल्म का रीमेक नब्बे के दशक में निर्देशक कुंदन शाह पहले अनिल कपूर और उसके बाद शाह रुख खान के साथ बनाना चाहते थे। 'लाल सिंह चड्ढा' फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी।

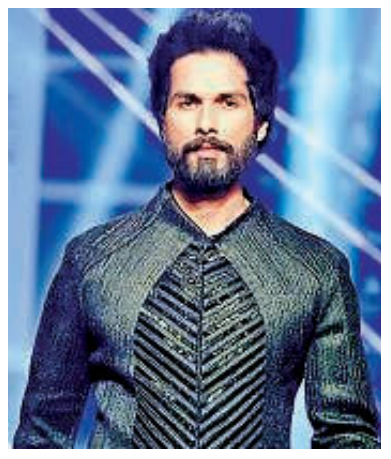

'जर्सी' में क्रिकेट खेलेंगे शाहिद कपूर

'कबीर सिंह' की सफलता के बाद शाहिद कपूर एक ऐसी फिल्म की तलाश में थे, जिसकी कहानी दमदार हो। अब 'जर्सी' फिल्म में उन्हें वह कहानी मिल गई है। 'कबीर सिंह' के बाद 'जर्सी' शाहिद कपूर की दूसरी फिल्म होगी, जो दक्षिण भारतीय फिल्म की आधिकारिक हिंदी रीमेक होगी। मूल तेलुगु फिल्म का नाम भी 'जर्सी' ही है। 'कबीर सिंह' में सर्जन का किरदार निभा चुके शाहिद अब 'जर्सी' में क्रिकेटर की भूमिका में होंगे। शूटिंग नवंबर के अंत में चंडीगढ़ में शुरू होगी। शाहिद ने क्रिकेट का अभ्यास शुरू भी कर दिया है। वह क्रिकेट सेशन के लिए रोज जाते हैं। शाहिद का कहना है कि 'कबीर सिंह' के बाद उन्हें निर्णय लेने में वक्त लगा, लेकिन जब 'जर्सी' फिल्म देखी, तो तय कर लिया की यह फिल्म करनी है। शाहिद के मुताबिक, यह एक अद्भुत प्रेरणादायक और व्यक्तिगत मानवीय सफर होगा, जिससे वह गहराई से जुड़ गए हैं। यह पहली बार नहीं है, जब शाहिद स्क्रीन पर क्रिकेट खेलेंगे। इससे पहले शाहिद कपूर 'दिल बोले हड़िप्पा' फिल्म में क्रिकेटर की भूमिका निभा चुके हैं।

भंसाली ने क्यों बदला 'गंगूबाई...' का सेट!

सलमान खान के साथ फिल्म 'इंशाअल्लाह' न बन पाने के बाद संजय लीला भंसाली ने एक के बाद एक दो फिल्में 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'बैजू बावरा' बनाने की घोषणा कर दी। वहीं सलमान भी अपनी अगली फिल्म 'राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई' की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसकी शूटिंग 4 नवंबर से शुरू होगी। 'इंशाअल्लाह' के बाद से ही भंसाली और सलमान के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही थीं। अब एक बार फिर से इनके बीच टकराव की खबर सामने आई है। दरअसल, संजय की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' का सेट मुंबई के महबूब स्टूडियो में बन रहा था। इसी बीच उन्हें पता चला कि सलमान की फिल्म 'राधे' का सेट भी उसी स्टूडियो में बन रहा है। यह पता चलते ही संजय ने अपने सेट की लोकेशन बदल दी। अब 'गंगूबाई काठियावाड़ी' का सेट मुंबई की फिल्म सिटी में स्थानांतरित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महबूब स्टूडियो के सेट पर संजय ने एक गाना भी शूट कर लिया था। सूत्रों की माने तो फिल्म और सेट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए संजय ने सेट पर किसी को मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं दी थी। महबूब स्टूडियो में 'राधे' का सेट लगने की वजह से बड़ी संख्या में मीडिया होने की

संभावना थी। जिससे संजय की गोपनीयता प्रभावित हो सकती थी। शायद इसी वजह से संजय ने सेट को स्थानांतरित करने का फैसला किया। फिल्म सिटी में 'गंगूबाई काठियावाडी' का सेट लगभग बनकर तैयार हो गया है।

अध्ययन

फफूंद के कारण खराब हो जाती है चाय की फसल, शोधकर्ताओं ने कहा-फफूंद से निजात पाकर बढ़ाई जा सकती है चाय की गुणवत्ता और किसानों की आमदनी

फफूंद के कारकों की पहचान करेगा फोल्डस्कोप

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : चाय भारत की एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसकी पत्तियों पर लगने वाली फफूंद के कारण इसके उत्पादकों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि इसके रोगजनकों (जीवाणुओं) की पहचान नहीं हो पाती। इसके लिए भारतीय शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में फोल्डस्कोप नामक एक बेहद सस्ते माइक्रोस्कोप को कारगर पाया गया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि फोल्डस्कोप के जरिये फसलों में रोगों की पहचान आसानी से की जा सकती है।

इस अध्ययन में क्लेडोस्पोरियम क्लेडोस्पोरोइड्स, जाइलेरिया हाइपोक्सिलीन, कलेक्टोरिकम कॉफिएनम, अल्टरनेरिआ अल्टेनाटा समेत कई फफूंद प्रजातियों की पहचान की गई है। इन फफूंद नमूनों को चाय में लीफ स्पॉट और लीफ ब्लाइट रोगों के लिए जिम्मेदार पाया गया है।

नर बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज, सिक्किम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने फोल्डस्कोप का उपयोग चाय की पत्तियों में कवक रोगजनकों के सर्वेक्षण और उनकी पहचान करने में किया है। शोधकर्ताओं को कहना है कि सस्ती और पोर्टेबल तकनीकें दूरदराज के इलाकों में आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सकता। फोल्डस्कोप ऐसी ही एक सामान्य-सी तकनीक है, जो फसलों में रोगों पहचान करने में उपयोगी हो सकता है।

भारत चाय का प्रमुख उत्पादक देश है। प्रतीकात्मक

मोबाइल फोन से भी जुड़ सकता है : फोल्डस्कोप एक पोर्टेबल फील्ड माइक्रोस्कोप है। शोध कार्यों में उपयोग होने वाले पारंपरिक अनुसंधान सूक्ष्मदर्शी की तरह इसे ऑप्टिकल गुणवत्ता देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसे कागज की पट्टी पर लेंस लगाकर बनाया जा सकता है और कैमरा फोन से जोड़कर बेहतर रिजॉल्यूशन प्राप्त की जा सकती है। शोधकर्ताओं में शामिल लांजे पी. वांगडी ने बताया कि अच्छी गुणवत्ता की चाय का उत्पादन बागान मालिकों के लिए एक चुनौती है। उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता कई कारकों पर निर्भर करती है। कवक रोगों के कारण होने वाला फसल नुकसान उनमें से एक है। बीमारियों की रोकथाम के लिए रोगों एवं रोगजनकों की पहचान के साथ-साथ रोगजनकों को पृथक करना महत्वपूर्ण होता है। इसमें फोल्डस्कोप को उपयोगी पाया गया है।

कृत्रिम नियंत्रण के लिए हो रहा अध्ययन

शोधकर्ता लांजे पी. वांगडी ने कहा कि सिक्किम के चाय बागानों में एकीकृत कीट प्रबंधन (आइपीएम) और रोगजनकों का जैविक पद्धति से प्रबंधन विशेष रूप से प्रभावी साबित हो सकता है। हम इन रोगों के कृत्रिम रूप से नियंत्रण के लिए अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्ययन शोध पत्रिका करंट साइंस में प्रकाशित किया गया है।